November
2020

IASBABA'S MONTHLY MAGAZINE

- उच्च शिक्षा के लिए एक वित्तीय मॉडल
- विश्व अराजकता से घिरी हुई है और यह लोकतंत्र के लिए खतरा है
- वैक्सीन की दौड़ में अंतिम चरण में, भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम
- भारत की विदेश नीति में होता परिवर्तन
- बिडेन के तहत, अमेरिका-भारत के भविष्य के संबंध
- 17 वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन हुआ
- भारत-लक्समबर्ग शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ

प्रस्तावना

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के परीक्षा प्रारूप में वर्तमान बदलाव के साथ, सामान्य अध्ययन-II और सामान्य अध्ययन III को साधारणतः समसामसयकी से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा, यूपीएससी की हालिया प्रवृत्ति के अनुसार, लगभग सभी प्रश्न समाचार-आधारित होने के बजाय मुद्दों पर आधारित हैं। इसलिए, तैयारी के लिए सही दृष्टिकोण केवल समाचार पढ़ने के बजाय मुद्दों को तयैार करना है।

इसे ध्यान में रखते हुए, हमारी वेबसाइट **www.iasbaba.com** दैनिक आधार पर मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए वर्तमान मामलों को कवर करती है। यह आपको विभिन्न राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों जैसे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइवमिंट, बिजनेस लाइन और अन्य महत्वपूर्ण ऑनलाइन स्रोतों से दिन के प्रासंगिक समाचार प्राप्त करने में मदद करेगा। समय के साथ, इनमें से कुछ समाचार प्रसंग महत्वपूर्ण मुद्दे बन जाएंगे।

UPSC ऐसे मुद्दों से सम्बंधित प्रश्न और इन पर सामान्य राय पर आधारित प्रश्न पूछती है। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए सामान्य जागरूकता और मुद्दे की समग्र समझ की आवश्यकता होती है। इसलिए, हम उम्मीदवारों के बीच सही समझ पैदा करना चाहते हैं – 'इन मुद्दों को कैसे कवर किया जाए ?

यह IASbaba की मासिक पत्रिका का 66 वां संस्करण है। यह संस्करण उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करता है जो NOVEMBER-2020 के महीने में खबरों में थे, जिन्हें **https://iasbaba.com/current-affairs-for-ias-upsc-exams/** से भी एक्सेस किया जा सकता है।

IASBABA से VALUE ADDITIONS

- **Think और Connectng the dots अवश्य पढ़ें और कनेक्ट करें।**
- **इसके अलावा, हमने Prelim और mains पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्नि snippets और टेस्ट योर नॉलेज (दैनिक करंट अफेयर्स पर आधारितPrelims MCQs) प्रस्तुत किया हैं जो आपको बेहतर revision के लिए मार्गदर्शन करेंगे।**
- **'Must Read' section,** आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करेगा कि, आप दैनिक आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों से किसी भी महत्वपूर्ण समाचार / संपादकीय को याद नहीं करेंगे।
- प्रत्येक समाचार लेख के तहत, **Connectng the dots** एक मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर जुड़ने और विचार करने की आपकी सोच को सुविधाजनक बनाता है। मूल रूप से, यह आपको बहु-आयामी दृश्य-बिंदु से एक मुद्दे को समझने में मदद करता है। आप मेन्स या इंटरव्यू देते समय इसके महत्व को समझेंगे।

'**Must Read' section**: हमने उन्हें पत्रिका में शामिल नहीं किया है। दैनिक आधार पर DNA का अनसुरण करने वाले इसका अनुसरण कर सकते हैं-

https://iasbaba.com/current-affairs-for-ias-upsc-exams/

"Tell my mistakes to me not to others, because these are to be corrected by me, not by them."

विषय वस्तु

इतिहास / संस्कृति / भूगोल

- मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन (Mansar Lake Development Plan inaugurated)
- 'अंतर्राष्ट्रीय सातवाधानम' कार्यक्रम का शुभारंभ ('International Satavadhanam' program launched)
- समाचार में धर्म: सरना धर्म (Religion in news: Sarna Religion)
- चर्चा में स्थल: पेरू (Place in news: Peru)
- समाचार में जगह: प्यूर्टो रिको (Place in news: Puerto Rico)
- सुस्त पूर्वोत्तर मानसून (Subdued Northeast Monsoon)

राजनीति / शासन

- केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना में विसंगतियां बताई गईं (Discrepancies pointed out in Central Vista Redevelopment Project)
- एकल पुरुष अभिभावक, अब बाल देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) के लिए पात्र हैं (Single Male Parent eligible for child care leave)
- सुधार की राह पर अर्थव्यवस्था (The road to economic recovery)
- अच्छे और सतर्क शासन के लिए पहल (Initiatives for Good and Vigilant Governance launched)
- उच्च शिक्षा के लिए एक वित्तीय मॉडल (A financial model for higher education
- एनडीपीएस कानून के तहत पुलिस के सामने दिया इकबालिया बयान सुबूत नहीं : सुप्रीम कोर्ट(Statements recorded by officers under the NDPS Act cannot be treated as confessions:SC)
- असंतुष्ट पत्नी के गुजारे भत्ते के भुगतान की गणना में बच्चे की देखभाल को भी शामिल किया जाये: सुप्रीम कोर्ट (Computation of maintenance to estranged wife will include child care: SC)
- राज्यों की वित्तीय क्षमता कमजोर हो रही है(The financial capacity of States is being weakened)
- मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 प्रारूप (Arbitration And Conciliation (Amendment) Ordinance, 2020 promulgated)
- वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा (Various development projects to be inaugurated in Varanasi)
- हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020
- तमिलनाडु NEET कोटा (Tamil Nadu NEET Quota)
- विशेष विवाह अधिनियम (SMA)(Special Marriages Act- SMA))
- सभी विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) को ऊर्जा संरक्षण (EC) अधिनियम, 2001 के तहत कवर किया जाना है (All the Electricity Distribution Companies (DISCOMs) to be covered under the Energy Conservation (EC) Act, 2001)
- मीडिया विनियमन (Media regulation)
- ड्राफ्ट नियम सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के तहत अधिसूचित
- अनुच्छेद 217 के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति (Additional Judges appointed as Permanent Judges of Allahabad HC under Article 217)
- अनुच्छेद 32 की सर्वोच्च न्यायालय व्याख्या (Supreme Court interpretation of Article 32)
- सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज लॉन्च हुआ (Safaimitra Suraksha Challenge launched)
- मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना (MITP) पर हस्ताक्षर हुए (Meghalaya Integrated Transport Project (MITP) signed)
- विश्व अराजकता से घिरी हुई है और यह लोकतंत्र के लिए खतरा है (A world in Chaos & Threats to Democracy)
- IBC के तहत संशोधित परिसमापन नियम (Amended liquidation regulations under IBC)
- तमिलनाडु में ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश जारी (Promulgation of ordinance to ban online Games in TN)
- पितृत्व अवकाश
- UMANG ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया
- बांध सुरक्षा विधेयक, 2019
- सहकारप्रज्ञ का शुभारंभ
- क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर के तहत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं स्वीकृत
- ग़ैरक़ानूनी धर्मान्तरण से निषेध अध्यादेश 2020,
- राष्ट्रीय पोषण मिशन पर रिपोर्ट: NITI Aayog

- जम्मू और कश्मीर में वन अधिकार अधिनियम
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया
- 'गरिमा गृह : ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए नेशनल पोर्टल' का ई-शुभारंभ'
- ड्राफ्ट मर्चेंट शिपिंग बिल, 2020
- पुलिस के लिए एक बेहतर भविष्य
- ब्रू जनजाति पुनर्वास के खिलाफ विरोध
- PRAGATI की बैठक आयोजित
- सामाजिक मुद्दे/ वेलफ़ेयर
- समाचार में समुदाय: असम के मियास (Community in news: Miyas of Assam)
- प्रसारभारती ने 51 शिक्षा टीवी चैनल शुरू किए (PrasarBharati to Launch 51 Education TV Channels)
- अरुणाचल प्रदेश सबसे अच्छा लिंगानुपात रिकॉर्ड किया गया है(Arunachal Pradesh records the best sex ratio)
- खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता के निर्माण और विस्तार के लिए योजना (Scheme For Creation And Expansion Of Food Processing And Preservation Capacities- CEFPPC)
- अटल संकाय विकास कार्यक्रम (Atal Faculty Development Programmes (FDPs)

महिलाओं से सम्बंधित मुद्दे

- गुजारा भत्ता दिशानिर्देश: रखरखाव कानूनों पर (Alimony guidelines: On maintenance laws)
- आपदाओं में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमताओं को मजबूत करना(Strengthening public health capacities in disasters)
- PPPs इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्तीय सहायता के लिए योजना को नया रूप दिया और जारी रखा जाए(The Scheme For Financial Support To PPPs in Infrastructure to be revamped and continued)
- महिला रोजगार(Women Employment)
- महिलाओं के अनुकूल शहर (Women Friendly Cities)

स्वास्थय समस्या

- स्कूल का बंद होना और पोषक तत्वों की कमी (School Closures and Nutrition Fallout)
- बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) रैंकिंग में भारत सबसे नीचे है(India ranks amongst the bottom in Body Mass Index (BMI) ranking)
- वैक्सीन की दौड़ में अंतिम चरण में, भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम(In vaccine race last lap, the key steps for India)
- डिलेरियम: पुराने कोविद -19 रोगियों के लिए लक्षणों में से एक (Delirium: One of the symptoms for older Covid-19 patients)
- भारत के कुपोषण की छाया से बाहर निकलना (Stepping out of the shadow of India's malnutrition)
- स्वास्थ्य नीति: आयुर्वेद डॉक्टर सामान्य सर्जरी कर सकते हैं (Health Policy: Ayurveda doctors to practise general surgery)

सरकारी योजनाएँ

- प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए फंड को बंद कर दिया गया (Funds meant for Pre-Matric Scholarship Scheme siphoned off)
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार (Emergency Credit Line Guarantee Scheme extended)

अंतरराष्ट्रीय

- भारत की विदेश नीति में होता परिवर्तन (The shifting trajectory of India's foreign policy)
- गिलगित-बाल्टिस्तान का महत्व (The importance of Gilgit-Baltistan)
- अमेरिका और पेरिस समझौता (US and Paris Agreement)
- संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (United Nations Industrial Development-UNIDO)
- समाचार में स्थल : टाइग्रे क्षेत्र, इथियोपिया (Place in news: Tigray region, Ethiopia)
- AIM-Sirius इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया गया (AIM–Sirius Innovation Programme 3.0 launched)
- वियतनाम और बांग्लादेश से सबक(Lessons from Vietnam and Bangladesh)
- आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौता हुआ (Peace Deal brokered Between Armenia And Azerbaijan)
- जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पारस्परिक समझौते (RAA) पर हस्ताक्षर किए Reciprocal Access Agreement (RAA) signed between Japan and Australia
- APEC आभासी बैठक आयोजित (APEC virtual meet held)
- चीन द्वारा भूटान में नये गांव पर दावा किया (New Village in Bhutan claimed by China)
- अवधि उत्पाद (नि: शुल्क प्रावधान) (स्कॉटलैंड) विधेयक / Period Products (Free Provision) (Scotland) Bill

भारत और विश्व

- भारतीय नौसेना जहाज ऐरावत ने मिशन सागर - II के तहत पोर्ट सूडान में प्रवेश किया
- भारत और इटली के बीच आभासी शिखर सम्मेलन हुआ (Virtual Summit between India and Italy held)
- बिडेन के तहत, अमेरिका-भारत के भविष्य के संबंध (Under Biden, the future of US-India ties)
- भारतीय राजनयिक प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति (ACABQ) के लिए चुने गए
- 17 वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन हुआ
- मालदीव के साथ 'रणनीतिक साझेदारी'
- अरुणाचल बॉर्डर के पास चीन का रेलवे निर्माण
- भारत और RCEP
- ब्रिक्स ने नई आतंकवाद विरोधी रणनीति अपनायी है
- प्रधानमंत्री-एफएमई योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण घटक का उद्घाटन
- भारत और भूटान वस्तुतः भूटान में रुपे कार्ड चरण -2 का शुभारंभ करेंगे
- भारत-लक्समबर्ग शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ
- 15 वां G-20 शिखर सम्मेलन आयोजित
- जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की बहु-पक्षीय तकनीकी समिति ने पेयजल और स्वच्छता में पाँच तकनीकों की सिफारिश की
- भारत और कजाकिस्तान के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 7 वां दौर आयोजित हुआ
- भारतीय सेना ने माइक्रोवेव हथियारों के इस्तेमाल से सम्बंधित रिपोर्ट को खारिज कर दिया है
- भारत ने अफगानिस्तान के लिए 150 परियोजनाओं की घोषणा की
- SDGs निवेशक मानचित्र भारत के लिए लॉन्च किया गया
- भारत-बहरीन के बीच समझौते

अर्थव्यवस्था

- अपनी तरह के पहले आदेश के बाद, RERA ने भूमि सौदे की सुविधा के लिए कमीशन पर एक सीमा का निर्धारण किया।
- पारंपरिक रोजगार श्रेणी के बाहर प्लेटफार्म कार्य को परिभाषित करने का प्रथम प्रयास
- प्राकृतिक गैस विपणन सुधार
- UPI ट्रांजैक्शंस 2 बिलियन का आंकड़ा पार किया
- भारत का विनिर्माण उत्पादन सबसे मजबूत वृद्धि दर्शाता है
- चीनी उद्योग: निर्यात सब्सिडी की आवश्यकता
- कैपिटल गुड्स सेक्टर को मजबूत करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति का
- ऑपरेशन ग्रीन्स - टॉप टू टोटल स्कीम
- उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना 10 और क्षेत्रों के लिए स्वीकृत
- आत्मानिर्भर भारत रोज़गार योजना
- वित्त मंत्री ने आत्मानिर्भर भारत 3.0 पर उपायों की घोषणा की
- यूके-जापान: ब्रेक्सिट के बाद के युग के लिए एक सौदा?
- भारत ने तकनीकी मंदी के दौर में प्रवेश किया: RBI
- डिजिटल कराधान और ओईसीडी: एक कमजोर स्तंभ पर
- कैलिब्रेटेड इकोनॉमिक पैकेज (आत्मनिर्भर भारत 3.0) - भाग 1
- पावर लाइनों के लिए आपातकालीन पुनर्प्राप्ति प्रणाली (ईआरएस)
- एशियाई अर्थव्यवस्थाओं का स्थानांतरण
- GIS वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) भारत का डिजिटल मैप
- लक्ष्मी विलास बैंक (LVB) संकट

कृषि

- केसर के कटोरे (Saffron bowl) का जल्द ही नॉर्थ ईस्ट का विस्तार किया जायेगा

पर्यावरण/ प्रदूषण

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)
- गंगा उत्सव 2020
- दिल्ली में वायु की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है
- ट्रिस्टन दा कुन्हा (Tristan da Cunha) ने अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा पूरी तरह से संरक्षित समुद्री भंडार घोषित किया

- भारत ने दो नवीन रामसर साइटों को शामिल किया
- भारत की प्रथम हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना
- डीम्ड वनों को समाप्त करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा पहल
- रोरिडो माइसेस फाइलोस्टैचिडिस (Roridomyces Phyllostachydis) -चमकने वाले मशरूम (Bioluminescent Mushroom)
- भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया
- 'ब्लू टाइड' परिघटना को महाराष्ट्र में देखा गया

समाचारों में जंतु / राष्ट्रीय उद्यान

- डेनमार्क के फॉर्मों में पल रहे मिंक या ऊदबिलाव के जरिए मनुष्यों में कोरोना वायरस (SARS-CoV-2) फैलने की पुष्टि की गई है।
- अंडमान में मेंढक की नई प्रजाति मिली
- विलो वॉर्ब्लर को भारत में पहली बार देखा गया

इन्फ्रास्ट्रक्चर / ऊर्जा

- जल एयरोड्रम और सी-प्लेन सेवा का उद्घाटन किया (Water Aerodrome and Sea-Plane service inaugurated)
- हिमालय के टेक्टोनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र
- हजीरा और घोघा के बीच रो-पैक्स सेवा शुरू (Hazira-Ghogha Ro-Pax Ferry Service to be inaugurated)
- सभी चार पहिया वाहनों के लिए FASTags अनिवार्य कर दिया गया है (FASTags mandatory for all four wheelers)
- दूरसंचार विभाग अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए नियमों को आसान बनाते है (Department of Telecom eases rules for other service providers)
- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना()Delhi-Ghaziabad-Meerut Regional Rapid Transit System Project
- सतत वैकल्पिक वहन योग्य परिवहन (SATAT) की ओर (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation (SATAT)
- महाराष्ट्र ने विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किए(Maharashtra sets up Desalination Plants)
- फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त संख्या संसाधन सुनिश्चित करने के संबंध में निर्णय (Decisions taken regarding Ensuring Adequate Numbering Resources for Fixed Line and Mobile Services)
- NIIF का ऋण प्लेटफ़ॉर्म स्वीकृत (NIIF's Debt Platform approved)

विज्ञान और तकनीक

- क्षुद्रग्रह 16 साइक (Asteroid 16 Psyche)
- NMM और HPC सुविधाओं के परिणामस्वरूप इसके आर्थिक लाभों में 50 गुना वृद्धि हुई है: NCAER रिपोर्ट (NMM and HPC facilities result in a 5 -fold increase in its economic benefits: NCAER Report)
- भविष्य में नई वैश्विक महामारियों के उभरने व फैलने की रफ़्तार और ज़्यादा तेज़ होगी: IPBES रिपोर्ट (Pandemics to emerge more often: New Report by IPBES)
- व्हाट्सएप ने आधिकारिक तौर पर एपेमेरल मैसेजिंग फीचर की घोषणा की है(WhatsApp officially announces Ephemeral Messaging feature)
- एक्स-रे और रेडियो संकेतों का मिश्रण पहली बार देखा गया (Mix of X-ray and radio signals observed for the first time)
- PSLV-C49 ने सफलतापूर्वक EOS-01 लॉन्च किया (PSLV-C49 successfully launches EOS- PSLV-C49 successfully launches EOS-01)
- भारत मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2020 को वस्तुतः आयोजित किया जाना है (India Mobile Congress (IMC) 2020 to be held virtually)
- थर्टी मीटर टेलीस्कोप या तीस मीटर की दूरबीन (Thirty Meter Telescope)
- एपोफिस का 2068 में पृथ्वी से टकराने की उम्मीद है (Apophis expected to hit Earth in 2068)
- परम सिद्धि ने 63 की वैश्विक रैंकिंग प्राप्त की
- भारतीय वैज्ञानिकों ने डचेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या डचेनी पेशी अपविकास के इलाज का प्रस्ताव दिया है(ndian Scientist proposes to have found treatment for Duchenne Muscular Dystrophy)
- प्रहरी -6 सैटेलाइट लॉन्च किया गया (Sentinel-6 Satellite launched)
- कोरोनावायरस मरीज न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित कर रहे हैं(Coronavirus patients develop Neutralising Antibodies)
- चीन का चांग'ते-5 चंद्र मिशन (China's Chang'e-5 lunar mission)
- इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (Electronic Vaccine Intelligence Network)
- ब्रेन फ़िंगरप्रिंटिंग (Brain Fingerprinting)

आपदा प्रबंधन

- DRDO ने फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम (FDSS) विकसित किया(DRDO develops Fire Detection and Suppression System (FDSS)
- चक्रवात का पूर्वानुमान (Cyclones forecast)

रक्षा / आंतरिक सुरक्षा / सुरक्षा

- राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल(National Cybercrime Reporting Portal)
- पिनका रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया(ENHANCED PINAKA Rocket successfully flight tested
- DRDO भवन में एंटी सैटेलाइट (A-SAT) मिसाइल स्थापित किया गया।(Anti-Satellite (A-SAT) Missile installed inside the DRDO Bhawan)
- कलवरी-क्लास सबमरीन INS वागीर को लॉन्च किया गया (Kalvari-Class Submarine INS Vagir launched)
- क्विक रिएक्शन सतह से हवा मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया(Quick Reaction Surface-to-Air Missile System successfully test-fired)
- असम-मिजोरम सीमा पर अशांति (Unrest along Assam-Mizoram border)
- हिमालय में वाटर बम (Water bomb in the Himalayas)
- ब्रह्मोस मिसाइल का भूमि-पर हमला करने वाले संस्करण सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया
- (Land-attack Version of BrahMos Missile successfully test-fired)
- भारतीय नौसेना द्वारा सी-गार्जियन ड्रोन (Sea Guardian Drones from USinducted by the Indian Navy)
- सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (Information Management And Analysis Centre -IMAC)

विविध

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

नवम्बर 2020 महीने के करेंट अफेयर्स MCQs की उत्तरकुंजी

इतिहास / संस्कृति / भूगोल

मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन (Mansar Lake Development Plan inaugurated)

भाग- GS प्रीलिम्स और GS- I – भूगोल और और GS- II- नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में-

- पर्यटन को बढ़ाने के लिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर में मानसर झील विकास योजना का उद्घाटन किया है।
- इस परियोजना को प्रत्येक वर्ष लगभग 20 लाख पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए तैयार किया जाता है।
- इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- मानसर झील जम्मू से 62 किमी दूर स्थित है।
- यह झील जंगल से ढकी पहाड़ियों की एक प्राकृतिक सीमा बनाती है।
- सुरिंसर-मानसर झीलें नवंबर 2005 में रामसर कन्वेंशन के रूप में नामित की गईं।
- तीर्थयात्रा के साथ-साथ विरासत के दृष्टिकोण से भी मानसर झील का अत्यधिक महत्व है

सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के निशान पाए गए (Traces of Dairy Production found in Indus Valley Civilisation)

भाग- GS प्रीलिम्स और GS I - प्राचीन इतिहास

समाचार में

- हाल ही में, भारतीय और कनाडाई पुरातत्वविदों द्वारा किये गए एक अध्ययन में पाया गया है कि हड़प्पावासियों द्वारा डेयरी उत्पादों का उत्पादन 2500 ईसा पूर्व में किया जा रहा था।

महत्वपूर्ण तथ्य

- सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन प्रचलित होने संबंधी साक्ष्यों की पहली बार वैज्ञानिक रूप से पुष्टि हुई है।
- यह परिणाम गुजरात के कोटड़ा भादली (Kotada Bhadli) में मिले मिट्टी के बर्तनों के अवशेषों के आणविक रासायनिक विश्लेषण (molecular chemichal techniques) पर आधारित हैं।
- शोधकर्ता स्थिर आइसोटोप विश्लेषण नामक प्रक्रिया का प्रयोग कर यह पहचानने में सक्षम थे कि पशुओं का प्रयोग कर डेयरी उत्पादों का निर्माण किया जाता था।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

सिंधु घाटी सभ्यता (IVC)

- इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है।
- भारत का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता के जन्म के साथ आरंभ हुआ।
- यह दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग 2,500 ईसा पूर्व में फला-फूला।
- इस सभ्यता के बारे में 1920 तक कुछ भी ज्ञात नहीं था, जब भारतीय पुरातात्विक विभाग ने सिंधु घाटी की खुदाई का कार्य आरंभ किया, जिसमें दो पुराने शहरों अर्थात मोहन जोदाड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेष निकल कर आए।
- 1924 में, ASI के महानिदेशक, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की।

'अंतर्राष्ट्रीय सातवाधानम' कार्यक्रम का शुभारंभ ('International Satavadhanam' program launched)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- I - संस्कृति

समाचार में

- हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय सातवाधानम' कार्यक्रम शुरू किया गया।
- एक साहित्यिक उपलब्धि के रूप में 'अवधमं' ने तेलुगु भाषा की गौरवशाली परंपरा में बहुत योगदान दिया है।
- इस कार्यक्रम का आयोजन डॉ. मेदसानी मोहन द्वारा तिरुपति में श्री कृष्णदेवराय सत्संग के तत्वावधान में किया गया था।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- अवधनाय कवि के साहित्यिक कौशल की एक परीक्षा की तरह है और इसमें मुश्किल साहित्यिक पोजरों को हल करना, कविताओं को सुधारना और एक साथ ऐसे कई कार्यों को करने की किसी व्यक्ति की क्षमता का परीक्षण करना शामिल है।
- इसकी उत्पत्ति संस्कृत साहित्यिक प्रक्रिया के रूप में हुई।
- यह आधुनिक समय में तेलुगु और कन्नड़ में कवियों द्वारा पुनर्जीवित किया गया था।
- इसमें विशिष्ट विषयों, मीटरों, रूपों, या शब्दों का उपयोग करके कविताओं का आंशिक सुधार शामिल है।

समाचार में धर्म: सरना धर्म (Religion in news: Sarna Religion)

भाग: GS प्रीलिम्स और जीएस- I - संस्कृति

समाचार में

- झारखंड सरकार ने केंद्र को सरना धर्म को मान्यता देने के लिए एक पत्र भेजने और 2021 की जनगणना में एक अलग कोड के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

सरना धर्म

- सरना विश्वास के अनुयायी प्रकृति की प्रार्थना करने में विश्वास करते हैं।
- विश्वास का आदर्श वाक्य "जल, जंगल, ज़मीन" है।
- इसके अनुयायी वन क्षेत्रों की रक्षा में विश्वास करते हुए पेड़ों और पहाड़ियों की प्रार्थना करते हैं।

क्या आप जानते हो?

- ऐसा माना जाता है कि पूरे देश में 50 लाख आदिवासियों ने 2011 की जनगणना में अपने धर्म को 'सरना' के रूप में रखा, हालांकि इसे किसी कोड के रूप में स्थान प्राप्त नहीं था।
- झारखंड में 32 जनजातीय समूह हैं, जिनमें से 8 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से सम्बंधित हैं।

चर्चा में स्थल: पेरू (Place in news: Peru)

भाग: GS प्रीलिम्स और जीएस- I - भूगोल

समाचार में

- पांच वर्षों में पेरू के पांचवें राष्ट्रपति, मैनुअल मेरिनो को पद ग्रहण करने के सिर्फ पांच दिन बाद सत्ता से बेदखल कर दिया गया, क्योंकि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन ने पेरू के राष्ट्रपतिय कथित रिश्वतखोरी पर आरोप लगाया गया था।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

पेरू

- यह पश्चिमी दक्षिण अमेरिका का एक देश है।
- यह उत्तर में इक्वाडोर और कोलम्बिया द्वारा, पूर्व में ब्राज़ील द्वारा, दक्षिण-पूर्व में बोलीविया द्वारा, दक्षिण दक्षिण में चिली, और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है।
- पेरू एक विविधता भरा देश है.जहाँ देश के उत्तर से दक्षिण पूर्व तक पर एंडीज़ पहाड़ फैला हुआ है और पश्चिम में कोस्टा (तट), एक संकीर्ण मैदान है, जो मौसमी नदियों द्वारा बनाए गए घाटियों को छोड़कर काफी हद तक शुष्क है। सिएरा (पहाड़ी क्षेत्र) एंडीज का क्षेत्र है; इसमें अल्टीप्लानो पठार के साथ-साथ देश की सबसे ऊंची चोटी, हुआस्करन 6786 मीटर (22,205 फीट) शामिल है। तीसरा क्षेत्र सेल्वा (जंगल) है, जो अमेज़न वर्षावन द्वारा कवर सपाट इलाके का एक विस्तृत विस्तार है जो पूर्व में फैला हुआ है। देश का लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र, इस क्षेत्र के भीतर स्थित है।
- यह देश द पैसिफिक प्यूमा का भाग है, जो लैटिन अमेरिका के प्रशांत तट के साथ-साथ राजनीतिक और आर्थिक समूहों का समूह है, यह देश सकारात्मक विकास, स्थिर मैक्रोइकॉनॉमिक की अर्थव्यवस्था को नींव बनना, बेहतर प्रशासन और वैश्विक एकीकरण का साझा रुझान रखते हैं।
- इसकी राजधानी लीमा है।

समाचार में जगह: प्यूर्टो रिको (Place in news: Puerto Rico)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- I - भूगोल और GS- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- दस वर्षों में तीसरी बार, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्यूर्टो रिको क्षेत्र ने राज्य के पक्ष में मतदान किया है, और इस तरह इसके साथ देश के वर्तमान 50 राज्यों के बराबर व्यवहार किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

प्यूर्टो रिको

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक अधीनस्थ क्षेत्र (unincorporated territory) है।
- प्यूर्टो रिको के लोगों को 1917 से संयुक्त राज्य के नागरिकता प्राप्त हैं और यह द्वीप एवं मुख्य भूमि के बीच स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं।
- क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका एक राज्य नहीं है, अतः प्यूर्टो रिको को अमेरिकी कांग्रेस में एक भी वोट प्राप्त नहीं है, 1950 के प्यूर्टो रिको संघीय संबंध अधिनियम के तहत, इस क्षेत्र को USA द्वारा अधीनस्थ क्षेत्र के रूप नियंत्रित किया जाता है।
- यह उत्तर-पूर्व कैरेबियन सागर में स्थित है।
- इसमें मुख्य मुख्य द्वीप और कई छोटे द्वीप जैसे मोना, कुलेब्रा और विएक्स शामिल हैं।
- इसकी राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर सैन जुआन है।

क्या आप जानतेहै?

- मूल रूप से स्वदेशी ताइनो लोगों द्वारा आबाद, प्यूर्टो रिको को 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस के आगमन के बाद स्पेन द्वारा उपनिवेशित किया गया था।
- 1898 में, स्पैनिश-अमेरिकी युद्ध के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्यूर्टो रिको का अधिग्रहण किया, जो एक निगमित क्षेत्रीय अधिकार बना हुआ है, जो इसे दुनिया की सबसे पुरानी कॉलोनी बनाता है।

सुस्त पूर्वोत्तर मानसून (Subdued Northeast Monsoon)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - I – जलवायु विज्ञान

समाचार में

- भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अब तक वर्षा की मात्रा में कमी हो रही है जो दर्शाता है कि इस वर्ष पूर्वोत्तर मानसून सुस्त बना हुआ है।

महत्वपूर्ण तथ्य

पूर्वोत्तर मानसून में कमी के कारण

- **प्रशांत महासागर में ला नीना की स्थिति:** ला नीना की स्थिति दक्षिण पश्चिम मानसून से जुड़ी वर्षा की तीव्रता में वृद्धि करती है, लेकिन पूर्वोत्तर मानसून से जुड़ी वर्षा पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ):** ITCZ की वर्तमान स्थिति ने मानसून के समय चल रहे खराब वर्षा में भी योगदान दिया है। वर्तमान में, ITCZ अपनी सामान्य स्थिति के उत्तर में स्थानांतरित हो गया है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

पूर्वोत्तर मानसून

- पूर्वोत्तर मानसून अक्टूबर से दिसंबर के मध्य प्रभावी होता है।
- यह दक्षिणी प्रायद्वीप तक ही सीमित है।

- इसे शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है।
- पूर्वोत्तर मानसून तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, यनम, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, माहे और लक्षद्वीप के लिए महत्वपूर्ण है।
- तमिलनाडु इन महीनों के दौरान अपनी वार्षिक वर्षा का लगभग 48% प्राप्त करता है, जिससे यह कृषि गतिविधियों को शुरू करने का प्रमुख कारक है।
- कुछ दक्षिण एशियाई देशों जैसे मालदीव, श्रीलंका और म्यांमार में भी अक्टूबर से दिसंबर के दौरान रिकॉर्ड वर्षा हुई है।

ला नीना

- ला नीना (जिसका अर्थ स्पेनिश भाषा में छोटी लड़की होता है) एक प्रतिसागरीय धारा है। इसका आविर्भाव पश्चिमी प्रशांत महासागर में उस समय होता है जबकि पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है।
- यह आमतौर पर अल नीनो के रूप में मौसम और जलवायु पर विपरीत प्रभाव डालता है, जो तथाकथित अल नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO) का गर्म चरण है।

ITCZ

- विषुवत वृत पर स्थित अंत:उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र हैं। यह भूमध्य रेखा के साथ उत्तर और दक्षिण की ओर की चालें उष्णकटिबंधीय में वर्षा का निर्धारण करती हैं।

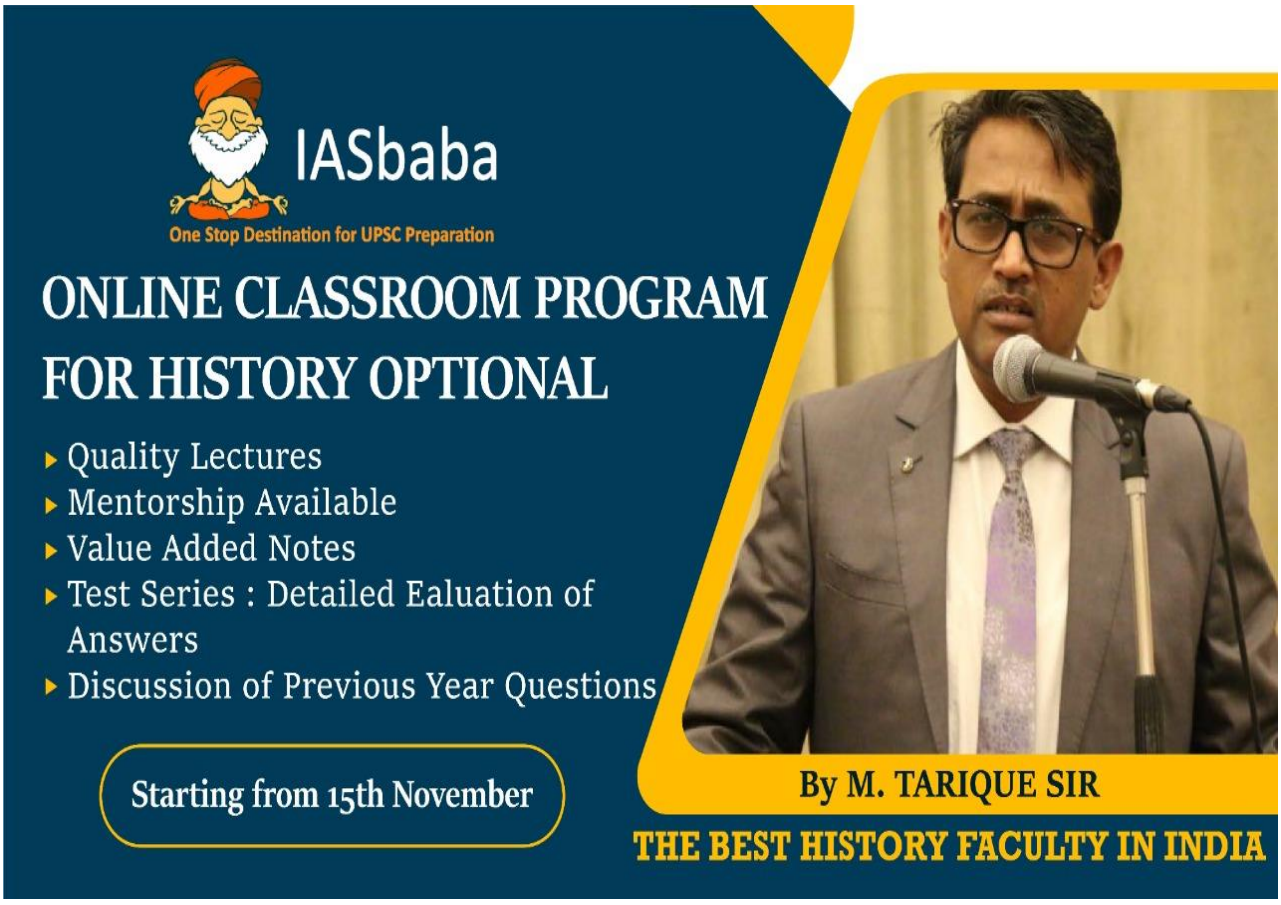

राजनीति / शासन

केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना में विसंगतियां बताई गईं (Discrepancies pointed out in Central Vista Redevelopment Project)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- II - संसद

समाचार में

- सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना हाल ही में समाचार में थी जब एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में इसकी प्रक्रिया में विसंगतियों के बारे में तर्क प्रस्तुत किया।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना

- यह नई दिल्ली के केंद्र में एक 3 किलोमीटर लंबा इलाका है जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाता है।
- संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और इसके आसपास राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले हरित क्षेत्र में मौजूद सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास की महत्वाकांक्षी योजना को आकार दिया जाएगा।
- केंद्र सरकार तीन किमी लंबे केंद्रीय विस्टा और संसद का पुनर्विकास कर रही है।
- सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाएगा, जो वर्तमान में दिल्ली भर में कई इमारतों में फैला हुआ है।

- मार्च 2022 तक इस नई संसद का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
- सार्वजनिक सुविधाओं और पार्किंग के साथ सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, नवंबर 2021 तक और मार्च 2024 तक एक नवीन सामान्य केंद्रीय सचिवालय बनकर तैयार हो जाएगा।
- संसद भवन और उत्तरी एवं दक्षिणी ब्लॉक को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको अन्य उपयोग में बदला जा सकता है।
- शास्त्रीभवन और कृषि भवन सहित 1947 के पूर्व की कुछ इमारतों के बाकी हिस्सों को ध्वस्त किए जाने की संभावना है।

एकल पुरुष अभिभावक, अब बाल देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) के लिए पात्र हैं (Single Male Parent eligible for child care leave)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- सरकारी पुरुष कर्मचारी जो एकल अभिभावक हैं, अब वे भी बाल देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) के हकदार होंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य

- एकल पुरुष अभिभावक, जिनमें अविवाहित कर्मचारी, विधुर और तलाकशुदा शामिल हैं, उनसे बच्चे हेतु बाल देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) उम्मीद की जा सकती है।
- एकल पुरुष अभिभावक में वे सभी कर्मचारी आएंगे जो अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा हैं और जिनके एक बच्चे की जिम्मेदारी अकेले उठाने की उम्मीद हो।
- कर्मचारी बाल देखभाल अवकाश पर होने पर भी लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) का लाभ उठा सकेगा। उन्होंने कहा कि पहले 365 दिन के लिए बाल देखभाल अवकाश छुट्टी वेतन का 100 फीसदी तक मंजूर की जा सकती है और अगले 365 दिन के लिए छुट्टी वेतन की 80 फीसदी हो सकती है।
- दिव्यांग बच्चे के मामले में, 22 वर्ष की आयु तक के बच्चों की देखभाल करने की स्थिति में इस शर्त को हटा दिया गया है।
- अब, किसी भी उम्र के विकलांग बच्चे के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा बाल देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) का लाभ उठाया जा सकता है।

क्या आप जानते है?

- चाइल्ड केयर लीव को अर्जित अवकाश माना जाता है।
- इसे आम तौर पर महिला कर्मचारियों को दिया जाता है।
- नाबालिग बच्चे (18 वर्ष तक के बच्चे) वाली महिला कर्मचारियों को दो नाबालिग बच्चों की देखभाल करने के लिए उनकी पूरी सेवा के दौरान दो साल की अधिकतम अवधि (अर्थात 730 दिन) के लिए चाइल्ड केयर लीव दिया जा सकता है।
- चाइल्ड केयर लीव की छुट्टी या तो बच्चों के पालन-पोषण के लिए दी जाती है या बच्चों की किसी भी ज़रूरत जैसे कि परीक्षा, बीमारी आदि की देखभाल के लिए दी जाती है।

सुधार की राह पर अर्थव्यवस्था (The road to economic recovery)

संदर्भ: आर्थिक गतिविधियों की वापसी और भारत में सक्रिय COVID-19 मामलों में गिरावट ने सुधार की उम्मीद जगाई है

क्या COVID-19 का वैश्विक पुनरुत्थान शेयर बाजार की वसूली के लिए खतरा है?

- शेयर बाजार ने अपने पूर्व- COVID के उच्च स्तर से थोड़ा नीचे कारोबार करने वाले बड़े कैप सूचकांकों ने उत्साह पूर्ण प्रतिक्रिया दी है।
- सरकार के कर संग्रह में तेजी आयी है। साथ ही कोरोना के मद्देनजर सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों की वजह से आर्थिक संकेतकों में भी सुधार जारी है।
- निवेश प्रवाह और बुनियादी बातों में सुधार ने बाजार को मौजूदा स्तरों तक खींच लिया है। निस्संदेह, अभी हम इससे पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकले हैं।
- अमेरिका और यूरोप में चल रही COVID-19 की दूसरी लहर, अमेरिकी चुनाव परिणाम आदि जैसे कारक हमारे बाजारों को प्रभावित करेंगे, यद्यपि यह अस्थायी रूप में है।

कौन से कारक फर्मों के लिए अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का निर्धारण करेंगे?

- भारत की आर्थिक रिकवरी, राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन के साथ-साथ उद्यमशीलता के प्रयासों जैसे कारकों द्वारा निर्धारित होगी।
- कम लीवरेज वाली फर्में, सुशासन, और पूंजी जुटाने की क्षमता, शुद्धता के साथ लागत में कटौती और मौजूदा स्थिति में अनुकूलन करने के लिए नवाचार न केवल फर्मों को जीवित रखेंगे, बल्कि इन्हें समृद्ध भी करेंगे।

यदि महामारी निरंतर बनी रहती है, तो ऐसे कौन से कारक है जिससे फर्मो के ठीक होने की उम्मीद हैं?

- आर्थिक गतिविधियों के सामान्य होने के साथ साथ **COVID-19 के सक्रिय मामलों में कमी** आ रही है।
- ऐसा प्रतीत हो रहा है कि टिके या **वैकसीन का निर्माण** सफलता के काफी करीब है।
- **मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता:** तेल, सोना और चीन से सामान के आयात में कमी ने भारत को चालू खाता-अधिशेष बना दिया है। अतः विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा ऋण से अधिक है।
- **विदेशी निवेश**: वैश्विक फर्म प्रत्यक्ष और साथ ही पोर्टफोलियो निवेश के लिए इच्छुक हैं।
- कृषि सुधारों से बड़ी ग्रामीण आबादी को भौतिक रूप से लाभ प्राप्त होगा।
- श्रम सुधार और डाक जीवन बीमा योजनाएं भारत के लिए एक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में सही कदम हैं।

आगे की राह

वे क्षेत्र जहां नीतिगत ध्यान देने की आवश्यकता है

- **क्रेडिट ट्रांसमिशन:** मौद्रिक नीति समायोजन है, लेकिन क्रेडिट ट्रांसमिशन में और सुधार की आवश्यकता है।
- **उधार लेने की लागत:** पॉलिसी की दरें जीवनकाल के निम्न स्तर पर हैं लेकिन उधार की लागत को उधारकर्ताओं के लिए कम किया जाना चाहिए।
- **क्षेत्र विशिष्ट में तेजी लाने की आवश्यकता है:** राजकोषीय प्रोत्साहन ने पिरामिड के निचले भाग में विकास का समर्थन किया है, लेकिन यात्रा, पर्यटन, होटल, खुदरा बिक्री, विमानन, बुनियादी ढांचे आदि क्षेत्रों को अधिक समर्थन की आवश्यकता है।
- **गैर-कर संसाधन:** राजकोषीय विवेक का मार्ग महत्वपूर्ण है**,** लेकिन इसे गैर-कर संसाधनों को बढ़ाकर प्राप्त करने की आवश्यकता है जैसे कि रणनीतिक विभाजन से प्राप्त आय और संपत्ति का मुद्रीकरण, सोने की जमा राशि में अटक गई पूंजी को अनलॉक करना आदि।
- **कानून का नियम:** व्यापार करने में आसानी में सुधार हुआ है लेकिन कानून के नियम को सुधारने की आवश्यकता है। हमारे कानून सबसे कम आम भाजक के लिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि बदमाश पर्याप्त सजा के बिना बच जाते हैं। इससे बाकी के लिए अनुपालन की लागत बढ़ जाती है। जब तक निवेशकों द्वारा कानून का अनुभव नहीं किया जाता है**,** तब तक निवेश में तेजी नहीं आ सकती है।
- **असमानता:** इन चुनौतीपूर्ण समय में असमानता में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन अंततः छोटी और मध्यम कंपनियों को प्रतिस्पर्धी और समृद्ध बनने की आवश्यकता है।

अच्छे और सतर्क शासन के लिए पहल (Initiatives for Good and Vigilant Governance launched)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - शासन

समाचार में

- हाल ही में, DARPG – प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के अंतिम दिन अच्छे और सतर्क शासन के लिए नई पहल का प्रारंभ किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- "महामारी में सुशासन प्रथाओं पर गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस पर विचार बॉक्स लॉन्च किया गया और DARPG के साथ-साथ MyGov प्लेटफॉर्म पर भी संचालित किया जा रहा है।
- "ई-गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ आचरण" पर सोशल मीडिया ट्वीट भी लॉन्च किया गया।
- "सतकार भारत**,** समृद्धि भारत" (Satark Bharat, Samriddh Bharat) पर गोलमेज पर चर्चा हुई।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

- प्रति वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन (31 अक्टूबर) पर किया जाता है।
- उद्देश्य: (1) नागरिक भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में अखंडता और एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करना; (2)भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध जारी रखने के लिए सरकार के संकल्प को दोहराना।
- 2020 के लिए विषय: "सतर्क भारत, समृद्ध भारत - Satark Bharat, Samriddh Bharat"

केंद्रीय सतर्कता आयोग

- यह एक स्वतंत्र सांविधिक (statutory) निकाय है।
- यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है।
- भारत का केन्द्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission- CVC) भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है।
- यह केंद्र सरकार के संगठनों में विभिन्न अधिकारियों को उनके सतर्कता कार्य की योजना, क्रियान्वयन, समीक्षा और सुधार करने की सलाह देते है।
- इस आयोग के गठन की सिफारिश संथानम समिति (1962-64) द्वारा की गयी थी।
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को संसद द्वारा वर्ष 2003 में पारित किया गया।
- इसमें एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त जो कि अध्यक्ष होता है तथा दो अन्य सतर्कता आयुक्त (सदस्य जो दो से अधिक नही हो सकते) होते हैं।
- आयोग में एक अध्यक्ष व दो सतर्कता आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व केन्द्रीय गृहमंत्री होते हैं।
- इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो), तक होता है। अवकाश प्राप्ति के बाद आयोग के ये पदाधिकारी केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं।

उच्च शिक्षा के लिए एक वित्तीय मॉडल (A financial model for higher education)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III

संदर्भ: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसका उद्देश्य 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% के सकल नामांकन अनुपात को प्राप्त करना है।

क्या आपको पता है?

- वर्तमान में, उच्च शिक्षा में भारत का सकल नामांकन अनुपात (GER) 28% है। यह वैश्विक औसत नामाकंन अनुपात 38% से काफी कम है और यह चीन के सकल नामांकन अनुपात (GER) 51% से काफी कम है।
- 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इस वर्ष 15,000 से अधिक स्नातक की उपाधि प्राप्त करेंगे, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) में सिर्फ एक राज्य विश्वविद्यालय, एरिज़ोना स्टेट विश्वविद्यालय, प्रत्येक वर्ष 13,500 विधार्थियों को स्नातक की उपाधि प्रदान करता है।

उच्च शिक्षा के साथ वित्तीय चिंताएं

- **अपर्याप्त अवसंरचना:** एनईपी 2020 में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मौजूदा संस्थानों की स्केलिंग के साथ-साथ नए प्रमुखों के निर्माण का आह्वान किया गया है।
- **धन की आवश्यकता**: जबकि मौजूदा संस्थानों के स्केलिंग-अप और नए संस्थानों के निर्माण के लिए अतिरिक्त बजटीय आवंटन की आवश्यकता होती है**,** जिससे उन्हें अच्छी तरह से आवर्ती आधार पर पैसे की आवश्यकता होती है।
- **आउटडेटेड वित्तीय मॉडल:** एनईपी उच्च शिक्षा और पी के लिए सकल घरेलू उत्पाद का एक निश्चित प्रतिशत आवंटित करके धन के इस मुद्दे को हल करने की कोशिश कर रहा है

1. **ट्यूशन फीस का पुनर्गठन - आय आकस्मिक ऋण का उपयोग**

- ट्यूशन फीस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में सबसे अधिक विश्वविद्यालयों के लिए आय का एक चौथाई तक योगदान करती है।
- आईआईटी में, ट्यूशन फीस केवल 6-7% तक योगदान करती है, क्योंकि छात्रों का केवल एक अंश (लगभग एक तिहाई) ट्यूशन फीस की ऊपरी सीमा का भुगतान करता है। अन्य लोग अपनी सामाजिक श्रेणी और आर्थिक स्थिति के आधार पर बहुत कम राशि का भुगतान करते हैं।
- यह योगदान न केवल अत्यधिक रियायती ट्यूशन फीस को बढ़ाकर, बल्कि सभी छात्रों को शुल्क-भुगतान की श्रेणी में लाकर भी बढ़ाया जा सकता है।
- यह एक केंद्रीयकृत वित्तीय ढांचे के माध्यम से संपार्श्विक-मुक्त और ब्याज मुक्त आय आकस्मिकता ऋण (ICL) की पेशकश करके छात्रों और उनके परिवारों को अग्रिम वित्तीय बाधाओं से अलग करके प्राप्त किया जा सकता है।
- ऑस्ट्रेलिया का उच्च शिक्षा ऋण कार्यक्रम (HELP) एक व्यापक रूप से प्रशंसित ICL मॉडल है जिसे ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है। पुनर्भुगतान ऋणी के आय स्तर से जुड़े होते हैं और सीधे ऑस्ट्रेलियाई कर अधिकारियों द्वारा एकत्र किए जाते हैं।
- ICL अमेरिका में दिए जाने वाले शिक्षा ऋणों से अलग है, जो बड़े पैमाने पर छात्र ऋण समस्याओं का कारण बने हैं।

2. **स्टार्टअप / प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क में अनुसंधान अनुदान / इक्विटी निवेश**

- आय का एक तिहाई अनुसंधान विबिन्न प्रकार गतिविधियों से आ सकते है। हालांकि अनुसंधान मुख्य रूप से सरकार द्वारा प्रायोजित है, अमेरिका और फ्रांस में विश्वविद्यालय गैर-सरकारी स्रोतों से अपने शोध कोष का एक तिहाई भाग जुटाते हैं
- आईआईटी जैसे HEI निजी क्षेत्र से धन का दोहन कर सकते हैं, अनुसंधान स्टार्ट-अप में निवेश कर सकते हैं और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बौद्धिक संपदा लाइसेंसिंग तंत्र को मजबूत कर सकते हैं।
- IIT बॉम्बे में IIT दिल्ली में फाउंडेशन ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (FITT) और IIT बॉम्बे में सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (SINE) जैसे संस्थान तकनीकी स्टार्ट-अप में संस्थागत इक्विटी निवेश की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।
- आईआईटी दिल्ली द्वारा दुनिया की सबसे सस्ती कोविड -19 परीक्षण किट का हालिया लॉन्च और आईआईटी दिल्ली स्टार्ट-अप्स द्वारा 4.5 मिलियन से अधिक निर्यात-गुणवत्ता वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति, HEIs द्वारा इस तरह के निवेश के संभावित छोटे प्रदर्शन हैं।

3. धर्मश्य दान

- हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) ने दुनिया भर के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई गई धर्मश्य दान की अवधारणा को आगे बढ़ाया है।
- एक बं धर्मश्य दान एक कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा निवेश की गई संपत्तियों का एकत्रीकरण है**,** जो अपने शैक्षिक मिशन समर्थन प्रदान करते है।
- एक संस्थान के धर्मश्य दान में वास्तव में सैकड़ों या हजारों व्यक्ति शामिल होते हैं।
- एक धर्मश्य दान दाताओं को इस उद्देश्य के साथ अपने निजी डॉलर को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए स्थानांतरित करने की अनुमति देता है कि जब तक कि संस्था का अस्तित्व बना रहेगा, वह इन उद्देश्यों के लिए कार्य करते रहेंगे। जब तक कि संस्था का अस्तित्व बना रहता है, यह दाता और एक संस्था के बीच एक कॉम्पैक्ट का प्रतिनिधित्व करती है।
- धर्मश्य दान न केवल पूर्व छात्रों से बल्कि उद्योग, परोपकारी और सरकारों से भी उठाए जाते हैं।
- पिछले साल, IIT दिल्ली ने 1 बिलियन $ के लक्ष्य के साथ एक एंडोमेंट फंड लॉन्च किया, जो हर साल 700 करोड़ की निवेश आय प्रदान करेगा।
- एक सफल बंदोबस्ती मॉडल को नौकरशाही बाधाओं को दूर करने के लिए फंड जुटाने वाली टीमों और निवेश नीति में बदलाव की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

- ट्यूशन फीस, अनुसंधान अनुदान, और धर्मश्य दान को अपनी स्वायत्तता बढ़ाने के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों की आय में एक तिहाई योगदान करना चाहिए और साथ ही वैश्विक रैंकिंग में सुधार भी होगा।

Connecting the dots

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम
- ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड

टेली लॉ योजना के जरिए लाखों लोगों को फायदा हुआ है(Lakhs of people benefit through Tele-Law)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - शासन

समाचार में

- हाल ही में टेली लॉ खबरों में था।
- लगभग 4 लाख लाभार्थियों को सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से कानूनी सलाह प्राप्त हुई।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

टेली लॉ कार्यक्रम

- यह 2017 में न्याय विभाग द्वारा पूर्व-मुकदमेबाजी चरण में मामलों को संबोधित करने के लिए शुरू किया गया था।
- इस कार्यक्रम के तहत, पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटरों के विशाल नेटवर्क पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन / इंस्टेंट कॉलिंग सुविधाओं की स्मार्ट तकनीक का उपयोग कमजोर समुदायों को समय पर और मूल्यवान कानूनी सलाह लेने के लिए पैनल वकीलों के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है।
- यह NALSA और CSC- सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अग्रिम पंक्ति के स्वयंसेवकों के एक समूह के माध्यम से समूहों और समुदायों के लिए प्रचलित है।

एनडीपीएस कानून के तहत पुलिस के सामने दिया इकबालिया बयान सुबूत नहीं : सुप्रीम कोर्ट(Statements recorded by officers under the NDPS Act cannot be treated as confessions:SC)

भाग: GS प्रीलिम्स और जीएस- **II** - न्यायपालिका

समाचार में

- SC के अनुसार नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस कानून) की धारा 67 के तहत एक पुलिस अधिकारी को दिया गया इकबालिया बयान एक सुबूत के रूप में स्वीकार्य बयान नहीं माना जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए बयानों को स्वीकारोक्ति नहीं माना जा सकता है।

- बहुमत का मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अधिनियम के तहत स्वीकार किए गए बयानों को आधार के रूप में रखा जाता है, तो यह संवैधानिक गारंटी का सीधा उल्लंघन होगा।
- अदालत ने यह भी कहा कि यहाँ प्रयुक्त संदर्भ "पुलिस अधिकारियों" के लिए किया जाता है, तो इसका मतलब न केवल राज्य पुलिस बल से संबंधित पुलिस अधिकारी होता है, बल्कि ऐसे अधिकारी भी शामिल होते हैं जो अन्य विभागों से संबंधित हो सकते हैं।
- न्यायलय के अनुसार सत्तारूढ़ दल कई मामलों में साक्ष्य को प्रभावित करेगा, जिसमें कथित ड्रग्स मामले की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा की जा रही है, जिसमें अभिनेता रिया चक्रवर्ती और 24 अन्य को आरोपी बनाया गया है।

असंतुष्ट पत्नी के गुजारे भत्ते के भुगतान की गणना में बच्चे की देखभाल को भी शामिल किया जाये: सुप्रीम कोर्ट (Computation of maintenance to estranged wife will include child care: SC)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - I – समाज और GS - II - न्यायपालिका

समाचार में

- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि असंतुष्ट पत्नी के गुजारे भत्ते के भुगतान की गणना में बच्चे की देखभाल को भी शामिल किया जाये

महत्वपूर्ण तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यदि महिला शिक्षित और पेशेवर रूप से योग्य हो, फिर भी उसे अपनी पारिवारिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रोज़गार के अवसरों का त्याग करने पड़े तो यह पति द्वारा देय मासिक अंतरिम रखरखाव को निर्धारित करते करते समय इस कारक को भी भत्ते का निर्धारण करते समय न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाएगा। ।
- अदालत ने यह भी पाया कि अंतरिम अनुरक्षण के अनुदान के लिए दलीलें वर्षों से अदालतों में लंबित है, भले ही कानून ने इसके लिए 60 दिन का समय निर्धारित किया हो, अदालत द्वारा नोटिस जारी करने की तारीख से ही पति की पत्नी के आवेदन पर पति द्वारा दिए गए अनुदान के रखरखाव का भुगतान करना होगा।
- ऐसा पहली बार हुआ है जब उच्चतम न्यायालय ने बच्चों की देखभाल करने के लिए महिलाओं द्वारा कैरियर के त्याग पर विचार किया है।
- SC ने फैसला सुनाया कि यह उसके लिए अंतरिम मुआवजे के अनुदान को बढ़ाने के लिए एक उचित घटक है , सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला महिलाओं के अंतरिम मुआवजे को बढ़ाने के लिए दिया गया है, ताकि वह बिना किसी परेशानी के जीवन जी सकें।
- आमतौर पर अदालतें ऐसे फैसले देने से पहले पति की आय और संपत्ति को ध्यान में रखती हैं, उसके बाद ही पत्नी को देने वाली राशि को निर्धारित किया जाता है।

- इसके अलावा न्यायालय के लिये अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को संबोधित करना भी काफी आवश्यक है। नियमों के अनुसार, एक वैवाहिक संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा अलग-अलग कानूनों जैसे- विशेष विवाह अधिनियम (1954), हिंदू विवाह अधिनियम (1955) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 आदि के तहत संबंध को समाप्त करने और गुज़ारे भत्ते के भुगतान के लिये अर्ज़ी दी जा सकती है।

राज्यों की वित्तीय क्षमता कमजोर हो रही है(The financial capacity of States is being weakened)

संदर्भ: विभिन्न माध्यमों से केंद्र सरकार ने राज्यों की राजकोषीय संसाधन क्षमता में काफी कमी की है। राज्यों को अपने नागरिकों की विकासात्मक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है लेकिन दुर्भाग्य से, राज्यों की वित्तीय क्षमता संरचनात्मक रूप से कमजोर हो रही है। इससे सम्बंधित कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:

1. वास्तविक विचलन में कमी

- वित्त आयोग, केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए करों में से राज्यों की हिस्सेदारी की सिफारिश करते हैं। उनकी सिफारिशों का आमतौर पर पालन किया जाता है।
- वर्ष 2014-15 के शुरूआत मेंवास्तविक विचलन वित्त आयोग के अनुमान **से** 14% कम था। इसके बाद के विचलन प्रत्येक वर्ष कम हुए हैं, 2019-20 की अवधि में यह -37% के साथ समाप्त हुई
- 2014-15 और 2019-20 के बीच**,** राज्यों को वित्त आयोग द्वारा अनुमानित 7,97,549 करोड़ रूपये कम मिला है।
- इससे राज्यों की राजकोषीय संसाधन क्षमता में एक निर्विवाद और पर्याप्त कमी हुई है।

2. विभाज्य पूल का कम होना

- केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न उपकर और अधिभार लगाये जाते है। वे विभाज्य पूल का भाग नहीं होते हैं। यह केंद्र को राजस्व जुटाने की अनुमति देता है और उन्हें राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है।
- कैग ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेस पूल के दुरुपयोग को भी उजागर किया है।
- जब करों को सेस और अधिभार के साथ बदल दिया जाता है, जैसा कि सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के मामले में बार-बार किया गया है, तो उपभोक्ता एक ही कीमत का वहन करता है। लेकिन केंद्र सरकार उस राजस्व का अधिक भाग रखती है और विभाज्य पूल के आकार को कम करती है। परिणामस्वरूप, राज्य के राजकोषीय संसाधन क्षमता में कमी हो जाती हैं।
- 2014-15 और 2019-20 के बीच, केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में उपकर और अधिभार 9.3% से बढ़कर 15% हो गया है
- अकेले 2019-20 में, केंद्र सरकार द्वारा सेस और सरचार्ज से 111 3,69,111 करोड़ रूपये एकत्र करने का अनुमान था, इसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाएगा।
- सरकार ने विभाज्य पूल के आकार को कम करने के लिए इस मार्ग का दोहन किया है।

3. जीएसटी की कमी

- वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को अपनाने के बाद से राज्यों को राजस्व का विस्तार करने की क्षमता बाधित हुई है।
- जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम के तहत, राज्यों को 2015-16 के आधार वर्ष राजस्व पर 14 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वृद्धि दर पर राजस्व के बीच के अंतर के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया गया है और जीएसटी से पांच वर्षों के लिए वास्तविक राजस्व जून 2022 तक समाप्त हो रहा है। इसकी भरपाई के लिए लेवी और सिन वस्तुओं पर उपकर लगाया जायेगा।
- राज्यों को जीएसटी मुआवजा 2021-22 के साथ समाप्त होगा। लेकिन सेस जारी रहेगा।
- 2019-20 के दौरान, उपकर 95,444 करोड़ रुपये था। इस वर्ष के असामान्य अपवाद के साथ, आने वाले वर्ष समान या अधिक उपकर राजस्व उत्पन्न करेंगे।
- COVID-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण, यह उम्मीद की जाती है कि राज्यों में लगभग 3 लाख करोड़ GST की कमी होगी और केंद्र कह रहा है कि यह केवल 1.8 लाख करोड़ की क्षतिपूर्ति करेगा।
- दूसरी ओर, राज्यों का तर्क है कि केंद्र सरकार को इस साल की जीएसटी की कमी को पूरा करना चाहिए और इसकी गणना राज्यों द्वारा की जनि चाहिए। उधार लिया गया संपूर्ण ऋण, उस अनुमानित उपकर राजस्व से चुकाया जा सकता है जो 2022 से आगे बढ़ना जारी रखेगा।

परिणामों

- **कम अनुदान:** ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अतिरिक्त, इस साल केंद्रीय अनुदान में भी काफी कमी की संभावना है। उदाहरण के लिए, कर्नाटक को वार्षिक अनुदान के रूप में 70,31,570 करोड़ आवंटित किए गए थे। वास्तविक अनुदान 37,17,372 करोड़ हो सकता है।
- **राजस्व में कमी:** इन सभी कारणों के कारण, राज्यों इस वर्ष अपने राजस्व में 20% -25% की गिरावट का अनुभव कर सकते है।
- **राज्यों द्वारा उधार में वृद्धि:** अपने वित्त के लिए इस तरह के चरम पर काबू पाने के लिए और अपने कल्याण और विकास जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए, राज्य अब भारी उधार का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। राज्यों द्वारा उधार में वृद्धि का बोझ कई वर्षों के लिए राज्य के बजट पर भारी पड़ेगा।
- **सामाजिक प्रभाव:** ऋण और ब्याज, वेतन और पेंशन, एवं स्थापना व्यय का भुगतान करने के बाद, विकास और कल्याण के लिए बहुत कम धन बचेगा। परिणामस्वरूप, प्रति व्यक्ति आय, मानव संसाधन विकास और गरीबी में प्रतिकूल परिणाम महसूस किए जाएंगे।

निष्कर्ष

- विकास और अवसरों एवं वृद्धि में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मजबूत राज्य एक मजबूत भारत का नेतृत्व करते हैं। राज्यों का व्यवस्थित रूप से कमजोर होना न तो संघवाद और न ही राष्ट्रीय हित में कार्य करता है।

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 प्रारूप (Arbitration And Conciliation (Amendment) Ordinance, 2020 promulgated)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS -II -पॉलिटी एंड गवर्नेंस

समाचार में

भारतीय राष्ट्रपति ने **'**मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम**'** 1996 में संशोधन करने के लिए **'**मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अध्यादेश 2020**'** को प्रख्यापित (promulgated) किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- अध्यादेश में**, 'धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से किये जाने वाले मध्यस्थता समझौते अथवा अनुबंधों'** के मामले में संबंधित पक्षकारों को **'मध्यस्थता निर्णय'** के प्रवर्तन पर बिना शर्त **'रोक'** (Stay) लगाए जाने का अवसर प्रदान किया गया है।
- अभी तक किसी मध्यस्थता फैसले के खिलाफ कानून की धारा 36 के तहत अपील दायर किए जाने के बावजूद इसे लागू किया जा सकता था।संशोधन के अनुसार, यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट होता है, कि संबंधित मामले में दिया गया 'मध्यस्थता निर्णय', प्रथमदृष्टया, 'धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से किये जाने वाले मध्यस्थता समझौते अथवा अनुबंधों' पर आधारित है, तो अदालत अधिनियम की धारा 34 के तहत, प्रदान किये गए 'मध्यस्थता निर्णय' पर अपील लंबित रहने तक बिना शर्त रोक लगा देगी।
- अध्यादेश में मध्यस्थता अधिनियम की 8वीं अनुसूची को निरसित कर दिया गया है। 8वीं अनुसूची में मध्यस्थों (Arbitrators) की आवश्यक अहर्ता के प्रमाणन संबंधी प्रावधान सम्मिलित थे।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - संविधान

समाचार में

- बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक वरिष्ठ पत्रकार की बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका पर सुनवाई की, जिसे पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया था।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है।
- इस प्रकार रिट जारी करने की शक्ति मुख्य रूप से प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक उपचार का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए किया गया प्रावधान है।
- रिट के पांच प्रकार हैं: बन्दी प्रत्यक्षीकरण**,** परमादेश**,** उत्प्रेषण**,** निषेधाज्ञा और अधिकार पृच्छा
- परमादेश: एक न्यायिक रिट जो एक उच्च न्यायालय के आदेश के रूप में जारी की जाती है या किसी व्यक्ति को सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य करने का आदेश देती है। यह कानूनी रूप से कार्य करने और गैर कानूनी कार्य के अंजाम से बचने के लिए, एक आदेश के रूप में एक न्यायिक उपाय है

- निषेधाज्ञा: निषेधाज्ञा का अर्थ है "मना करना या बंद करना" और आम बोलचाल में इसे 'स्टे आर्डर' के रूप में जाना जाता है। जब कोई निचली अदालत या एक अर्ध न्यायिक निकाय एक विशेष मामले में अपने अधिकार क्षेत्र में प्रद्त्त अधिकारों को अतिक्रमित कर किसी भी मुक़दमें की सुनवाई करती है तो सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोई भी उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है। भारत में, निषेधाज्ञा को मनमाने प्रशासनिक कार्यों से व्यक्ति की रक्षा के लिए जारी किया जाता है।
- **उत्प्रेषण (Certiorari)**:उत्प्रेषण एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ 'सूचित करने के लिए' है। 'उत्प्रेषण' को एक न्यायिक आदेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आचरण से संबंधित होता है और कानूनी कार्यवाही में उपयोग किया जाता है। इसे निगम जैसे संवैधानिक और सांविधिक निकायों, कंपनियों और सहकारी समितियों जैसे निकायों और सहकारी समितियों तथा निजी निकायों तथा व्यक्तियों के खिलाफ जारी अदालत द्वारा प्रमाणित और कानून के अनुसार किसी भी कार्रवाई के रिकार्ड की आवश्यकता होती है।
- **अधिकार पृच्छा (Quo warranto)** : • अधिकार पृच्छा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "किस वारंट द्वारा"। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसका वह हकदार नहीं है तब न्यायालय इस (अधिकार पृच्छा) को जारी कर सकता है और व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है।
- **बंदी प्रत्यक्षीकरण**: बंदी प्रत्यक्षीकरण एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है कि "आपके पास शरीर होना चाहिए"। रिट एक अदालत के समक्ष एक ऐसे आदमी को पेश करने के लिए जारी की जाती है जिसे हिरासत में या जेल में रखा गया है और हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया है और यदि यह पाया जाता है कि हिरासत में अवैध तरीके से रखा गया है तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति को रिहा करा देती है। रिट का उद्देश्य अपराधी को दंडित करने का नहीं होता लेकिन अवैध तरीके से हिरासत में लिए गये व्यक्ति को रिहा कराना होता है।

क्या आप जानते है?

- सितंबर, 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट दायर नहीं किया जा सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जैसा कि मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत प्रदान की जाती है, उसे गैरकानूनी हिरासत नहीं माना जा सकता है।

भारत के आईटी सेक्टर में इंस्पेक्टर राज का अंत (The End of Inspector Raj in India's IT Sector)

संदर्भ: सरकार ने दूरसंचार विभाग के अन्य सेवा प्रदाता यानि ओएसपी दिशानिर्देशों को काफी सरल कर दिया है और IT / ITeS उद्योग के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। 50 लाख लोगों को रोजगार देने वाले उद्योग के लिए, यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

अन्य सेवा प्रदाता (OSP) क्या हैं?

- OSP ऐसी इकाइयाँ प्रदान कर रहे हैं जो दूरसंचार सेवाओं का उपयोग करते हुए अनुप्रयोग सेवाएँ, IT सक्षम सेवाएँ या किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग सेवाएँ प्रदान कर रही हैं। यह शब्द व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ), ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (केपीओ), आईटी सक्षम सेवा (आईटीईएस) के, कॉल सेंटर, आदि को संदर्भित करता है।
- दूसरे शब्दों में, ओएसपी अपने संचालन के लिए दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करने वाली कंपनियां हैं जैसे टेली-बैंकिंग, टेली-मेडिसिन, टेली-ट्रेडिंग, ई-कॉमर्स, कॉल-सेंटर संचालन आदि।
- OSP विनियम 1990 के दशक में पेश किए गए थे, जब भारत में व्यापार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ) शुरू हुई थी और भारतीय दूरसंचार उद्योग BSNL से परे जा रहा था।
- सरकार ने उद्योग को विकसित करने और संसाधनों की कमी के कारण यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए OSP नियम और शर्तें पेश कीं।

ओएसपी के लिए पहले विनियामक शासन क्या था?

- शर्तों में OSP लाइसेंस के लिए पंजीकरण, बीपीओ फर्मों और बैंक गारंटी को ट्रैक करने के लिए लगातार रिपोर्टिंग दायित्व शामिल हैं।
- सूत्रधार (facilitator) के रूप में जो शुरू हुआ वह धीरे-2 बोझ बन गया, जैसे-जैसे उद्योग बढ़ता गया साल दर इनकी वजह से समस्या बढती गयी।
- उदाहरण के लिए, लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली कंपनी को प्रति कार्यालय 1 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी का भुगतान करना चाहिए। इसलिए, यदि कंपनी के 76 कार्यालय हैं, तो उसे बैंक गारंटी के रूप में 76 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ता था। जबकि एक बड़ी फर्म इसे वहन कर सकती है, परन्तु छोटी कंपनियों पर यह बोझ है।
- उन कंपनियों के लिए जो नए परिचालन के लिए आधार के रूप में भारत का उपयोग करने या न करने का मूल्यांकन कर रही थीं, इन विनियमों ने उनके संचालन के लिए उच्च स्तर की बाधाएं उत्पन्न कर दीं और इस प्रकार उन्हें भारत में अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए हतोत्साहित किया गया।

नए दिशानिर्देश

- नए दिशानिर्देशों के अनुसार, देश में सेवाएं प्रदान करने के लिए ओएसपीज़ को डॉट में रजिस्टर करना होता था। नए दिशानिर्देशों में रजिस्ट्रेशन की जरूरत को हटा दिया गया है।
- संकीर्ण परिभाषा के अनुसार डेटा-संबंधित कार्यों में लगे बीपीओ उद्योग को ओएसपी नियमों के दायरे से बाहर कर दिया गया है।
- वे कुछ संस्थाएँ जिनके लिए OSP नियम अब लागू होते हैं, उन्हें केवल कुछ सुरक्षा दायित्वों का पालन करने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा, नेटवर्क आरेख की आवश्यकता और घर से काम करने वाले सभी एजेंटों के लिए स्थिर आईपी पते का उपयोग करने जैसे प्रतिबंधों को भी दूर किया गया है।

नए नियमों के गुण

- **इंस्पेक्टर राज का अंत:** OSP के लिए नियामक शासन को अब उदार बनाया गया है और प्रभावी ढंग से इंस्पेक्टर राज को समाप्त कर दिया गया है जो कि इन पुराने नियमों ने इतने लंबे समय तक बनाए रखा था।
- **व्यापार बढ़ाने में आसानी:** लगातार रिपोर्टिंग दायित्वों के साथ दूर करने से व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन (BPM) उद्योग के अनुपालन बोझ में काफी कमी आएगी।
- भ्रष्टाचार को रोकता है: पिछली व्यापक परिभाषा दूरसंचार विभाग (DoT) के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के यादृच्छिक कृत्यों का कारण था जो नियमों और विनियमों की भाषा में निहित अस्पष्टता का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र थे।
- **इंडिया आईटी सेक्टर को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है:** इसका उद्देश्य उद्योग को मजबूत गति प्रदान करना है और भारत को दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी आईटी क्षेत्राधिकारों में से एक के रूप में अग्रणी बनाना है।
- **कंपनियों के लिए लचीलापन:** रिमोट वर्किंग पिक अप और **OSP** की अवधारणा के साथ, यह एक कंपनी को इस बात का विकल्प देता है कि वे अपने डिलीवरी मॉडल को कैसे चाहते हैं।
- **स्टार्टअप के लिए बढ़ावा:** छोटी फर्म और स्टार्टअप, जिनके लिए बैंक गारंटी एक अतिरिक्त तनाव थी, अब आराम से हैं। इससे उद्यमी को इस क्षेत्र में बहुत अधिक वित्तीय विरोधाभासों के बिना अपने व्यवसाय के संचालन को शुरू करना आसान हो जाता है
- **नए मॉडल को नए सामान्य करने के लिए अनुकूलन:** नए नियम WFH या 'कहीं से भी काम' की सुविधा प्रदान करेंगे, उदाहरण के लिए, कंपनियां अपने कर्मचारी को पूर्वोत्तर या भारत के किसी भी सुदूर कोने में रख सकती हैं और फिर भी काम कर रहे दूरस्थ सेवा का लाभ उठा सकती हैं
- **शहरी महानगर की घोषणा:** यह उम्मीद है कि अगले पांच वर्षों में आईटी कार्यबल के करीब 25-30 प्रतिशत छोटे शहरों और कस्बों में जा सकते हैं, जो शहरी भार को कम करने और क्षेत्रीय रूप से संतुलित विकास की ओर बढ़ने में मदद करेगा।
- **विदेशी निवेश आकर्षित करना**: OSP विनियमों में अब कोई अड़चन नहीं है, और ऑफशोरिंग (भारत जैसे कम लागत वाले देशों के लिए प्रतिभाओं) को उठाते हुए, वैश्विक कंपनियां अपने भारत के कार्यों का तेजी से विस्तार कर सकती हैं।
- **महिला रोजगार को बढ़ावा देना:** एक फायदा यह है कि कंपनियां एक नए टैलेंट पूल में टैप कर सकती हैं जैसे कि टीयर -2 और टियर -3 शहरों में युवा महिला कर्मचारियों की संख्या, जो सामाजिक मजबूरियों के कारण दूर से काम करने के लिए उपयुक्त हैं।

निष्कर्ष

- नौकरशाहों के कैडर जिनका व्यवसाय नियामक परिदृश्य के इस अस्पष्ट कोने का प्रबंधन करना था, इनको भंग करना होगा और उन्हें कहीं और बेहतर उपयोग में लाना होगा।
- ये सुधार श्रम और कृषि सुधार के साथ संयुक्त रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण 2.0 की ओर इशारा करते हैं।

Connecting the dots

- श्रम सुधार
- कृषि सुधार

वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा (Various development projects to be inaugurated in Varanasi)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - I - प्राचीन इतिहास और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप;

समाचार में

- भारतीय प्रधान मंत्री वाराणसी में सारनाथ लाइट और साउंड शो सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

सारनाथ

- सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास वाराणसी शहर से 10 किमी उत्तर-पूर्व में स्थित एक स्थल है।
- सारनाथ में हिरण पार्क: गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म की शिक्षा दी और बौद्ध संघ कोंडाना के प्रबुद्धता के माध्यम से अस्तित्व में आया।
- इसे इसिपतन के रूप में भी जाना जाता है।
- इस शहर को बुद्ध द्वारा तीर्थयात्रा के चार स्थानों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है, जहाँ उनके भक्त अनुयायियों को जाना चाहिए।
- ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था जिसे "धर्म चक्र प्रवर्तन" का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार-प्रसार का आरंभ था।
- इस सुत्त के अंतर्गत, उन्होंने चार महान सत्य और उससे जुड़ी शिक्षाओं को सिखाया।

क्या आप जानते है?

- जैन ग्रन्थों में इसे 'सिंहपुर' कहा गया है और माना जाता है कि जैन धर्म के ग्यारहवें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म यहाँ से थोड़ी दूर पर हुआ था।

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- आंध्र प्रदेश सरकार की तर्ज पर, हरियाणा विधानसभा ने एक अहम विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- राज्य विधानसभा ने स्थानीय उम्मीदवारों के लिए हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 को निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया है।
- सभी कंपनियां, समाज, ट्रस्ट, सीमित देयता भागीदारी फर्म, साझेदारी फर्म और 10 या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने वाला कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के दायरे में आएगा।
- इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कोई संस्था शामिल नहीं होगी।
- एक उम्मीदवार "जो हरियाणा राज्य में अधिवासित है" जिसे स्थानीय उम्मीदवार कहा जाता है और वह निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के दौरान इस आरक्षण का लाभ उठाने में सक्षम होगा।
- हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपए से कम है
- एक नियोक्ता इस 75% भर्ती प्रतिबंध से छूट का दावा कर सकता है, लेकिन केवल एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद और केवल अगर सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी मानते हैं कि छूट के लिए नियोक्ता का अनुरोध सही है।
- नियोक्ता पर न्यूनतम 10,000 रु और अधिकतम 2 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि एक बार यह स्थापित हो जाता है कि नियोक्ता ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

क्या आप जानते है?

क्या यह आरक्षण विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है?

- हरियाणा विधानसभा में इस बात को लेकर चिंता जताई गई थी कि विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है।
- हालांकि, हरियाणा सरकार का दावा है कि जबकि अनुच्छेद 16 "सार्वजनिक रोजगार" के बारे में बात करता है, जबकि यह विधेयक बिलकेवल "निजी क्षेत्र के रोजगार" से संबंधित है।

तमिलनाडु NEET कोटा (Tamil Nadu NEET Quota)

संदर्भ: तमिलनाडु के राज्यपाल ने एक विधेयक पर अपनी सहमति दी, जिसमें NEET के लिए योग्य सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए स्नातक चिकित्सा प्रवेश में 7.5% सीटें आरक्षित करने की मांग की गई थी। तमिलनाडु विधानसभा ने इस साल सितंबर में कोटा पर एक विधेयक पारित किया था।

NEET क्या है?

- यह सरकारी और निजी दोनों मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रवेश परीक्षा है।
- NEET-UG ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट (AIPMT) और 2013 में राज्यों या कॉलेजों द्वारा स्वयं आयोजित सभी व्यक्तिगत MBBS परीक्षाओं को प्रतिस्थापित किया।
- NTA - नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NEET-UG परीक्षा के लिए नियामक संस्था, भारत के विभिन्न हिस्सों में हर साल इसे कई भाषाओं में आयोजित करती है।
- NTA की जिम्मेदारी प्रवेश परीक्षा के आयोजन, परिणाम की घोषणा और निदेशालय सामान्य स्वास्थ्य सेवा, भारत सरकार को "ऑल इंडिया रैंक मेरिट लिस्ट" प्रदान करने तक सीमित है, 15% अखिल भारतीय काउंसलिंग के लिए कोटा सीटें और राज्यों / अन्य परामर्श अधिकारियों को परिणाम प्रदान करना है।
- NTA एक मुख्य पाठ्यक्रम दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसके तहत सभी स्कूल बोर्डों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखा गया है।

NEET की आलोचना:

तमिलनाडु ने NEET का विरोध क्यों किया?

- वह राज्य जो NEET (राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा) के विरोध में उनमें तमिलनाडु प्रमुख राज्य था।
- जो प्राथमिक तर्क दिए गए थे, उनमें से एक यह था कि NEET एमबीबीएस डिग्री के लिए दौड़ से बाहर होने वाले छात्रों की कुछ श्रेणियों को आगे बढ़ाएगा, और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने का उसका लक्ष्य निराशा जनक है।
- राज्य सरकार ने तर्क दिया किसरकारी स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र कोचिंग का खर्च नहीं उठा पाएंगे जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक होगा।
- 2017 के बाद से, जब NEET तमिलनाडु में लागू किया गया था, केवल सरकारी स्कूलों के 14 छात्र एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने में कामयाब रहे हैं।

राज्य ने क्या किया?

- MBBS सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए NEET का उपयोग करने की अनिवार्यता ने आलोचकों को सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए य नुकसान की ओर इशारा किया और इस मोर्चे पर निवारण की तलाश की जा रही है।
- छात्रों को परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए सरकार ने NEET के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर चलाए।
- 2018-2019 और 2019-2020 में, तमिलनाडु के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 700 सरकारी-स्कूली के छात्र जिन्होंने नीट के परीक्षा पास की उनमें से मात्र नौ को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिला।

- सरकारी स्कूल के छात्रों और निजी-स्कूल के छात्रों के बीच "वास्तविक असमानताओं" को सही करने के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी. कल्याणरायसन की अध्यक्षता में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था।
- आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सामाजिक-आर्थिक कारकों जैसे जाति, धन, पैतृक व्यवसाय द्वारा बनाई गई संज्ञानात्मक खाई के कारण से सरकारी स्कूलों के छात्रों को निजी स्कूलों में उनके समकक्षों की तुलना में नुकसान हुआ है। अभिभावक शिक्षा, लिंग, आदि, और इन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को NEET के लिए कुछ महीनों की गहन कोचिंग द्वारा नहीं पाटा जा सकता है, भले ही इसे मुफ्त में प्रदान किया गया हो "।
- इसने सरकारी छात्रों के लिए 10% सीटें अलग रखने की सिफारिश की।
- परिणामस्वरूप, विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया जिसमें एमबीबीएस प्रवेश में सरकारी-स्कूल के छात्रों के लिए 7.5% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने की मांग की गई थी।
- क्षैतिज आरक्षण उस समुदाय पर ध्यान दिए बिना लागू किया जाता है, जिससे छात्र संबंधित है, जिस प्रकार विकलांग व्यक्तियों या पूर्व-सेवा कर्मियों के वार्डों के लिए आरक्षित कोटा।
- सरकार ने यह भी निर्दिष्ट किया कि यदि किसी सरकारी-स्कूल के छात्र ने उच्च अंक प्राप्त किए हैं, तो वह अपने सामुदायिक आरक्षण के आधार पर सीट आवंटित करने का विकल्प चुन सकते है।

इस प्रवेश सत्र के लिए सरकारी स्कूलों के छात्र कितनी सीटों के पात्र होंगे?

- सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में, अखिल भारतीय कोटा के तहत 15% सीटें अलग रखी गई हैं, और शेष 85% आरक्षण के नियम के अनुसार भरे जाने के लिए, स्टेट कोटा के लिए उपलब्ध होंगे।
- सीटों का एक और प्रतिशत (निजी स्व-वित्तपोषण महाविद्यालयों में 65%, और निजी, स्व-वित्तपोषण अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में 50%) को भी सरकार के कोटे में जोड़ा जाएगा।
- राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इस साल, कुल 4,058 सीटों है और इसमें से 7.5% यानी 304 सीट इसके अंतर्गत आते है केए लि राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार।
- राज्य सरकार ने दोहराया है कि मेडिकल प्रवेश के लिए 69% जाति-आधारित आरक्षण की अखंडता को संरक्षित किया जाएगा।

निष्कर्ष

- जहां 14 छात्रों को तीन साल में प्रवेश दिया गया था, सरकारी स्कूलों के 304 छात्रों को चिकित्सा शिक्षा लेने का अवसर मिलेगा, बशर्ते उन्होंने NEET को पास किया हो।

विशेष विवाह अधिनियम (SMA)(Special Marriages Act- SMA))

संदर्भ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय में कहा कि सिर्फ विवाह करने के उद्देश्य से किया गया धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है और ऐसे में शादी के लिए धर्म बदलना शून्य माना जाएगा।

विशेष विवाह अधिनियम क्या है?

- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (SMA) को विभिन्न धर्मों को मानने वाले जोड़ों की शादी को आसान बनाने और नागरिक विवाह को प्राथमिकता देने के लिए लागू किया गया था।
- विभिन्न जातियों या धर्मों या राज्यों के लोग SMA के तहत विवाह करते हैं जिसमें विवाह पंजीकरण के माध्यम से किया जाता है।
- अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अंतर-धार्मिक विवाह को संबोधित करना और सभी धार्मिक औपचारिकताओं के धर्मनिरपेक्ष संस्थान के रूप में विवाह की स्थापना करना था, जिसके लिए मात्र पंजीकरण की आवश्यकता होती है।

SMA की विशेषताएं क्या हैं?

- **मूल आयु मानदंड: SMA** के तहत किन्हीं दो व्यक्तियों का विवाह **21** वर्ष की आयु के पुरुष और **18** वर्ष की आयु के पुरुष के अधीन हो सकता है।
- **बुनियादी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है:** न तो जीवनसाथी का जीवन होना चाहिए; दोनों को मान्य सहमति देने में सक्षम होना चाहिए, इस तरह के व्यक्ति को किसी भी मानसिक विकार से पीड़ित नहीं होना चाहिए जो उन्हें शादी के लिए अनफिट कर देता है।
- **धार्मिक कानूनों से संबंधित प्रतिबंध:** वे निषिद्ध संबंधों की डिग्री के भीतर नहीं होना चाहिए - अर्थात, उन्हें इस तरह से संबंधित नहीं होना चाहिए कि उनका धर्म ऐसे विवाह की अनुमति नहीं देता है।
- **नोटिस की प्रक्रिया:** एक इच्छित शादी के पक्षकारों को उस जिले के 'विवाह अधिकारी' को नोटिस देना चाहिए जिसमें उनमें से एक ने कम से कम 30 दिनों के लिए निवास किया था। नोटिस को 'मैरेज नोटिस बुक' में दर्ज करना होगा और इसकी एक प्रति कार्यालय में एक विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।
- नोटिस के तीन महीने के भीतर शादी को रद्द कर दिया जाना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है, तो एक ताजा नोटिस की आवश्यकता होगी।
- **विवाह के लिए आपत्तियों का प्रावधान:** कोई भी व्यक्ति इस आधार पर नोटिस के प्रकाशन के **30** दिनों के भीतर शादी पर आपत्ति कर सकता है कि यह वैध विवाह के लिए शर्तों में से एक का उल्लंघन करता है। विवाह अधिकारी को आपत्ति में पूछताछ करना है और **30** दिनों के भीतर निर्णय देना है। यदि वह विवाह की अनुमति से इनकार करता है, तो जिला अदालत में अपील की जा सकती है। अदालत का फैसला अंतिम होगा।
- **अविभाजित परिवार के सदस्य:** इसके अलावा, अधिनियम कहता है कि जब एक अविभाजित परिवार का एक सदस्य जो हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन धर्मों को मानता है, **SMA** के तहत शादी करता है, तो इसका परिणाम परिवार से उसका "विच्छेद" होता है।

SMA की आलोचनाएं अर्थात अंतर-विश्वास वाले जोड़ों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाएं?

- **व्यावहारिक कठिनाइयाँ:** सूचना, प्रकाशन और आपत्ति से संबंधित प्रावधानों ने कई लोगों के लिए अंतर-विश्वास विवाहों पर रोक लगाना मुश्किल बना दिया है।
- **परिवार द्वारा जबरदस्ती रणनीति के लिए कमजोर:** स्थानीय पंजीकरण कार्यालय में प्रचार का मतलब यह हो सकता है कि परिवार के सदस्यों को संघ द्वारा आपत्ति करने पर इसे जबरन रोकना पड़ सकता है।

- **फ्रिंज समूहों द्वारा उत्पन्न खतरे:** विवाह कार्यालयों के नोटिस बोर्डों पर नजर रखने और पार्टियों के विवरण को नीचे रखने के लिए अंतर-विश्वास विवाहों के विरोध में दक्षिणपंथी समूहों की रिपोर्टें आई हैं ताकि उन्हें छोड़ दिया जाए या उन्हें मना किया जा सके।
- **गोपनीयता की घुसपैठ:** किसी भी तिमाही से दी जाने वाली पूर्व सार्वजनिक सूचना पर कानून की विशेषताएं और आपत्तियां, धर्मों में शादी करने के इच्छुक लोगों की सुरक्षा और गोपनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं।
- **समानता के अधिकार का उल्लंघन:** हिंदू और मुस्लिम विवाह कानूनों के मामले में, पूर्व सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए, **SMA** में इस तरह की आवश्यकता को **SMA** के तहत शादी के लिए चुनने वालों के समानता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। ।
- **धार्मिक रूपांतरण के लिए धक्का: SMA** में शामिल जटिलताओं के कारण, इच्छुक दंपति को उनमें से एक के व्यक्तिगत कानून के तहत करना आसान हो जाता है, दूसरे के साथ धार्मिक रूपांतरण का विकल्प चुना जाता है। जबकि इस्लाम और ईसाई धर्म में रूपांतरण के औपचारिक साधन हैं, हिंदू धर्म में धर्मांतरण के लिए कोई निर्धारित समारोह नहीं है।

क्या विवाह के लिए धर्मांतरण के खिलाफ कानून हैं?

- हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2019, और उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2018, दोनों गलत तरीके से, बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, उत्पीड़न, खरीद और विवाह द्वारा द्वारा धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाते हैं '।
- दोनों कानूनों में एक अलग सेक्शन है, जिसके तहत विवाह के उद्देश्य के लिए धर्मांतरण नहीं है, लेकिन विवाह केवल रूपांतरण के उद्देश्य से किया जाता है, किसी भी पक्ष द्वारा एक याचिका के आधार पर पारिवारिक न्यायालय द्वारा इसे शून्य घोषित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

व्यक्तिगत मामला होने पर विवाह को तब तक नियंत्रित किया जाना चाहिए, जब तक कि यह सामाजिक बुराइयों की ओर न ले जाए। भारत जैसे उदार लोकतांत्रिक देश में चुनाव की स्वतंत्रता को प्रधानता दी जानी चाहिए।

Connecting the dots

- महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु

सभी विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) को ऊर्जा संरक्षण (EC) अधिनियम, 2001 के तहत कवर किया जाना है (All the Electricity Distribution Companies (DISCOMs) to be covered under the Energy Conservation (EC) Act, 2001)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - ऊर्जा क्षेत्र

समाचार में

- केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण (ईसी) अधिनियम, 2001 के पूर्वावलोकन के तहत सभी विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) को कवर करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- अधिसूचना को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के परामर्श से तैयार किया गया था।
- इसके अनुसार, राज्य / संयुक्त विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की धारा 36) के तहत वितरण लाइसेंस जारी करने वाली सभी संस्थाओं को नामित उपभोक्ता (डीसी) के रूप में अधिसूचित किया जाता है।
- इस अधिसूचना के बाद, सभी DISCOMs ईसी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, जैसे प्रत्येक प्रबंधक के लिए ऊर्जा प्रबंधक की नियुक्ति, ऊर्जा लेखा और लेखा परीक्षा आदि के तहत शासित होंगे।
- इससे पहले, DISCOM जिनकी वार्षिक ऊर्जा हानियाँ 1000 MU या इससे अधिक थीं, केवल DC के रूप में कवर की गई थीं।
- अब इस अधिसूचना के साथ, EC अधिनियम के तहत कवर किए गए DISCOMs की संख्या 44 से बढ़कर 102 हो जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

- यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है।
- यह विकासशील नीतियों और रणनीतियों में सहायता करता है।
- **उद्देश्य:** भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना।

मीडिया विनियमन (Media regulation)

संदर्भ: भारत सरकार ने ऑनलाइन कंटेंट प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई फिल्मों और ऑडियो-विज़ुअल कार्यक्रमों" के साथ-साथ समेत तमाम डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म्स को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लाने का आदेश जारी किया।

दूसरे शब्दों में, केंद्र सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम और अन्य जैसे ओवर द टॉप (Over The Top -OTT) प्लेटफार्मों या वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाताओं को लाया है।

क्या आपको पता है?

- भारतीय प्रेस परिषद (The Press Council of India) प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करती है,
- न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (News Broadcasters Association-NBA) समाचार चैनलों का प्रतिनिधित्व करता है और उन्हें नियंत्रित करता है
- भारत के विज्ञापन मानक परिषद विज्ञापन को नियंत्रित करता है
- केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (**CBFC)** फिल्मों की निगरानी करता है।

- हालांकि, डिजिटल सामग्री को नियंत्रित करने वाला कोई कानून या स्वायत्त निकाय नहीं है।

मुद्दे की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- समय-समय पर, सरकार ने इन प्लेटफार्मों की निगरानी करने की आवश्यकता का संकेत दिया था।
- अक्टूबर 2019 में, सरकार ने संकेत दिया था कि वह नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसी वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए "नकारात्मक" सूची जारी करेगी।
- सरकार यह भी चाहती थी कि प्लेटफार्म समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण की तर्ज पर एक स्व-नियामक संस्था के साथ आएं।
- सरकार के हस्तक्षेप की पुष्टि करते हुए, जनवरी 2019 में, आठ वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं ने एक स्व-नियामक कोड पर हस्ताक्षर किए थे जिसने इन प्लेटफार्मों पर सामग्री के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक सेट तैयार किया था।

ओटीटी प्लेटफार्मों द्वारा अपनाया गया स्व-नियामक कोड क्या था?

ओटीटी द्वारा अपनाया गया कोड पांच प्रकार की सामग्री को प्रतिबंधित करता है। इनमें शामिल है-

1. सामग्री जो जानबूझकर और दुर्भावना से राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करती है
2. कोई भी दृश्य या कहानी लाइन जो बाल पोर्नोग्राफ़ी को बढ़ावा देती है
3. कोई भी सामग्री जो "दुर्भावनापूर्वक" धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने से सम्बंधित है
4. कोई भी सामग्री जो "जानबूझकर और दुर्भावनापूर्वक" आतंकवाद को बढ़ावा देती है या प्रोत्साहित करती है
5. कोई भी सामग्री जिसे कानून या न्यायालय द्वारा प्रदर्शनी या वितरण के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

सरकार ने इस कोड का समर्थन करने से इनकार कर दिया था।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत डिजिटल मीडिया को लाना

- **अधिक अनियंत्रित नहीं:** इससे ओटीटी प्लेटफार्मों पर सरकार का नियंत्रण होगा, जो अब तक अनियमित थे।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में व्यवहार करता है:** ऐसी नियामक शक्तियां कार्यकारी को स्वतंत्र प्रेस पर नियंत्रण प्रदान करती हैं, जिससे अनिवार्य रूप से यह प्रतिकूल हो जाता है।
- **इस सन्दर्भ में उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई की जा रही है:** ऐसे कार्यकारी आदेश पारित करना सर्वोच्च न्यायालय में "ओवर द टॉप" (ओटीटी) प्लेटफार्मों पर सामग्री से संबंधित जनहित याचिका को ओवर लैप करता है।
- यह नए युग के डिजिटल मीडिया (स्टैंड-अलोन न्यूज़ पोर्टल्स जो पहले से ही दूर रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं) के बीच एक कृत्रिम अंतर पैदा करके प्रेस को विभाजित और शासित करना चाहता है - जो कि भविष्य का मीडिया है।

- **विघटनकारी नवाचार:** सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रण में डिजिटल मीडिया का भविष्य आशा के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ता है,यह समकालीन पत्रकारिता और मीडिया प्रैक्टिशनर और मीडिया उद्यमी दोनों के लिए और नए स्टार्टअप के लिए इस क्षेत्र को प्रभावित करता है।
- **लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध:** जुझारू पत्रकारिता को नाकाम करने के लिए यह सोची समझी पहल है। यह हमारे लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है।

निष्कर्ष

सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिजिटल माध्यम पर उपलब्ध सामग्री राष्ट्र के और समाज के हित को प्रभावित नहीं करती है, उसके लिए यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विनियम भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करते हैं।

Connecting the dots

- सुदर्शन टीवी केस
- नेट तटस्थता
- श्रेया सिंघल केस

ड्राफ्ट नियम सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के तहत अधिसूचित

भाग: GS प्रीलिम्स और जीएस- **II** - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 संहिता पर केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने मसौदा अधिनियम को अधिसूचित किया है

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह अधिनियम अन्य निर्माण कामगारों को केंद्रसरकार और राज्य सरकार या राज्य कल्याण बोर्ड की चिन्हित वेबसाइट पर आधारआधारित पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराएगा।
- इन नियमों में ऐसे मजदूरों के लिए भी ग्रेच्युटी के प्रावधान किए गए हैं जिन्हें निर्धारित अवधि के लिए रोजगारउपलब्ध कराया जा रहा है।
- इन नियमों में उपलब्ध प्रावधान से किसी प्रतिष्ठान के लिए एकल इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण कराना होगा जिसमें व्यवसायिकगतिविधियों के बंद होने की स्थिति में पंजीकरण का निरस्तीकरण भी शामिल है।
- ईपीएफओ और ईएसआईसी के दायरे से किसीव्यवसायिक प्रतिष्ठान के बाहर होने के संबंध में नियम और शर्तों के भीप्रावधान इसमें किए गए हैं।
- भवन निर्माण या अन्य निर्माण कर्मियों के लिएसेस का भुगतान और स्वतः आंकलन की प्रक्रिया को इन नियमों में विस्तार से उल्लेखित किया गया है।
- स्व आकलन के उद्देश्य से रोजगार प्रदाता को राज्य केलोक निर्माण विभाग या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या रियल स्टेट नियामकप्राधिकरण को जमा कराए गए दस्तावेज या रिटर्न के आधार पर निर्माण लागत कीगणना करनी होगी।

- सेस के भुगतान में देरी पर लगाए जाने वाले ब्याज दर को भी प्रतिमाह 2% से घटाकर 1% किया गया है।

अनुच्छेद 217 के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति (Additional Judges appointed as Permanent Judges of Allahabad HC under Article 217)

भाग: GS प्रीलिम्स और जीएस- **II** - संविधान

समाचार में

- भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारतीय संविधान के अनुच्छेद **217 (1)** के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में **28** अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

अनुच्छेद 217 (1)

- एक उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उनके हाथ के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और, मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में परामर्श दिया जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
- भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश [अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित रूप में पद धारण करेगा और किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा, जब तक वह [बासठ वर्ष]** की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।]* परंतु-
    - कोई न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
    - किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड (4) में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा।

किसी न्यायाधीश का पद, राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्यक्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय को, अंतरित किए जाने पर रिक्त हो जाएगा।

अनुच्छेद 32 की सर्वोच्च न्यायालय व्याख्या (Supreme Court interpretation of Article 32)

सन्दर्भ- हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश **एसबोबडे .ए.** (S A Bobde) की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि हम संविधान के **अनुच्छेद 32** के तहत दायर याचिकाओं को 'हतोत्साहित' करने का प्रयास कर रहे हैं.

- सुप्रीम कोर्ट ने यह बात केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स द्वारा पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई के लिए अनुच्छेद 32 के तहत दायर **बंदी प्रत्यक्षीकरण** (Habeas Corpus) याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, जिन्हें तीन अन्य लोगों के साथ हाथरस**,** उत्तर प्रदेश जाते समय गिरफ्तार किया गया था।

अनुच्छेद 32 **क्या है?**

- अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है. यह एक मौलिक अधिकार है. इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है कि वह अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर सकता है .
- अनुच्छेद **32** संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है**,** या संविधान के भाग **III** में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने के अधिकार की पुष्टि करता है।
- किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिये सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के पास निर्देश**,** आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रिट जारी की जा सकती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण (**Habeas Corpus)** रिट**,** परमादेश (**Mandamus)** रिट**,** प्रतिषेध (**Prohibition)** रिट**,** उत्प्रेषण (**Certiorari)** रिट और अधिकार पृच्छा (**Qua Warranto)** रिट.
- आपातकाल की अवधि को छोड़कर अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 32 **का महत्व**

- यह अनुच्छेद संविधान के भाग **III** में समानता**,** स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता**,** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता सहित अन्य मौलिक अधिकारों के साथ शामिल है।
- केवल अगर इनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो एक व्यक्ति अनुच्छेद **32** के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।
- संविधान सभा की बहसों में डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने कहा कि अनुच्छेद **32** के बिना यह संविधान एक अशक्तता होगा। उन्होंने आगे कहा कि "यह संविधान की आत्मा है और इसका हृदय है"
- अनुच्छेद **32** सबसे बड़ी सुरक्षा उपायों में से एक है, जिसे व्यक्ति की रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रदान किया जा सकता है।

- चूंकि अनुच्छेद 32 एक व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर एक उपाय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है, "यह संविधान के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकारों के लिए एक मौलिक अधिकार है"।

क्या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में उच्च न्यायालयों जाया जा सकता है?

- उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को पाँच प्रकार के रीटो के माध्यम से मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या अधिनियमित करने के लिए जाया जा सकता है।
- सिविल या आपराधिक मामलों में, एक पीड़ित व्यक्ति के लिए उपलब्ध प्रथम उपाय परीक्षण अदालतों का है, उसके बाद उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है।
- जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने की बात आती है, तो कोई व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय या सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। अनुच्छेद **226,** हालांकि अनुच्छेद **32** की तरह मौलिक अधिकार नहीं है।

अनुच्छेद 32 पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणियां रही हैं?

- मद्रास (1950) के रोमेश थाप्पारव्स राज्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि अनुच्छेद **32** मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक "गारंटीकृत" (**SC** मना नहीं कर सकता) उपाय प्रदान करता है।
- आपातकाल के दौरान, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर बनाम एस एसएसखुला (**1976)** में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद **32** के तहत नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार खो देता है

हाल के रुझान

- पत्रकार सिद्दीकप्पन के मामले में, अदालत ने पूछा कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय में क्यों नहीं जा सकते। इसमें केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा गया है और इस हफ्ते के आखिर में इस मामले की सुनवाई होगी।
- महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और अन्य के खिलाफ कथित अपमानजनक सामग्री के लिए तीन मामलों में गिरफ्तार नागपुर के एक व्यक्ति द्वारा दायर किए गए अनुच्छेद **32** को लागू करने वाले एक अन्य मामले में, उसी बेंच ने उसे पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया।
- एक अन्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीश बेंच ने महाराष्ट्र विधानसभा के सहायक सचिव को एक अवमानना नोटिस जारी किया था, जिसने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को लिखे पत्र में उनसे शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए सवाल उठाया था। अदालत ने तब कहा था कि अनुच्छेद **32** के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण करने का अधिकार स्वयं एक मौलिक अधिकार है
- उपरोक्त उदाहरणों को नागरिक कार्यकर्ताओं द्वारा न्यायपालिका के कामकाज की आलोचना करने के लिए उद्धृत किया गया है जहां शीर्ष स्तर पर न्यायमूर्ति तक पहुंच प्रभाव और शक्ति के लिए उत्तरदायी है।

निष्कर्ष

संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह अंततः उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक व्यक्तिगत न्यायाधीश के विवेक पर है कि यह तय किया जाए कि किसी मामले में हस्तक्षेप किया गया है, जिसे पहले उच्च न्यायालय भी सुन सकता है।

Connecting the dots

- **न्यायिक सुधार**

सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज लॉन्च हुआ (Safaimitra Suraksha Challenge launched)

भाग: GS प्रीलिम्स और जीएस- **II** - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने **243** शहरों में सफाइमित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी सीवर या सेप्टिक टैंक क्लीनर का जीवन कभी भी 'खतरनाक सफाई' के मुद्दे के कारण समाप्त न हो।

महत्वपूर्ण बिंदु

- चैलेंज को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था।
- उद्देश्य: सीवरों और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई को रोकना और उनकी मशीन से सफाई को बढ़ावा देना।
- 243 शहरों के प्रतिनिधियों की ओर से 20 अप्रैल, 2021 तक सभी सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु मशीनों के प्रयोग और खतरनाक सफाई से किसी भी व्यक्ति की मौत को रोकने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्धता की गई।

- प्रतिभागी शहरों का वास्तविक जमीनी स्तर पर मूल्यांकन मई 2021 में एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाएगा और उसके परिणाम 15 अगस्त, 2021 को घोषित किए जाएंगे।
- शहरों को तीन उप-श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा- 10 लाख से अधिक की आबादी के साथ, 3 से 10 लाख की आबादी और 3 लाख तक की आबादी वाले शहर। सभी श्रेणियों के विजेता शहरों को मिलने वाली कुल पुरस्कार राशि 52 करोड़ रुपये होगी।

क्या आप जानते है?

- मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम (2013) और उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णय द्वारा स्पष्ट रूप से खतरनाक एवं हानिकारक सफाई गतिविधियां प्रतिबंधित हैं यानी कि कोई भी व्यक्ति बिना सुरक्षात्मक उपकरण के किसी सेप्टिक टैंक या सीवर में प्रवेश नहीं कर सकता है।

मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना (MITP) पर हस्ताक्षर हुए (Meghalaya Integrated Transport Project (MITP) signed)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने मेघालय राज्य के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए **120** मिलियन $ की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना (MITP)** नवीन, जलवायु-लचीला और प्रकृति-आधारित समाधानों का उपयोग करके लगभग 300 किमी के रणनीतिक सड़क सेगमेंट और स्टैंड-अलोन पुलों में सुधार करेगी।
- यह खंड प्रमुख कृषि क्षेत्रों, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों, लघु उद्योगों, प्रमुख कस्बों और अयोग्य आबादी को बाजार, स्वास्थ्य और शिक्षा केंद्रों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गलियारों से जोड़ने का काम करेंगे।
- यह निर्माण के समय और लागत दोनों को कम करने के लिए पूर्वनिर्मित पुलों जैसे अभिनव समाधानों का भी समर्थन करेगा।
- यह प्रोजेक्ट COVID-19 महामारी के कारण प्रभावित होने वाली विकास गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए राज्य की सरकार **"Restart Meghalaya Mission"** का भी सहयोग करेगा।

विश्व अराजकता से घिरी हुई है और यह लोकतंत्र के लिए खतरा है (A world in Chaos & Threats to Democracy)

संदर्भ: ट्रम्प चुनाव को नकारने का प्रयास अंतिम तक करते रहे (जिसमें वह हार गए थे), और अमेरिकन आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग उनका समर्थन करता दिख रहा है, यह लोकतंत्र के लिए खतरे को प्रदर्शित करता है।

लोकतंत्र के लिए खतरा

- **पहचान की राजनीति का उदय:** पहचान के मुद्दे, या पहचान के लिए खतरा, लोकतंत्रों के चुनावों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन रहे हैं।
- **प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग:** साइकोमेट्रिक तकनीक (एक ला कैंब्रिज एनालिटिका) का उपयोग करके शिकायतों का हेरफेर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किए गए डीप फेक का उपयोग लोकतंत्र के वर्तमान धारणाओं के लिए खतरे में वृद्धि हुई है।
- **सामाजिक अशांति:** थाईलैंड, बेलारूस और किर्गिस्तान में विरोध प्रदर्शन
- **यूरोप में धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा:** हाल ही में आतंकवादी हमलों की लहर, एक इस्लामिक स्टेट (आईएस) समर्थक द्वारा पेरिस के स्कूली अध्यापक की हत्या से शुरू हुई, जिसके बाद नीस में आईएस की हिंसा हुई, यह धर्मनिरपेक्ष विश्वास पर एक बड़ा हमला रहा।
- आतंकवाद का पुनरुत्थान हो रहा है, अल-कायदा फिर से प्रमुख होता जा रहा है। आईएस फ्रांस में हमले के साथ लौट आया है - पेरिस और नीस - और ऑस्ट्रिया में (वियना) कुछ उदाहरण है
- **सूचनात्मक निरंकुशता:** कई लोकतांत्रिक राष्ट्र आज सरकार के घटनाओं के समर्थन या प्रचार के लिए डेटा में हेरफेर करते हैं।

भारत में लोकतंत्र को चुनौती

- उच्च ध्रुवीकरण
- पाकिस्तान द्वारा सहायता प्राप्त जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का खतरा है, जो सत्तावादी प्रवृत्ति को बढ़ाता है।
- चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमा मुद्दे
- सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध
- पाकिस्तान द्वारा गिलगित-बाल्टिस्तान में विधानसभा चुनावों का आयोजन
- भारत ,अफगानिस्तान में लगातार हाशिए पर जा रहा है, जहां तालिबान का नियंत्रण बढ़ रहा है।

IBC के तहत संशोधित परिसमापन नियम (Amended liquidation regulations under IBC)

संदर्भ: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (**The Insolvency and Bankruptcy Board of India-IBBI)** ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) नियम में संशोधन किया है।

IBBI द्वारा घोषित नए नियम क्या हैं?

- **परिसमापन प्रक्रिया को गति देना:** ऐसी कंपनियों के त्वरित परिसमापन को सुनिश्चित करने के लिए जो **IBC** के तहत बोली लगाने में असमर्थ हैं, परिसमापन किसी भी व्यक्ति को "आसानी से वसूली योग्य संपत्ति नहीं" सौंप सकता या हस्तांतरित कर सकता है।
- **हितधारकों के साथ परामर्श:** संपत्ति का उक्त हस्तांतरण या असाइनमेंट हितधारकों की समिति के परामर्श से किया जाना चाहिए।
- "एक आसानी से वसूली योग्य संपत्ति नहीं है" की परिभाषा में कॉर्पोरेट देनदार की कोई भी संपत्ति शामिल होगी, जिसे उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से बेचा नहीं जा सकता था। परिसमापन के तहत कंपनी की कोई भी या सभी संपत्ति, जो कुछ विवाद का सामना कर रही है या कुछ धोखाधड़ी लेनदेन में शामिल है, को परिसमापक द्वारा बेचा जा सकता है।
- **परिसमापन में आसानी:** एक कंपनी के लिए परिसमापक को परिसमापन के तहत एक बार में कंपनी की पूरी संपत्ति को बेचने के लिए इंतजार नहीं करना होगा, और विभिन्न बोली लगाने वालों के पास आने पर उनका निपटान किया जा सकता है।
- **डिफ़ॉल्ट की प्रक्रिया में आसानी:** आईबीबीआई ने यह भी कहा है कि वित्तीय लेनदार डिफ़ॉल्ट के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, अपनी खुद की पुस्तक जमा कर सकते हैं जो कॉर्पोरेट देनदार द्वारा ऋण के भुगतान की चूक स्थापित करता है।
- वित्तीय लेनदार किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के आदेश की एक प्रति संलग्न कर सकते हैं, जो एक आदेश के माध्यम से स्थापित किया गया है कि कंपनी ने ऋण भुगतान कर चूकी थी।
- **लेनदारों के लिए** IBC **प्रक्रिया में लचीलापन:** दिवाला नियामक ने भी कुछ लेनदारों को अनुमति देने के लिए नियमन में संशोधन किया है, कंपनी के अन्य लेनदारों जो परिसमापन प्रक्रिया समाप्त होने का इंतजार नहीं करना चाहते हैं, उनके कारण ऋण आवंटित या स्थानांतरित करके प्रक्रिया से बाहर निकलना चाहते हैं।
- **लघु वित्त लेनदारों की मदद करता है:** मान लीजिए कि एक छोटे वित्तीय लेनदार को कंपनी के परिसमापन की प्रतीक्षा में मूल्य नहीं मिलता है क्योंकि वे जोखिम नहीं रखते हैं। अब, वे इन परिसंपत्तियों को किसी बड़े खिलाड़ी को बेच सकते हैं और प्रक्रिया से बाहर निकल सकते हैं।

नए संशोधित नियमों के लिए संभावित चुनौतियां क्या हैं?

- नए नियमों को कानून की अदालत या उपयुक्त फोरम में परीक्षण करना होगा क्योंकि इसकी परिभाषा "आसानी से वसूली योग्य संपत्ति नहीं है" जो विवादास्पद है।
- सवाल यह है कि क्या **IBBI,** एक विनियमित कानून के तहत, किसी भी संशोधन के माध्यम से, किसी के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।
- एक और संशोधित विनियमन जिसे चुनौती दी जाने की संभावना है, आईबीबी के बारे में है कि परिसमापक के प्राधिकारी की मंजूरी के साथ परिसमापक के बीच असंबद्ध संपत्ति के वितरण के लिए परिसमापक को **IBBI** की अनुमति देता है।
- इससे लेनदारों को बढ़ावा मिलेगा, वे वित्तीय या परिचालन होंगे, परिसंपत्तियों के वितरण को चुनौती देंगे, और दावा करेंगे कि एक या दूसरे पक्ष द्वारा परिसमापक का पक्ष लिया गया है

निष्कर्ष

- महामारी प्रेरित मंदी के मद्देनजर, परिसमापन प्रक्रिया को आसान बनाने में दिवालिया कंपनियों से जल्दी बाहर निकलने और पूंजीगत संपत्तियों को वापस संचलन अर्थव्यवस्था में वापस लाने में मदद मिलती है।

तमिलनाडु में ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश जारी (Promulgation of ordinance to ban online Games in TN)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - I - सामाजिक मुद्दे और जी GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- तमिलनाडु सरकार सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग पर एक अधिसूचना जारी करके रोक लगा दी है। पकड़े जाने पर **5,000** रुपये और छह महीने तक के कारावास की सजा का प्रावधान है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सरकार ने यह कदम कई लोगों द्वारा इस तरह की गेमिंग में कथित रूप से पैसे गंवाने और आत्महत्या कर लिए जाने के बाद उठाया है। राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के आधार पर राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने अध्यादेश जारी किया।
- आत्महत्या की ऐसी घटनाओं से बचने और निर्दोष लोगों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया।
- कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरण, सामान्य गेमिंग हाउस और जीत या पुरस्कार राशि वितरित करने के लिए धन के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण का उपयोग करके साइबर स्पेस में किसी भी प्रकार के सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

क्या आप जानते है?

- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ऑनलाइन गेम और जुआ के कुछ रूपों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- कर्नाटक ऑनलाइन गेम और गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून भी बना रहा है।

पितृत्व अवकाश

संदर्भ: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक प्रतिस्पर्धी टेस्ट श्रृंखला के बीच में पितृत्व अवकाश के लिए कहा, और उन्हें प्रदान किया गया।

- मातृत्व अवकाश के विपरीत, भारत में पिता के लिए कोई कानून नहीं है।

क्या आपको पता है?

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा पिछले महीने जारी की गई समय-उपयोग सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में अवैतनिक कार्य पर लगभग चार घंटे अधिक समय बिताती हैं, जिसमें कर्मचारियों की महिलाओं की भागीदारी के लिए गंभीर परिणाम हैं।
- भारत दुनिया के 187 देशों में से 90 में से एक है, जिसके पास यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय नीतियां नहीं हैं कि नए पिता को अपने बच्चों के साथ पर्याप्त भुगतान का समय मिल सके।
- मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 गर्भवती महिलाओं को कुल 26 सप्ताह के लिए छुट्टी लेने की अनुमति देता है, जिसमें से 8 सप्ताह तक प्रसव से पहले दावा किया जा सकता है।
- महिला को मातृत्व अवकाश पर जाने से पहले तीन महीने के लिए अपने दैनिक वेतन की दर पर लाभ प्राप्त करने की भी योजना है।

क्या भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश मिलता है?

- सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है।
- सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम 551 (a) के माध्यम से पितृत्व अवकाश के लिए 1999 में प्रावधान किए।
- यह किसी भी पुरुष केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (प्रशिक्षुओं और प्रोबेशनरों सहित) को दो से कम बच्चों के साथ 15 दिन की पितृत्व अवकाश से 15 दिन पहले या छह महीने के भीतर बच्चे की डिलीवरी की तारीख का लाभ उठाने की अनुमति देता है।
- यह उन मामलों तक भी पहुंचता है जहां एक बच्चे को गोद लिया गया है।
- कई कंपनियों ने एक ही मॉडल को अपनाया है।

निष्कर्ष

- कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव के संदर्भ में पितृत्व अवकाश एक महत्वपूर्ण विकास है, लेकिन इसका भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

UMANG ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप; ई-शासन

समाचार में

- UMANG के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को हाल ही में इसके 3 वर्षों के अवसर के लिए लॉन्च किया गया था।
- यह उन चुनिंदा देशों में लॉन्च किया गया है जिनमें यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं।
- प्राथमिक मंत्रालय: आईटी मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह किसी भी समय, भारत सरकार की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विदेशों में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, एनआरआई और भारतीय पर्यटकों की मदद करेगा।
- यह UMANG पर उपलब्ध 'भारतीय संस्कृति' सेवाओं के माध्यम से भारत को दुनिया में ले जाने में भी मदद करेगा और भारत आने के लिए विदेशी पर्यटकों के बीच रुचि पैदा करेगा।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- **UMANG** मोबाइल ऐप (नए युग के शासन के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन) भारत सरकार का एक एकल बहुभाषी, बहु-सेवा मोबाइल ऐप है।
- यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों और राज्य सरकारों की उच्च प्रभाव सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है।
- **उद्देश्य:** भारत में मोबाइल शासन को फास्ट ट्रैक करना।
- **विकसित:** राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन **(NeGD),** इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा ।
- **UMANG** कई सरकारी सेवाओं जैसे कि हेल्थकेयर, वित्त, शिक्षा, आवास, ऊर्जा, इत्यादि के लिए आसान पहुँच प्रदान करके नागरिकों के लिए ईज़ ऑफ लिविंग को सक्षम बनाता है।
- **UMANG** के प्रमुख भागीदार: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना विभाग, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन और कर्मचारी चयन आयोग **(SSC)** के मंत्रालय।
- यह एक 'डिजिटल इंडिया' पहल है।
- फरवरी **2018** में यूएई ने दुबई, यूएई में आयोजित **6** वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ एम-सरकार सेवा पुरस्कार प्राप्त किया।

बांध सुरक्षा विधेयक, 2019

- इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बांध सुरक्षा के लिए समितियों और प्राधिकरणों को शामिल करते हुए एक व्यापक संघीय संस्थागत ढांचे की मदद से भारत के प्राचीन बांधों के जोखिमों से निपटना है।

क्या आपको पता है?

- भारत में 5,344 बड़े बांध हैं, जिनमें से लगभग 293, 100 साल से अधिक पुराने हैं और 1,041 50 से 100 साल पुराने हैं।
- इन बांधों में से लगभग 92% अंतर-राज्यीय नदियों पर हैं, और उनमें से कई पर दुर्घटनाओं ने उनके रखरखाव की आवृत्ति और दक्षता के रूप में चिंताएं पैदा की हैं।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- बिल देश भर में निर्दिष्ट बांधों की चौकसी, निरीक्षण, परिचालन और रखरखाव संबंधी प्रावधान करता है। इन बांधों में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले, या 10 मीटर से 15 मीटर की ऊंचाई तथा विशिष्ट डिजाइन और स्ट्रक्चर वाले बांध शामिल हैं।

- बिल दो राष्ट्रीय निकायों: राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कमिटी और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अथॉरिटी की स्थापना करता है। कमिटी के कार्यों में बांध सुरक्षा मानदंडों से संबंधित नीतियां बनाना और रेगुलेटरों को सुझाव देना है। अथॉरिटी के कार्यों में राष्ट्रीय कमिटी की नीतियों को लागू करना, राज्य बांध सुरक्षा संगठनों (एसडीएसओज़) को तकनीकी सहायता प्रदान करना और राज्य बांध सुरक्षा संगठनों (एसडीएसओज़) के बीच, और एसडीएसओ एवं उस राज्य के बांध मालिकों के बीच के विवादों को सुलझाना शामिल है।
- बिल दो राज्य स्तरीय निकायों: राज्य बांध सुरक्षा कमिटी और राज्य बांध सुरक्षा संगठन की स्थापना भी करता है। ये निकाय अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले बांधों की चौकसी, निरीक्षण, और परिचालन की निगरानी एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे।
- बिल की अनुसूची में राष्ट्रीय निकायों और राज्य बांध सुरक्षा कमिटी के कार्यो का उल्लेख है। इन अनुसूचियों को सरकारी अधिसूचना के जरिए संशोधित किया जा सकता है।
- बिल के अंतर्गत अपराधों के फलस्वरूप दो वर्ष तक की कैद, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

प्रमुख मुद्दे और बांध सुरक्षा विधेयक का विश्लेषण

1. **संघवाद का मुद्दा:**
   - बिल देश के सभी निर्दिष्ट बांधों पर लागू होता है। इनमें राज्यों के भीतर बहने वाली और राज्यों के बीच बहने वाली, दोनों प्रकार की नदियों पर बने बांध शामिल हैं। संविधान के अनुसार, राज्य जल जैसे विषय पर कानून बना सकते हैं जिनमें पानी का स्टोरेज और जल शक्ति भी शामिल हैं।
   - फिर भी अगर जनहित में जरूरी माना जाता हो तो संसद भी अंतरराज्यीय नदी घाटियों को रेगुलेट और विकसित कर सकती है। अब प्रश्न यह है कि क्या संसद को पूरी तरह से राज्य के भीतर बहने वाली नदियों पर निर्मित बांधों को रेगुलेट करने का अधिकार है।

2. **तमिलनाडु द्वारा विरोध**
   - जिस राज्य में चार बांध हैं - मुल्लापेरियार**,** परम्बिकुलम**,** थुक्कक्कडवु और पेरुवरिपल्लम - जो इसके स्वामित्व में हैं**,** लेकिन पड़ोसी राज्य केरल में स्थित हैं।
   - वर्तमान में**,** इन बांधों पर अधिकार राज्यों के बीच पहले से मौजूद दीर्घकालिक समझौतों द्वारा शासित हैं।
   - विधेयक के प्रावधानों का तात्पर्य है कि बांध के मालिक राज्य के पास किसी अन्य राज्य में स्थित बांध की सुरक्षा और रखरखाव पर अधिकार नहीं होगा।
   - इस प्रकार**,** तमिलनाडु चार बांधों से ऊपर की सुरक्षा पर अधिकार खो देगा जो केरल राज्य के साथ पहले से मौजूद समझौते का उल्लंघन है।

3. **कारण प्रक्रिया**
   - राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कमिटी, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अथॉरिटी और राज्य बांध सुरक्षा कमिटी के कामकाज का उल्लेख बिल की अनुसूची में है।
   - इन अनुसूचियों को सरकारी अधिसूचना के जरिए संशोधित किया जा सकता है।
   - प्रश्न यह है कि क्या अथॉरिटी के मुख्य कामकाज को एक अधिसूचना के जरिए संशोधित किया जा सकता है या क्या इन संशोधनों को संसद द्वारा पारित होना चाहिए।

निष्कर्ष

- उचित कानूनी ढांचे के अभाव में, इन बड़ी संख्या में बांधों की सुरक्षा और रखरखाव चिंता का कारण है। इसलिए राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए विधेयक को पारित किया जाना चाहिए।

Connecting the dots

- अंतर राज्यीय नदी जल विवाद
- मुल्लापेरियार बांध का मुद्दा

सहकारप्रज्ञ का शुभारंभ

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप; ई-शासन

समाचार में

- सहकारप्रज्ञ 'हाल ही में लॉन्च किया गया था।
- कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया
- **उद्देश्य:** ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सहकारप्रज्ञ के **45** नए प्रशिक्षण मॉड्यूल होंगे।
- **प्रशिक्षण:** राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और लक्ष्मणरावइनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान और विकास अकादमी (LINAC)।
- सहकारप्रज्ञापाल ने एनसीडीसी द्वारा देश भर में **18** क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से एनसीडीसी की प्रशिक्षण क्षमता को **18** गुना बढ़ा दिया और एनसीडीसी द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया गया।

क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर के तहत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं स्वीकृत

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - **III** - खाद्य प्रसंस्करण

समाचार में

- सरकार ने स्कीम फॉर एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो-प्रोसेसिंग बस्टर के तहत 234 करोड़ रुपये से अधिक के खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के सात प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
- देश में कृषि प्रसंस्करण समूहों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए Pradro Mantri Kisan Sampada Yojana के तहत 2017 में कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए निर्माण की योजना को मंजूरी दी गई।

- इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढाँचे का विकास करना है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

प्रधानमन्त्री किसान सम्पदा योजना

- 2016 में, MoFPI ने कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण समूहों (SAMPADA) के विकास के लिए एक योजना शुरू की।
- इसे 2016-20 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ के आवंटन के साथ लागू करने का प्रस्ताव था।
- 2017 में, SAMPADA का नाम बदलकर Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY) कर दिया गया।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
- उद्देश्य: (1) कृषि के पूरक के लिए; (2) प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता बनाने के लिए; (3) प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने के लिए मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को आधुनिक और विस्तारित करना; (4) अपव्यय को कम करने के लिए प्रमुख मूल्य जोड़ना।
- पीएमकेएसवाई के तहत सात घटक योजनाएं: (1) मेगा फूड पार्क; (2) एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य परिवर्धन अवसंरचना; (3) कृषि-प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा; (4) पिछड़े और अग्रगामी संबंधों का निर्माण; (5) खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का निर्माण / विस्तार; (6) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना; (7) मानव संसाधन और संस्थान।
- पीएमकेएसवाई के तहत, अनुदान की सहायता के रूप में पूंजीगत सब्सिडी, पात्र परियोजना लागत के 35% से 75% तक की अधिकतम निर्दिष्ट सीमा के अधीन, बुनियादी ढाँचा, लॉजिस्टिक परियोजनाओं और स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत निवेशकों को प्रदान की जाती है। देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की

ग़ैरक़ानूनी धर्मान्तरण से निषेध अध्यादेश 2020,

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप**;** ई-शासन

समाचार में

- यूपी कैबिनेट ने हाल ही में शादी के लिए धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी।
- नया कानून के अनुसार यह साबित करने के लिए कि धर्म परिवर्तन शादी के लिए नहीं था**,** बचाव पक्ष पर आरोप लगा सकता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- जबरन , प्रलोभन, अथवा किसी अन्य दबाव से किया गया धर्म परिवर्तन संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। इस प्रावधान में आरोपी पाए जाने पर न्यूनतम कम से कम 15 हज़ार रुपये अर्थदंड तथा एक वर्ष के कारावास का प्रावधान है। जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- नाबालिग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के धर्मान्तरण पर करने में कम से कम 25 हज़ार रुपये अर्थदंड तथा और 3 वर्ष कारावास का प्रावधान है जिसे दस साल बढ़ाया जा सकता है।
- गैरकानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन में न्यूनतम 50000 रुपये अर्थदंड और 3 वर्ष कारावास का प्रावधान है जिसे दस साल बढ़ाया जा सकता है।

क्या आप जानते हो?

- अध्यादेश को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय द्वारा एक फैसले में कहा गया था कि किसी साथी को चुनने या किसी व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार नागरिक जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का भाग था।
- पहले के अदालती फैसले में भी कहा गया था कि 'शादी के लिए धार्मिक रूपांतरण अस्वीकार्य था', विधी के अनुसार यह सही नहीं था।

राष्ट्रीय पोषण मिशन पर रिपोर्ट: NITI Aayog

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - **II** - नीतियां और हस्तक्षेप**;** स्वास्थ्य

समाचार में

- हाल ही में, NITI Aayog ने “भारत में पोषण पर तेजी लाने वाली प्रगति: यह क्या लेगा” जारी किया है।
- यह राष्ट्रीय पोषण मिशन या पोषण अभियान पर तीसरी प्रगति रिपोर्ट है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- तीसरी प्रगति रिपोर्ट (अक्टूबर 2019-अप्रैल 2020) बड़े स्तर के डेटासेट के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर सामना की गई जमीन और कार्यान्वयन चुनौतियों पर स्थिति को ध्यान में रखती है।
- ये डेटासेट NFHS-4 और व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण (CNNS पर आधारित हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) द्वारा परिभाषित वैश्विक लक्ष्य की तुलना में भारत के लक्ष्य स्टंटिंग पर रूढ़िवादी हैं। क्योंकि भारत द्वारा स्टंटिंग स्तर को 2022 तक 13.3% कम करने के विपरीत स्टंटिंग की व्यापकता दर 5% है।
- WHA के लक्ष्य की तुलना में गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के प्रसार के स्तर को 50.3% (2016) से घटाकर 34.4% (2022) और किशोर में लड़कियों में इसे 52.9% (2016) से कम करके 39.66% करना था
- महामारी के मद्देनजर, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि गरीबी और भूख को गहरा करना मिशन के तहत परिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने में देरी हो सकती है।

NITI Aayog के सुझाव:

- **स्टंटिंग पर:** (**1**) एकीकृत बाल विकास सेवा (**ICDS**) में व्यवहार परिवर्तन के हस्तक्षेप और मानार्थ भोजन की खुराक दोनों का उपयोग करके पूरक खिला में सुधार करना**;** (2) लड़कियों और महिलाओं में निवेश की दिशा में काम करना**;** (**3**) पानी में सुधार**,** स्वच्छता**,** साबुन से हाथ धोना और बच्चों के मल के स्वच्छ निपटान।
- **वेस्टिंग पर:** (**1**) ऐसे हस्तक्षेपों को शामिल करना जो गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) के उपचार से परे हैं और मध्यम विनाश को भी संबोधित करते हैं**;** (**2**) एसएएम की सुविधा-आधारित उपचार तक पहुंचने के लिए स्केल-अप करना**;** (**3**) राष्ट्रीय स्तर पर बर्बादी को रोकने और एकीकृत प्रबंधन के लिए तत्काल एक पूरी रणनीति जारी करना।
- **एनीमिया पर:** केवल स्वास्थ्य क्षेत्र के हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए परिदृश्य-निर्धारण**,** जो प्रजनन आयु की महिलाओं में एनीमिया में मामूली सुधार प्राप्त करेगा।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

राष्ट्रीय पोषण मिशन

- 2018 में लॉन्च किया गया
- यह भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है।
- उद्देश्य: बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना।
- यह NITI Aayog द्वारा "KuposhanMukt Bharat" या कुपोषण मुक्त भारत, 2022 तक प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ तैयार की गई एक राष्ट्रीय पोषण रणनीति द्वारा समर्थित है।
- उद्देश्य: (1) क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% प्रति वर्ष स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन को कम करने के लिए; (2) मिशन-मोड में कुपोषण की समस्या का समाधान करना।
- कुल बजट का 50% विश्व बैंक या अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों से आता है और शेष 50% केंद्र के बजटीय समर्थन के माध्यम से है।
- केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र के बजटीय समर्थन को 60:40 में विभाजित किया गया है, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 और बिना विधायिका के केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 100%।

जम्मू और कश्मीर में वन अधिकार अधिनियम

संदर्भ: जम्मू-कश्मीर सरकार ने अब वन अधिकार अधिनियम को लागू करने का निर्णय लिया है।
जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य में जनजातीय राजनीति **2006** के वन आरक्षण अधिनियम (एफआरए) के राजनीतिक आरक्षण और अधिनियमन / विस्तार के दोहरे मुद्दों पर केंद्रित थी।

राजनीतिक आरक्षण मुद्दे की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- राजनीतिक आरक्षण का अभाव आदिवासियों (आदिवासी लोगों) के हाशिए पर रखनेका का एक प्रमुख कारण था
- आदिवासियों को अपने मुद्दों और मांगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए गैर-आदिवासी नेतृत्व पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ा है।
- राजनीतिक आरक्षण के अभाव का मतलब था कि विधान सभा में उनके मुद्दों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था।
- आदिवासियों का वोट शेयर लगभग 21 विधानसभा क्षेत्रों में एक प्रमुख निर्णायक कारक है, फिर भी वे राजनीतिक रूप से हाशिए पर रहे।
- हालांकि, अनुच्छेद 370 (अगस्त 2019) की समाप्ति के तुरंत बाद आदिवासियों को राजनीतिक आरक्षण प्रदान किया गया। इसे सही दिशा में एक कदम माना गया।
- राजनीतिक आरक्षण का वास्तविक प्रभाव जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के लिए चुनाव होने के बाद ही देखा जाएगा।

एफआरए का मुद्दा

- J & K की विशेष स्थिति के निरस्त होने के बाद, आदिवासियों को राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने में कोई देरी नहीं हुई। हालांकि, एफआरए के विस्तार में ऐसा ही आग्रह नहीं दिखाया गया था
- वास्तव में, एफआरए बहुत पहले जम्मू-कश्मीर में होना चाहिए था - अनुच्छेद 370 में ऐसा कुछ भी नहीं था जो विधान सभा को एक समान कानून बनाने से नहीं रोकता था।
- एफआरए ने आदिवासियों को जम्मू-कश्मीर पहुंच और स्वामित्व अधिकार, वन-आधारित आजीविका अधिकार और मामूली वन उपज अधिकार प्रदान किया।
- एफआरए के कार्यान्वयन की कमी के कारण, आदिवासी भूमि की रक्षा नहीं की गई थी और आदिवासियों, विशेष रूप से खानाबदोशों के पास न तो भूमि अधिकार थे और न ही पुनर्वास अधिकार।

अब जब एफआरए को लागू किया जा रहा है, तो क्या यह आदिवासियों के मुद्दों को हल करेगा?

- कई आदिवासी परिवारों को जम्मू-कश्मीर में वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से लाभ होने की संभावना नहीं है
- एफआरए को लागू करना एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि, विस्थापन और बेरोजगारी की आशंकाओं को कम करने के बजाय, कानून ने केवल उन आशंकाओं को बढ़ाया है।
- यह मुख्य रूप स 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर सरकार के फैसले की पृष्ठभूमि के खिलाफ हो रहा है ताकि रोशनी अधिनियम को शून्य घोषित किया जा सके। (लेख के अंत में अधिनियम का विवरण है)।
- मंत्रियों, विधायकों, नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों सहित कई प्रभावशाली लोगों को राज्य भूमि के स्वामित्व के संदिग्ध हस्तांतरण के कारण रोशनी अधिनियम विवादास्पद रहा है।
- रोशनी अधिनियम ने कई गरीबों और भूमिहीन आदिवासियों को मालिकाना हक भी प्रदान किया, लेकिन अब भूमि उनसे वापस ले ली जाएगी (क्योंकि अधिनियम शून्य और शून्य होगा)। ऐसे परिदृश्य में, आदिवासी एफआरए के तहत स्वामित्व के अपने दावों को साबित करने में विफल रहेंगे।

- इसके अलावा, पिछले कुछ हफ्तों में, खानाबदोशों के खिलाफ निष्कासन और विध्वंस अभियान बिना किसी पुनर्वास योजना के तेज हो गए हैं। फिर, एफआरए, ऐसे गरीब, भूमिहीन आदिवासियों को लाभान्वित करने की संभावना नहीं है।

निष्कर्ष

- एक कट-ऑफ तारीख के बिना, रोशनी अधिनियम को शून्य और शून्य घोषित करने के बाद भूमि को पुनः प्राप्त किया जा रहा है, और बलपूर्वक निष्कासन के साथ, कई आदिवासी परिवारों को एफआरए के कार्यान्वयन से लाभ होने की संभावना नहीं है।

जम्मू और कश्मीर राज्य भूमि (व्यवसायियों के स्वामित्व का मामला) अधिनियम -रोशनी अधिनियम

- अधिनियम ने भूमि के अनधिकृत कब्जे को नियमित किया।
- इसने उन लोगों को कानूनी स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जिन्होंने कई दशकों में जम्मू और कश्मीर में सरकारी जमीन हड़प ली थी।
- यह कानूनभूस्खलन के अवैध अधिनियम को वैध बनाने के लिए शुल्क के संग्रह के लिए प्रदान किया गया है।
- इस प्रकार जुटाए गए धन का उपयोग जम्मू और कश्मीर में बिजली उत्पादन के उन्नयन के लिए किया जाना था।
- यही कारण है कि इस अधिनियम को रोशनी अधिनियम और घोटाला रोशनी घोटाला कहा जाता है।
- कोई भी व्यक्ति जिसने पहले सरकारी भूमि का एक भाग हड़प लिया था, अधिकारियों से संपर्क कर सकता है, शुल्क का भुगतान कर सकता है और भूमि का वास्तविक मालिक बन सकता है।
- इसके पीछे का कारण यह था कि जिन लोगों ने गरीबों से ऐसी जमीन नहीं खरीदी थी, जिन्होंने सरकार पर कुछ ढांचा खड़ा कर दिया था और वे जमीन के नए कानूनी मालिक बन गए।
- न्यायालय ने रोशनी अधिनियम को असंवैधानिक ठहराया और सरकार को निर्देश दिया कि वह कानून के तहत नियमित रूप से ज़मीन हड़पने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों की पूरी पहचान करे।
- जम्मू और कश्मीर सरकार ने रोशनी अधिनियम के तहत होने वाले सभी भूमि हस्तांतरण को रद्द करने का आदेश जारी किया।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - I - सोसायटी और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल शुरू किया गया।
- **उद्घाटन:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत

महत्वपूर्ण बिंदु

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों के संरक्षण) नियम, **2020** की अधिसूचना जारी होने के बाद विकसित किया गया था।
- यह पोर्टल देश में कहीं से भी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करेगा।
- सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह ट्रांसजेंडर व्यक्ति को किसी भी भौतिक इंटरफ़ेस के बिना और किसी भी कार्यालय का दौरा किए बिना आई-कार्ड प्राप्त करने में मदद करता है।
- पोर्टल के माध्यम से, वे अपने आवेदन की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं जो प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
- ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और पहचान पत्र को उनकी स्व-कथित पहचान के अनुसार प्राप्त करना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, **2019** का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है।

'गरिमा गृह : ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए नेशनल पोर्टल' का ई-शुभारंभ'

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - I – समाज और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- गरिमा गृह :ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक आश्रय गृह का 'हाल ही में वडोदरा, गुजरात में ई-उद्घाटन किया गया था।
- **उद्घाटन:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत

महत्वपूर्ण बिंदु

- आश्रय स्थल का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करना है, जिसमें आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं। इसके अलावा, यह समुदाय में व्यक्तियों के क्षमता-निर्माण/कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा जो उन्हें सम्मान और सम्मान का जीवन जीने में सक्षम बनायेगा।
- वडोदरा में यह पहला ऐसा घर है।
- **31** मार्च, **2021** तक, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना, कोलकाता, जयपुर, रायपुर, भुवनेश्वर और मणिपुर में भी ऐसे घर होंगे जिन्हें **25** व्यक्तियों की क्षमता वाला **"**गरिमा गृह**"** कहा जाएगा।
- उन्हें ट्रांसजेंडर समुदाय के नेतृत्व वाले संगठनों द्वारा चलाया जाएगा।
- आश्रय समुदाय के सदस्यों को आजीविका के अवसरों से जोड़ने के लिए कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे।
- यह एक पायलट प्रोजेक्ट है
- इसके सफल होने पर, देश के अन्य हिस्सों में इसी तरह की योजनाओं को बढ़ाया जाएगा।

ड्राफ्ट मर्चेंट शिपिंग बिल, 2020

भाग: GS प्रीलिम्स और जीएस- III – इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने मर्चेंट शिपिंग बिल, 2020 का मसौदा प्रकाशित किया है और इसे सार्वजनिक परामर्श के लिए खोल दिया है।
- ड्राफ्ट बिल को 1958 के मर्चेंट शिपिंग एक्ट और 1838 के कोस्टल वेसल्स एक्ट को रीप्लेस करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

इस बिल में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- यह विधेयक में त्यागे गए जहाजों पर भारतीय नाविकों के कल्याण में सुधार करने का प्रयास करता है।इसमें ऐसे जहाजों की सुरक्षा का भी प्रावधान है।
- यह बिल व्यापार करने में आसानी को भी बढ़ावा देता है।इसने भारतीय जहाजों के लिए सामान्य व्यापार लाइसेंस की आवश्यकता को पूरा किया है।
- यह बिल पंजीकरण के इलेक्ट्रॉनिक रूपों को सक्षम बनाता है।यह इलेक्ट्रॉनिक समझौतों, रिकॉर्ड और लॉग-बुक को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है।
- इस विधेयक में भारत के टन भार को बढ़ाने और पोत को एक पारम्परिक संपत्ति बनाने का प्रयास किया गया है।
- इस विधेयक में भारत को भरोसेमंद शिपिंग क्षेत्राधिकार के रूप में बढ़ावा देने का भी प्रावधान है।
- यह समुद्री घटनाओं के खिलाफ समुद्री आपातकालीन प्रतिक्रिया को विनियमित करने के लिए पहली बार वैधानिक ढांचे को पेश करने का प्रयास करता है।
- यह विधेयक भारत को एक सक्रिय प्रवर्तन क्षेत्राधिकार बनाएगा।
- यह महानिदेशक की शक्तियों को भी शामिल करता है ताकि असुरक्षित जहाजों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
- इस विधेयक में प्रदूषण निवारण मानकों के सक्रिय प्रवर्तन के प्रावधान भी शामिल हैं।

पुलिस के लिए एक बेहतर भविष्य

संदर्भ: पुलिस महानिदेशक (DGP) सम्मेलन दिसंबर की शुरुआत में होने वाला है।

वर्षों के माध्यम से सम्मेलन

- **सम्मेलन की नींव:** 12 जनवरी, 1950 को स्वतंत्र भारत में पहली बार संबोधित करते हुए, तत्कालीन डिप्टी पीएम और गृह मंत्री सरदार पटेल ने आशा व्यक्त की कि प्रांतीय पुलिस नागरिक शक्ति की सहायताअपने दम पर कानून और व्यवस्था को संभालेगी, और सेना पर निर्भर नहीं होगी। उन्होंने राज्यों के बीच अधिक समन्वय के साथ आपराधिक जांच में बेहतर परिणाम की उम्मीद की है।
- सम्मेलनों का प्रभाव: वार्षिक सम्मेलन की सिफारिशें, प्रारंभिक वर्षों में, पुलिस के बुनियादी ढांचे, मानव संसाधनों के प्रेरण और तकनीकी उन्नयन को काफी बढ़ावा देती हैं।
- **1950 से 1970 के दशक के दौरान चिंता:** सांप्रदायिक हिंसा, महिलाओं के खिलाफ अपराध, वाहन-चोरी और कई अन्य मुद्दों ने मौजूदा समय की चिंताओं को प्रतिबिंबित किया।

- 1970 से 1990 के दशक के दौरान चिंता: पंजाब में आतंकवाद और जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद 1980 और 90 के दशक में प्रमुख विषय बन गए।
- **21 वीं सदी की चिंताएं:** पुलिस आधुनिकीकरण, साइबर अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग, इन्फोडेमिक्स, मॉब लिंचिंग और घृणा अपराध नई चुनौतियां हैं जिनका सामना आज के समय में पुलिस कर रही है।
- हालांकि, अतीत में सम्मेलनों के दौरान, गृह मंत्रियों द्वारा महत्वपूर्ण घोषणाओं को काफी हद तक नजरअंदाज किया गया है

1. पुलिस आयुक्तालय प्रणाली

- 1962 में, लालबहादुर शास्त्री ने 500,000 से अधिक लोगों वाले शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरू करने का आह्वान किया।
- उन्होंने महसूस किया कि अपराधों और कानून-व्यवस्था को संभालने के लिए, पुलिस के पास सभी शक्तियां होनी चाहिए।

आगे का रास्ता

- **जमीनी स्तर पर पोस्टिंग:** यदि पुलिस स्टेशनों को पहुंचाना है, तो एसएचओ की पोस्टिंग पुलिस अधीक्षकों द्वारा की जानी चाहिए न कि सचिवीय फाइलों पर।
- **डीजीपी को स्वायत्तता:** पुलिस को एक पेशेवर संगठन घोषित किया जाना चाहिए जहां सीईओ, यहां के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने अपने फील्ड कमांडरों के हस्तांतरण पर अधिकार का हनन किया है और उन्हें अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है।
- **सम्मेलन में पारदर्शिता:** डीजीपी के प्रस्तावों का सार्वजनिक प्रसारण नागरिकों को प्रबुद्ध करेगा और उन्हें लागू करने के लिए मुख्यमंत्रियों (सीएम) पर नैतिक दबाव डालेगा।
- **2020 के सम्मेलन का एजेंडा:** पुलिस की भूमिका और कार्यप्रणाली पर देशव्यापी ध्यान आकर्षित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को इस वर्ष के सम्मेलन के एजेंडे पर आधारित होना चाहिए जैसे कि नागरिकता विरोधी (संशोधन) अधिनियम आंदोलन, दिल्ली दंगे, , हाथरस घटना, तूतीकोरिन थाने में हुई मौत और सुशांत सिंह राजपूत का मामला। भविष्य के लिए रोड मैप का सुझाव देते हुए, डीजीपी को इस वर्ष आंदोलन और दंगों से निपटने पर चर्चा करनी चाहिए।
- **पुलिस थानों में महत्वपूर्ण फोरेंसिक सहायता का अभाव।**
- **विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग:** डीजीपी के लिए यह निर्णय लेने का समय है कि राजद्रोह कानून, मानहानि और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, केवल असाधारण मामलों में ही उपयोग किए जाते हैं।
- **पुलिस के राजनीतिकरण से बचें:** आखिरकार, पुलिस नेताओं को पेशेवर मामलों पर राजनीतिक नेतृत्व या नौकरशाही को जगह नहीं देने का संकल्प करना चाहिए और कानून की भावना का पालन करते हुए एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए।

निष्कर्ष

- लोकतंत्र में, पुलिस सुशासन के लिए आधारशिला होती है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

Connecting the dots

- पुलिस सुधारों का लंबा इतिहास

- पुलिस सुधार और न्यायिक निर्णायक

ब्रू जनजाति पुनर्वास के खिलाफ विरोध

भाग: GS प्रीलिम्स और जीएस- I - सोसायटी और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- हाल ही में, उत्तर त्रिपुरा के कुछ हिस्सों ने ब्रू जनजाति के प्रस्तावित पुनर्वास पर हिंसक विरोध प्रदर्शन किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- जनवरी 2020 में, केंद्र द्वारा दो राज्य सरकारों और ब्रू प्रतिनिधियों को त्रिपुरा में स्थायी रूप से बसने की अनुमति देने के लिए एक चतुर्भुज समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- राज्य ने त्रिपुरा में 300 परिवारों के साथ छह जिलों में 12 पुनर्वास स्थलों की योजना बनाई है।
- केंद्र ने 600 करोड़ रु की निधि के साथ एक विशेष विकास परियोजना की घोषणा की है।
- इस समझौते से त्रिपुरा में बंगाली और मिज़ो समूहों के विरोध का सामना करना पड़ा।
- वे दावा करते हैं कि कंचनपुरवाल्ड के उत्तरी त्रिपुरा जिले में स्थायी रूप से हजारों प्रवासियों को बसाने से जनसांख्यिकीय असंतुलन पैदा होता है, स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और संभावित रूप से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होती है।
- यह भी आरोप लगाया गया था कि जम्पुई हिल रेंज से बंगाली और मिज़ो परिवार, जो ब्रूस द्वारा अत्याचार के कारण भाग गए थे, अभी तक दो दशकों में फिर से बसाए नहीं गए थे।

महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन

ब्रू

- ब्रू या रींग पूर्वोत्तर भारत का एक समुदाय है।
- यह ज्यादातर त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहता है।
- त्रिपुरा में, वे एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में पहचाने जाते हैं।
- मिजोरम में, उन्हें उन समूहों द्वारा लक्षित किया गया है जो उन्हें राज्य के लिए स्वदेशी नहीं मानते हैं।
- 1997 में, जातीय संघर्ष के बाद, लगभग 37,000 ब्रुस मिजोरम भाग गए और उन्हें त्रिपुरा में राहत शिविरों में रखा गया।
- तब से, 5,000 मिजोरम में लौट आए हैं, जबकि 32,000 अभी भी उत्तरी त्रिपुरा में छह राहत शिविरों में रहते हैं।

PRAGATI की बैठक आयोजित हुई

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - संघवाद; शासन

समाचार में

- हाल ही में, प्रधान मंत्री (पीएम) ने **33** वीं **PRAGATI** बैठक की अध्यक्षता की है।

महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन

प्रगति

- **PRAGATI** प्रो-एक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए मल्टीमॉडल प्लेटफॉर्म है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं
- **2015** में लॉन्च किया गया
- **इसके द्वारा डिज़ाइन किया गया:** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की सहायता से प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) टीम।
- यह पीएम को संबंधित केंद्र और राज्य के अधिकारियों के साथ जमीनी स्तर की स्थिति की पूरी जानकारी और नवीनतम दृश्यों के साथ मुद्दों पर चर्चा करने में सक्षम बनाता है।
- यह त्रिस्तरीय प्रणाली है: पीएमओ, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव।
- **उद्देश्य: (1)** शिकायत निवारण**; (2)** कार्यक्रम कार्यान्वयन**; (3)** परियोजना की निगरानी
- **PRAGATI** प्लेटफॉर्म नवीनतम तकनीकों जैसे डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक तकनीक का उपयोग करता है।
- **महत्व: (1)** यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है**; (2)** यह ई-पारदर्शिता और ई-जवाबदेही को वास्तविक समय की उपस्थिति और प्रमुख हितधारकों के बीच आदान-प्रदान के लिए एक मजबूत प्रणाली है**; (3)** यह ई-गवर्नेंस और सुशासन में एक अभिनव परियोजना है।

सामाजिक मुद्दे/ वेलफ़ेयर

समाचार में समुदाय: असम के मियास (Community in news: Miyas of Assam)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- I – समाज

समाचार में

- हाल ही में, एक प्रस्तावित मिया संग्रहालय में चार-चैपोरियों में रहने वाले लोगों की संस्कृति और विरासत को दर्शाते हुए असम में नया विवाद छिड़ गया है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

असम के मियास

- 'मिया' समुदाय में पूर्वी बंगाल (अब बांग्लादेश) से असम के मुस्लिम प्रवासियों के वंशज शामिल हैं।
- उन्हें 'मियास' के रूप में जाना जाता है, इन्हें क्सर अपमानजनक तरीके से देखा जाता है।
- यह समुदाय कई चरण में यंहा से प्रवास कर गया है - **1826** में यह असम के ब्रिटिश के प्रवेश से शुरू हुआ और विभाजन और **1971** के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में जारी रहा।
- उनके प्रवासन से क्षेत्र की जनसांख्यिकीय संरचना में परिवर्तन हुआ है।
- स्वदेशी लोगों के बीच असंतोष के कारण छह साल लंबे (**1979-85)** विदेशी विरोधी असम आंदोलन ने "अवैध आप्रवासी" को यंहा से बहार कर दिया, जिसे नौकरियों, भाषा और संस्कृति को संभालने की कोशिश के रूप में माना जाता था।

चार-चापोरिस

- चार-चापोरिस ब्रह्मपुत्र के नदी द्वीपों की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं।
- ये मुख्य रूप से बंगाली मूल के मुसलमानों द्वारा बसे हैं।
- एक चर तैरता हुआ द्वीप है जबकि चापोरिस निम्न रूप से बाढ़-ग्रस्त नदी तट हैं।
- जबकि बंगाली मूल के मुसलमान मुख्य रूप से इन द्वीपों पर कब्जा कर रहें हैं, अन्य समुदाय जैसे मिसिंग, देओरिस, कोचरिस, नेपाली यहां निवास करते हैं।

प्रसारभारती ने 51 शिक्षा टीवी चैनल शुरू किए (PrasarBharati to Launch 51 Education TV Channels)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II – शिक्षा

समाचार में

- यह एक ऐतिहासिक कदम में, भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन और भू-सूचना विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञान पर हस्ताक्षर किया है।
- एमओयू के तहत, 51 डीटीएच शिक्षा टीवी चैनल सभी डीडी फ्रीडिश दर्शकों के लिए डीडी सह-ब्रांडेड चैनल के रूप में उपलब्ध होंगे।
- इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों सहित हर घर में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम लाना है।
- कौशल विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और देश के अंतिम व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए **24x7** सभी दर्शकों के लिए सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध होंगी।

अरुणाचल प्रदेश सबसे अच्छा लिंगानुपात रिकॉर्ड किया गया है(Arunachal Pradesh records the best sex ratio)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - I –समाज

समाचार में

- तीन उत्तर-पूर्वी राज्य "नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़ों" में **2018** की रिपोर्ट में अरुणाचल शीर्ष पर हैं।
- **तैयार:** भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा
- अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में प्रति **1000** पुरुषों पर पैदा हुई **1,084** महिलाओं के साथ भारत में सबसे अच्छा लिंग अनुपात दर्ज किया है।
- इसके बाद **965** महिलाओं पर नागालैंड और **964** पर मिजोरम है।

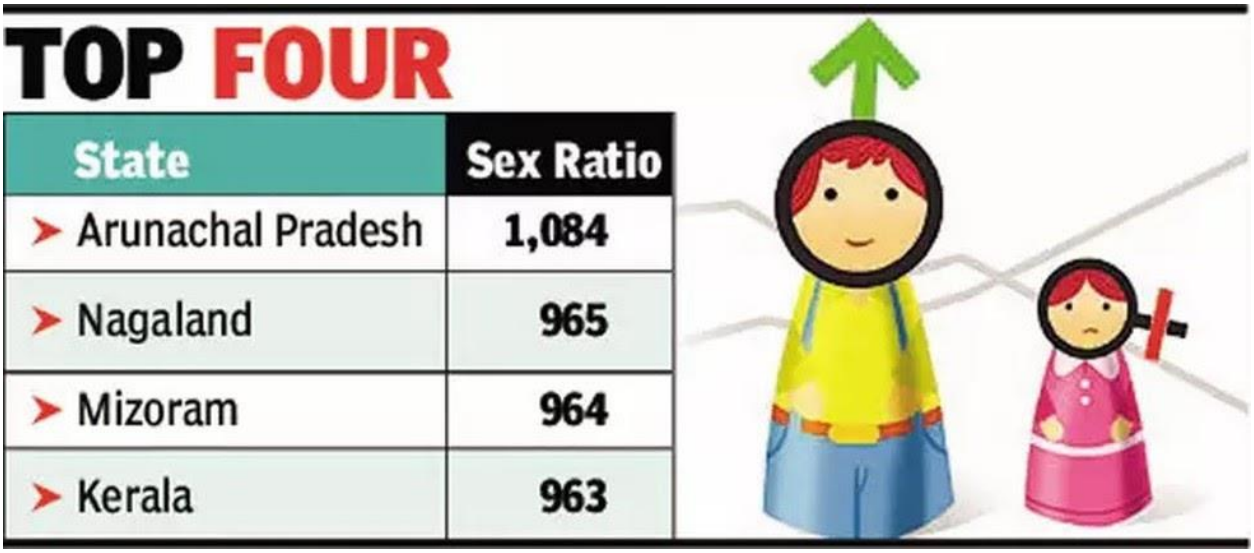

महत्वपूर्ण तथ्य

- लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है।
- यह जनसंख्या के लिंग अंतर को नापने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
- सबसे कम लिंगानुपात मणिपुर (**757),** लक्षद्वीप (**839)** और दमन और दीव (**877),** पंजाब (**896)** का है।
- अन्य पूर्वोत्तर राज्य: असम- **904,** मेघालय - **942** और त्रिपुरा - **945**।

खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता के निर्माण और विस्तार के लिए योजना (Scheme For Creation And Expansion Of Food Processing And Preservation Capacities- CEFPPC)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- **III -** खाद्य प्रसंस्करण

समाचार में

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता (CEFPPC) के निर्माण और विस्तार के लिए योजना के तहत 320 करोड़ रुपये से अधिक के 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
- महत्वपूर्ण तथ्य
- **उद्देश्य: (1)** प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण**; (2)** प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने के लिए मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के आधुनिकीकरण और विस्तार**,** मूल्य वर्धन में कमी का प्रमुख कारण है।
- यह योजना केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों / संयुक्त उपक्रमों / किसान उत्पादक संगठन (**FPOs) / NGO,** आदि जैसे संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

अटल संकाय विकास कार्यक्रम (Atal Faculty Development Programmes (FDPs)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- II - शिक्षा

समाचार में

- शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में प्रौद्योगिकी में उभरते क्षेत्रों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) से जुड़े उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 46 ऑनलाइन **AICTE** प्रशिक्षण और शिक्षण (ATAL) अकादमी संकाय विकास कार्यक्रम (**FDPs)** का उद्घाटन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- एफडीपी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (**2020)** के अनुसार **22** भारतीय राज्यों में आयोजित की जाएगी।
- ATAL अकादमी का उद्देश्य: (1) भारत में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करना; (2) विभिन्न उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देना। **IIT, IIITs, NITs CU** और रिसर्च लैब इन **ATAL FDP** का आयोजन कर रहे हैं।

क्या तआप जानते है?

- लंदन स्थित संगठन**,** बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने FDP को एक विश्व रिकॉर्ड के रूप में मान्यता दी है**,** जिसके तहत **100** से अधिक उभरते क्षेत्रों में **1,000** ऑनलाइन एफडीपी को आईआईटी**,** एनआईटी और **IIs** जैसे प्रमुख संस्थानों में एक लाख संकाय सदस्यों को लाभ होगा।

महिलाओं से सम्बंधित मुद्दे

गुजारा भत्ता दिशानिर्देश: रखरखाव कानूनों पर (Alimony guidelines: On maintenance laws)

संदर्भ: पति द्वारा निर्जन महिलाओं को अक्सर खुद को और अपने बच्चों को बनाए रखने के लिए साधन की कमी के कारण, गंभीर तनाव में छोड़ दिया जाता है और उन्हें निराश्रित कर दिया जाता है।
आमतौर पर रखरखाव के मामलों को **60** दिनों में निपटाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कानूनी खामियों की वजह से सालों लग जाते हैं।

गुजारा भत्ता संबंधी दिशानिर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला

1. आवेदन की तारीख से हकदार गुजारा भत्ता:

- उच्चतम न्यायालय ने **4** नवंबर को कहा कि पत्नियों और बच्चे अदालत में इसके लिए आवेदन करने की तिथि से पति से गुजारा भत्ता / रखरखाव का पाने के हकदार है।
- यह तर्क इस पर आधारित था कि रखरखाव कानूनों का प्राथमिक उद्देश्य एक पत्नी और आश्रित बच्चों को विनाश और यो खाना-बदोशी से बचाने के लिए है।

2. बच्चों के शैक्षिक व्यय:

- बच्चों के खर्च, उनकी शिक्षा, बुनियादी जरूरतों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों सहित, गुजारा भत्ता की गणना करते समय अदालतों द्वारा इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों का शिक्षा खर्च सामान्यतः पिता द्वारा वहन किया जाना चाहिए।
- यदि पत्नी काम कर रही है और पर्याप्त रूप से कमा रही है, तो खर्च को पार्टियों के बीच आनुपातिक रूप से साझा किया जा सकता है

3. स्थायी गुजारा भत्ता:

- न्यायालय ने कहा कि यह उचित नहीं होगा कि पति अपनी पत्नी को जीवन भर के लिए स्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश दे, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि समकालीन समाज में विवाह उचित समय तक नहीं होते हैं।
- न्यायालय ने इस प्रकार कहा कि स्थायी गुजारा भत्ते का निर्धारण करते समय विवाह की अवधि का लेखा-जोखा होना चाहिए।

4. पति का नैतिक कर्तव्य:

- पति की यह दलील कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, यदि वह सक्षम है और उसके पास शैक्षणिक योग्यता है तो यह उसे अपनी पत्नी के दैनिक देखभाल के नैतिक कर्तव्य से वंचित नहीं करता है।

5. दंड प्रावधान:

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि रखरखाव के अनुदान के लिए न्यायिक आदेश पतियों द्वारा विधिवत लागू किए जाते हैं, अदालत ने यह भी कहा कि उल्लंघन से नागरिक हिरासत और यहां तक कि बाद की संपत्ति की कुर्की जैसी सजा हो सकती है।

6. **पारदर्शिता:** आवेदक पत्नी और प्रतिवादी पति दोनों को एक रखरखाव के मामले में अपनी संपत्ति और देनदारियों का खुलासा करना होगा।
7. **महिलाओं के कष्टों को स्वीकार करती है:** अदालत ने कहा कि रखरखाव कानूनों की अधिकता के बावजूद, महिलाओं को सालों से खाली हाथ छोड़ दिया गया था, जो एक खराब शादी के बाद, संघर्ष कर रही थीं।
8. **प्रस्तावना की लंबी अवधि :** यदि आवेदन की तारीख से रखरखाव का भुगतान नहीं किया जाता है, तो रखरखाव की मांग करने वाला पक्ष आवेदन के निपटान के लिए उठाए गए समय से वंचित रह जाएगा, जो अक्सर कई वर्षों में चलता है।
9. **लिव-इन कपल्स के लिए समानता:** निर्णय ने दोहराया कि सीआरपीसी की धारा **125** में वर्षों से एक साथ रहने वाले जोड़े भी शामिल होंगे। सीआरपीसी की धारा **125** के तहत रखरखाव के अनुदान के लिए शादी का सख्त सबूत पूर्व शर्त पर आधारित नहीं होना चाहिए।
10. **अन्य अदालतों के लिए दिशानिर्देश: SC** ने परिवार की अदालतों, मजिस्ट्रेटों और निचली अदालतों के लिए एक समान और व्यापक दिशा-निर्देश दिए हैं, जिनका पालन करते हुए महिलाएं अपने पति से रखरखाव की मांग करती हैं।
11. कई नियमों के तहत पति को गुजारा भत्ता देने में असमानता
    - न्यायालय ने देखा कि महिलाएं विभिन्न कानूनों के तहत गुजारा भत्ता के लिए दावा कर सकती हैं, जिनमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, **2005** और सीआरपीसी की धारा **125**, या हिंदू विवाह अधिनियम, **1955** के तहत शामिल हैं।
    - इस प्रकार, अदालत ने कहा कि यह **"**प्रत्येक कार्यवाही के तहत रखरखाव का भुगतान करने के लिए पति को निर्देशित करने के लिए असमान होगा**"**, नागरिक और परिवार अदालतों से पिछले निर्णय पर ध्यान देने का आग्रह किया।

निष्कर्ष

- वैवाहिक मुकदमेबाजी के बड़े और बढ़ते प्रतिशत को देखते हुए, कुछ स्पष्टता की आवश्यक थी।

Connecting the dots

- सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विधेयक: प्रावधान और विश्लेषण
- सरोगेसी विनियमन विधेयक

आपदाओं में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमताओं को मजबूत करना(Strengthening public health capacities in disasters)

संदर्भ: यूरोप का अधिकांश भाग **COVID-19** की दूसरी लहर देख रहा है, जो पहले की तुलना में खराब है।

दूसरी लहर और चुनौतियां

- सार्वजनिक रूप से वर्णन किया गया: महीनों तक महामारी के साथ रहने का सामूहिक मानस पर एक निराशाजनक प्रभाव पड़ा है।
- कम हो चुकी उर्जा क्षमता: ऐसे 'डिसेन्सिटिस' के कारण, ऐसी आपदाएँ जो अचानक और हड़ताली नहीं होती हैं - जैसे **COVID-19** महामारी की दूसरी लहर- कम से कम होती हैं।
- आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क को प्रभावित करना: दुर्भाग्य से, उपरोक्त दोनों ने कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे को कमजोर किया है।

भारत का आपदा प्रबंधन ढांचा

- 2005 में, भारत ने आपदा प्रबंधन अधिनियम (DMA) लागू किया, जिसने पूरे देश में आपदाओं के प्रबंधन के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया।
- किसी आपदा की स्थिति में लागू किए जाने वाले बड़े पैमाने पर प्रतिक्रियाशील, तदर्थ उपायों को शामिल किया गया था, जिसे अधिनियम के तहत रोकथाम, शमन और सभी प्रकार की आपदाओं के लिए व्यवस्थित योजना के साथ प्रतिस्थापित किया जाना था।
- आपदा प्रबंधन के विचारों को विकास के हर पहलू और विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों में शामिल किया जाना था
- आपदा प्रबंधन अधिनियम **COVID-19** के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक किए गए कुछ कानूनों में से एक है, जिसमें उपायों की एक सीमा से लेकर - लॉकडाउन लगाने से लेकर मास्क और चिकित्सा सेवाओं के मूल्य नियंत्रण तक शामिल हैं।
- **चिंता w.r.t आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क**: जबकि कुछ जगह पर वास्तव में प्रबंधन फ्रेमवर्क अधिनियम को प्राप्त कर लिया है, यह दृष्टिकोण काफी हद तक प्रतिक्रियाशील है, सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता पर जोर देना और आपदाओं के लिए चिकित्सा स्थिरता के संदर्भ में महत्वपूर्ण अंतराल अभी भी उपस्थित है।

महामारी और सीखने के लिए DMA का उपयोग करने का अनुभव

1. निजी क्षेत्र में कमियां

- स्वास्थ्य सेवाएं और उनके निरंतर विकास आपदा-लगाए दबाव की संभावना से अनजान हैं।
- **संकट के समय में निजी क्षेत्र की गैर-निर्भरता:** मई में निजी अस्पतालों में उपचार की कीमतों के कैपिंग के बाद से, भारत में अस्पतालों द्वारा ओवर चार्जिंग के कई उदाहरण सामने आए हैं, कुछ मामलों में लाइसेंस निलंबित भी करना पड़ा।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के भविष्य के रोड मैप में निजी क्षेत्र का महत्व**: निजी क्षेत्र की निर्भरता महत्वपूर्ण है क्योंकि अस्पताल की देखभाल सेवाओं के भविष्य के विकास को सार्वजनिक रूप से

वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा के तहत मुख्य रूप से परिकल्पित किया जा रहा है, जो निजी क्षेत्र के नेतृत्व में होने की संभावना है

- **निजी क्षेत्र में संरचनात्मक कमजोरी**: देश में निजी अस्पतालों का एक बड़ा भाग छोटे उद्यम हैं जो बीमा के लिए समावेशी मानदंडों को पूरा नहीं कर सकते हैं। आपदा संबंधी देखभाल संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इनमें से कई छोटे अस्पताल अनुपयुक्त हैं।
- **आपदा तैयारी और लाभ के बीच असंगति:** आपदा तैयारी अस्पतालों के लिए एक मजबूत "व्यावसायिक मामला" नहीं बनाती है, जो अधिक लाभदायक क्षेत्रों में निवेश करना पसंद करते हैं।
- **सबक:** मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता के बिना आपदाओं से निपटना संभव नहीं है। आपदा कानून के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कानूनी जनादेश पेश करने का यह एक मजबूत मामला है

2. DMA में कमजोरी

- DMA आपदाओं के रूप में प्रगतिशील घटनाओं की पहचान करने में विफल रहता है (जो फिर भी बहुत नुकसान पहुंचाता है, अक्सर आपदाओं से अधिक), इस प्रकार तपेदिक और आवर्तक डेंगू के प्रकोप जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों को दबाने में उपेक्षा होती है।
- अगर उन्हें आपदाओं के रूप में पहचाना जाता, तो वे रोकथाम, तत्परता और प्रतिक्रिया के मामले में मजबूत कार्रवाई को आकर्षित करते।
- **प्राथमिक देखभाल के साथ अपर्याप्त एकीकरण:** प्राथमिक देखभाल बहुस्तरीय कार्रवाई, सामुदायिक सहभागिता, रोग निगरानी और आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान जैसी चीजों के लिए है, जो सभी आपदा प्रबंधन के लिए केंद्रीय हैं। आपदा प्रबंधन का यह क्षेत्र, विशेष रूप से निम्न-आय सेटिंग के लिए प्रासंगिक है, इसकी अनदेखी की गई है।
- **सबक:** आपदा प्रबंधन के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को केंद्रीय बनाना, आपदाओं के लिए स्वास्थ्य प्रणाली और सामुदायिक लचीलापन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसके अलावा, 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ तालमेल, किया जा सकता है।

निष्कर्ष

- जबकि कोरोनो वायरस महामारी ने उद्देश्य गंभीरता और व्यक्तिपरक गंभीरता दोनों को मिटा दिया है,परन्तु इसके] मूल्यवान संदेश और पाठ चारों ओर बिखरे हुए हैं। यह हमारे लिए है कि हम दृष्टि न खोएं और उनसे सीखें।

PPPs इन्फ्रास्ट्रक्चर को वित्तीय सहायता के लिए योजना को नया रूप दिया और जारी रखा जाए(The Scheme For Financial Support To PPPs in Infrastructure to be revamped and continued)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप

समाचार में

- भारतीय पीएम की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बुधवार को 2024-25 तक इंफ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को वित्तीय सहायता के लिए योजना को जारी रखने और दुरुस्त करने को मंजूरी दी, जिसकी कुल राशि 8,100 करोड़ रुपये है

महत्वपूर्ण तथ्य

- आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय ने 2006 में "इंफ्रास्ट्रक्चर में पीपीपी के लिए वित्तीय सहायता के लिए योजना" (व्यवहार्यता अंतराल निधि योजना) की शुरुआत की।
- संशोधित योजना मुख्य रूप से सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी भागीदारी को मुख्यधारा में लाने के लिए दो उप-योजनाओं का परिचय देने से संबंधित है:

उप योजना -1

- यह सामाजिक क्षेत्रों जैसे अपशिष्ट जल उपचार, जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों आदि को पूरा करेगा।
- इस श्रेणी के तहत पात्र परियोजनाओं में कम से कम 100% परिचालन लागत की वसूली होनी चाहिए।
- केंद्र सरकार परियोजना की कुल परियोजना लागत (टीपीसी) का अधिकतम 30% वीजीएफ और राज्य सरकार / प्रायोजन केंद्रीय मंत्रालय / सांविधिक इकाई के रूप में प्रदान करेगी, जो टीपीसी के 30% तक अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकती है।

उप योजना -2

- यह उप योजना प्रदर्शन / पायलट सामाजिक क्षेत्रों की परियोजनाओं का समर्थन करेगी।
- परियोजनाएं स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों से हो सकती हैं, जहां कम से कम 50% परिचालन लागत वसूली है।
- ऐसी परियोजनाओं में, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर पूंजीगत व्यय का 80% तक और पहले पांच वर्षों तक संचालन और रखरखाव (O & M) लागत का 50% तक प्रदान करेंगी।

महिला रोजगार(Women Employment)

संदर्भ: वर्ष 2020 में महिलाओं की स्थिति से संबंधित दो प्रमुख घटनाओं की वर्षगांठ है।

- सबसे पहले, **भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति (CSWI)** ने संयुक्त राष्ट्र **(UN)** को 'टुवार्ड इक्वेलिटी' रिपोर्ट सौंपी है, जो भारत में महिला-संवेदनशील नीति निर्धारण पर केंद्रित है, जो लैंगिक समानता पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है।
- दूसरा, यह बीजिंग प्लेटफार्म फॉर एक्शन की **25** वीं वर्षगांठ है, जो महिलाओं की स्थिति और राज्य के नेतृत्व वाले सशक्तिकरण के विश्लेषण के लिए एक बेंचमार्क है।

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के मुद्दे

- **आर्थिक विकास रोजगार में तब्दील नहीं:** भारत में महिला रोजगार के रुझान उच्च आर्थिक विकास, कम प्रजनन क्षमता, और महिला स्कूली शिक्षा में वृद्धि के साथ प्रतिध्वनित नहीं होते हैं।
- **महिला श्रम बल भागीदारी दर में गिरावट:** आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), **2018-19** से पता चलता है कि महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम भागीदारी दर (**2011** से **2019** तक) में **35.8%** से **26.4%** तक की गिरावट का सामना करना पड़ा, और शहरी क्षेत्रों में ठहराव लगभग **20.4%** है।
- **निम्न वैश्विक रैंकिंग:** इसके अलावा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में भारत को **153** देशों में से **149** रैंक प्राप्त हुई है।
- **वेज गैप: 2019** ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार, पुरुषों के लिए **34%** से कम (समान योग्यता और काम के लिए) महिलाओं के साथ लैंगिक वेतन अंतर एशिया में सबसे अधिक है। यह भारत के समान पारिश्रमिक अधिनियम, **1976** की गारंटी के बावजूद महिलाओं के श्रम बल में भागीदारी करता है।
- **कृषि का उन्मूलन:** कृषि जो लगभग पूरी तरह से अनौपचारिक क्षेत्र है, लगभग **60%** महिलाएं कार्यरत हैं, जो बिना किसी क्रेडिट पहुंच, सब्सिडी, छोटे उपकरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों की कमी के साथ भूमिहीन मजदूरों का निर्माण करती हैं।
- **अबीसमल भूमि का स्वामित्व: 2019** में केवल **13%** महिला के पास अपनी भूमि थी।
- **विनिर्माण क्षेत्र में कम भागीदारी:** विनिर्माण केवल लगभग **14%** महिला श्रम शक्ति में कार्यरत है (लगभग पूरी तरह से अनौपचारिक रूप से)।
- **देखभाल कार्य सेवा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पर हावी है:** राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) **2005** के अनुसार, **4.75** मिलियन घरेलू कामगारों में से **60%** से अधिक महिलाएं हैं।
- **घरेलू काम का असमान लिंग विभाजन:** महिलाएं घरेलू काम में पुरुषों की तुलना में तीन गुना (एनएसएस के अनुसार) या यहां तक कि छह बार (ओईसीडी के अनुसार) खर्च करती हैं।
- **अत्यधिक स्वास्थ्य वर्धक कार्य:** डब्ल्यूएचओ के अनुसार, दुनिया की **70%** स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कार्यकर्ता महिलाएँ हैं। भारत में, महिलाएँ **ASHA** कार्यकर्ताओं की अग्रिम पंक्ति के रूप में अपरिहार्य हैं।

- **महामारी के प्रतिकूल प्रभाव:** भारत में, भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्र (**CMIE**) के अनुसार **39%** महिलाओं ने अप्रैल और मई में **29%** पुरुषों की तुलना में अपनी नौकरी खो दी, जो कि महामारी के संदर्भ में है।

महिलाओं के मुद्दों पर हाल ही में पारित तीन श्रम कोडों की आलोचना

- कानूनों से श्रम संबंधों को बदलने की उम्मीद की जाती है, लेकिन वे केवल आसान व्यवसाय को समाप्त करते हैं।
- कोड न तो लिंग वेतन अंतर को स्वीकार करते हैं और न ही मजदूरी और बोनस का भुगतान नहीं करते हैं, और सामाजिक सुरक्षा, बीमा, भविष्य निधि, मातृत्व लाभ, या ग्रेच्युटी के संदर्भ में अनौपचारिक (ज्यादातर महिलाओं) श्रमिकों को अनदेखा करते हैं।
- यद्यपि महिलाओं को रात की पाली में काम करने की अनुमति है, लेकिन जवाबदेही और जिम्मेदारी पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से भी सुरक्षा गायब है।
- मातृत्व लाभ **2017** के संशोधन से अपरिवर्तित बने हुए हैं, एक असंवेदनशील रूप से गोद लेने की नीति के साथ, जो उन महिलाओं को अनुदान देती है जो तीन महीने से कम उम्र के शिशुओं को गोद लेती हैं, यह अनदेखी करते हुए कि गोद लेने के समय अधिकांश बच्चे बहुत बड़े हैं।

निष्कर्ष

- हाल के श्रम कोड ने महिलाओं की कार्य स्थितियों की उपेक्षा की हैं।
- लिंग समानता की कामना नहीं की जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक नीति और संहिता भारत के कार्यबल के विशाल अनुपात को प्रभावित करती है।

महिलाओं के अनुकूल शहर (Women Friendly Cities)

संदर्भ: भारत में शहरी नियोजन लैंगिक दृष्टिकोण का कारक नहीं है। महिलाओं की चिंताओं को दूर करने के लिए शहरों को नया रूप देने की जरूरत है।

मुद्दे

- व्यक्तिगत सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा
- इन सभी का महिलाओं की स्थिति पर एक गुणक प्रभाव पड़ता है - ये सार्वजनिक स्थानों, नौकरियों और यहां तक कि कितना अवकाश समय व्यतीत कर सकते हैं, उनकी पहुंच को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- महिलाओं की चिंताओं के प्रति उदासीनता एक कठिन आवागमन और खराब चाइल्डकैअर सुविधाओं का परिणाम है।
- वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों का अलगाव स्वचालित रूप से घर से काम करने के लिए आवागमन बढ़ाता है और महिलाओं के लिए प्रवेश बाधाओं को बनाता है।

- साझा परिवहन आमतौर पर असुरक्षित पाया गया है। लेकिन समर्पित फुटपाथ या साइकिल ट्रैक के अभाव में, महिला यात्रियों के पास बहुत कम विकल्प हैं।

आगे का रास्ता

- शहरों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए, शहरी नियोजकों को दो मुख्य मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए- हिंसा से सुरक्षा और पर्याप्त चाइल्डकेयर समर्थन।
- मिश्रित भू-उपयोग, आवासीय इलाकों में कार्यालय अंतरिक्ष और वाणिज्यिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करके, सड़कों के नियमित उपयोग, बेहतर प्रकाश व्यवस्था का निर्माण और महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **चंडीगढ़ मॉडल -** इस शहर ने स्थानीय बाजारों, वाणिज्यिक कार्यालयों, स्कूलों, सार्वजनिक पार्कों, डाकघरों, पुलिस चौकियों और चिकित्सा क्लीनिकों में प्रत्येक छोटे इलाके या क्षेत्र के डिजाइन में फैक्टरिंग की है।
- विश्वसनीय चाइल्ड केयर सुविधाएं, आवश्यक हैं यदि हम महिलाओं को नौकरी के बाजार में प्रवेश करने, नौकरियों को बनाए रखने और अवकाश गतिविधियों को आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं।
- यह सुनिश्चित करना कि पूरे शहर में पर्याप्त क्रेच उपलब्ध हैं, महिलाओं को मुफ्त में सेट करना और उनके माता-पिता के कर्तव्यों के निर्वहन में उनका समर्थन करना महत्वपूर्ण है।
- निर्माण स्थलों के लिए, मोबाइल क्रेच एक जवाब हो सकता है।

स्वास्थय समस्या

स्कूल का बंद होना और पोषक तत्वों की कमी (School Closures and Nutrition Fallout)

संदर्भ: COVID-19 प्रेरित लॉकडाउन के मद्देनजर भारत में अनिश्चित कालीन स्कूल बंद होने के कारण 116 मिलियन बच्चे प्रभावित हुए, जिसने सबसे बड़े स्कूल-फीडिंग कार्यक्रम को मध्याह्न भोजन योजना को बाधित किया है।

क्या आपको पता है?

- **FAO** द्वारा विश्व **2019** की रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा और पोषण राज्य के अनुसार, भारत में लगभग **194.4** मिलियन लोग कुपोषित हैं।
- एक वास्तविक समय की निगरानी करने वाले उपकरण ने अनुमान लगाया कि अप्रैल 2020 तक, स्कूल बंद होने के कारण, वैश्विक स्तर पर **369** मिलियन बच्चे स्कूली भोजन से दूर हो गये थे, जिनमें से एक बड़ी संख्यां भारत में थी।

अहम मुद्दे

- 2030 **तक 'जीरो हंगर' लक्ष्य को पूरा करने के लि एमुश्किल है:** हाल ही में **2020** के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स (**GHI)** रिपोर्ट में भारत **107** देशों में से **94** पर और श्रेणी 'गंभीर' में अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे है।
- **नामांकन दर गिरने का खतरा:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार **COVID-19** और बाल श्रम पर, यह चेतावनी देती है कि जब तक स्कूली सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत नहीं किया जाता है, एक जोखिम है कि कुछ बच्चे वापस भी नहीं लौट सकते।

मध्याह्न भोजन योजना के बारे में

- इस योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार करना है जिसका स्कूलों में नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- भारत में मध्याह्न भोजन को मध्याह्न भोजन योजना (MDMS) दिशानिर्देश, 2006 के अनुसार मध्याह्न भोजन द्वारा 450 Kcal ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन प्रदान करना चाहिए, जिसमें पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लोहा, फोलिक एसिड, विटामिन-ए आदि शामिल हैं।)।
- यह सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक के सभी स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ, बच्चे की पोषण संबंधी आवश्यकता का लगभग एक तिहाई है।
- हालांकि, कई शोध रिपोर्ट, और यहां तक कि एमडीएमएस के संयुक्त समीक्षा मिशन, **2015-16** ने उल्लेख किया कि कई बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते हैं, जिससे स्कूल के मध्यान्ह भोजन बच्चों के लिए पोषण का एक प्रमुख स्रोत बन जाता है, विशेष रूप से कमजोर समुदायों के लोगों के लिए ।

COVID-19 महामारी के दौरान MDMS का क्या हुआ?

- मार्च और अप्रैल **2020** के आदेशों में, **COVID-19** महामारी और स्कूलों को बंद करने के मद्देनजर, भारत सरकार ने घोषणा की कि सामान्य रूप से गर्म-पका हुआ मिड-डे मील या एक समान खाद्य सुरक्षा भत्ता / सूखा राशन प्रदान किया जाएगा। छुट्टी के समय भी स्कूल जाने वाले सभी बच्चे इसके पात्र होंगे।
- इसे यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि उनकी प्रतिरक्षा और पोषण से समझौता न किया जाए।
- इस निर्णय को लेने में लगभग तीन महीने लगे, राज्य अभी भी इसे लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
- भारतीय खाद्य निगम **(FCI)** के फूड ग्रेन बुलेटिन के अनुसार, अप्रैल और मई, 2020 के दौरान एफसीआई से एमडीएमएस के तहत अनाजों का उठाव 221.312 हजार टन था, जो अप्रैल और मई, 2019 (281.932 हजार टन) की तुलना में 22% कम होता है।
- **23** राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे जिन्होंने **2019** में इसी महीने की तुलना में अप्रैल-मई **2020** में **FCI** से अनाज की कमी की सूचना दी थी।
- उदाहरण के लिए, बिहार राज्य, जिसने अप्रैल और मई **2019** में **44.585** हजार टन का उत्पादन किया, **2020** में इन दो महीनों के दौरान कोई उतार-चढ़ाव नहीं हुआ था।
- डेटा और मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि स्कूल के भोजन के बदले में सूखे राशन वितरण अनियमित हैं।
- स्कूल के भोजन और कामकाजी स्कूलों की कमी के लिए अन्य चिंताजनक तथ्य यह है कि कमजोर घरों में परिवार की आय में गिरावट को पूरक करने के लिए श्रम में संलग्न बच्चों की रिपोर्टें आ रही है।

महामारी की अवधि के दौरान MDMS के कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए अभिनव रणनीति

1. स्थानीय छोटे किसान की भागीदारी

- **COVID-19** संकट ने भी ऐसे विकेंद्रीकृत मॉडल और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता को प्रोत्साहित किया है।
- स्थानीय छोटे किसानों की स्कूल के फीडिंग में किसानों की भागीदारी इस तरह की पोषण पहलों में शामिल हो सकती है।
- एक आजीविका मॉडल स्थापित किया जा सकता है जो स्थानीय छोटे किसानों को अनाज, सब्जियों और अंडों की आपूर्ति के लिए मध्याह्न भोजन प्रणाली से जोड़ता है।
- यह न केवल बच्चों की प्रोटीन और छिपी हुई भूख की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है, बल्कि उत्पादन और खेती प्रणालियों में विविधता ला सकता है, ग्रामीण आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बदल सकता है, और आत्मानिर्भर (पोषण आत्मनिर्भरता) एजेंडा को पूरा कर सकता है।

स्कूल पोषण (रसोई) गार्डन

- मध्याह्न भोजन के लिए ताजी सब्जियां प्रदान करने के लिए **MDMS** के तहत स्कूल पोषण (रसोई) गार्डन एक और पहल हो सकती है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए योग्य बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है और स्कूल के मध्यान्ह भोजन केंद्र में भोजन तैयार करने और वितरित करने की योजना बनाई जा सकती है।
- यह ओडिशा जैसे राज्यों में बुजुर्गों और अन्य लोगों के लिए मुफ्त शहरी कैंटीन या सामुदायिक रसोई के समान है।
- इसके अलावा, योजना की उपलब्धता के बारे में पर्याप्त जागरूकता की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- स्कूलों को फिर से खोलने के संबंध में अनिश्चितता के साथ, यह सुनिश्चित करने के लिए नवाचार की आवश्यकता है कि न केवल भोजन, बल्कि पोषण लाखों बच्चों तक नियमित रूप से पहुंचाया जाए। उनमें से कई के लिए, यह गर्म-पकाया भोजन शायद दिन का सबसे अच्छा भोजन होता था।

बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) रैंकिंग में भारत सबसे नीचे है(India ranks amongst the bottom in Body Mass Index (BMI) ranking)

भाग: GS प्रीलिम्स और जी GS- II - स्वास्थ्य

समाचार में

- द लांसेट में एक अध्ययन के अनुसार, भारत उन देशों में क्रमशः नीचे से तीसरे और पांचवें स्थान पर है जहां **19** वर्षीय लड़कियों और लड़कों का बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) कम है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- **2,181** अध्ययनों के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद **200** देशों में **2019** में ऊंचाई और बीएमआई रुझानों के लिए नए अनुमान प्रदान किये है।
- कुक आइलैंड्स में **29.6** के उच्च और इथियोपिया में **19.2** के निचले स्तर की तुलना में **19** वर्षीय लड़कों का बीएमआई **20.1** है।
- भारतीय लड़कियों के लिए, बीएमआई फिर से **20.1** है, जबकि टोंगा में **29.0** की उच्च और तिमोर-लेस्ते में **19.6** का निचला स्तर पर है।
- भारतीय **19**-वर्षीय बच्चों की औसत ऊंचाई लड़कों के लिए **166.5** सेमी और लड़कियों के लिए **155.2** सेमी है, जो नीदरलैंड के लड़कों (**183.8** सेमी) और लड़कियों (**170** सेमी) की ऊंचाई से काफी नीचे है।

क्या आप जानते है?

- बीएमआई को मीटर में ऊंचाई के वर्ग द्वारा विभाजित किलो में वजन के रूप में मापा जाता है।

- डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देश सामान्य बीएमआई सीमा को **18.5** से **24.9** के बीच परिभाषित करते हैं, **25** या अधिक के रूप में अधिक वजन, और **30** या अधिक के रूप में मोटापा माना जाता है।

वैक्सीन की दौड़ में अंतिम चरण, भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम(In vaccine race last lap, the key steps for India)

संदर्भ: पिछले कुछ महीनों में विज्ञान में लगभग अनूठे प्रयासों ने एक ऐतिहासिक कम समय में वादे के साथ (प्रमुख फार्मा कंपनियों, फाइजर और मॉडर्ना से) कम से कम दो **COVID-19** टीके (प्रमुख फार्मा कंपनियों, फाइजर और मॉडर्न से) प्राप्त किए हैं।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उसके साथी एस्ट्राजेने का दिसंबर के अंत तक अपने चरण-**3** परीक्षणों के परिणामों की उम्मीद कर रहे हैं, और कथित तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के बीच पहले परीक्षण में एक अच्छी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया देखी गई है

COVID-19 वैक्सीन के लिए मूल्यांकन मानदंड क्या होना चाहिए?
COVID-19 के लिए उम्मीदवार के टीके का मूल्यांकन तकनीकी मापदंडों और प्रोग्रामेटिक उपयुक्तता पर किया जाना चाहिए। एक आदर्श टीका इन सभी को प्रदान करेगा -

1. एक वैक्सीन जो उच्च डिग्री (विशेष रूप से गंभीर बीमारी के खिलाफ **90%** + सुरक्षात्मक), व्यापक पैमाने (विभिन्न प्रकारों के खिलाफ) और टिकाऊ (कम से कम पांच साल अगर आजीवन नहीं) की प्रतिरक्षा प्रदान करती है
2. एक टीका जो सुरक्षित है (थोड़ा या कोई दुष्प्रभाव नहीं और निश्चित रूप से कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं)
3. एक टीका जो सस्ता है (वर्तमान बचपन के टीकों के समान);
4. एक वैक्सीन जो प्रोग्रामेटिक रूप से उपयुक्त है (एकल खुराक, कमरे के तापमान पर रखी जा सकती है या **2** डिग्री सेल्सियस और **4** डिग्री सेल्सियस, सुई-रहित डिलीवरी के बीच सरलतम प्रशीतन की जरूरत है।
5. एक वैक्सीन जो मल्टीडोसेविअल्स में उपलब्ध है, जिसमें लंबे समय तक शैल्फ जीवन होता है और तेजी से उत्पादन के लिए उत्तरदायी है।

एक मुश्किल टीके को विकसित करना
ऐतिहासिक रूप से, हमने कोरोनावायरस टीकों के विकास में कई कठिनाइयों का सामना किया है।

- **कोई संदर्भ टीके नहीं:** हालांकि गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम (SARS) और मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम (MERS) के खिलाफ टीकों के विकास में कुछ प्रयास किए गए थे, लेकिन अभी तक किसी भी कोरना वायरस के लिए किसी लाइसेंस प्राप्त टीके की मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

- **पुन: संक्रमण का खतरा:** पिछले कोरोनावायरस टीके इम्युनोजेनिक पाए गए (द्वितीय चरण के अनुसार एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं), लेकिन प्रभावी ढंग से बीमारी (चरण **III)** के अधिग्रहण को रोकने के लिए एक चिंता का विषय नहीं है कि फिर से संक्रमण संभव हो सकता है
- **अपर्याप्त दीर्घकालिक अनुभव:** वैक्सीन के प्रतिरक्षात्मक परिणामों के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी हैं क्योंकि ये टीके नई तकनीकों का उपयोग करते हैं जिनके साथ हमारे पास दीर्घकालिक या बड़ी आबादी का अनुभव नहीं है।
- **पोस्ट-लाइसेंसर सर्विलांस सिस्टम की आवश्यकता:** टीकों की सुरक्षा के बारे में, हमेशा दुर्लभ (एक मिलियन में) या देरी (महीनों या वर्षों से) की संभावनाएं होती हैं, गंभीर प्रतिकूल घटनाएं जो बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू होने के बाद ही सामने आएंगी; इसके लिए एक अच्छी पोस्ट-लाइसेंसर निगरानी प्रणाली की आवश्यकता है।

विभिन्न उम्मीदवार COVID-19 **टीकों को देखते हुए, टीकाकरण के लिए और टीकाकरण करते समय सरकार की रणनीति क्या होनी चाहिए?**

- **जोखिम श्रेणी के आधार पर रैंकिंग:** पहला नियम यह होगा कि आप अपने सभी अंडे एक टोकरी में न रखें। हम पहले से ही जानते हैं कि सरकार ने विभिन्न स्रोतों से वैक्सीन की आपूर्ति की योजना बनाई है
- **दूसरा नियम प्राथमिकता देना होगा:** डब्ल्यूएचओ ने टीका प्राप्तकर्ताओं के लिए प्राथमिकता के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके लिए, हमें जोखिम श्रेणी और टीकाकरण में आसानी से प्रोग्राम उप-समूहों को रैंक करने की आवश्यकता है। टीकाकरण शुरू होना चाहिए जहां ये दो मानदंड प्रतिच्छेद करते हैं - स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता और पुलिसकर्मियों
- तीसरा नियम जनसंख्या के टीकाकरण करने के लिए कई चैनलों का उपयोग किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण विचार समता और लागत के होंगे।

आगे की चुनौतियां

1. सामान्य जनसंख्या का टीकाकरण

- निजी क्षेत्र या जिला अस्पतालों सहित, कोल्ड स्टोरेज आवश्यकताओं का उपयोग करके स्वास्थ्य कर्मियों (और पुलिसकर्मियों) की तरह फ्रंटलाइन श्रमिकों का टीकाकरण करना
- समस्या विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूहों (बुजुर्गों और सह-रुग्णता वाले लोगों) के टीकाकरण में उत्पन्न होती है
- सामुदायिक आवास की तुलना में संस्थागत बुजुर्गों का टीकाकरण करना आसान हो सकता है।
- समाधान: उम्र और सह-रुग्णता की उपस्थिति और निकटतम बूथ में नियुक्ति के आवंटन के लिए पहले से पंजीकरण प्रक्रिया के आधार पर एक कतारबद्ध प्रणाली के तकनीकी समाधान के कुछ प्रकार बनाने के लिए एकमात्र व्यवस्थित विकल्प है

2. वैक्सीन वितरण में समानता सुनिश्चित करना

- सबसे बड़ी चुनौती सबसे गरीब और सबसे कमजोर (मलिन बस्तियों / प्रवासियों / शरणार्थियों / विकलांग लोगों) को टीकाकरण करना होगा।
- **समाधान:** पहुंच के मुद्दों के कारण, आउटरीच दृष्टिकोण (बूथों के साथ-साथ नागरिक समाज द्वारा सुगम वेब-सक्षम नियुक्तियों के साथ)को अपनाना चाहिए।
- **संस्थागत अनुभव:** भारत ने पल्स पोलियो अभियान, आधार कार्ड नामांकन और चुनावों के दौरान सामाजिक गतिशीलता प्रयासों के माध्यम से बड़े सबक सीखे हैं, जो अच्छे मॉडल के रूप में काम करेंगे
- **रणनीतिक उपयोग:** यह उम्मीद की जाती है कि एक बार जब हम लगभग 60% आबादी (कवरेज एक्स प्रभावशीलता के संदर्भ में) की रक्षा करेंगे तो महामारी फिर से शुरू हो जाएगी। हालांकि, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह कवरेज अच्छी तरह से फैला हुआ है, अन्यथा फोकल प्रकोप गरीब वैक्सीन कवरेज वाले क्षेत्रों में घटित होता रहेगा।
- इससे पहले भी एक रिंग टीकाकरण रणनीति (रिपोर्ट किए गए मामलों के आसपास की आबादी का टीकाकरण) का उपयोग करने की संभावना बढ़ जाती है।

3. बाजार की ताकतों का मुद्दा

- एक बड़ी चुनौती यह होगी कि बहुत से लोग वैक्सीन के लिए भुगतान करने और शीघ्र पहुँच के लिए तैयार होंगे।
- जाहिर है, जब तक हम चरण **1** लाभार्थियों के एक बड़े हिस्से को कवर नहीं करते हैं, तब तक सरकार को अन्य समूहों के साथ चिंता नहीं करनी चाहिए।
- हालांकि, सरकार को ऐसे लोगों के लिए बाजार संचालित मूल्य पर वैक्सीन को निजी क्षेत्र में उपलब्ध कराने की अनुमति देनी चाहिए।
- यह नैतिक और साथ ही सरकार के लिए लागत-बचत होगी, यदि यह सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम से टीकों को नहीं हटाती है।
- सरकार द्वारा वितरित वैक्सीन या निजी क्षेत्र से एक व्यक्ति के लिए प्रतीक्षा करने का निर्णय किया जाना चाहिए, न कि सरकार द्वारा। यह सरकार को "जरूरतमंद" लोगों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए भी स्वतंत्र करेगा।

निष्कर्ष

- कई देशों ने पहले से ही अपनी प्राथमिकता नीति को प्रकाशित किया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सरकार के पास इस संबंध में एक निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रकाशित नीति है, भले ही इसे लेकर कुछ लोगों में नाराज़गी हो।

डिलेरियम: पुराने कोविद -19 रोगियों के लिए लक्षणों में से एक (Delirium: One of the symptoms for older Covid-19 patients)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - स्वास्थ्य

समाचार में

- एक नया अध्ययन, इस तथ्य का समर्थन करता है कि डिलेरियम पुराने रोगियों में कोरोनोवायरस संक्रमण की भविष्यवाणी कर सकता है जिनमें कोविद **-19** के कोई अन्य विशिष्ट लक्षण नहीं दिखाते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- डिलेरियम मानसिक क्षमताओं में एक गंभीर गड़बड़ी है जिसके परिणामस्वरूप भ्रमित सोच और पर्यावरण के प्रति जागरूकता में कमी आती है।
- डिलेरियम की शुरुआत आमतौर पर तेजी से होती है - घंटों या कुछ दिनों के भीतर।
- डिलेरियम से अक्सर एक या एक से अधिक योगदान करने वाले कारकों से पता लगाया जा सकता है, जैसे कि एक गंभीर या पुरानी बीमारी, चयापचय संतुलन में बदलाव (जैसे कम सोडियम), दवा, संक्रमण, सर्जरी, या अल्कोहल या ड्रग का नशा ।

क्या आप जानते है?

डिमेंशिया और मनोभ्रंश

- डिमेंशिया और मनोभ्रंश को भेद करना विशेष रूप से मुश्किल हो सकता है, और एक व्यक्ति के पास दोनों हो सकते हैं।
- **शुरुआत:** प्रलाप की शुरुआत कम समय के भीतर होती है, जबकि मनोभ्रंश आमतौर पर अपेक्षाकृत मामूली लक्षणों से शुरू होता है जो समय के साथ धीरे-धीरे बिगड़ते हैं।
- **ध्यान:** ध्यान केंद्रित करने या ध्यान बनाए रखने की क्षमता डिमेंशिया से काफी प्रभावित होती है। डिमेंशिया के शुरुआती चरणों में एक व्यक्ति आम तौर पर सतर्क रहता है।
- **उतार-चढ़ाव:** डिमेंशिया के लक्षणों की उपस्थिति पूरे दिन में काफी और बार-बार उतार-चढ़ाव कर सकती है।

भारत के कुपोषण की छाया से बाहर निकलना (Stepping out of the shadow of India's malnutrition)

संदर्भ: हालिया में प्रकाशित दो रिपोर्ट - FAO द्वारा "विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2020" पर प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट और विश्व संस्थान के हंगर रिपोर्ट-2020, "बेहतर पोषण, बेहतर कल" - दस्तावेज़ ने चौंका देने वाली जानकारी साँझा की है।

अल्पपोषण की व्यापकता (PoU)

- अल्पपोषण उन लोगों के प्रतिशत को मापता है जो अपनी आवश्यक आहार ऊर्जा की आवश्यकता की तुलना में अपर्याप्त कैलोरी का उपभोग कर रहे हैं।
- भारत में, कुपोषण में कमी नहीं आई है क्योंकि गरीबी के मामले में गिरावट आई है।

- प्रतिशत के संदर्भ में, **PoU** ने भारत के लिए **2001** और **2018** के बीच **24.7%** की गिरावट की है; जबकि चीन (**76.4%**), नेपाल (**74%**), पाकिस्तान (**42%**), अफगानिस्तान (**37.4%**) और बांग्लादेश (**18.9%**) में भी गिरावट आई है।
- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चीन में गिरावट भारत की तुलना में अधिक है, हालांकि यह **2000** में **PoU** के निम्न स्तर के साथ शुरू हुआ था।
- इसके विपरीत, अफगानिस्तान (**47.8%**) जिसने भारत (**18.6%**) की तुलना में अधिक आधार के साथ शुरुआत की थी, में गिरावट की उच्च दर का अनुभव किया गया है।
- नोट- तथ्य यह है कि, आर्थिक रूप से, जबकि अफगानिस्तान अपेक्षाकृत अधिक गरीब है और पिछले दो दशकों में कई लंबे संघर्षों से गुजरा है, यह भारत की तुलना में कुपोषण को कम करने में अधिक सफल रहा है।
- इसलिए, **PoU** के आधार स्तर के बावजूद, इनमें से अधिकांश देशों ने इस आयाम पर भारत से बेहतर काम किया है।

मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा (PMSFI) की व्यापकता

- ये निष्कर्ष खाद्य असुरक्षा अनुभव स्केल सर्वेक्षण के माध्यम से प्रमाणित होते हैं, जो दुनिया की लगभग **90%** आबादी को कवर करता है।
- क्योंकि इसे भारत में आयोजित करने की अनुमति नहीं है, प्रत्यक्ष अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।
- हालांकि, अनुमान बताते हैं कि **2014-16** के बीच, भारत में कुल आबादी का लगभग **29.1%** खाद्य असुरक्षित था, जो **2017-19** में **32.9%** तक बढ़ गया।
- निरपेक्ष संख्या के संदर्भ में, **2014** में कुल आबादी का लगभग **375** मिलियन मामूली या गंभीर खाद्य असुरक्षित था, जो **2019** में लगभग **450** मिलियन हो गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 **कुपोषण से निपटने में क्यों विफल रहा?**

अधिनियम के बावजूद प्रत्येक नागरिक "किफायती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता वाले भोजन की पहुंच" सुनिश्चित करने के बावजूद, दो महत्वपूर्ण तत्व जो अभी भी इससे बहार है-

- दालों जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों का गैर-समावेश
- संभावित लाभार्थियों का बहिष्कार।

आने वाले दिनों में खतरे

- बढ़ती बेरोजगारी और गहरे आर्थिक मंदी के साथ आने वाले वर्षों में कुपोषण की समस्या गहरा सकती है।
- मौजूदा **COVID-19** महामारी कमजोर समूहों के लिए सामान्य रूप से स्थिति को और अधिक खराब कर देगी।

आगे का रास्ता

- नीति में एक प्रमुख बदलाव को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तत्काल सार्वभौमिकरण को शामिल करना है जो निश्चित रूप से प्रकृति में अस्थायी नहीं होना चाहिए।
- गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों और अभिनव हस्तक्षेपों का वितरण करना होगा जैसे कि अन्य चीजों के बीच सामुदायिक रसोई की स्थापना करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम देश में कम से कम इस कुपोषण के कुछ हिस्से का प्रयोग करते हैं, मौजूदा कार्यक्रमों के सही उपयोग और विस्तार की समय की जरूरत बनी हुई है।

Connecting the dots

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स **(GHI)**
- नोबेल शांति पुरस्कार **2020**

स्वास्थ्य नीति: आयुर्वेद डॉक्टर सामान्य सर्जरी कर सकते हैं (Health Policy: Ayurveda doctors to practise general surgery)

संदर्भ: केंद्रीय चिकित्सा परिषद, भारतीय चिकित्सा पद्धति को विनियमित करने के लिए आयुष मंत्रालय के तहत गठित एक वैधानिक संस्था, 20 नवंबर को, एक राजपत्र अधिसूचना जारी करके स्नातकोत्तर (पीजी) आयुर्वेदिक चिकित्सकों को विभिन्न प्रकार की सामान्य सर्जरी जैसे- ईएनटी, नेत्र विज्ञान और दंत चिकित्सा प्रक्रिया के लिए औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

यह निर्णय भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, **2016** में संशोधन के बाद आयुर्वेद के पीजी छात्रों को सामान्य सर्जरी का अभ्यास करने की अनुमति देता है।

स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही उठाये गए कदम

- 2019 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम के पारित होने से मध्य-स्तर के देखभाल प्रदाताओं - सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं - को भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में शामिल करने के प्रस्तावों के औपचारिकरण की अनुमति मिल गई।
- वे देश भर में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में काम करेंगे, और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित करेंगे, साथ ही रोगियों के उपचार के लिए उनके उपयोग के लिए सीमित मात्रा में दवाइयों का उपयोग करेंगे।
- इस कदम ने आधुनिक चिकित्सा चिकित्सकों के मजबूत विरोध को भी आकर्षित किया था, जिन्होंने इसे अल्प ज्ञान वाले डॉक्टरों के माध्यम से एक प्रकार का क्वैकेरी के रूप में ब्रांड किया था।
- कई देशों में स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच बढ़ाने के लिए नर्स चिकित्सकों के रूप में मध्य-स्तर के देखभाल प्रदाताओं का उपयोग किया गया है, हालांकि प्रशिक्षण, प्रमाणन और मानकों के आसपास सख्त सुरक्षा उपायों को अपनाया गया है।

क्या गैर-एलोपैथिक डॉक्टरों को कानूनी रूप से और चिकित्सकीय रूप से शल्य चिकित्सा करने की अनुमति है?

- वर्तमान बहस आयुर्वेद में स्नातकोत्तर छात्रों को शल्या (सामान्य सर्जरी) और शलाक्य (आंख, कान, नाक, गला, सिर और गर्दन, ओरो-डेंटिस्ट्री से निपटने) की अनुमति देने के इर्द-गिर्द घूमती है।
- इसका कई एलोपैथिक पेशेवरों द्वारा तुरंत विरोध किया गया था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने इसे एलोपैथी से शर्तों का उपयोग करके चिकित्सा प्रणालियों के मिश्रण की अनुमति देने के एक मोड के रूप में शुरू किया था।
- आयुष मंत्रालय ने बाद में स्पष्ट किया कि शल्य और शलाक्य स्नातकोत्तर अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालयों में अपने (शल्य चिकित्सा) विभागों में इन प्रक्रियाओं को पहले से ही सीख रहे थे।

क्या अल्पकालिक प्रशिक्षण उन्हें शल्यचिकित्सा आयोजित करने के लिए तैयार कर सकता है और क्या यह भारत में चिकित्सा मानकों को कम करेगा?

- इस तरह, स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक सर्जिकल प्रशिक्षण अल्पकालिक नहीं, बल्कि औपचारिक रूप से तीन वर्षीय पाठ्यक्रम है।
- क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों में की जाने वाली शल्यचिकित्सा में एक ही मानक और परिणाम होते हैं क्योंकि एलोपैथिक संस्थानों को रोगी सुरक्षा के हित में अन्वेषण और विस्तृत औपचारिक जांच की आवश्यकता होती है।

क्या गैर-एलोपैथिक डॉक्टर जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, वे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब चिकित्सक-रोगी अनुपात को कम करेगा?

- अब तक, ऐसा कोई प्रतिबंध मौजूद नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक सर्जिकल पोस्टग्रेजुएशन करने वाले गैर-एलोपैथिक डॉक्टरों को सीमित करता है।
- उन्हें अपनी पसंद के किसी भी प्रक्रिया में अभ्यास करने के लिए एलोपैथिक स्नातकों और स्नातकोत्तर के समान अधिकार हैं।

एलोपैथिक सर्जन अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में अभ्यास करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है?

- सर्जन सहित एलोपैथिक डॉक्टरों की कमी और अनिच्छा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए अब एक पुरानी समस्या है।
- सरकार ने ग्रामीण बांड जैसे तंत्रों द्वारा इसे संबोधित करने का प्रयास करता है, जो स्नातकोत्तर सीटों में कोटे का प्रावधान है जिन्होंने ग्रामीण सेवा की है, साथ ही हाल ही में, मेडिकल कॉलेजों और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना है ।
- हालांकि, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित विशेषज्ञों की कमी है।

- सरकार को तथ्य-आधारित दृष्टिकोण, जैसे कार्य-साझाकरण, कुशल और गुणवत्ता रेफरल तंत्र द्वारा समर्थित, द्वारा इस अंतर को संबोधित करने के रचनात्मक तरीकों का पता लगाने की आवश्यकता है।
- मध्य-स्तर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का आगमन, जैसे कई राज्यों में सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाता, इन प्रदाताओं को स्वास्थ्य सेवा के कुछ तत्वों (निवारक, प्रचारक और सीमित उपचारात्मक) को स्थानांतरित करने का एक अवसर है, जबकि भूमिका और कैरियर की प्रगति की स्पष्टता सुनिश्चित करते हैं। ।

क्या आयुर्वेदिक सर्जनों को केवल एलोपैथिक सर्जनों की सहायता करने की अनुमति देना समझदारी है, न कि स्वयं सर्जरी करना?

- आयुष धाराएँ चिकित्सा की मान्यता प्राप्त प्रणाली हैं, और जैसे कि स्वतंत्र रूप से चिकित्सा का अभ्यास करने की अनुमति है।
- उनके पास स्नातक और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण दोनों के साथ मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें कुछ प्रणालियों के लिए शल्यचिकित्सा विषय शामिल हैं, जैसे कि आयुर्वेद।
- हालांकि, दवा की प्रणालियों में दृष्टिकोण में अंतर है, और इसलिए यह मॉडल क्रॉस-पैथी के लिए अनुमति देता हैं।
- एलोपैथिक सर्जनों के साथ काम करने वाले आयुर्वेदिक सर्जनों के लिए एक प्रशिक्षुता मॉडल नियामक ग्रे जोन में आ सकता है। इसे आधुनिक चिकित्सा में सर्जिकल दृष्टिकोण के विज्ञान में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को फिर से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता हो सकती है।
- फिर भी, वहाँ एक सीमा का निर्धारण किया जा सकता है कि उन्हें क्या करने की अनुमति है।
- ऐसा कोई भी प्रयोग रोगी की सुरक्षा को संकट में डाल सकता है, और इसलिए सावधानीपूर्वक निरीक्षण और मूल्यांकन की आवश्यकता होगी।

क्या यह प्रक्रिया सही है?

- कई मरीज़ आयुष प्रदाताओं से विशेष रूप से उपचार प्राप्त करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ उपचार के इस रूप को मौजूदा एलोपैथिक उपचार के पूरक के रूप में अपनाते हैं।
- इस प्रक्रिया के द्वारा, सर्जरी की तरह, जोखिम तत्व अधिक हो सकता है।
- मरीजों को यह जानने और समझने का अधिकार है कि उनका सर्जन कौन होगा, वे किस चिकित्सा पद्धति से संबंधित हैं और उनकी विशेषज्ञता और प्रशिक्षण का स्तर क्या है।
- शहरी और ग्रामीण रोगियों के बीच देखभाल की गुणवत्ता में अंतर नहीं होना चाहिए - हर कोई प्रशिक्षित पेशेवरों से गुणवत्ता और साक्ष्य-आधारित देखभाल के अधिकार का हकदार है।

निष्कर्ष

सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए कदम उठाने होंगे, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सर्जरी करने के लिए आयुर्वेद चिकित्सकों को शामिल करते समय सुरक्षा मानकों को बनाए रखा जाए।

Connecting the dots

- **चिकित्सा शिक्षा:** केंद्रीकरण अत्यधिक कठोर है

सरकारी योजनाएँ

प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए फंड को बंद कर दिया गया (Funds meant for Pre-Matric Scholarship Scheme siphoned off)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - कल्याणकारी योजनाएं

समाचार में

- हाल ही में एक जांच में पाया गया है कि झारखंड में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत गरीब छात्रों के लिए जो पैसा आवंटित किया गया था, वह निकाल लिया गया है,परन्तु छात्रों तक नहीं पहुंच रहा है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

- यह सभी राज्यों में छात्रों के लिए केंद्र पोषित छात्रवृत्ति योजना है।
- इसके तहत मैट्रिक तक की पढ़ाई के दौरान अल्पसंख्यक समाज के गरीब और मेधावी बच्चों को केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से डीबीटी के जरिए पैसे मुहैया कराए जाते हैं, यह हर साल खुलता है और इसे अगस्त से नवंबर के बीच लागू किया जाता है।
- उद्देश्य: अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध जिनके अभिभावक की वार्षिक आय **1** लाख से कम है, ऐसे छात्रों की मदद करना
- पात्रता: छात्रों को अपनी कक्षा की परीक्षा में कम से कम **50%** स्कोरप्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- यह हर साल इसे दो स्तरों में दिया जाता है: कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों को 1000 रुपए प्रति वर्ष और कक्षा 5 से दसवीं तक के बच्चों को 5700 रुपए प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार (Emergency Credit Line Guarantee Scheme extended)

भाग: GS प्रीलिम्स और जीएस- **II** - कल्याण योजनाएं और जीएस- **III** - उद्योग

समाचार में

- केंद्र सरकार ने आपातकाल क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (**Emergency Credit Line Guarantee Scheme)** यानी ईसीएलजीएस (**ECLGS)** को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब लोग इस स्कीम का फायदा 30 नवंबर तक उठा सकते हैं। इस पैकेज के तहत ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए **3** लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना शुरू की गई थी, जिससे तहत अब तक **2** लाख करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS)

- यह योजना मई **2020** में घोषित किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी।
- **उद्देश्य:** विभिन्न क्षेत्रों को ऋण प्रदान करके कोरोनोवायरस-प्रेरित लॉकडाउन के कारण होने वाले संकट को कम करने के लिए।
- **29** फरवरी, **2020** तक बकाया अपने ऋण का **20%** की सीमा तक **MSMEs,** व्यावसायिक उद्यमों, **MUDRA** उधारकर्ताओं और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत ऋण के लिए पूरी तरह से गारंटी और संपार्श्विक मुक्त अतिरिक्त ऋण प्रदान करना।
- **पात्रता: 29** फरवरी, **2020** तक **50** करोड़ और वार्षिक कारोबार के साथ **250** करोड़ रुपये तक बकाया क्रेडिट वाले उधारकर्ता
- **कार्यकाल:** प्रिंसिपल रीपेमेंट पर एक साल की मोहलत सहित चार साल।

अंतरराष्ट्रीय

भारत की विदेश नीति में होता परिवर्तन (The shifting trajectory of India's foreign policy)

संदर्भ: तीसरी भारत-यू.एस. भारत के विदेश और रक्षा मंत्रियों और अमेरिकी राज्य सचिवों और रक्षा मंत्रियों के बीच **2 + 2** मंत्रिस्तरीय वार्ता **26-27** अक्टूबर को दिल्ली में संपन्न हुई।

बैठक का मुख्य परिणाम

- भू-स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते (BECA) पर हस्ताक्षर
- दो दिवसीय बैठक में मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग पर कदम उठाने पर चर्चा हुई, जिसमें सैन्य- सैन्य सहयोग, सुरक्षित संचार प्रणाली और सूचना साझाकरण, रक्षा व्यापार और औद्योगिक मुद्दों को एक नए स्तर पर शामिल किया गया।
- BECA पर हस्ताक्षर के साथ, भारत अब सभी अमेरिकी-संबंधित मूलभूत सैन्य समझौतों (2016 में LEMOA पर हस्ताक्षर किए गए और COMCASA 2018 में हस्ताक्षर किए गए)
- सैन्य-सैन्य संधि प्रभावी रूप से क्षेत्र में व्यापक अमेरिकी रणनीतिक वास्तुकला के लिए भारत को जोड़तीहै।

सैन्य संधि का महत्वपूर्ण विश्लेषण

- **भारत की सैन्य स्वतंत्रता के बारे में आशंकाएँ:** इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने के पिछले प्रयासों का इस आधार पर विरोध किया गया था कि यह भारत की सुरक्षा और सैन्य मामलों में स्वतंत्रता से समझौता करेगा।
- **रणनीतिक स्वायत्तता इसे खोखला कर देगी:** समझौतों में निर्मित दो तरह से सूचनाओं के आदान-प्रदान का प्रावधान हैं जो रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने पर भारत के रुख के साथ समर्थन नहीं करती है।
- **व्यापक चीन विरोधी गठबंधन ने आकर्षित किया:** संस्थापक समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राथमिक बल चीन द्वारा उत्पन्न खतरा था, और इसके हस्ताक्षर के साथ भारत, चीन विरोधी व्यापक गठबंधन की तरफ झुक गया है
- **पावर पॉलिटिक्स में गैर-तटस्थता:** भारत ने तटस्थता की अपनी पिछली नीति को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया है, और पावर ब्लॉक्स (अमेरिका और चीन) से अपनी समान दूरी बनाए रखी है।
- **भारत-रूस प्रभाव का संबंध:** अमेरिका से संबंधित मूलभूत सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले से भारत, भारत-रूस संबंधों पर प्रभाव नहीं डाल सकता है, जो आधी सदी से अधिक समय से भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख आधार रहा है।

इन संधिओं पर हस्ताक्षर करने और भारत-अमेरिका संबंधों को गहरा करने के पक्ष में तर्क

- यह तर्क दिया जाता है कि संधि में निर्मित पर्याप्त भारत-विशिष्ट सुरक्षा उपाय हैं और चिंता का कोई कारण नहीं है।

- यह भी तर्क दिया जा सकता है कि नई नीति अनिवार्य रूप से एक व्यावहारिक है, जो वैश्विक विकार की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनायी गयी है।
- यह तर्क भी दिया जा सकता है कि वैचारिक रूप से अज्ञेय का रवैया आज की मौजूदा परिस्थितियों के अनुकूल है।

चीन पर प्रभाव - शांति बनाए रखना एक कठिन चुनौती है

- चीन-भारत संबंध कभी भी आसान नहीं रहे हैं। 1988 से, भारत ने एक ऐसी नीति अपनाई है जिसने चीन के साथ टकराव से बचने के लिए एक प्रीमियम रखा है।
- 2017 में डोकलाम के बाद भी, भारत ने बेहतर संबंधों को बनाए रखने के लिए वुहान और ममल्लापुरम में प्रयास किया। यह अब तेजी से समस्याग्रस्त हो जाएगा क्योंकि भारत, अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है।
- अमेरिका के साथ उच्च स्तरीय खुफिया और अन्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत के साथ सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर करने की इच्छा ने यह सुझाव दिया है कि भारत ने अपनी पसंद का चुनाव कर लिया है, जिससे चीन-भारत संबंधों बिगड़ सकते है।
- भारत के कई पड़ोसी (श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश), जिन्हें आमतौर पर भारत के प्रभाव क्षेत्र के भीतर माना जाता है, वर्तमान में कई मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण से बाहर हो गए हैं।
- एक ही समय में, चीन और अमेरिका दोनों अलग-अलग हो रहे हैं, यहाँ पर अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं।
- उदाहरण के लिए, मालदीव ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी विस्तारवाद का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी सेना के साथ एक सैन्य समझौता किया है।

आगे का रास्ता

- **पश्चिम एशिया:** भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कूटनीतिक हैंडलिंग के माध्यम से, नवीनतम यूएई-इजरायल संपर्क क्षेत्र में भारत के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। भारत को ईरान- संबंधों को पुनः स्थापित करने और बहाल करने के लिए अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जो हाल के वर्षों में निश्चित रूप से भयावह हो गए हैं।
- **अफगानिस्तान:** , उस देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हाल के दशकों में किए गए जबरदस्त निवेश को देखते हुए, भारत को तय करना चाहिए कि इस समय नीति में बदलाव अफगानिस्तान में भारत के उद्देश्यों की पूर्ति कैसे करेगा।
- **शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ):** जब भारत यूसीओ के साथ अपने नए संबंधों पर विचार करते हुए एससीओ की सदस्यता के लिए जाता है, तो संबंधो को मजबूत करने के लिए भारत को फिर से प्रयास करना होगा और इसे फिर से विकसित करने की आवश्यकता होगी
- **गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM):** इसी तरह, भले ही वर्तमान में भारत के पास एक अलग दृष्टिकोण है, लेकिन NAM को नजरअंदाज कर दिया गया है, और नीतिगत नुस्खों के मामले में अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी समूह से खुद को दूर कर लिया है, भारत नए गठबंधन पैटर्न का अनुसरण कर रहा है
- **रूस:** भारत एक समय में एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में रूस पर भरोसा करने की उम्मीद कर सकता है, जब रूस-चीन संबंधों में व्यापक रूप से विस्तार हुआ है और दोनों देशों के बीच एक

रणनीतिक अभिनंदन मौजूद है। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों को कौशल और निपुणता के साथ संभालने की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

नई दिल्ली के कूटनीतिक कौशल का परीक्षण अब किया जाएगा कि देश प्रभावी रूप से क्या अमेरिकी सुरक्षा वास्तुकला का एक भाग बन गया है

Connecting the dots

- सार्क और बिम्सटेक का भविष्य
- दुनिया में बढ़ते ध्रुवीकरण के समय में भारत की गुटनिरपेक्ष नीति

गिलगित-बाल्टिस्तान का महत्व (The importance of Gilgit-Baltistan)

संदर्भ: 1 नवंबर को, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान ने घोषणा की कि उनकी सरकार गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को "अस्थायी प्रांतीय दर्जा" देगी।

गिलगित बाल्टिस्तान (जी-बी) के बारे में

- इस क्षेत्र का दावा भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर की तत्कालीन रियासत के हिस्से के रूप में किया जाता है क्योंकि यह 1947 में भारत में अपने प्रवेश के समय मौजूद था।
- हालांकि**,** पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के पश्चिमी सिरे पर गिलगित और इसके दक्षिण में बाल्टिस्तान स्थित है, यह इलाका **4** नवंबर **1947** के बाद से ही पाकिस्तान के प्रशासन में है.

- जी-बी के पश्चिम में अफगानिस्तान है, इसके दक्षिण में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) है, और पूर्व में जम्मू-कश्मीर स्थित है।

गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में एक संक्षिप्त इतिहास

- 1935 में गिलगित को रजा हरि सिंह ने अंग्रेजों को पट्टे पर दे दिया था क्योंकि तब गिलगित बाल्टिस्तान उस समय सोवियत और ब्रिटिश द्वन्द का भाग था।
- अगस्त 1947 में अंग्रेजों ने G-B लौटा दिया और हरि सिंह ने गिलगित स्काउट्स की कमान संभालने के लिए अपने प्रतिनिधि ब्रिगेडियर घनसार सिंह को गवर्नर और मेजर विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन को भेजा।
- **1** नवंबर **1947** को, जम्मू-कश्मीर के शासक हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर किए थे, और भारतीय सेना पाकिस्तान से कबिलियाई आक्रमणकारियों को बाहर निकालने के लिए घाटी में करती है, इसके विरोध में गिलगित में हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह हुआ।
- गिलगित स्काउट्स ने अपने कमांडर, मेजर विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन के नेतृत्व में भारत के खिलाफ विद्रोह किया जिसने पाकिस्तानी का साथ दिया और बाद में पाकिस्तानी प्रशासनिक नियंत्रण जी-बी पर लागु कर दिया गया।
- पाकिस्तान ने जी-बी के अधिग्रहण को स्वीकार नहीं किया, हालांकि उसने क्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण ले लिया।
- भारत के संयुक्त राष्ट्र में जाने के बाद और कश्मीर में स्थिति पर सुरक्षा परिषद में प्रस्तावों की एक श्रृंखला पारित की गई थी, पाकिस्तान का मानना था कि न तो जी-बी और न ही पीओके को पाकिस्तान में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे कश्मीर में जनमत संग्रह के लिए अंतरराष्ट्रीय मामले को कमजोर किया जा सकता है।
- पाकिस्तान ने यह भी कहा कि यदि कश्मीर में कभी कोई जनमत संग्रह होता है, तो जी-बी में वोट भी महत्वपूर्ण होंगे।

वर्तमान स्थिति क्या है?

- हालांकि पाकिस्तान, भारत की तरह, जी-बी के भाग्य को कश्मीर से जोड़ता है, परन्तु इसकी प्रशासनिक व्यवस्था पीओके के लोगों से अलग है।
- जबकि पीओके का अपना संविधान है जो अपनी शक्तियों और उनकी सीमाओं को पाकिस्तान के रूप में स्थापित करता है, जी-बी को ज्यादातर कार्यकारी शक्तियों द्वारा शासित किया जाता है। 2009 तक, इस क्षेत्र को केवल उत्तरी क्षेत्र कहा जाता था।
- इसे अपना वर्तमान नाम केवल गिलगित-बाल्टिस्तान (सशक्तीकरण और स्वशासन) आदेश, **2009** के साथ मिला, जिसने उत्तरी क्षेत्र विधान परिषद को विधान सभा से बदल दिया।
- NALC एक निर्वाचित निकाय था, लेकिन यह पाकिस्तान सरकार के लिए एक सलाहकार की भूमिका से अधिक नहीं था।

- हालांकि पाकिस्तान में लंबे समय से जी-बी को अस्थायी प्रांतीय दर्जा प्रदान करने की मांग की गई थी, लेकिन कई कारकों ने इस स्थिति को प्रदान करने की दिशा में एक बल दिया।

जी-बी के लोग क्या चाहते हैं?

- जी-बी के लोग वर्षों से मांग कर रहे हैं कि इसे पाकिस्तान का भाग बनाया जाए, उनके पास वही संवैधानिक अधिकार नहीं हैं जो पाकिस्तान के पास हैं।
- इनका भारत के साथ वास्तव में कोई संबंध नहीं है।
- कुछ ने पूर्व में पीओके के साथ विलय की मांग की है, लेकिन जी-बी के लोगों का कश्मीर के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है। वे कई गैर-कश्मीरी जातीयताओं से संबंधित हैं, और विभिन्न भाषाओं में बोलते हैं, इनमें से कोई भी कश्मीरी नहीं है।
- अनुमानित **1.5** मिलियन जी-बी निवासियों में से अधिकांश शिया हैं। शियाओं को निशाना बनाने वाले चरमपंथी संप्रदायवादी उग्रवादी समूहों को हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है
- पाकिस्तान पर जी-बी के लोगों में भी असंतोष है जो अपने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को निर्धारित करते हैं।
- लेकिन प्रमुख भावना यह है कि पाकिस्तानी संघ का भाग होते ही क्या ये सभी सुधर जायेगा।
- यंहा स्वतंत्रता के लिए एक छोटा सा आंदोलन जरूर चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत कम आकर्षण है।

पाकिस्तान में जी-बी की स्थिति को बदलने की सम्भावना के पीछे प्रमुख कारक

- पिछले एक साल में जी-बी प्रांतीय दर्जा देने की योजना को गति प्राप्त हुई।
- **भारत कारक:** जम्मू और कश्मीर के **5** अगस्त, **2019** के पुनर्गठन के बाद जी-बी पर अपने दावों का जोर देने से भारत को धक्का लग सकता है।
- **चीनी कारक:** ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि परिवर्तन की स्थिति इस क्षेत्र में चीनी हितों से भी जुड़ी हुई है, जिनकी महत्वाकांक्षी परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीईपीसी) इस क्षेत्र से गुजरती है। यह क्षेत्र पाकिस्तान को एकमात्र क्षेत्रीय सीमा प्रदान करता है, और इस तरह चीन के साथ एक भूमि मार्ग है, जहां यह झिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र से मिलता है।
- **घरेलू राजनीति:** स्थिति में बदलाव उस समय भी आता है जब पाकिस्तान सरकार विपक्षी दलों के विरोध का सामना कर रही है। जी-बी क्षेत्र का यह पुनर्गठन सत्तारूढ़ दल को अपनी साख को मजबूत करने और विरोधों से ध्यान हटाने के लिए काम करेगा।

बदली हुई स्थिति का परिणाम

- यह जम्मू और कश्मीर की स्थिति को बदलने के लिए भारत के तर्क को और मजबूत करेगा और UNSC जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों में कूटनीतिक चोरी प्रदान करेगा।
- भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है, यदि दोनों देशों द्वारा -जैसा करो ,वैसा भरो दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

- यह चीन-पाकिस्तान धुरी को मजबूत करने का भी संकेत देता है क्योंकि पाकिस्तान अपने **CPEC** अवसंरचनात्मक परियोजना के लिए चीन को सुरक्षा का आश्वासन देना चाहता है
- कश्मीर संघर्ष जो अब तक द्विपक्षीय था, विशेष रूप से त्रिपक्षीय संघर्ष में बदल सकता है क्योंकि चीन आक्रामक तरीके से **CPEC** परियोजना पर जोर दे रहा है जो जी-बी क्षेत्र से गुजरती है।

निष्कर्ष

भारत की सुरक्षा एजेंसियों और राजनयिकों को इस नए विकास को गंभीरता से देखना चाहिए और जी-बी क्षेत्र पर भारत के क्षेत्रीय दावों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

अमेरिका और पेरिस समझौता (US and Paris Agreement)

सन्दर्भ: संयुक्त राज्य अमेरिका बुधवार को औपचारिक रूप से **पेरिस जलवायु समझौते को 4** नवंबर **2020 छोड़ दिया**, तीन साल बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पूर्ववर्ती बराक ओबामा की महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा गया था।

क्या है पेरिस समझौता?

- दिसंबर **2015** में, **195** देशों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (**UNFCCC**) के भीतर एक समझौते (नवंबर **2016** में लागू हुआ) पर ग्रीनहाउस-गैस-उत्सर्जन शमन, अनुकूलन और वित्त के लिए समझौता किया
- **उद्देश्य:** पेरिस समझौते का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है, जिससे सदी के अंत तक तापमान वृद्धि को पूर्वऔद्योगिक स्तर के 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सके। यह समझौता पांच साल के चक्र पर काम करता है। विकसित देश अल्प विकसित और विकासशील देशों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराते हैं। किसी देश की सरकार अकेले बूते इन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकती है, इसलिए समझौते में विभिन्न संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है।
- इस समझौते में एक और महत्वपूर्ण बिंदु **2050** और **2100** के बीच "शुद्ध शून्य उत्सर्जन" प्राप्त करना था। राष्ट्रों ने "इस सदी के उत्तरार्ध में ग्रीनहाउस गैसों के स्रोत और निष्कासन द्वारा मानवजनित उत्सर्जन के बीच संतुलन हासिल करने का संकल्प लिया है"।
- विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और अनुकूलन उपायों के लिए विकासशील देशों की मदद करने के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए भी कहा गया था।
- एक समीक्षा तंत्र के हिस्से के रूप में, विकसित देशों को हर दो साल में "सांकेतिक" राशि का संचार करने के लिए कहा गया था जो वे अगले दो वर्षों में उठा पाएंगे, और इस बात की जानकारी सार्वजनिक वित्तीय स्रोतों से कितनी होगी। ।
- इसके विपरीत, विकासशील देशों को स्वैच्छिक आधार पर हर दो साल में ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए "प्रोत्साहित" किया जाता है।
- इस समझौते में सूखे, बाढ़ आदि जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण कम विकसित राष्ट्रों द्वारा सामना किए गए वित्तीय घाटे को संबोधित करने के लिए एक तंत्र भी शामिल है। हालांकि, विकसित राष्ट्रों

को वित्तीय दावों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसे इसमें शामिल नहीं किया गया है या किसी भी दायित्व के लिए यह आधार भी प्रदान नहीं करता है।

अमेरिका ने पेरिस समझौते को क्यों छोड़ दिया?

- अपने **2016** के राष्ट्रपति अभियान के दौरान, डोनाल्ड ट्रम्प ने पेरिस समझौते को अमेरिकी हितों के लिए "अनुचित" बताया था, और कहा कि यदि चुने गए तो समझौते से बाहर निकलने का वादा किया था।
- जून **2017** में, उद्घाटन के महीनों बाद, ट्रम्प ने समझौते को छोड़ने के लिए अपनी सरकार के फैसले की घोषणा की
- अमेरिका पेरिस समझौते से तुरंत बाहर नहीं निकल सका**,** हालांकि**,** संयुक्त राष्ट्र के नियमों ने एक देश को समझौते के लागू होने के तीन साल बाद यानी **4** नवंबर**, 2019** को लागू करने की अनुमति दी।
- अमेरिका ने औपचारिक रूप से उस दिन को छोड़ने के लिए आवेदन किया**,** और अनिवार्य रूप से साल भर की प्रतीक्षा अवधि के अंत में **4** नवंबर**, 2020** को प्रस्थान स्वतः ही प्रभावी हो गया।

ग्लोबल लीडरशिप रोल से यूएस के पीछे हटने की प्रवृत्ति

ट्रम्प प्रेसीडेंसी (2016 के बाद) के बाद से, यूएस -

- यू.एन. मानवाधिकार परिषद और यू.एन. सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को से बाहर निकला
- पेरिस समझौते और ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकला
- यू.एन. जनसंख्या निधि (**UNFPA)** और यू.एन. एजेंसी के लिए धन की कटौती जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों (**UNRWA)** को मदद करती है
- एक अमेरिकी प्रवासन समझौते का विरोध किया

पेरिस समझौते से अमेरिका की वापसी की आलोचना क्या थी?

- यह पहल आम जिम्मेदारी के सिद्धांत के विरुद्ध है।
- **GHGs** उत्सर्जन अतीत की बात है और भविष्य में इसे कम करने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए अमेरिका पर एक नैतिक दायित्व डालता है।
- अमेरिका द्वारा उठाए गए कदम के परिणामस्वरूप डोमिनोज़ प्रभाव हो सकता है**,** अन्य राष्ट्र भी इस सौदे से पीछे हट सकते हैं। यह जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे व्यापक सौदे में से एक होगा।
- यह चीन को संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान विशेष रूप से अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ पर्यावरणीय नेतृत्व दिखाने का अवसर प्रदान करता है।
- जबकि अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर है**,** अमेरिकी राज्यों और कंपनियों के कई अभी भी सौदे के लिए खुद को पार्टी मानते हैं।

क्या पेरिस समझौते से अमेरिका के वापस जुड़ने की कोई संभावना है?

- डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बिडेन ने लंबे समय तक कहा है कि अगर वह **2020** के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो अमेरिका इससे फिर से जुड़ जाएगा।
- औपचारिक रूप से **UNFCCC** में आवेदन करने के तीस दिन बाद, अमेरिका फिर से पेरिस फ्रेमवर्क का एक भाग बन जाएगा, और **2030** के लिए अपने उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- बिडेन, जो संभवतः **2021** से अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ट्रम्प की जगह ले सकते हैं, ने **2** ट्रिलियन **$** खर्च की योजना का प्रस्ताव किया है जिसमें स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु के अनुकूल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना शामिल है।

भारत और जलवायु उत्सर्जन

- हाल के दशकों के त्वरित आर्थिक विकास के बावजूद, भारत का वार्षिक उत्सर्जन **0.5** टन प्रति व्यक्ति है, वैश्विक औसत **1.3** टन से नीचे है।
- चीन का कुल **C02** उत्सर्जन दुनिया का **29.51%** है और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन **7.7** है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का कुल **C02** उत्सर्जन दुनिया का **14.34%** है और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन **16.1** है।
- संचयी उत्सर्जन के मामले में, **2017** तक भारत का योगदान **1.3** बिलियन की आबादी के लिए केवल 4% था, जबकि केवल 448 मिलियन की आबादी वाला यूरोपीय संघ, 20% के लिए जिम्मेदार था।
- भारत उन कुछ देशों में से एक है जो वर्तमान में अपनी पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ट्रैक पर है।

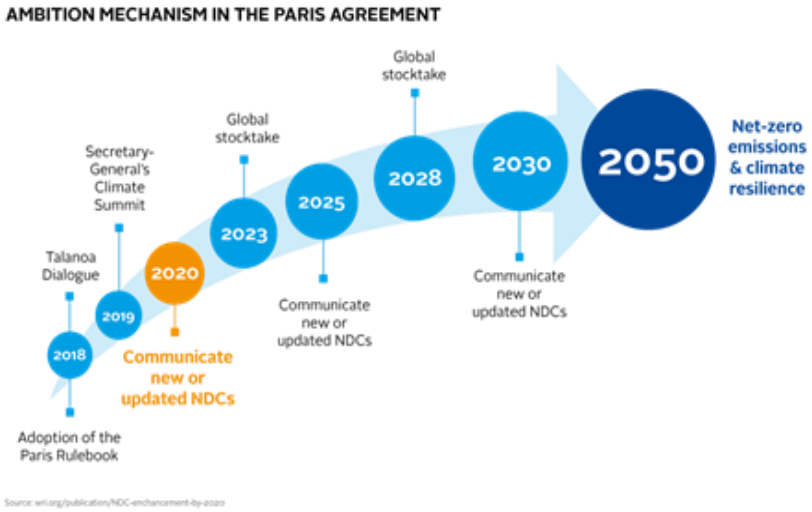

Connecting the dots:

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
- डब्ल्यूएचओ से अमेरिका द्वारा सदस्यता को वापस लेना

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (United Nations Industrial Development-UNIDO)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - ग्लोबल ग्रुपिंग

समाचार में

- नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठनों (UNIDO) के प्रतिनिधि ने कहा है कि आर्थिक विकास की क्षेत्रीय क्लस्टर अवधारणा भारतीय सफलता की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- **UNIDO** संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है।
- **170** राज्य **1** अप्रैल **2019** तक **UNIDO** के सदस्य हैं
- **जनादेश:** सदस्य राज्यों में समावेशी और सतत औद्योगिक विकास **(ISID)** को बढ़ावा देने और तेजी लाने के लिए।
- **मुख्यालय:** वियना, ऑस्ट्रिया।
- इसकी स्थापना **1966** में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी।

समाचार में स्थल : टाइग्रे क्षेत्र, इथियोपिया (Place in news: Tigray region, Ethiopia)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- इथियोपिया के प्रधान मंत्री की घोषणा के बाद इथियोपिया एक गृह युद्ध के कगार पर है, उसने देश के उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र में सशस्त्र बलों द्वारा कथित रूप से हिंसक हमले का मुकाबला करने के लिए सैनिकों को आदेश दिया था।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- टाइग्रे क्षेत्र इथियोपिया के नौ क्षेत्रों (किलकिलट) में सबसे उत्तरी है।
- यह टाइग्रेन, इरोब और कुनमा लोगों की मातृभूमि है।
- इसे संघीय संविधान के अनुसार क्षेत्र 1 के रूप में भी जाना जाता है।
- राजधानी और सबसे बड़ा शहर: मेकेल।
- इसकी सीमा उत्तर में इरिट्रिया, पश्चिम में सूडान, दक्षिण में अमहारा क्षेत्र और पूर्व और दक्षिण पूर्व में अफ़ार क्षेत्र से लगती है।

क्या आप जानते है?

- नवंबर **2020** की शुरुआत में, क्षेत्र और इथियोपियाई संघीय सरकार ने संघर्ष किया, जिसमें टाइग्रे, मेकेले की राजधानी में कुछ गोलियों चलने की सूचना दी गई।
- सितंबर में भी संघर्ष हुआ था, जब तिग्रे ने इथियोपियाई संघीय सरकार के अपमान में स्थानीय चुनाव आयोजित किए थे।
- इन चुनावों को संघीय सरकार द्वारा "अवैध" माना जाता था, जो आगे चलकर टाइग्रे अधिकारियों के साथ टकराव का कारण बना।

AIM-Sirius इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया गया (AIM–Sirius Innovation Programme 3.0 launched)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - अंतर्राष्ट्रीय संबंध और GS - III - नवाचार

समाचार में

- अटल इनोवेशन मिशन (**AIM**) और सिरियस, रूस ने **AIM – Sirius Innovation Program 3.0** लॉन्च किया।
- यह भारतीय और रूसी स्कूली बच्चों के लिए 14-दिवसीय आभासी कार्यक्रम है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- पहला भारत-रूस द्विपक्षीय युवा नवाचार पहल, एआईएम-सीरियस कार्यक्रम दोनों देशों के लिए तकनीकी समाधान (वेब- और मोबाइल-आधारित) विकसित करने का प्रयास करता है।
- दो सप्ताह के कार्यक्रम में, **48** छात्र और **16** शिक्षक और संरक्षक **8** आभासी उत्पाद और मोबाइल एप्लिकेशन बनाएंगे, जो कोविद -**19** महामारी के मद्देनजर वैश्विक चुनौतियों का सामना करेंगे।
- छात्र टीमों द्वारा विकसित नवाचार **21** वीं सदी की तकनीकों जैसे ऐप डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग आदि का लाभ उठाएंगे।

वियतनाम और बांग्लादेश से सबक(Lessons from Vietnam and Bangladesh)

संदर्भ: बांग्लादेश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा परिधान निर्यातक बन गया है, जबकि वियतनाम का निर्यात पिछले आठ वर्षों में लगभग **240%** बढ़ा है।

वियतनाम की सफलता की कहानी

- सस्ता कार्यबल
- मुख्य रूप से मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के माध्यम से खुली व्यापार नीति, जो यह सुनिश्चित करती है कि इसके महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत वियतनाम में बने उत्पादों पर आयात शुल्क नहीं लेते हैं।
- विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए घरेलू कानून संशोधित: विदेशी फर्म स्थानीय व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, ईयू फर्में दुकानें खोल सकती हैं, खुदरा व्यापार में प्रवेश कर सकती हैं, और सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के लिए बोली लगा सकती हैं। वे बिजली, रियल एस्टेट, अस्पताल, रक्षा और रेलवे परियोजनाओं में भाग ले सकते हैं।
- एफडीआई से जुड़ी निर्यात रणनीति: **2019-20** में, वियतनाम को **16** $ बिलियन से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ। परिणामस्वरूप, वियतनाम का निर्यात **2010** में **83.5** बिलियन डॉलर से बढ़कर **2019** में **279** बिलियन $ हो गया।

बांग्लादेश की सफलता की कहानी

- बांग्लादेश में, यूरोपीय संघ और अमेरिका बड़े पैमाने पर निर्यात करते हैं।
- यूरोपीय संघ कम से कम विकसित देशों (एलडीसी) से परिधान और अन्य उत्पादों के आयात की अनुमति देता है जैसे शुल्क मुक्त बांग्लादेशी उत्पाद।
- भारत, एक अच्छे पड़ोसी के रूप में, बांग्लादेश के सभी उत्पादों को शुल्क मुक्त (शराब और तंबाकू को छोड़कर) स्वीकार करता है।
- अफसोस की बात है कि बांग्लादेश को चार से सात वर्षों में ऐसे लाभ नहीं हो सकते हैं क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है और वह एलडीसी का दर्जा खो देता है। बांग्लादेश अपने निर्यात की टोकरी में विविधता लाने के लिए चालाकी से काम कर रहा है।

वियतनाम और बांग्लादेश मॉडल के कौन से तत्व भारत का अनुकरण कर सकते हैं?

- **बड़ी फर्मों का समर्थन:** बांग्लादेश से महत्वपूर्ण सीखने के लिए एक त्वरित कारोबार के लिए बड़ी कंपनियों का समर्थन करने की आवश्यकता है। ब्रांड निर्माण, गुणवत्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने, और विपणन में निवेश करने के लिए बड़ी फर्मों को तैनात किया जाता है। छोटी फर्में बड़ी कंपनियों के लिए आपूर्तिकर्ताओं के रूप में शुरू होती हैं और अंततः बढ़ती हैं।

- **व्यापार शुरू करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान दें:** वियतनाम ने निवेशकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू नियमों को बदल दिया है। वियतनाम का अधिकांश निर्यात पाँच क्षेत्रों में होता है जिसने व्यापार में वृद्धि को बढ़ाने में मदद की है। इसके विपरीत, भारत के निर्यात अधिक विविध हैं जो बढ़ने के लिए धीमी हैं लेकिन फिर भी दीर्घकालिक रूप से वैश्विक वृद्धि के लिए लचीलापन प्रदान करता हैं।

वियतनाम के विकास मॉडल में कमजोरियाँ

- जीडीपी अनुपात **(EGR)** का उच्च निर्यात- वियतनाम का **EGR 107%** है। निर्यात पर इस तरह की उच्च निर्भरता डॉलर लाती है, लेकिन यह देश को वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को कमजोर बनाता है।
- बड़ी अर्थव्यवस्थाओं / निर्यातक देशों का **EGR** बहुत कम संख्या में होती है। अमेरिका का **EGR 11.7%,** जापान का **18.5%,** भारत का **18.7%** है। यहां तक कि चीन के लिए, अपनी सभी व्यापार समस्याओं के साथ, **EGR 18.4%** है।
- जैविक आर्थिक विकास में कमी: वियतनाम में निर्यात का त्वरित निर्माण बड़े बहुराष्ट्रीय निवेश से हुआ। लेकिन इसके अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कहीं और उत्पादित वस्तुओं को अंतिम रूप से तैयार किया जाता हैं। ऐसे मामलों में, राष्ट्रीय निर्यात बड़े दिखते हैं, लेकिन शुद्ध डॉलर का लाभ कम होता है।

निष्कर्ष

- भारत, वियतनाम के विपरीत, एक विकसित घरेलू और पूंजी बाजार है। विनिर्माण और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए, भारत पूर्व-अनुमोदित कारखाने स्थानों के साथ क्षेत्रीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर सकता है।
- भले ही भारत एक खुली व्यापार नीति का पालन करता है, लेकिन इसमें घरेलू चैंपियन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक स्वस्थ मिश्रण होना चाहिए।
- जबकि निर्यात एक प्राथमिकता है, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की कीमत पर इसका पीछा नहीं किया जाना चाहिए।

आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौता हुआ (Peace Deal brokered Between Armenia And Azerbaijan)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध; स्वास्थ्य

समाचार में

- आर्मीनिया और अजरबैजान ने नगोर्नो-काराबाख के विवादित क्षेत्र में सैन्य संघर्ष समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
- रूस ने अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक नई शांति समझौते की मध्यस्थता की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- नए शांति समझौते के अनुसार, दोनों पक्ष अब उन क्षेत्रों में स्थिति बनाए रखेंगे, जो वर्तमान में उनके पास हैं।
- इसका अर्थ है अजरबैजान के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ, क्योंकि यह हाल के संघर्ष के दौरान अपने खोए हुए क्षेत्र के 15-20% से अधिक प्राप्त कर चुका है।
- आगे, इस समझौते के तहत, सभी सैन्य अभियान निलंबित हैं।
- रूसी शांति सैनिकों को नागोर्नो-काराबाख में संपर्क की रेखा और लाचिन गलियारे के साथ तैनात किया जाएगा जो इस क्षेत्र को आर्मेनिया से जोड़ता है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (CSTO)

- संघर्ष में रूस की भूमिका कुछ हद तक अपारदर्शी है क्योंकि यह दोनों देशों को हथियारों की आपूर्ति करता है और आर्मेनिया के साथ एक सामूहिक गठबंधन में है जिसे सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ) कहा जाता है।
- सीएसटीओ एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसे **15** मई **1992** को हस्ताक्षरित किया गया था।
- **1992** में, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल से संबंधित छह पोस्ट-सोवियत राज्यों ने सामूहिक सुरक्षा संधि (जिसे "ताशकंद संधि" या "ताशकंद संधि" भी कहा जाता है) पर हस्ताक्षर किए।
- सदस्य: आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान।
- मुख्यालय: मास्को, रूस।

जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पारस्परिक समझौते (RAA) पर हस्ताक्षर किए Reciprocal Access Agreement (RAA) signed between Japan and Australia

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- **जापान और ऑस्ट्रेलिया** ने **दक्षिण चीन सागर और प्रशांत द्वीप देशों** में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक "लैंडमार्क रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जापानी प्रधानमंत्री **योशीहिदे सुगा** और ऑस्ट्रेलियाई के प्रधानमंत्री **स्कॉट मॉरिसन** द्वारा **पारस्परिक संपर्क समझौते (Reciprocal Access Agreement)** नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पारस्परिक गठबंधन समझौते (**RAA**) क्वाड गठबंधन के विदेश मंत्रियों के मिलने के कुछ हफ्तों के बाद आता है**,** जिसमें टोक्यो में अमेरिका और भारत शामिल हैं।
- यह संधि जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को एक-दूसरे के देशों में जाने और प्रशिक्षण और संयुक्त संचालन करने की अनुमति देती है।
- ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री ने कहा कि संधि उनके सुरक्षा संबंधों को मजबूत करेगी और रक्षा बलों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करेगी।
- दोनों पक्ष जापानी सेना को जरूरत पड़ने पर ऑस्ट्रेलियाई सेना की सुरक्षा के लिए एक ढांचे की आवश्यकता पर भी सहमत हुए।

APEC आभासी बैठक आयोजित (APEC virtual meet held)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS **-** II **-** अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- हाल ही में, 21-सदस्यीय एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) मंच की एक आभासी बैठक हुई।
- इस बैठक की मेजबानी मलेशिया ने की थी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इस वर्ष एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विकास में 2.7% की गिरावट की उम्मीद है, APEC का ध्यान आर्थिक सुधार में तेजी लाने और एक किफायती टीका विकसित करने पर था।
- फोकस क्षेत्र: व्यापार और निवेश**,** डिजिटल अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी**,** संरचनात्मक सुधार**,** आर्थिक और तकनीकी सहयोग और विषयगत और संस्थागत मामले।

- APEC नेताओं ने बोगोर गोल्स को बदलने के लिए पुटराया विजन 2040, एक नई 20-वर्षीय विकास दृष्टि को अपनाया, जहां नेताओं ने 1994 में व्यापार और निवेश को मुक्त और खोलने के लिए सहमति व्यक्त की।
- उन्होंने ऐसे चुनौतीपूर्ण समय पर आर्थिक सुधार को चलाने के लिए स्वतंत्र, खुले, निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण, पारदर्शी और पूर्वानुमानित व्यापार और निवेश वातावरण के महत्व को भी पहचाना (कोविद -**19**)।
- उन्होंने एशिया-प्रशांत क्षेत्र (एफटीएएपी) के मुक्त व्यापार क्षेत्र और एपीईसी इंटरनेट और डिजिटल अर्थव्यवस्था रोडमैप (एआईडीईआर) पर भी चर्चा की।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC)

- **स्थापना:** 1989
- **सदस्य:** 21
- भारत इसका सदस्य नहीं है।
- सदस्य: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, चीनी ताइपे, थाईलैंड, वियतनाम और विलियम संयुक्त राज्य अमेरिका।
- इसके 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं लगभग 2.8 बिलियन लोगों का घर है और विश्व जीडीपी का लगभग 59% और 2015 में विश्व व्यापार का 49% का प्रतिनिधित्व किया।
- भारत ने **APEC** में सदस्यता का अनुरोध किया था, और संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी से प्रारंभिक समर्थन प्राप्त किया था।
- अधिकारियों ने भारत को शामिल होने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है क्योंकि भारत प्रशांत महासागर की सीमा साँझा नहीं करता है, जो सभी मौजूदा सदस्य करते हैं।
- भारत को पहली बार नवंबर **2011** में पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था।

चीन द्वारा भूटान में नये गांव पर दावा किया (New Village in Bhutan claimed by China)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- हाल ही में, चीनी मीडिया ने दावा किया कि भूटान के पास चीन द्वारा बनाया गया एक नया सीमावर्ती गांव चीनी क्षेत्र पर था।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इस गांव की जारी छवियां भूटान और चीन द्वारा विवादित क्षेत्र पर अपना स्थान दर्शाती हैं।
- दक्षिण पश्चिम चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के याडोंगकाउटी (एक प्रशासनिक क्षेत्र) में पैंगडा के गांव को नया बनाया गया है और अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सितंबर **2020** में शांगडुई गांव से **124** लोगों के साथ **27** घर स्वैच्छिक रूप से शांगडुई गांव से पंगु गांव में स्थानांतरित हो गए हैं।
- यह **2017** के बाद पहली बार है कि डोकलाम क्षेत्र के पास एक चीनी आवासीय क्षेत्र देखा गया है**,** जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
- भूटान ने आधिकारिक रूप से अपने क्षेत्र में किसी भी चीनी गांव की उपस्थिति से इनकार किया है।
- चीन के नक्शे के अनुसार**,** गांव चीन के क्षेत्र में है।
- चीन ने भारत को चीन-भूटान सीमा विवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया और यह भ्रम पैदा कर दिया कि चीन भूटानी क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है।

अवधि उत्पाद (नि: शुल्क प्रावधान) (स्कॉटलैंड) विधेयक / Period Products (Free Provision) (Scotland) Bill

भाग: GS प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- स्कॉटलैंड की सरकार ने देश में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त में सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। यह स्कॉटलैंड को ऐसा कदम उठाने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बनाता

है। 'Period Products (Free Provision) Scotland Bill' को विधायिका में सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ऐसा कदम उठाने वाला स्कॉटलैंड पहला देश है।
- बिल को "अवधि गरीबी" से निपटने के उद्देश्य से पारित किया गया था, जो तब होता है जब कुछ लोग जिन्हें अवधि उत्पादों की आवश्यकता होती है, उन्हें वहन करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
- **केंद्रीय उद्देश्य:** मासिक धर्म के बारे में जागरूकता फैलाना
- **उद्देश्य:** (1) लिंग संबंधी बाधाओं को दूर करना; (2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मासिक धर्म वालों को नि: शुल्क रूप से पीरियड उत्पादों की सुविधा उपलब्ध है।

क्या आप जानते हो?

'अवधि गरीबी' क्या है?

- कुछ परिस्थितियां महिलाओं और ट्रांस लोगों के लिए सेनेटरी उत्पादों तक पहुंच को मुश्किल बनाती हैं।
- इनमें बेघर स्थित, जबरदस्ती, नियंत्रण और हिंसक रिश्ते और स्वास्थ्य की स्थिति जैसे एंडोमेट्रियोसिस शामिल हैं।

भारत और विश्व

भारतीय नौसेना जहाज ऐरावत ने मिशन सागर - II के तहत पोर्ट सूडान में प्रवेश किया

भाग: GS प्रीलिम्स और जीएस- **II -** अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- 'मिशन सागर- **II**' के हिस्से के रूप में**,** भारतीय नौसेना जहाज ऐरावत ने हाल ही में पोर्ट सूडान में प्रवेश किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और COVID-19 महामारी को दूर करने के लिए अनुकूल विदेशी देशों को सहायता प्रदान कर रही है।
- आईएनएस ऐरावत उसी उद्देश्य के लिए सूडान के लोगों के लिए 100 टन खाद्य सहायता की खेप लेकर जा रहा है।
- मिशन सागर- II मई-जून 2020 में किए गए पहले मिशन सागर का अनुसरण कर रहा है, जिसमें भारत मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस तक पहुंचा और खाद्य सहायता और दवाइयां प्रदान की।
- मिशन सागर- II के भाग के रूप में, भारतीय नौसेना जहाज ऐरावत सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्य सहायता पहुंचाएगा।

भारत और इटली के बीच आभासी शिखर सम्मेलन हुआ (Virtual Summit between India and Italy held)

भाग: GS प्रीलिम्स और जीएस- **II -** अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- भारतीय प्रधान मंत्री और इतालवी प्रधान मंत्री के बीच एक आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था।

महत्वपूर्ण बिंदु

- हाल के दिनों में भारत-इटली संबंधों में तेजी से वृद्धि हुई है।
- क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, दोनों पक्ष विशेष रूप से जी-20 में बहुपक्षीय मंचों पर निकट समन्वय के लिए सहमत हुए।
- इटली दिसंबर 2021 में G-20 की अध्यक्षता करेगा और उसके बाद 2022 में इसका आयोजन भारत करेगा।
- एक साथ, भारत और इटली दिसंबर 2020 से जी 20 ट्रोइका का भाग लेंगे।
- भारत ने अनुसमर्थन प्रक्रिया पूरी होते ही ISA में शामिल होने के इटली के फैसले का स्वागत किया।
- शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, मत्स्य पालन, जहाज निर्माण, डिजाइन आदि में 15 समझौता ज्ञापनों / समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
- दोनों देशों को 2012 के सामान संबंधो को मजबूत करने के उत्सुक हैं, जो इतालवी नाविकों द्वारा मछली मारते हुए केरल के तट पर मछली पकड़ने की नाव के दो भारतीय चालक दल के सदस्यों की हत्या करने के बाद से ख़राब हो गए थे।

क्या आप जानते हो?

- इटली वर्तमान में यूरोपीय संघ में भारत का पांचवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- द्विपक्षीय व्यापार 2019 में 9.52 बिलियन यूरो का था।
- भारत इतालवी आयात के लिए **16** वें स्थान पर है।

बिडेन के तहत, अमेरिका-भारत के भविष्य के संबंध (Under Biden, the future of US-India ties)

संदर्भ: लंबे समय तक अमेरिकी चुनावों के परिणाम से आखिरकार जो बिडेन को राष्ट्रपति-चुनाव घोषित किया गया। 20 जनवरी 2021 को बिडेन-कमला हैरिस प्रशासन शपथ ग्रहण करेगा।
अमेरिका के लिए, भारत-अमेरिका संबंध एक अत्यंत परिणामी सिद्ध हो सकते है -

- **चीन फैक्टर:** चीन की जवाबी कार्रवाई के लिए अमेरिका की उम्मीदों के लिए भारत आवश्यक है। परिणामस्वरूप, सुरक्षा सहयोग किसी भी भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की आधारशिला बन गया है।
- **नई सहस्राब्दी नई दिशा:** जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने पहली बार भारत को "प्राकृतिक सहयोगी" के रूप में सह-चुनाव करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता शुरू की, एक प्रतिबद्धता जो 2008 में ऐतिहासिक नागरिक परमाणु समझौते के परिणामस्वरूप हुई।

ट्रम्प युग में भारत-अमेरिका संबंध कैसे आगे बढ़े हैं?

- **फास्ट डिप्लोमेसी:** डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के तहत पिछले चार वर्षों में, भारत-अमेरिका सुरक्षा सहयोग ब्रेकनेक गति से आगे बढ़ा।
- **प्रमुख रक्षा साझेदार की स्थिति:** 2016 में, अमेरिका ने भारत को एक मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में नामित किया, जिसके कारण अन्य चीजों के अलावा, इसने भारत को सैन्य और दोहरे उपयोग वाली अमेरिकी प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम किया।
- **मूलभूत रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए:** तीन वर्षों में, तीन रक्षा समझौते - **LEMOA, COMCASA, BECA -** पर हस्ताक्षर किए गए।
- **सामरिक संवाद के लिए संस्थागत संरचना: 2018** में, दोनों देशों ने **2 + 2** रणनीतिक वार्ता शुरू की, जो उच्चतम स्तर के संवादों में से एक है जिसे कभी संस्थागत रूप दिया गया था।
- **संयुक्त अभ्यास: 2019** में, अमेरिका और भारत ने टाइगर ट्राइंफ का आयोजन किया, उनके बीच पहली त्रिकोणीय सेवा (जमीन, नौसेना और वायु सेना) अभ्यास है।
- **QUAD: 2020** में, ऑस्ट्रेलिया भारत, जापान और अमेरिका के साथ मिलकर भारत के नेतृत्व वाले मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करने में शामिल हो गया, जिससे क्वाड को बड़ा प्रोत्साहन मिला।
- **चीनी आक्रामकता ने उत्प्रेरक के रूप में काम किया:** अमेरिका के विचार में, जबकि यह हमेशा सहयोग के इस स्तर में संलग्न होने के लिए तैयार था, यह चीन के साथ सीमा पर संघर्ष था जिसने भारत को अमेरिका के साथ गहराई से जुड़ने के लिए और अधिक तैयार किया।

अमेरिका और भारत दोनों ही गहरे संबंधों के संदर्भ में एक ही पृष्ठ पर होने के बावजूद, ऐसी बाधाएँ हैं जो इस प्रकार बनी हुई हैं:

- **भारतीय सैन्य प्रणाली रूस पर निर्भर करती है:** अमेरिका का मानना है कि भारत, जो अभी भी **60%** से **70%** रूस पर सैन्य पुनरुत्थान और हार्डवेयर के लिए निर्भर रहता है, उसे भविष्य में भारत को उस तरह के युद्ध के साथ चुनाव करना होगा, जिसे भारत संरेखित करना चाहता है। भारत अब एक ला कार्टे सैन्य मेनू (à la carte military menu;) का चयन कर सकता है; बल्कि उसे एक सिस्टम चुनना होगा।
- **रणनीतिक स्वायत्तता पर भारत का आग्रह:** विशेषज्ञों के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और वह रणनीतिक स्वायत्तता का प्राप्त करने की इच्छा रखता है। एक राष्ट्रवादी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी की शक्ति (पूर्ण बहुमत) का उपयोग अमेरिका द्वारा एक खोए हुए अवसर के रूप में किया जा सकता है।
- **घरेलू मुद्दे:** राष्ट्रपति बिडेन मानवाधिकारों के लिए अधिक प्रतिबद्ध होंगे, जो उदाहरण के लिए, कश्मीर के लिए भारत के साथ दरार उत्पन्न कर सकता है।

राष्ट्रपति बिडेन के तहत भारत-अमेरिका संबंध के लिए संभावित

- इन बाधाओं के बावजूद, बिडेन प्रशासन विशेष रूप से संबंध को नहीं बदलेगा और, कई मायनों में, यह और भी मजबूत हो सकता है।
- किसी भी अमेरिकी चिंताओं, जैसे कि कश्मीर, सार्वजनिक रूप से बजाय निजी तौर पर व्यक्त किए जाने की अधिक संभावना है।
- राष्ट्रपति ट्रम्प के तहत, निर्णय लेना अधिक तदर्थ और कई बार अराजक सिद्ध हुआ था। नौकरशाही के अपने संदेह के कारण ट्रम्प द्वारा अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णय संरचना का विघटन, इस अराजकता में शामिल हो गया।
- राष्ट्रपति बिडेन अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णय संरचना को बहाल करेंगे - जैसे नियमित अंतर-एजेंसी बैठकें, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठकें - और एक प्रक्रिया जिसके द्वारा नौकरशाही की सिफारिशें और निर्णय राष्ट्रपति के कार्यालय तक पहुँचेंगे।
- बिडेन को जलवायु वित्त पोषण की बात करने पर भी विचार करने की अधिक संभावना है, जो भारत को अपनी पेरिस जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए चाहिए।
- राष्ट्रपति बिडेन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नेतृत्व की भूमिका की अमेरिकी वापसी को उलट देंगे और अमेरिका के नेतृत्व में नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय आदेश को फिर से जीवित करने में मदद करेंगे। यह भारत के हित में है क्योंकि अमेरिका द्वारा छोड़े गए स्थान पर चीन का कब्जा होगा (जो भारत के हित में है)

निष्कर्ष

- हालांकि यह निर्विवाद है कि ट्रम्प और मोदी के मध्य सम्बन्ध अच्छे थे, बिडेन और मोदी दोनों के मध्य रिश्ते व्यावहारिक होने की संभावना हैं जो वास्तव में भू-राजनीतिक मजबूरियों से सम्बंधित है।

भारतीय राजनयिक प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति (ACABQ) के लिए चुने गए

भाग: GS प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध; महत्वपूर्ण संगठन

समाचार में

- हाल ही में, भारतीय राजनयिक विदिशामित्रा को प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न (**ACABQ**) पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के लिए चुना गया था।
- **ACABQ** संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र महासभा सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति करती है।
- सदस्यों का चयन व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाता है।
- महासभा की पाँचवीं समिति, जो प्रशासनिक और बजटीय मुद्दों से निपटती है, ने इसकी सिफारिश की थी
- वह 1 जनवरी, 2021 से तीन साल के कार्यकाल के लिए चुनी गई हैं।
- भारत को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जनवरी 2021 से शुरू होने वाले दो साल के कार्यकाल के लिए एक गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भी चुना गया था।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

प्रशासनिक और बजट संबंधी प्रश्नों पर सलाहकार समिति (ACABQ)

- **ACABQ** में उनकी व्यक्तिगत क्षमता में विधानसभा द्वारा नियुक्त 16 सदस्य होते हैं
- ACABQ यह सुनिश्चित करता है कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में निधि योगदान को अच्छे प्रभाव में रखा जाए और यह अनिवार्य रूप से वित्त पोषित हो।
- कार्य: (1) महासचिव द्वारा महासभा को प्रस्तुत किए गए बजट की जांच और रिपोर्ट करना; (2) किसी भी प्रशासनिक और बजटीय मामलों से संबंधित महासभा को सलाह देना।

17 वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन हुआ

भाग: GS प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- हाल ही में, भारत ने 17 वें आसियान-भारत आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- आसियान का वर्तमान अध्यक्ष वियतनाम है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- शिखर सम्मेलन ने कोविद -19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक उथल-पुथल से उबरने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया और आगे व्यापक-आधार रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीके।
- भारत ने आसियान को भारत की अधिनियम पूर्व नीति के केंद्र में रखा।
- यह माना गया कि इस क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और उत्तरदायी आसियान आवश्यक है।
- भारत ने भारत-प्रशांत महासागरीय पहल (**IPOI**) और इंडो-पैसिफिक पर आसियान आउटलुक के बीच अभिसरण को मजबूत करने के महत्व पर प्रकाश डाला**,** ताकि एक स्वतंत्र**,** खुला**,** समावेशी और नियम-आधारित क्षेत्र सुनिश्चित किया जा सके।
- इसमें आसियान द्वारा सुरक्षा और विकास के लिए सभी क्षेत्र (**SAGAR)** विजन में सहयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।
- भारत **2019** में **15**-राष्ट्र **RCEP** समझौते से बाहर निकलने के बावजूद व्यापार बढ़ाने के तरीकों का पता लगाएगा।
- भारत ने दक्षिण चीन सागर में शांति बनाए रखने और बढ़ावा देने के महत्व की पुष्टि की।
- इसने स्वस्थ और समग्र जीवन के स्रोत के रूप में पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में सहयोग और नियमित आदान-प्रदान के महत्व को भी रेखांकित किया।
- भारत ने माल समझौते (आसिता) में आसियान-भारत व्यापार की शुरुआती समीक्षा का आह्वान किया**,** जो लंबे समय से लंबित है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान)
- यह एक क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है।
- इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
- संस्थापक सदस्य: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड।
- वर्तमान दस सदस्य: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।
- सदस्य राज्यों के अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर, प्रतिवर्ष अध्यक्षता करता है।
- यह व्यापार में 86.9 बिलियन अमरीकी डालर के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

मालदीव के साथ 'रणनीतिक साझेदारी'

संदर्भ: मालदीव के विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है

मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलीह के तहत, द्विपक्षीय सहयोग, विशेष रूप से आर्थिक मोर्चे पर, एक मॉडल बन गया है जिसे नई दिल्ली सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति को सफल बनाने के लिए अपना सकती है।

मालदीव में भारत के कई रणनीतिक हित हैं:

- **भौगोलिक निकटता:** मालदीव भारत के पश्चिमी तट के बहुत करीब है- यह मिनिकॉय से मुश्किल से **70** समुद्री मील दूर है और भारत के पश्चिम तट से **300** समुद्री मील दूर है। इसलिए किसी भी समुद्री क्षेत्रीय विवादों से बचने के लिए एक दोस्ताना संबंध की आवश्यकता है।
- मालदीव से मिनिकॉय द्वीप का एक बार का दावा दोनों देशों के बीच **1976** की समुद्री सीमा संधि द्वारा हल किया गया था**,** जिसके तहत मालदीव ने मिनिकोय को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी है।
- **संचार के वाणिज्यिक सागर लाइनों के करीब:** हिंद महासागर के माध्यम से चलने वाले वाणिज्यिक समुद्री लेन के केंद्र में इसकी स्थिति (विशेष रूप से **8 ° N** और **1 and ° N** चैनल)। इसलिए**,** क्षेत्र में समुद्री डकैती को रोकने और व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मालदीव सरकार के घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता है
- **तीसरे देश का हस्तक्षेप:** मालदीव के क्षेत्र में तीसरे राष्ट्र की नौसैनिक उपस्थिति की अनुमति देने की क्षमता भारत के लिए महत्वपूर्ण सामरिक महत्व के साथ इसे लागू करती है**,** जहां भारत खुद को क्षेत्र में एक अनौपचारिक सुरक्षा गारंटर मानता है।
- **कट्टरता और आतंकवाद का खतरा:** पिछले दशक के दौरान कट्टरता का तेजी से विकास हुआ और यह अक्सर कहा गया कि द्वीपसमूह का प्रति व्यक्ति के हिसाब से सीरिया में सबसे ज्यादा संख्या में विदेशी लड़ाकों में से है। अतःभारत मालदीव में उत्पन्न होने वाले इस्लामिक कट्टरता को रोक सकता है
- **भारतीय प्रवासी:** मालदीव में भारतीय लगभग **25,000 (**मालदीव की जनसंख्या का **5.6%** के लिए लेखांकन) की अनुमानित ताकत वाला दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। मालदीव में रह रहे भारतीयों की रक्षा और सुरक्षा के लिए मालदीव के साथ निकट सहयोग भी महत्वपूर्ण है
- **मल्टी-लेटरल फोरम:** मालदीव भी सार्क का सदस्य है। क्षेत्र में अपना नेतृत्व बनाए रखने के लिए भारत के लिए मालदीव का एक बोर्ड पर होना महत्वपूर्ण है।

दशकों से, भारत ने मालदीव को आपातकालीन सहायता दी है

- **ऑपरेशन कैक्टस: 1988** में**,** जब हथियारबंद भाड़े के सैनिकों ने राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम के खिलाफ तख्तापलट का प्रयास किया**,** तो भारत ने पैराट्रूपर्स और नेवी जहाजों को भेजा और ऑपरेशन कैक्टस के तहत वैध नेतृत्व बहाल किया।

- 2004 की सुनामी एक और अवसर था जहां भारत ने क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए खाद्य और आपूर्ति के मामले में अपनी सहायता भेजी
- 2014 में माले में पीने के पानी की कमी को मानवीय आपदा बनने से रोक दिया गया था जब भारत ने भाग लिया पीने के लिए पीने का पानी पाँच सी 17 और भारतीय वायु सेना के IL17 परिवहन विमान के माध्यम से मालदीव भेजा गया था।
- **COVID-19 सहायता:** निरंतर COVID-19 व्यवधान के चरम पर, भारत ने त्वरित समय में **250** मिलियन **$** की सहायता प्रदान की। नई दिल्ली ने मालदीव में चिकित्सा आपूर्ति में भी तेजी लाई, एक
- नए कार्गो फेरी की शुरुआत की और एक हवाई यात्रा बुलबुला भी खोला

द्विपक्षीय संबंध में राजनीतिक चुनौतियां

- जल संकट होने पर अब्दुल्ला यामीन (वर्तमान में विपक्षी पार्टी के नेता और कारावास के लिए जेल गए) सत्ता में थे। संबंधों में शुरुआती तनाव के बावजूद, भारत ने मानवीय आधार पर मदद की।
- विरोधी खेमे द्वारा भारत विरोधी प्रदर्शन: अब, यामीन शिविर ने नई दिल्ली के भौतिक, सामाजिक और सामुदायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर विकासात्मक धन के खिलाफ इंडिया आउट अभियान शुरू किया है
- सत्तारूढ़ पार्टी में आंतरिक रूंबिंग: भारत को विरोध प्रदर्शनों के साथ-साथ श्री सल्लिह की सत्तारूढ़ मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के भीतर सामयिक रंबल के बारे में चिंतित होना चाहिए। सत्तारूढ़ दल में राजनीतिक अस्थिरता भारत के साथ देश के संबंधों को प्रभावित कर सकती है।

निष्कर्ष

- चुनौतियों के बावजूद, भारत सरकार की इंडिया फर्स्ट नीति के 'रणनीतिक साझेदारी' में राहत ले सकता है।
- साझा समुद्रों में भारत की बढ़ती भूस्थैतिक चिंताओं को देखते हुए, भारत को अपने समुद्री पड़ोसी के साथ बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने में सक्रिय होना चाहिए।

अरुणाचल बॉर्डर के पास चीन का रेलवे निर्माण

भाग: GS प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- चीन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रेलवे लाइन पर काम शुरू कर दिया है।
- यह सिचुआन प्रांत को तिब्बत में न्यिंगची से जोड़ेगा, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) को मुख्य भूमि चीन के साथ जोड़ने वाला दूसरा ऐसा मार्ग होगा।
- पहले किंघई-तिब्बत रेलवे लाइन ने ल्हासा को हिंटरलैंड से जोड़ा।

- रेलवे लाइन काफी हद तक सीमा क्षेत्र में चीन के सैन्य कर्मियों और सामग्री परिवहन और रसद आपूर्ति की दक्षता और सुविधा में सुधार करेगी। इस प्रकार, चीन एक लाभप्रद स्थिति में हो सकता है।
- परियोजना लाइन के साथ नाजुक पारिस्थितिक वातावरण, भारत के लिए पारिस्थितिक चिंताओं को बढ़ा सकता हैं।

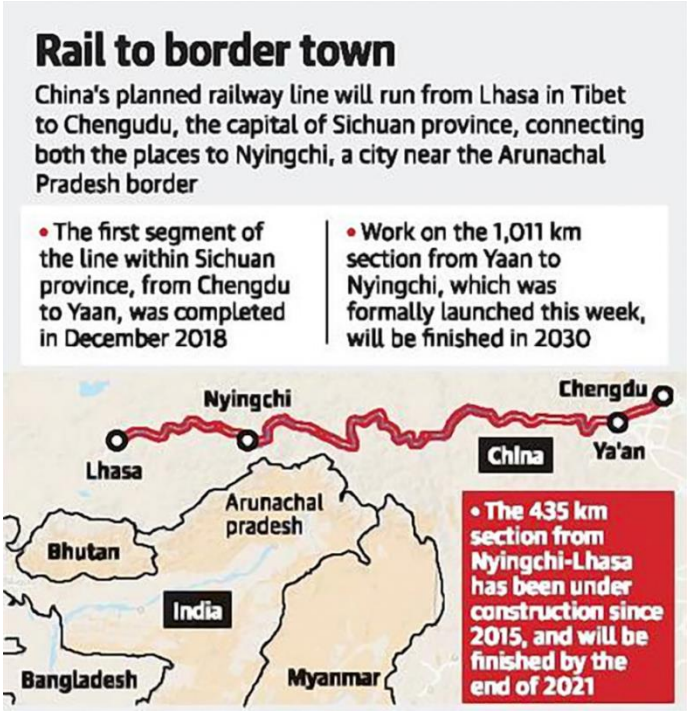

भारत और RCEP

संदर्भ: चीन सहित एशिया-प्रशांत के **15** देशों ने **15** नवंबर **2020** को वियतनाम द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) पर हस्ताक्षर किए। इन देशों के बीच क्षेत्रीय वृहद आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) करार हुआ है। इस समझौते में भारत शामिल नहीं है। यहां तक कि जब भारत ने पिछले साल चर्चाओं से बाहर रहने के बाद बाहर रहने का विकल्प चुना था, नए ट्रेडिंग ब्लॉक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वार्ता की मेज पर लौटने के लिए भारत के लिए दरवाजा खुला रहेगा।

RCEP क्या है?

- इस समझौते में आसियान के 10 देशों (इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलयेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस) के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। अमेरिका भी इस समझौते में शामिल नहीं है।
- **उद्देश्य:** सौदे का उद्देश्य सभी 16 देशों में फैले "एकीकृत बाजार" बनाना है। इससे इन देशों में से प्रत्येक के उत्पादों और सेवाओं के लिए इस क्षेत्र में उपलब्ध होना आसान हो जाएगा।

- **मेगा व्यापार सौदा:** इसे "सबसे बड़ा" क्षेत्रीय व्यापार समझौते के रूप में वर्णित किया गया था क्योंकि दुनिया की आबादी के लगभग आधे हिस्से में दुनिया के निर्यात में योगदान देने वाले देशों में वैश्विक जीडीपी का लगभग 30% भाग है।

- इस सौदे को समाप्त करने के लिए वार्ता 2013 से जारी थी, और भारत को समझौते से बाहर रहने के लिए नवंबर 2019 में अपने निर्णय तक हस्ताक्षरकर्ता होने की उम्मीद थी।

INDIA'S TRADE BALANCE WITH RCEP MEMBERS

RCEP Member	2018-19	2019-20
ASEAN	-21.85	-23.82
China	-53.58	-48.65
South Korea	-12.05	-10.81
Japan	-7.91	-7.91
New Zealand	-0.25	-0.14
Australia	-9.61	-6.93

All figures in $ billion

Source: Ministry of Commerce and Industry

भारत क्यों बाहर चला गया?

- **व्यापार का प्रतिकूल संतुलन:** भारत के 15 RCEP देशों में से 11 के साथ व्यापार घाटे हैं, और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत निर्यात बढ़ाने के लिए कई RCEP सदस्यों के साथ अपने मौजूदा द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाने में असमर्थ रहा है।
- **चीनी सामानों के डंपिंग का डर:** भारत ने चीन को छोड़कर RCEP के सभी देशों के साथ FTA पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत के लिए प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि RCEP पर हस्ताक्षर करने के बाद चीन के सस्ते उत्पाद की भारतीय बाजार में बाढ़ आ जायेगी।
- **ऑटो-ट्रिगर तंत्र की गैर-स्वीकृति:** आयात में आसन्न वृद्धि से निपटने के लिए, भारत एक ऑटो-ट्रिगर तंत्र की मांग कर रहा था जिसने भारत को ऐसे उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने की अनुमति दी होगी जहां आयात एक निश्चित सीमा को पार करते हैं। हालांकि, आरसीईपी में अन्य देश इस प्रस्ताव के खिलाफ थे।
- **उत्पत्ति के नियमों पर सहमति का अभाव:** उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड हैं। भारत मूल के नियमों के "संभावित परिधि" के बारे में चिंतित था। उत्पादों के मार्ग को रोकने के लिए इस सौदे में पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं थे।

- **घरेलू उद्योगों की रक्षा:** बातचीत के दौरान, डेयरी उद्योग ने सुरक्षा की मांग की क्योंकि इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने पर उद्योग को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इसी तरह, इस्पात और कपड़ा क्षेत्रों ने भी सुरक्षा की मांग की है।
- **एमएफएन स्थिति:** भारत आरसीईपी को निवेश के अध्याय से सबसे पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) के दायित्वों को बाहर करना चाहता था, विशेषकर उन देशों को जिनके साथ सीमा विवाद हैं, इसका लाभ अपने रणनीतिक सहयोगियों को दे रहा था।
- **बाजार पहुंच का मुद्दा:** आरसीईपी में चीन जैसे देशों में बाजार पहुंच के मुद्दों पर स्पष्ट आश्वासन और भारतीय कंपनियों पर गैर-टैरिफ बाधाओं का भी अभाव था।
- **उपरोक्त मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्धता की कमी:** भारत ने "मौलिक मुद्दों" और वार्ता के दौरान लगातार "चिंताओं" को उठाया था और इस स्टैंड को लेने के लिए प्रेरित किया गया था क्योंकि वे समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तय समय सीमा तक हल नहीं किए गए थे।
- **बुरे समझौते से बेहतर कोई समझौता नहीं करना है:** भारत का रुख एक नई व्यवस्था में प्रवेश करने के लाभों और लागतों की "स्पष्ट-दृष्टि गणना" पर आधारित था, और यह कि बुरे समझौते से बेहतर कोई समझौता नहीं करना है।

भारत के निर्णय के लिए चीन कितना प्रभावित होगा ?

- आर्थिक कारणों (डंपिंग का डर) के अलावा, चीन के साथ बढ़ते तनाव सौदे पर भारत की कठोर स्थिति का एक प्रमुख कारण है।
- इस सौदे में चीन की भागीदारी पहले से ही भारत के लिए विभिन्न आर्थिक खतरों के कारण मुश्किल साबित हो रही थी, गालवान घाटी में दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आ गई है।
- भारत ने चीन के साथ अपने संपर्क को कम करने के लिए जो विभिन्न उपाय किए हैं, संभवतः आरसीईपी पर हस्ताक्षर नहीं करना उनमें से एक है।

चीन के लिए RCEP क्यों महत्वपूर्ण है?

- चीन कोविद -19 अवरोधों को दूर करने और आपूर्ति श्रृंखला तंत्र को फिर से जीवित करने का प्रयास कर रहा है और संभवतः अमेरिकी राष्ट्रपति-चुनाव जो बिडेन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है।
- इंडो-पैसिफिक अब तक कमजोर अर्थव्यवस्था के साथ अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के दोहरे मार्ग पर कार्यरत था।
- चीन आर्थिक आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है जबकि अमेरिका सुरक्षा पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- भारत के लिए, RCEP में शायद ही कोई फर्क पड़ता है क्योंकि इसमें पहले से ही ASEAN के साथ FTAs और जापान और दक्षिण कोरिया के साथ CEPA (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते) हैं।

भारत ने क्या फैसला लिया?

- **अप्रत्यक्ष रूप से चीन को लाभ:** RCEP चीन समर्थित व्यापार सौदा है, भारत के बिना इस पर हस्ताक्षर करना चीन की आर्थिक शक्ति को और मजबूत करेगा। यह भारत के पड़ोस को प्रभावित करेगा क्योंकि चीन पहले से ही अपनी आर्थिक मदद के माध्यम से इस क्षेत्र को प्रभावित करने की कोशिश करता है।
- **भारत की अधिनियम पूर्व नीति पर प्रभाव:** ऐसी चिंताएं हैं कि भारत के फैसले से आरसीईपी सदस्य देशों के साथ उसके द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर असर पड़ेगा, क्योंकि वे ब्लॉक के भीतर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
- **बड़े बाजार पर हारना:** आरसीईपी द्वारा प्रस्तुत बड़े बाजार को टैप करने के लिए यह कदम भारत को कम गुंजाइश के साथ छोड़ सकता है - सौदे का आकार विशाल है, क्योंकि दुनिया की आबादी के 2 बिलियन से अधिक देशों में खाते शामिल हैं।
- **अन्य पहलों पर प्रभाव:** ऐसी भी चिंताएँ हैं कि भारत का निर्णय भारत-प्रशांत में ऑस्ट्रेलिया-भारत-जापान नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। यह संभावित रूप से तीनों के बीच एक आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल को बढ़ावा देने के लिए अनौपचारिक वार्ता पर काम करता है।

अब भारत के पास क्या विकल्प हैं?

- **भविष्य में शामिल हो सकते हैं:** जापान ने आरसीईपी समझौते को "भारत द्वारा उपयोग के लिए खुला" रखने के लिए कड़ी मेहनत की और यह भी कहा कि भारत आरसीईपी की बैठकों में एक "पर्यवेक्षक" के रूप में भाग ले सकता है।
- **आरसीईपी बैठकों में पर्यवेक्षक:** आरसीईपी हस्ताक्षरकर्ता राज्यों ने कहा कि वे भारत के साथ बातचीत शुरू करने की योजना बन रहे हैं, क्योंकि यह "लिखित रूप में" समझौते में शामिल होने के अपने इरादे का अनुरोध प्रस्तुत करता है, और यह अपने अभिगमन से पहले एक पर्यवेक्षक के रूप में बैठकों में भाग ले सकता है।
- **RCEP इंडो-पैसिफिक पर अपनी दृष्टि से जुड़ा नहीं है:** भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति से पीछे हटने वाला नहीं था, न ही आरसीईपी का निर्णय इंडो-पैसिफिक के लिए उसके दृष्टिकोण से जुड़ा था
- **अन्य विकल्पों की खोज:** इस बात पर भी विचार चल रहा है कि यह अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर जोर देने के लिए भारत के हित में काम करेगा।

निष्कर्ष

- भारत ने 2017 में वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव से बाहर रहना चुना, तो बहुत लोगों की राय थी कि भारत खुद को अलग-थलग कर सकता है। तीन साल बाद, भारत की स्थिति को समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों द्वारा मान्यता दी गई है और कई लोगों ने कहा है कि भारत का निर्णय सही था।

- इसी तरह, **RCEP** पर भारत का निर्णय जो सिद्धांतों पर आधारित था, अन्य समान विचारधारा वाले देशों द्वारा मान्यता प्राप्त होगा।
- सेक्टरों के बाहर बैठकर और टैरिफ दीवारों का निर्माण करने के बजाय, हमें उद्योग को प्रतिस्पर्धी होने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, और आरसीईपी में प्रवेश के जल्द से जल्द अवसर प्राप्त करना चाहिए।

ब्रिक्स ने नई आतंकवाद विरोधी रणनीति अपनायी है

भाग: GS प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- पांच देशों के समूह ब्रिक्स ने आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आतंकवाद-रोधी एक नई रणनीति अपनाई है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- **उद्देश्य:** (1) ब्रिक्स देशों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को पूरक और मजबूत करना; **(2)** आतंकवाद के खतरे को रोकने और उससे निपटने के वैश्विक प्रयासों में एक सार्थक योगदान देना।
- ब्रिक्स देशों ने इस बात की पुष्टि की कि अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है और आतंकवाद का कोई भी कार्य अपराध है और इसका कोई औचित्य नहीं है।
- उन्होंने यह भी माना कि आतंकवाद को रोकने और आतंकवादियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

क्या आप जानते है?

- ब्रिक्स पांच प्रमुख उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संघ का संक्षिप्त नाम है।

प्रधानमंत्री-एफएमई योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण घटक का उद्घाटन

भाग: GS प्रीलिम्स और जीएस- II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उपक्रम योजना औपचारिकरण (पीएम-एफएमई योजना) योजना के क्षमता निर्माण घटक का उद्घाटन किया।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

प्रधानमंत्री-एफएमई योजना

- इसे आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया था।
- यह केन्द्र प्रायोजित योजना है।
- **उद्देश्य:** (1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना**;** (2) क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देना**;** (3) किसान उत्पादक संगठनों**,** स्वयं सहायता समूहों और उत्पादकों सहकारी समितियों को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए सहायता प्रदान करना।

- दृष्टि: रुपये के परिव्यय के साथ मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सीधे सहायता के लिए 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।

भारत और भूटान वस्तुतः भूटान में रुपे कार्ड चरण -2 का शुभारंभ करेंगे

भाग: GS प्रीलिम्स और GS-II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- भारत के प्रधान मंत्री और भूटान वस्तुतः नवंबर 2020 (20 नवंबर) को भूटान में RuPay कार्ड चरण -2 का शुभारंभ करेंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य

- दोनों प्रधानमंत्रियों ने अगस्त **2019** में भारतीय पीएम की भूटान यात्रा के दौरान संयुक्त रूप से परियोजना का चरण **-1** शुरू किया था।
- भूटान में **RuPay** कार्ड के चरण **-1** के कार्यान्वयन ने भूटान में भारतीय आगंतुकों को भूटान में एटीएम और बिक्री टर्मिनलों के बिंदुओं तक पहुंचने में सक्षम बनाया है।

- चरण -**2** अब भूटानी कार्डधारकों को भारत में **RuPay** नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देगा।

भारत-लक्समबर्ग शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ

भाग: GS प्रीलिम्स और जीएस- **II -** अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- हाल ही में पहली बार भारत-लक्ज़मबर्ग वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ।

महत्वपूर्ण बिंदु

- लक्ज़मबर्ग यूरोपियन यूनियन का संस्थापक सदस्य है।
- इस संदर्भ में, दोनों देशों ने भारत-यूरोपीय संघ के व्यापार समझौतों और निवेश समझौतों पर आगे आंदोलन सहित भारत-यूरोपीय संघ संबंधों को और मजबूत करने पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
- लक्ज़मबर्ग के प्रधानमंत्री ने लक्ज़मबर्ग के इरादे को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए कहा।
- भारतीय पीएम ने लक्समबर्ग को डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया है ।
- नेताओं ने आर्थिक और व्यापार संबंधों की समीक्षा के लिए भारत और बेल्जियम-लक्ज़मबर्ग आर्थिक संघ के बीच 17 वें संयुक्त आर्थिक आयोग पर विचार कर रहे है।
- शिखर सम्मेलन के साथ तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते थे: (1) इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (इंडिया आईएनएक्स) और लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौता ज्ञापन; (2) भारतीय स्टेट बैंक और लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौता ज्ञापन; (3) इन्वेस्ट इंडिया और लक्सिनोवेशन के बीच एमओयू

15 वां G-20 शिखर सम्मेलन आयोजित

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- हाल ही में आयोजित 15 वें **G-20** शिखर सम्मेलन में**,** भारतीय प्रधान मंत्री ने **COVID-19** महामारी को मानवता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यह दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।
- **आयोजित:** सऊदी अरब द्वारा एक आभासी प्रारूप में।

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारतीय पीएम ने पोस्ट-कोरोना विश्व के लिए एक नए ग्लोबल इंडेक्स का आह्वान किया जिसमें चार प्रमुख तत्व शामिल हैं।
  - एक विशाल टैलेंट पूल का निर्माण
  - यह सुनिश्चित करना कि प्रौद्योगिकी समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे
  - शासन की प्रणालियों में पारदर्शिता
  - ट्रस्टीशिप की भावना के साथ धरती माता के साथ व्यवहार करना।
- यह देखते हुए कि **COVID** के बाद से घर से ही काम को निपटाना व्यवहार में आ गया है, इसलिए जी-20 देशों को एक वर्चुअल सचिवालय का गठन करना चाहिए, जिसमें दस्तावेजों का संग्रहण हो सकें।
- 15वां जी-20 शिखर सम्मेलन 22 नवंबर 2020 तक जारी रहेगा और समापन दिवस पर घोषणापत्र जारी किया जाएगा और सऊदी अरब द्वारा समूह की अध्यक्षता इटली को सौंपी जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

G20

- यह 19 देशों और यूरोपीय संघ (ईयू) की सरकारों और केंद्रीय बैंक का एक अंतरराष्ट्रीय मंच है।
- इसकी 1999 में स्थापना हुई
- **उद्देश्य:** अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के संवर्धन से संबंधित नीति पर चर्चा करना। G20 ने 2008 से अपने एजेंडे का विस्तार किया है।
- **20 सदस्य:** भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ

जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की बहु-पक्षीय तकनीकी समिति ने पेयजल और स्वच्छता में पाँच तकनीकों की सिफारिश की

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप और GS - III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में

- जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की बहु-पक्षीय तकनीकी समिति ने राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर समस्याओं के समाधान करने की सुविधा के लिए पेयजल और स्वच्छता में पाँच तकनीकों की सिफारिश की है।
- जल शक्ति मंत्रालय का 2024 तक हर गांव में प्रत्येक घर में स्वच्छ पानी के लिए घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के जल जीवन मिशन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसके के लिए मंत्रालय नवीन तकनीकी संसाधनों को महत्व देता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- जिन पाँच तकनीकों की सिफारिश की गई है उनमें से पहली है - ग्राउंडफॉस एक्यूप्योर यानि यह सौर ऊर्जा से चलने वाला जल उपचार संयंत्र है जो पानी को अत्यधिक फिल्टर कर सकता है।
- दूसरा है - जनाज़ल वॉटर ऑन व्हील। यह एक इलेक्ट्रिक वाहन जो जीपीएस लोकेशन पर आधारित होता है ताकि इससे घरों तक सुरक्षित पानी पहुंचाया जा सके।
- एक अन्य तकनीक प्रेस्टो ऑनलाइन क्लोरीनेटर है। यह एक ऐसा ऑनलाइन क्लोरीनेटर है जो बैक्टीरिया के प्रदूषण को हटाने के लिए पानी से कीटाणुशोधन का काम करता है।
- जोहकासो तकनीक की सिफारिश के अनुरूप यह रसोई और स्नानघर के लिए पानी को शुद्ध करने की जल उपचार प्रणाली है इसे भूमिगत स्थापित किया जा सकता है।
- अंतिम नवीन प्रौद्योगिकी एफ बी टी ई सी (**FBTec®**)के उपयोग से विकेंद्रीकृत सीवेज उपचार प्रणाली को इकट्ठा किया जा सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

जलजीवन मिशन

- यह 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है।
- यह स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन पर केंद्रित है।
- वर्षा जल संग्रहण, भूजल पुनर्भरण और पुन: उपयोग के लिए घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण, अन्य सरकारी कार्यक्रमों / योजनाओं के साथ अभिसरण में किया जाएगा।
- यह पानी के लिए एक सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल हैं।
- वित्तीय प्रारूप: केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10, अन्य राज्यों के लिए 50:50 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% है।

भारत और कजाकिस्तान के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 7 वां दौर आयोजित हुआ

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- भारत और कजाकिस्तान के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का **7** वां दौर हाल ही में आयोजित किया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य

- परामर्श के दौरान, दोनों पक्षों ने अपने सामरिक भागीदारी के ढांचे के भीतर द्विपक्षीय सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा की।
- परामर्श ने राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक, ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, कांसुलर और सांस्कृतिक मामलों को कवर किया।
- "कजाकिस्तान में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता" पर एएमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

भारतीय सेना ने माइक्रोवेव हथियारों के इस्तेमाल से सम्बंधित रिपोर्ट को खारिज कर दिया है

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- भारतीय सेना ने एक रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों पर माइक्रोवेव हथियारों का इस्तेमाल किया ।

महत्वपूर्ण बिंदु

- माइक्रोवेव हथियार को 'डायरेक्ट एनर्जी वेपंस' कहा जाता है अर्थात इन्हें एक प्रकार का प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार माना जाता है।
- ऐसे हथियारों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये कम घातक होते हैं, जिससे कोई गंभीर चोट लगने या मौत का खतरा नहीं होता।
- वे एक लक्ष्य पर ध्वनि, लेजर या माइक्रोवेव के रूप में अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा का लक्ष्य रखते हैं।
- वे एक मानव लक्ष्य की त्वचा में उपस्थित पानी को गर्म करने के लिए उच्च-आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय विकिरण के बीम का उपयोग करते हैं, जिससे दर्द और असुविधा होती है।
- माना जाता है कि कुछ देशों ने मानव और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रणालियों को लक्षित करने के लिए इन हथियारों को विकसित किया है।
- इस बात पर चिंता जताई गई है कि क्या वे आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या लंबे समय में एक कार्सिनोजेनिक प्रभाव डाल सकते हैं।

क्या आप जानते है?

- चीन ने पहली बार 2014 में एक एयर शो में पॉली डब्ल्यूबी -1 नामक अपने "माइक्रोवेव हथियार" को प्रदर्शित किया था।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक प्रोटोटाइप माइक्रोवेव शैली का हथियार भी विकसित किया है, जिसे वह "एक्टिव डेनियल सिस्टम" कहता है।
- अमेरिका ने स्पष्ट रूप से अफगानिस्तान में इस तरह के एक हथियार को तैनात किया, लेकिन मानव लक्ष्यों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किए बिना इसे वापस ले लिया।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- माइक्रोवेव ओवन में, एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब जिसे मैग्नेट्रॉन कहा जाता है, यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों (माइक्रोवेव) का उत्पादन करता है जो उपकरण के धातु के इंटीरियर के चारों फैलते हैं, और भोजन द्वारा अवशोषित होते हैं।
- माइक्रोवेव भोजन में पानी के अणुओं को उत्तेजित करते हैं, और उनका कंपन गर्मी पैदा करता है जो
- अक्सर सूखे खाद्य पदार्थों की तुलना में भोजन को पकाता है।
- उच्च पानी की मात्रा वाले खाद्य पदार्थ एक माइक्रोवेव में तेजी से पकते हैं।

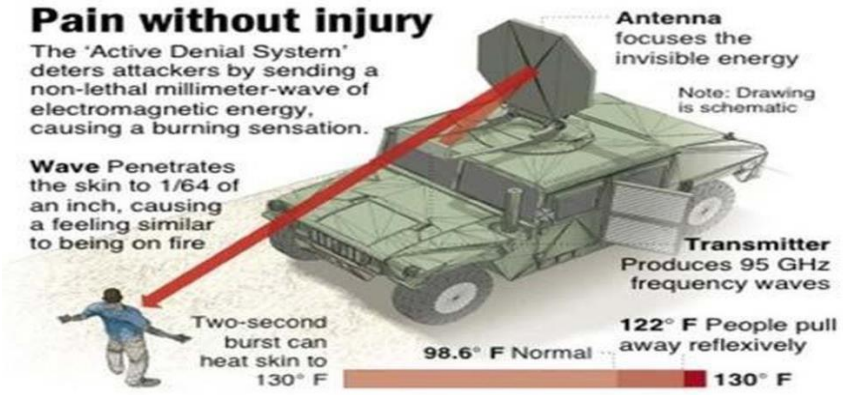

भारत ने अफगानिस्तान के लिए 150 परियोजनाओं की घोषणा की

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- हाल ही में, अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में, भारत ने 80 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की 150 परियोजनाओं की घोषणा की है।
- सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और यूरोपीय संघ (ईयू) के अधिकारियों और अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- साथ ही, यूएसए ने जनवरी 2021 तक अफगानिस्तान में अपनी सैन्य उपस्थिति को लगभग 2,500 तक कम करने का निर्णय लिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत उच्च-प्रभाव वाले सामुदायिक विकास परियोजनाओं के चरण- IV का शुभारंभ करेगा, जिसमें 80 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की लगभग 150 परियोजनाएँ शामिल हैं।
- इसने शहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो काबुल शहर के 2 मिलियन निवासियों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करेगा।
- यह 2009 की 202 किलोमीटर पुल-ए-खुमरी ट्रांसमिशन लाइन पर बनाता है, जिसके माध्यम से भारत शहर को शक्ति प्रदान करता है।

SDGs निवेशक मानचित्र भारत के लिए लॉन्च किया गया

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और इन्वेस्ट इंडिया ने भारत के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) निवेशक मानचित्र का शुभारंभ किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इसने छह महत्वपूर्ण एसडीजी सक्षम क्षेत्रों में 18 निवेश अवसर क्षेत्र (IOAs) निर्धारित किए, जो देश को सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
- छह फोकस क्षेत्र: शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ, वित्तीय सेवाएँ, नवीकरणीय ऊर्जा और विकल्प और टिकाऊ पर्यावरण।
- पहचाने गए 18 IOAs में से 10 पहले से ही परिपक्व निवेश योग्य क्षेत्र हैं जिन्होंने निजी इक्विटी और वेंचर कैपिटल गतिविधि देखी गयी है।
- शेष आठ IOAs उभरते हुए अवसर हैं, जिन्होंने शुरुआती स्तर के निवेशकों को आकर्षित किया है।
- मानचित्र में आठ श्वेत रिक्त स्थान की भी पहचान की गई है, जिन्होंने निवेशकों की रुचि को देखा है और नीतिगत समर्थन और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ पांच से छह वर्षों में IOAs में विकसित होने की क्षमता है।

क्या आप जानते है?

- इन्वेस्ट इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है।

भारत-बहरीन के बीच समझौते

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में

- हाल ही में, भारत और बहरीन रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों सहित अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए सहमत हुए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- द्विपक्षीय मुद्दों, और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश, बुनियादी ढांचे, आईटी, फिनटेक, स्वास्थ्य, हाइड्रोकार्बन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र शामिल थे।
- दोनों देशों ने अपने कोविद -19 संबंधित सहयोग को और मजबूत करने की पुष्टि की।
- बहरीन ने दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और चिकित्सा पेशेवरों की आपूर्ति के माध्यम से महामारी के दौरान भारत द्वारा प्रदान की गई सहायता की सराहना की।
- उन्होंने दोनों देशों के बीच एयर बबल व्यवस्था के संचालन पर संतोष व्यक्त किया।
- भारत ने आगामी महीनों में होने वाले तीसरे भारत-बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत आने के लिए बहरीन के निमंत्रण को नवीनीकृत किया।

क्या आप जानते है?

- एयर बबल (यात्रा गलियारे या यात्रा बुलबुले) दो देशों के बीच स्थापित सिस्टम हैं जो एक दूसरे को सुरक्षित मानते हैं और दोनों देशों के वाहक को किसी भी प्रतिबंध के बिना यात्रियों को उड़ाने की अनुमति देते हैं।

अर्थव्यवस्था

अपनी तरह के पहले आदेश के बाद, RERA ने भूमि सौदे की सुविधा के लिए कमीशन पर एक सीमा का निर्धारण किया।

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III- अर्थव्यवस्था

समाचार में

- अपने पहले आदेश में, हरियाणा के रेरा ने भूमि सौदे की सुविधा के दौरान दलालों द्वारा लगाए जा रहे कमीशन पर एक सीमा का निर्धारण किया।
- अब, हरियाणा में कोई भी रियल एस्टेट एजेंट खरीदार और विक्रेता से प्रति सौदा **0.5%** से अधिक कमीशन नहीं ले सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम

- मई 2016 में रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए यह प्रभावी हुआ।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य अपारदर्शी उद्योग में पारदर्शिता और दक्षता लाना है।
- इसमें एक त्वरित निवारण प्रणाली स्थापित करने सहित उपभोक्ता हित की रक्षा के लिए एक जनादेश है।
- यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है।
- यह 500 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड के आकार वाले सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं पर लागू होता है या 8 अपार्टमेंट या अधिक के साथ परियोजनाएं।
- प्रत्येक राज्य को केंद्रीय कानून को ढांचे के रूप में रखते हुए अपना नियामक स्थापित करना होगा।
- किसी भी लेनदेन को निष्पादित करने से पहले रियल एस्टेट एजेंटों को प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
- डेवलपर्स नियामक के साथ परियोजना को पंजीकृत किए बिना एक भूखंड, अपार्टमेंट या भवन खरीदने के लिए व्यक्तियों, बाजार, पुस्तक, बिक्री या आमंत्रित नहीं कर सकते।
- यदि नियमों का नियमित रूप से पालन नहीं किया जाता है तो परियोजना रद्द की जा सकती है।
- डेवलपर्स बिक्री के बाद सेवाओं के लिए जवाबदेह हैं।
- डेवलपर पांच साल के लिए संरचनात्मक नुकसान को सुधारने के लिए उत्तरदायी है।
- RERA के लागू होने के बाद, नए लॉन्च की संख्या में कमी आई है क्योंकि डेवलपर्स पर पैसे के उपयोग के बारे में पारदर्शी होने का अधिक दबाव है।

पारंपरिक रोजगार श्रेणी के बाहर प्लेटफार्म कार्य को परिभाषित करने का प्रथम प्रयास

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II और GS III- रोजगार; समांवेशी विकास

समाचार में

- सामाजिक सुरक्षा पर कोड, 2020, भारतीय कानून में पहली बार, पारंपरिक रोजगार श्रेणी के बाहर 'प्लेटफॉर्म वर्क' को परिभाषित करने का प्रयास किया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्लेटफ़ॉर्म का काम पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर काम की व्यवस्था का मतलब है।
- संगठन या व्यक्ति विशिष्ट समस्याओं या सेवाओं के लिए अन्य संगठनों या व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए एक ऑनलाइन मंच का उपयोग करते हैं।
- भुगतान के बदले इन गतिविधियों को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
- **महत्व: (1)** यह श्रमिकों के लचीलेपन और काम की डिलीवरी पर स्वामित्व का वादा करता है; **(2)** रोजगार गहन क्षेत्र; **(3)** शहरीकरण की तेज गति के कारण विकास के लिए संभावित क्षेत्र; **(4)** मंच कार्यकर्ताओं द्वारा भेजे गए प्रेषण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का विकास।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

सामाजिक सुरक्षा पर कोड, 2020

- यह नौ सामाजिक सुरक्षा कानूनों जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारियों की पेंशन योजना, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, की जगह लेगा।
- यह असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को सार्वभौमिक बनाता है।
- कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान भी पहली बार बढ़ाए जाएंगे।
- यह सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी भुगतान को पांच साल से एक वर्ष तक करने की समय सीमा को कम करता है।

प्राकृतिक गैस विपणन सुधार

संदर्भ: भारत का प्राकृतिक गैस विपणन सुधार जो अक्टूबर 2020 में घोषित किया गया था, भारत ऊर्जा फोरम में, इस विषय पर बहुत चर्चा की गई थी।

हाल ही में सरकार द्वारा घोषित प्राकृतिक गैस विपणन सुधार क्या हैं?

- नीति का उद्देश्य पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से गैस उत्पादकों द्वारा बाजार में बेची जाने वाली गैस के बाजार मूल्य की खोज करने के लिए मानक प्रक्रिया को निर्धारित करना है।
- हाइड्रोकार्बन महानिदेशक (DGH) उत्पादकों को ई-बिडिंग प्लेटफॉर्म का सुझाव देगा। यह सभी सरकारी संस्थाओं और अन्य विश्वसनीय कंपनियों को सूचीबद्ध करेगा। डीजीएच उसी के लिए दिशानिर्देश भी जारी करेगा।

- प्रोड्यूसर्स के पास पारदर्शी सार्वजनिक डोमेन के विभिन्न प्लेटफार्मों के बीच एक विकल्प होगा कि देश में कोयला, स्पेक्ट्रम और खनिज की नीलामी कैसे होती है।
- जबकि उत्पादक कंपनियों को स्वयं बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी, अन्य सभी खिलाड़ियों और संबद्ध कंपनियों को बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी। इससे गैस के विपणन में अधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और बढ़ावा मिलेगा
- नीति उन ब्लॉकों के क्षेत्र विकास योजनाओं (एफडीपी) को विपणन स्वतंत्रता भी प्रदान करेगी जिसमें उत्पादन साझा अनुबंध पहले से ही मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।

सुधारों का महत्व

- **बोली लगाने में एकरूपता:** यह अस्पष्टता से बचने और व्यवसाय करने में आसानी के लिए योगदान करने के लिए विभिन्न संविदात्मक शासनों और नीतियों में बोली प्रक्रिया में एकरूपता लाएगा।
- **व्यापार करने में आसानी को बढ़ाता है:** प्राकृतिक गैस के उत्पादन, बुनियादी ढांचे और विपणन से संबंधित नीतियों की पूरी इको-प्रणाली को व्यापार करने में आसानी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ और अधिक पारदर्शी बनाया गया है।
- **घरेलू उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करना:** प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए ये सुधार आत्मानिर्भर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे।
- **जलवायु अनुकूल:** बढ़ी हुई गैस उत्पादन खपत पर्यावरण के सुधार में मदद करेगी। उदाहरण के लिए, जब प्राकृतिक गैस को जलाया जाता है, तो यह कोयले की तुलना में 45 प्रतिशत कम कार्बन डाइऑक्साइड और तेल की तुलना में 30 प्रतिशत कम उत्पादन करता है।
- **रोजगार सृजन:** घरेलू उत्पादन शहर के गैस वितरण और संबंधित उद्योगों जैसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों में निवेश बढ़ाने में मदद करेगा। यह एमएसएमई सहित गैस खपत वाले क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद करेगा।

सुधारों की आलोचना

1. नए सुधार सभी गैस उत्पादन पर लागू नहीं होते हैं

- नई ई-बिडिंग प्रक्रिया उन खोजों को नियंत्रित करेगी जो फरवरी 2019 के बाद से स्ट्रीम पर आई थीं। अनिवार्य रूप से, नई व्यवस्था ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के उत्पादकों पर लागू होगी।
- सरकार ने स्पष्ट किया कि मौजूदा गैस-मूल्य निर्धारण फार्मूला नामांकन की व्यवस्था के तहत मौजूदा खोजों से उत्पादन के लिए लागू रहेगा।
- लगभग 80 प्रतिशत भारतीय घरेलू गैस का उत्पादन राष्ट्रीय तेल कंपनियों को नामांकन के आधार पर दिए गए ब्लॉकों से किया जाता है। नतीजतन, इस गैस को दी गई नई विपणन स्वतंत्रता का लाभ नहीं मिलता है।
- सभी प्राकृतिक गैसों की कीमतों को मुक्त नहीं करने का कारण यह है कि यदि गैस की कीमतें बढ़ती हैं, तो उर्वरक और बिजली की लागत बढ़ जाएगी;

- **परिणामतः घरेलू उत्पादन कम है:** जब तक ओएनजीसी जैसे मौजूदा उत्पादक अपने द्वारा उत्पादित गैस से अधिक कमाई करने में सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें अधिक गैस की खोज / निकालने में निवेश करने के लिए संसाधन नहीं मिलेंगे

2. गैस के लिए कई प्रकार की कीमतों का अस्तित्व

- इसके लिए घरेलू मूल्य दिशानिर्देश हैं- इसे पहले प्रशासित मूल्य तंत्र (APM) कहा जाता था - और इसके तहत उत्पादित गैस 1.79 $ प्रति mmBtu में बेची जाती है। हालांकि, उत्पादन की लागत काफी अधिक है।
- गैस की कीमतों को कम रखने के बाद नए निवेश को कम कर दिया, 2016 में, सरकार ने कीमतें बढ़ा दीं (4.5 $ से 5.5 $ प्रति mBtu की सीमा में), लेकिन केवल नई खोजों के लिए और वह भी गहरे या अति-गहरे पानी में उत्पादित गैस के लिए उच्च तापमान-उच्च दबाव वाले क्षेत्र; यदि गैस का उत्पादन ऑनशोर होता है, तो इसकी उच्च कीमत नहीं मिलती है।
- इसके अलावा, वहाँ आयातित कीमतें हैं जो लगभग 5-7 $ प्रति mmBtu हैं।
- सुधारों के बाद, गैस के लिए एक मूल्य होगा, उदाहरण के लिए, तटवर्ती या अपेक्षाकृत उथले पानी में पाया जाता है; यह मूल्य बाजार-निर्धारित होगा।

3. इस तथ्य के अलावा कि मार्केटिंग की स्वतंत्रता को कच्चे तेल तक और मौजूदा प्राकृतिक गैस उत्पादन तक नहीं बढ़ाया गया है

निष्कर्ष

प्रकृतिक गैस विपणन सुधार तब फल देगा जब घरेलू उत्पादन बंद हो जाता है और बाजार परिपक्व हो जाते है

UPI ट्रांजैक्शंस 2 बिलियन का आंकड़ा पार किया

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III – अर्थव्यवस्था

समाचार में

- हाल ही में UPI लेनदेन खबरों में था।
- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, BHIM-UPI पर किए गए कुल लेनदेन अक्टूबर 2020 में एक महीने में 2 बिलियन का आंकड़ा पार कर गए।

महत्वपूर्ण बिंदु

- UPI वर्तमान में NPCI संचालित प्रणालियों में सबसे बड़ी है।
- अन्य प्रणालियों में राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस (**NACH**), तत्काल भुगतान सेवा (**IMPS**), आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (**AePS**), भारत बिल भुगतान प्रणाली (**BBPS**), **RuPay** आदि शामिल हैं।

- डिजिटल लेनदेन पहले से ही बढ़ रहे थे लेकिन कोविद -**19** के कारण लगाए गए लॉकडाउन ने इसकी तीव्रता में वृद्धि की है।
- इसके अलावा**,** भारत का डिजिटल भुगतान **2,153** ट्रिलियन से रूपये से बढ़कर **2025** तक **7,092** ट्रिलियन होने की संभावना है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)

- एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक umbrella organisation है।
- यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत आरबीआई और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की एक पहल है।
- यह कंपनी अधिनियम 1956 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) की धारा 25 के प्रावधानों के तहत "नॉट फॉर प्रॉफिट" कंपनी है।
- उद्देश्य: भौतिक और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को बुनियादी ढाँचा प्रदान करना।

क्या आप जानते है ?

डिजिटल लेनदेन की चुनौतियां

- साइबर अपराध, जै-से दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर Cerberus
- धोखाधड़ी के दावे, चार्जबैक, नकली खरीदार खाते, पदोन्नति / कूपन का दुरुपयोग, खाता अधिग्रहण, पहचान की चोरी, आदि।

भारत का विनिर्माण उत्पादन सबसे मजबूत वृद्धि दर्शाता है

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III- अर्थव्यवस्था

समाचार में

- आईएचएस मार्किट इंडिया परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) के अनुसार**,** भारत के विनिर्माण उत्पादन में अक्टूबर 2020 में 13 वर्षों में सबसे मजबूत वृद्धि देखी गई।
- नोमुरा इंडिया बिज़नेस रिज्यूमेनेशन इंडेक्स (NIBRI) ने भी सुधार दिखाया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) सितंबर में **56.8** से बढ़कर अक्टूबर में **58.9** हो गया।
- अक्टूबर में एनआईबीआरआई **82.4** तक सुधरा**,** सितंबर में **80.3** से **2.1** अंक की वृद्धि।
- **NIBRI** आर्थिक गतिविधि के सामान्यीकरण की गति के जापानी ब्रोकरेज का साप्ताहिक ट्रैकर है।
- कारण: **(1)** बिक्री में वृद्धि**; (2)** एक्सपोर्ट ऑर्डर में वृद्धि**; (3) IIP** में सुधार

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

क्रय प्रबंधकों की सूची

- पीएमआई व्यावसायिक गतिविधि का एक संकेतक है - दोनों विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में।
- इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग की जाती है।
- एक समग्र सूचकांक भी बनाया गया है।
- पीएमआई संक्षेप में बताता है कि क्रय प्रबंधकों द्वारा देखी गई बाजार की स्थिति का विस्तार, तटस्थ या अनुबंधित है।
- उद्देश्य: कंपनी के निर्णय निर्माताओं, विश्लेषकों और निवेशकों को वर्तमान और भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- पीएमआई आमतौर पर हर महीने की शुरुआत में जारी किया जाता है।
- इसलिए, यह आर्थिक गतिविधि का एक अच्छा प्रमुख संकेतक माना जाता है।

क्या आप जानते है?

- PMI दुनिया भर में 40 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए IHS मार्किट द्वारा संकलित किया गया है।
- IHS मार्किट दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को चलाने वाले प्रमुख उद्योगों और बाजारों के लिए
- सूचना, विश्लेषण और समाधान में एक वैश्विक मंच है।

चीनी उद्योग: निर्यात सब्सिडी की आवश्यकता

संदर्भ: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि केंद्र सरकार 2020-21 के चीनी के लिए अपनी निर्यात सब्सिडी के विस्तार पर विचार नहीं कर रही है।
उद्योग के अत्यधिक स्टॉक के कारण इस क्षेत्र में एक 'ऊर्ध्वाधर पतन' की चेतावनी दी है, जिसका प्रभाव आने वाले वर्षों में महसूस किया जा सकता है।

चीनी उद्योग सीजन की शुरुआत से पहले ही निर्यात के लिए क्यों तैयार है?

- (अक्टूबर-नवंबर) चीनी सीजन की शुरुआत में, उद्योग अपनी बैलेंस-शीट तैयार करता है और अपेक्षित उत्पादन, पिछले सीज़न के कैरी फॉरवर्ड स्टॉक, माइनस घरेलू खपत और निर्यात, यदि कोई हो, को ध्यान में रखता है।
- यह चीनी बैलेंस-शीट अगले सत्र के लिए चीनी की उपलब्धता को निर्धारित करती है।
- असामान्य रूप से उच्च स्टॉक के मामले में, एक्स-मिल की कीमतें वर्तमान सीजन के साथ-साथ आगामी सीजन के लिए कम रहती हैं, जिसके परिणामस्वरूप चीनी क्षेत्र के लिए तरलता संकट उत्पन्न होता है।

1	ओपनिंग स्टॉक इस सीज़न (2020-21)	107 लाख टन
2	वार्षिक उत्पादन अनुमान (2020-21)	326 लाख टन
3	इथेनॉल उत्पादन के लिए अनुमानित मोड़	20 लाख टन
4	इस मौसम में कुल उपलब्ध शर्करा संतुलन (2020-21) = (1 + 2) -3	413 लाख टन

5	इस मौसम में घरेलू खपत का अनुमान	260 लाख टन
6	अगले सीजन (2021-22 का सीजन) का ओपनिंग स्टॉक = (4-5)	153 लाख टन

- अगले सीजन में यह असामान्य रूप से उच्च स्टॉक, सरकारी सब्सिडी की तरह निर्यात प्रोत्साहन के बिना, सेक्टर के ऊर्ध्वाधर पतन हो सकता है।
- इस इन्वेंट्री को सही करने का एक तरीका कम से कम 50 लाख टन चीनी के निर्यात को बढ़ावा देना है। तब उद्घघान स्टॉक 105 लाख टन होगा, जिससे मिलों को एक स्वस्थ सूची और साथ ही निर्यात से तरलता मिलेगी।

सरकारी सब्सिडी के बिना चीनी निर्यात करने के लिए मिलों में अनिच्छा क्यों व्याप्त हैं?

- अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विनिर्माण लागत और कच्ची चीनी की मौजूदा कीमत के बीच के अंतर, मिलों में अनिच्छा के उपज का कारण है।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी अनुबंध 21-22 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रहे हैं, जबकि उत्पादन की लागत 32 रुपये है।
- मूल्य बेमेल ने किसी भी निर्यात संभावनाओं को खारिज कर दिया है क्योंकि इससे मिलों को और नुकसान होगा।
- विडंबना यह है कि मिलों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है जब भारतीय चीनी ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बनाई है।
- पिछले सीज़न में, भारत ने 60 लाख टन के रिकॉर्ड चीनी निर्यात किया है, जिसमें से 57 लाख टन पहले ही देश से बाहर जा चुका है। शेष खेप दिसंबर के अंत तक निकलने की उम्मीद है।

मिलों ने पिछले सीजन में चीनी का निर्यात कैसे किया?

- पिछले सत्र का रिकॉर्ड निर्यात स्तर केवल केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित सब्सिडी कार्यक्रम के कारण ही संभव था।
- मिलों को निर्यात में **10.448** रुपये प्रति किलो चीनी की परिवहन सब्सिडी का वादा किया गया था।
- इस सब्सिडी ने मिलों को उत्पादन लागत और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बीच अंतर को पाटने में मदद की थी।
- इसके अलावा, केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय अनुपालन के बारे में सख्त था, जिसके कारण मिलों को निर्यात के मामले में लाइन में लगना पड़ा।
- अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अधिक मांग के कारण भारतीय मिलों को अच्छे निर्यात की सूचना मिली।

पिछले सीज़न के निर्यात ने मिलों को पर्याप्त तरलता उत्पन्न करने में मदद की है?

- नहीं। केंद्र सरकार को मिलों के कारण निर्यात सब्सिडी जारी करना बाकी है और कुल देय 6,900 करोड़ रुपये के बराबर है।

- व्यक्तिगत मिलों ने निर्यात की सुविधा के लिए ऋण लिया था और अब उन्हें बैंकों को ब्याज देना होगा।
- बफर स्टॉक को बनाए रखने के लिए 3,000 करोड़ रुपये के अवैतनिक ब्याज ने भी मिलों की बैलेंस सीट को कड़ी चोट दी है।
- कोविद -19 महामारी ने सब्सिडी जारी करने में और देरी की है, जिसके कारण कई मिलों को सीजन की शुरुआत में पर्याप्त तरलता नहीं मिली है।

लेकिन ईधन उत्पादन पर सरकार के जोर को देखते हुए मिलों द्वारा इथेनॉल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं किया जा सकता है?

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने इथेनॉल के खरीद मूल्य में 1-3 प्रति लीटर वृद्धि की घोषणा की है। यह सरकार द्वारा चीनी के बजाय इथेनॉल के उत्पादन की दिशा में गन्ना हटाने के लिए मिलों द्वारा दिया गया संकेत है।
- पिछले साल, केंद्र सरकार ने मिलों के लिए इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए एक ब्याज सबवेंशन स्कीम की घोषणा की थी।
- हालांकि लेइथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना एक बहुत जरूरी कदम है, इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए समय की आवश्यकता होगी, (भौतिक मॉड्यूल निर्माण)
- वर्तमान क्षमता के साथ, मिलें 426 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन कर सकती हैं, जिसके लिए 15-20 लाख टन चीनी की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

- जबकि इथेनॉल उत्पादन की दिशा में मिलों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का कदम निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, इसके लिए अधिक पूंजी और समय की आवश्यकता होगी।
- वर्तमान मौसम के लिए, यदि निर्यात में व्यवहार्य नहीं है, तो न केवल भारत अपने बाजार में हिस्सेदारी खो देगा, लेकिन मिलों को निश्चित रूप से तरलता की कमी महसूस होगी।

Connecting the dots

- अधिशेष अवस्था में एमएसपी: गन्ना मूल्य निर्धारण और दूध का मूल्य निर्धारण

कैपिटल गुड्स सेक्टर को मजबूत करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - अर्थव्यवस्था

समाचार में

- सरकार ने इस क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और दुनिया के लिए विनिर्माण केंद्र बनने के लिए कैपिटल गुड्स (CG) सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक 22 सदस्यीय अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- समिति प्रौद्योगिकी विकास, मातृ प्रौद्योगिकी विकास, वैश्विक मूल्य श्रृंखला, कौशल प्रशिक्षण, वैश्विक मानकों, कस्टम कर्तव्यों आदि सहित कैपिटल गुड्स सेक्टर से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देगी।
- अध्यक्ष: भारी उद्योग विभाग के सचिव
- समिति त्रैमासिक बैठक करेगी

ऑपरेशन ग्रीन्स - टॉप टू टोटल स्कीम

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - अर्थव्यवस्था

समाचार में

- ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत TOP से TOTAL तक, 50% परिवहन सब्सिडी अब भारत के किसी भी स्थान पर पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों के लिए हवाई परिवहन के लिए उपलब्ध कराई गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- एयरलाइंस वास्तविक अनुबंधित माल ढुलाई शुल्क का केवल 50% चार्ज करने के माध्यम से सीधे आपूर्तिकर्ता को परिवहन सब्सिडी प्रदान करेगी और सब्सिडी के रूप में MoFPI से शेष 50% का दावा करेगी।
- योजना को मंजूरी दी गई और संशोधित योजना दिशानिर्देश नवंबर 2020 में अधिसूचित किए गए।
- मात्रा और कीमत के बावजूद अधिसूचित फलों और सब्जियों की सभी खेप 50% भाड़ा अनुदान के लिए पात्र होगी।
- योग्य हवाई अड्डे: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम (बागडोगरा), और उत्तर-पूर्व से त्रिपुरा, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के सभी हवाई अड्डे पहाड़ी राज्यों।

क्या आप जानते है'?

- परिवहन सब्सिडी को पहले दिसंबर में किसान रेल योजना के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत चलाया गया था।
- रेलवे अधिसूचित फल और सब्जियों पर केवल 50% भाड़ा प्रभार लिया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 स्वीकृत

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - अर्थव्यवस्था

समाचार में

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- बैंकिंग आईएफसी के प्रमुख केन्द्रित क्षेत्रों में से एक है और इससे नियत समय में आईएफएससी में अन्य घटक परिचालनों के संचालन और सहायता की उम्मीद की जाती है। इस प्रकार आईएफएससी में निहित बैंकिंग परिचालन के मुख्य सिद्धांतों का स्वत:पूर्ण विनियम वांछित क्षमता तक पहुंचने वाले आईएफएससी का एक महत्वपूर्ण कदम है। पराधिकरण ने अपनी बैठक में बैंकिंग विनियमों के मसौदे को अपनी मंजूरी दी, जिससे बैंकिंग परिचालन के विभिन्न पहलुओं के लिए उचित नियम लागू करने का मार्ग प्रशस्त होता है, जो आईएफएससी में स्वीकार्य होंगे।

बैंकिंग विनियमों के मुख्य पहलू इस प्रकार हैं –

- आईएफएससी बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने की जरूरतों को क्रम से स्थापित करना।
- भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों (जिनके पास एक मिलियन अमरीकी डॉलर से कम नेटवर्क न हो) को आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों में किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति देना।
- भारत में रहने वाले व्यक्तियों (जिनके पास एक मिलियन अमरीकी डॉलर से कम नेटवर्क न हो) को भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत जमा योजना (एलआरएस) के तहत कोई अनुमति प्राप्त करंट अकाउंट या पूंजीगत लेखा लेन-देन या इनके किसी भी संयोजन के लिए स्वतंत्ररूप से परिवर्तनीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति देना।
- ऋण वृद्धि, क्रेडिट बीमा और बिक्री, पोर्टफोलियो की खरीदारी, निर्यात प्राप्तियों की फैक्टिंग, फोरफेटिंग कार्य तथा विमान लिजिंग सहित उपकरणों की लिजिंग करने समेत आईबीयू की गतिविधियों की अनुमति देना।
- व्यवसाय का यह निर्धारण करने के लिए प्राधिकरण को अनुमति देना कि क्या किसी बैंकिंग यूनिट को भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति और भारत से बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ आईएनआर आयोजित करने की अनुमति दी जाए। लेकिन इसके साथ यह शर्त है कि ऐसे व्यापार के संबंध में वित्तीय लेन-देन का निपटान स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में हो।

उपरोक्त विनियमों को नियत समय में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना 10 और क्षेत्रों के लिए स्वीकृत

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - अर्थव्यवस्था

समाचार में

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित 10 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

Priority	Sectors	Implementing Ministry/Department	Approved financial outlay over a five-year period Rs.crore
1	Advance Chemistry Cell (ACC) Battery	NITI Aayog and Department of Heavy Industries	18100
2	Electronic/Technology Products	Ministry of Electronics and Information Technology	5000
3	Automobiles & Auto Components	Department of Heavy Industries	57042
4	Pharmaceuticals drugs	Department of Pharmaceuticals	15000
5	Telecom & Networking Products	Department of Telecom	12195
6	**Textile Products: MMF segment and technical textiles**	**Ministry of Textiles**	**10683**
7	Food Products	Ministry of Food Processing Industries	10900
8	High Efficiency Solar PV Modules	Ministry of New and Renewable Energy	4500
9	White Goods (ACs & LED)	Department for Promotion of Industry and Internal Trade	6238
10	Speciality Steel	Ministry of Steel	6322
		Total	**145980**

क्षेत्र और कार्यान्वयन मंत्रालय / विभाग इस प्रकार हैं

- एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी: एनआईटीआईयोग और भारी उद्योग विभाग
- इलेक्ट्रॉनिक / प्रौद्योगिकी उत्पाद: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- ऑटोमोबाइल और ऑटो अवयव: भारी उद्योग विभाग
- फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स: फार्मास्युटिकल्स विभाग
- दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद: दूरसंचार विभाग
- कपड़ा उत्पाद (MMF खंड और तकनीकी वस्त्र): कपड़ा मंत्रालय
- खाद्य उत्पाद: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।
- उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।
- व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी): उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग।
- विशेष इस्पात: इस्पात मंत्रालय।

क्या आप जानते है?

अधिसूचित पीएलआई योजनाएँ निम्नलिखित क्षेत्रों में पहले से ही उपलब्ध हैं:

- मोबाइल विनिर्माण और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक: MEITY।
- महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री / दवा बिचौलियों और सक्रिय दवा सामग्री: फार्मास्यूटिकल्स विभाग।
- चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण: फार्मास्यूटिकल्स विभाग

आत्मानिर्भर भारत रोज़गार योजना

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप और GS - III – अर्थव्यवस्था

समाचार में

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने COVID-19 रिकवरी के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए AATMANIRBHAR BHARAT ROZGAR YOJANA की नई योजना की घोषणा की

महत्वपूर्ण तथ्य

आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना स्थापना के लिए पात्रता मानदंड

- EPFO के साथ पंजीकृत कंपनी यदि उन्होंने सितंबर 2020 में कर्मचारियों के संदर्भ आधार की तुलना में नए कर्मचारी शामिल किए हैं:
  - न्यूनतम दो नए कर्मचारियों यदि कर्मचारी 50 या उससे कम है.
  - पांच नए कर्मचारी यदि कर्मचारी 50 या उससे अधिक है.

सभी नए कर्मचारियों के लिए सब्सिडी लेने के लिए योजना शुरू होने के बाद ईपीएफओ के साथ पंजीकरण करने वाले प्रतिष्ठान.

- 30 जून 2021 तक चालू रहेगी योजना
- केंद्र सरकार से आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना सब्सिडी सहायता
- केंद्रीय सरकार निम्नलिखित मानदंडों पर 01.10.2020 पर या उसके बाद लगे नए पात्र कर्मचारियों के संबंध में दो साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी:
  - 1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान: कर्मचारी का योगदान (वेतन का 12%) और नियोक्ता का योगदान (वेतन का 12%) कुल मजदूरी का 24%.
  - 1000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान: केवल कर्मचारी के ईपीएफ अंशदान (ईपीएफ वेतन का 12%)

पात्र नए कर्मचारी के आधार लिंक्ड ईपीएफओ अकाउंट (यूएएन) में क्रेडिट अपफ्रंट प्राप्त करने के लिए सब्सिडी सहायता

वित्त मंत्री ने आत्मानिर्भर भारत 3.0 पर उपायों की घोषणा की

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप और GS- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने Aatma Nirbhar Bharat 3.0 के तहत भारत सरकार की अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन के रूप में विभिन्न उपायों की घोषणा की।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई में घोषणा.
- इस योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है।
- गारंटीड और संपार्श्विक-मुक्त.

- पात्र इकाइयाँ - MSME इकाइयाँ, व्यवसाय उद्यम, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत ऋण और MUDRA लोन लेने वाले
  - 12.11.2020 तक योजना अपडेट
  - 61 लाख कर्जदारों के लिए 2.05 लाख करोड़ रुपये मंजूर
  - 1.52 लाख करोड़ रु का डिसबर्सल
- ECLGS 2.0 का शुभारंभ: तनावग्रस्त क्षेत्रों की सहायता करने के लिए गारंटीड क्रेडिट
- 10 चैंपियन सेक्टर्स के लिए आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से जुड़े इंसेंटिव्स के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) -शहरों के लिए 18,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय
- निर्माण और अवसंरचना के लिए सहायता - सरकारी निविदाओं पर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) और प्रदर्शन सुरक्षा में छूट
- डेवलपर्स और घर खरीदने वालों के लिए आवासीय रियल एस्टेट आयकर राहत के लिए मांग बूस्टर
- इंफ्रा डेट फाइनेंसिंग के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये का प्लैटफॉर्म - 6000 करोड़ रुपये एनआईआईएफ डेट प्लेटफॉर्म में इक्विटी इन्फ्यूजन
- सब्सिडी वाले उर्वरकों के लिए कृषि को 65,000 करोड़ रुपये का समर्थन
- ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए - पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत बढ़ी हुई रूपरेखा
- मनरेगा को 2020-21 के बजट में 61,500 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।
- प्रॉजेक्ट एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए -, आईडीईएएस योजना के तहत लाइन्स ऑफ क्रेडिट के माध्यम से परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए EXIM बैंक को 3,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग को भारतीय कोविड टीका के अनुसंधान और विकास के लिए कोविड सुरक्षा मिशन के लिए 900 करोड़ रुपये प्रदान किए गए'

यूके-जापान: ब्रेक्सिट के बाद के युग के लिए एक सौदा?

संदर्भ: व्यापार के लिए यूके के पहले बड़े पोस्ट-ब्रेक्सिट सौदे को चिह्नित करते हुए, यू.के. और जापान के बीच व्यापार समझौते को सील कर दिया गया था।

व्यापार सौदे की मुख्य विशेषताएं

- ब्रिटेन ने कहा है कि इस सौदे का मतलब यह है कि जापान को निर्यात का 99% भाग टैरिफ-मुक्त होगा, और यह 2018 की तुलना में लंबे समय में 15.2 बिलियन पाउंड ($ 19.9 बिलियन) तक व्यापार बढ़ा सकता है।
- यह सौदा 2026 में चरणों में जापानी कारों पर ब्रिटेन के टैरिफ को हटाता है, जो जापान-यूरोपीय संघ के व्यापार समझौते के समान है।

- ब्रिटेन ने ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) मुक्त व्यापार समझौते के लिए 11-सदस्यीय व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने में अपनी रुचि व्यक्त की है। जापान ने इस व्यापार सौदे में शामिल होने के लिए ब्रिटेन की उत्सुकता का स्वागत किया है।\
- जापान पहले से ही CPTPP का सदस्य है, जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चिली, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम को भी जोड़ता है।

सौदे का महत्व

- ब्रिटेन अब जापान के कृषि बाजार तक पहुंच बना सकेगा, जो पहले यूरोपीय संघ के दायरे में आता था।
- व्यापार सौदा यूरोपीय संघ-जापान आर्थिक साझेदारी समझौते पर आधारित है, जो कम कर्तव्यों और प्रक्रियाओं के साथ राष्ट्रों के बीच सुचारू व्यापार प्रदान करता है
- यूएसए के इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव उद्योग द्वारा गहन प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर जापान के ऑटो उद्योग को लाभ मिलेगा।
- समझौते में उत्पत्ति और डेटा साझा करने के नियमों पर कुछ लचीलापन है, इसके अलावा भौगोलिक संकेतों की अतिरिक्त संख्या के लिए मान्यता भी है
- यह सौदा ब्रिटेन को रहत देता है जब वह 31 दिसंबर, 2020 को यूरोपीय संघ (ईयू) से बाहर निकल जायेगा ।
- ब्रिटेन जापान के साथ इस व्यापार समझौते का एक उदाहरण बनाना चाहता है ताकि अन्य देशों के साथ समझौते पर हमला किया जा सके।
- ब्रिटेन जापान के साथ व्यापार समझौते को लंदन के 11-सदस्यीय सीपीटीपी में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार मानता है

भारत ने तकनीकी मंदी के दौर में प्रवेश किया: **RBI**

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - अर्थव्यवस्था

समाचार में

- अपने सालाना बुलेटिन के एक हिस्से के रूप में RBI ने "नाउकास्टिंग" या अर्थव्यवस्था की स्थिति के वर्तमान या बहुत निकट भविष्य की भविष्यवाणी शुरू कर दी है। पहले "नाउकास्टिंग" की भविष्यवाणी यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई, अगस्त, सितंबर) में 8.6% तक गिर सकती है। RBI की डिक्शनरी में नाउकास्ट शब्द का उपयोग किया गया है। जैसे फोरकास्ट का अर्थ भविष्यवाणी होता है, वैसे ही नाउकास्ट का अर्थ वर्तमान हालात का ब्यौरा देना है।

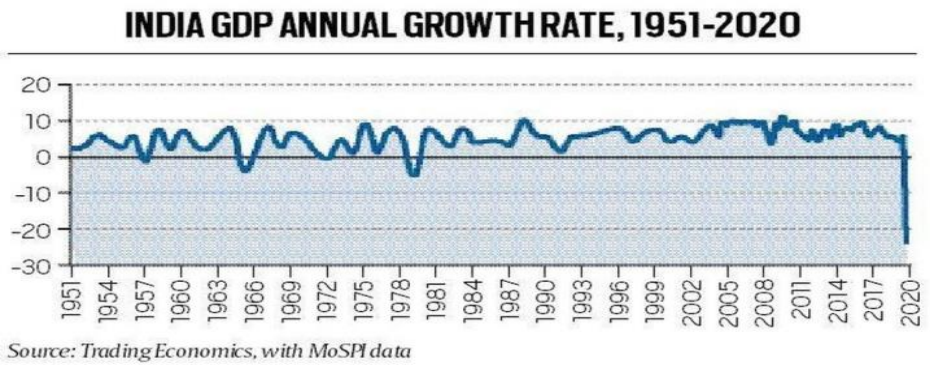

Source: Trading Economics, with MoSPI data

महत्वपूर्ण बिंदु

- 11 नवंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एक अधिकारी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक साल पहले की तुलना में 8.6 प्रतिशत घटने का अनुमान है।
- इस तरह लगातार दो तिमाहियों में जीडीपी घटने के साथ देश पहली बार मंदी में घिरा है। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के असर से पहली तिमाही में 23.9 प्रतिशत का संकुचन हुआ था।
- दूसरी तिमाही के जीडीपी के सरकारी आंकड़े अभी नहीं आए है पर केंद्रीय बैंक के अनुसंधानकर्ताओं ने तात्कालिक पूर्वानुमान विधि का प्रयोग करते हुए अनुमान लगाया है कि सितंबर तिमाही में संकुचन 8.6 प्रतिशत तक रहा होगा।
- इन अनुसंधानकर्ताओं के विचार जारी आरबीआई के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित हुए हैं।
- आरबीआई ने पहले ही अनुमान लगा रखा है कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 9.5 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।
- 'भारत तकनीकी रूप से 2020-21 की पहली छमाही में अपने इतिहास में पहली बार आर्थिक मंदी में चला गया है।
- 'इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स' यानी आर्थिक कामकाज का सूचकांक शीर्षक से लिखे गये लेख में कहा गया है कि लगातार दूसरी तिमाही में आर्थिक संकुचन होने का अनुमान है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि गतिविधियां धीरे-धीरे सामान्य होने के साथ संकुचन की दर कम हो रही है और स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है।

महत्त्वपूर्ण शब्द

मंदी का दौर

- यह एक ऐसा चरण है जब जीडीपी एक तिमाही से दूसरी तिमाही में अनुबंधित होती है।

मंदी

- जब कोई मंदी का दौर लंबे समय तक टिकता है, तो उसे मंदी कहा जाता है।
- मंदी के दौरान, आर्थिक गतिविधि में एक महत्वपूर्ण गिरावट अर्थव्यवस्था में फैलती है और कुछ महीनों से लेकर एक साल से अधिक तक रह सकती है।

तकनीकी मंदी

- जब वास्तविक जीडीपी में कम से कम दो लगातार तिमाहियों के लिए गिरावट आई है।

डिजिटल कराधान और ओईसीडी: एक कमजोर स्तंभ पर

संदर्भ: अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से संबंधित कर चुनौतियां पिछले एक दशक में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है।

इस सन्दर्भ में, OECD ने इसकी पहचान OECD / G20 बेस एरोसियन और प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) प्रोजेक्ट के मुख्य क्षेत्रों में से एक के रूप में की, जो 2015 के BEPS एक्शन 1 रिपोर्ट के लिए अग्रणी है।

बेस एरोसियन और प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) क्या है?

- बेस एरोसियन और प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) उस घटना को संदर्भित करता है जहां कंपनियां अपने लाभ को अन्य कर न्यायाल यों में स्थानांतरित करती हैं, जिनमें आम तौर पर कम दरें होती हैं, जिससे भारत में कर आधार का क्षरण होता है।
- भारतीय अधिकारियों ने ऐसे उपाय किए हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कॉर्पोरेट को अंतर्राष्ट्रीय दरों पर कर लगाया जाये ताकि उन्हें लाभ के स्थानांतरण के तरीकों का दुरुपयोग करने से रोका जा सके।

2015 BEPS एक्शन 1 रिपोर्ट क्या है?

- 2015 में, जब ओईसीडी ने एक्शन प्लान 1 रिपोर्ट जारी की, जिसमें ऐसे खंभे थे जो डिजिटल अर्थव्यवस्था के कराधान का मार्गदर्शन करें। इसने पहचान लिया
  - तटस्थता
  - दक्षता
  - निश्चितता और सरलता
  - प्रभावशीलता और निष्पक्षता
  - लचीलापन

ओईसीडी, डिजिटाइजेशन और बीईपीएस पर कराधान

- डिजिटल कंपनियों पर कर लगाने पर बहस और फोकस तब बढ़ा जब देशों ने एकपक्षीय, एकतरफा उपायों को लागू करना शुरू किया।
- जनवरी 2019 में, ओईसीडी ने एक नीति नोट जारी किया जिसमें कहा गया था कि नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय चर्चा दो केंद्रीय स्तंभों: स्तंभ एक और स्तंभ दो पर केंद्रित होगी।
- स्तंभ एक अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से संबंधित व्यापक चुनौतियों को संबोधित करेगा और कर अधिकारों के आवंटन पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- स्तंभ एक का उद्देश्य व्यवसाय के मुनाफे पर कर के अधिकारों के आवंटन को एक तरह से वैश्विक समझौते तक पहुंचाना है, जो कि बाजार के अधिकार क्षेत्र के लिए इन अधिकारों का विस्तार करता है।
- स्तंभ पर ओईसीडी ब्लूप्रिंट एक भविष्य के समझौते के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है जो आय के शुद्ध कराधान की अवधारणा का पालन करेगा, दोहरे कराधान से बचें और जितना संभव हो उतना सरल और आसान प्रशासन करें।
- स्तंभ दो शेष BEPS चिंताओं (सामूहिक रूप से, BEPS 2 परियोजना) को सुलझाएगा

चिंता

- **अंतर्राष्ट्रीय नियमों में परिवर्तन:** स्तंभ एक के तहत कर लगाने के अधिकारों के पुन: आवंटन से अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं जिसके तहत बहुराष्ट्रीय व्यवसाय संचालित होते हैं और देशों के व्यवसायों और कर राजस्व के समग्र कर दायित्व पर महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं।
- **नीति नोट में सर्वसम्मति का अभाव है:** ब्लूप्रिंट यह स्वीकार करता है कि यह आम सहमति दस्तावेज नहीं है और समाधान की कई प्रमुख विशेषताएं हैं जिन्हें केवल राजनीतिक निर्णयों के माध्यम से हल किया जा सकता है।
- **आगे की राजनीतिक कार्रवाई की आवश्यकता है:** ब्लूप्रिंट नोट करता है कि कई मुद्दों पर राजनीतिक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जिसमें नए कर लगाने के अधिकार के तहत आवंटित किए जाने वाले अवशिष्ट लाभ की मात्रा, अनिवार्य बंधन विवाद समाधान का दायरा आदि शामिल हैं।
- **सिद्धांतों पर लघु**: ब्लूप्रिंट OECD द्वारा 2015 एक्शन 1 रिपोर्ट में विस्तृत कई सिद्धांतों पर कम है।

निष्कर्ष

सर्वसम्मति के अभाव में, एकतरफा उपायों के कारण होने वाली अनिश्चितता बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर संकटों से जुड़ने की उम्मीद है।

Connecting the dots

- बिग टेक का प्रभुत्व

कैलिब्रेटेड इकोनॉमिक पैकेज (आत्मनिर्भर भारत 3.0) - भाग 1

संदर्भ: 12 नवंबर को, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने तीसरे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणाओं की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें 2.65 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय शामिल है।

पिछले पैकेज के बारे में

- प्रथम प्रोत्साहन में कैश-फ्लो मिसमैच को संबोधित करके लॉकडाउन के नुकसान को ध्यान में रखा गया था। यह आपातकालीन ऋण सुविधाओं, मैक्रो-विवेकपूर्ण नीतियों, आस्थगित करों और विनियामक निषेध के उपयोग से किया गया था। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर दिवालिया होने से रोकना था।
- दूसरा प्रोत्साहन मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों को दिया गया था क्योंकि वे आय के झटके के साक्षी नहीं थे, जैसे कि उन्हें खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करना था।
- इसके अतिरिक्त, सरकार ने अपने व्यय को बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और राज्य सरकारों को अपनी व्यय प्रतिबद्धताओं के साथ रखने के लिए अवसर दिया, जिसमें पूंजीगत परिव्यय भी शामिल था।

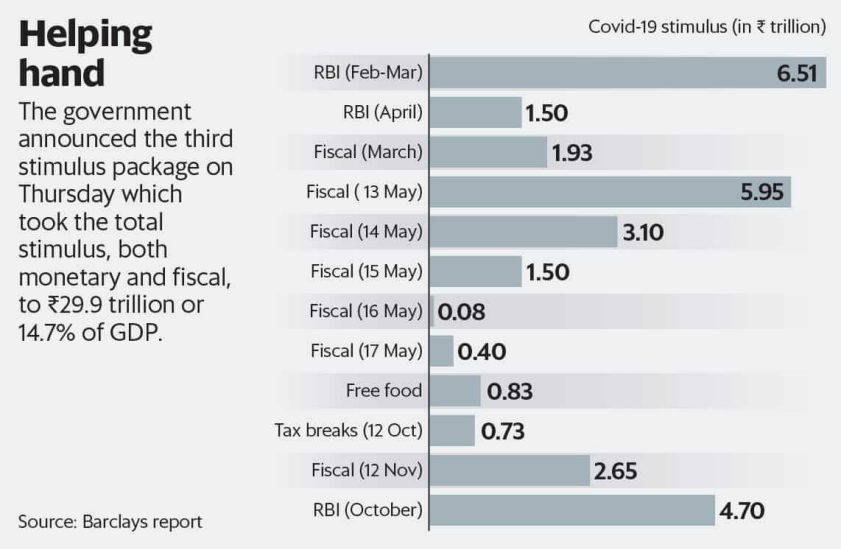

Image Source: Livemint

तृतीय पैकेज के बारे में

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई में घोषणा.

- इस योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है।
- गारंटीड और संपार्श्विक-मुक्त.
- पात्र इकाइयाँ - MSME इकाइयाँ, व्यवसाय उद्यम, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत ऋण और MUDRA लोन लेने वाले
  - 12.11.2020 तक योजना अपडेट
  - 61 लाख कर्जदारों के लिए 2.05 लाख करोड़ रुपये मंजूर
  - 1.52 लाख करोड़ रु का डिसबर्सल
- ECLGS 2.0 का शुभारंभ: तनावग्रस्त क्षेत्रों की सहायता करने के लिए गारंटीड क्रेडिट
- 10 चैंपियन सेक्टर्स के लिए आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से जुड़े इंसेंटिव्स के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) -शहरों के लिए 18,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय
- निर्माण और अवसंरचना के लिए सहायता - सरकारी निविदाओं पर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) और प्रदर्शन सुरक्षा में छूट
- डेवलपर्स और घर खरीदने वालों के लिए आवासीय रियल एस्टेट आयकर राहत के लिए मांग बूस्टर
- इंफ्रा डेट फाइनेंसिंग के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये का प्लैटफॉर्म - 6000 करोड़ रुपये एनआईआईएफ डेट प्लेटफॉर्म में इक्विटी इन्फ्यूजन
- सब्सिडी वाले उर्वरकों के लिए कृषि को 65,000 करोड़ रुपये का समर्थन
- ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए - पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत बढ़ी हुई रूपरेखा
- मनरेगा को 2020-21 के बजट में 61,500 करोड़ रुपये प्रदान किए गए।

- प्रॉजेक्ट एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए -, आईडीईएएस योजना के तहत लाइन्स ऑफ क्रेडिट के माध्यम से परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए EXIM बैंक को 3,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग को भारतीय कोविड टीका के अनुसंधान और विकास के लिए कोविड सुरक्षा मिशन के लिए 900 करोड़ रुपये प्रदान किए गए'

पावर लाइनों के लिए आपातकालीन पुनर्प्राप्ति प्रणाली (ईआरएस)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - अर्थव्यवस्था

समाचार में

- हाल ही में ट्रांसमिशन लाइन टावरों की विफलता की स्थिति में बिजली संचरण की त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए एक स्वदेशी प्रौद्योगिकी, आपातकालीन पुनर्प्राप्ति प्रणाली (ईआरएस) विकसित की गई थी। ।
- विकसित: स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर (SERC), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की घटक प्रयोगशाला द्वारा

महत्वपूर्ण बिंदु

- वर्तमान में, ईआरएस सिस्टम आयातित हैं और लागत अपेक्षाकृत अधिक है।
- यह तकनीकी विकास भारत में पहली बार विनिर्माण को सक्षम करेगा, जो एक आयात विकल्प होगा।
- इसके अलावा, इसमें आयातित प्रणालियों के लगभग 40% खर्च होंगे।
- ईआरएस एक हल्का मॉड्यूलर सिस्टम है जिसका उपयोग चक्रवात / भूकंप, या मानव निर्मित व्यवधान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ट्रांसमिशन लाइन टावरों के पतन के तुरंत बाद बिजली को बहाल करने के लिए अस्थायी समर्थन संरचना के रूप में किया जाता है।
- यह संरचनात्मक रूप से अत्यधिक स्थिर बॉक्स अनुभागों से बना है।
- यह हल्का, मॉड्यूलर और पुन: प्रयोज्य है।
- इसे 2-3 दिनों में बिजली की बहाली के लिए आपदा स्थल पर जल्दी से इकट्ठा किया जा सकता है।

लिब्रेटेड इकोनॉमिक पैकेज (आत्माननिर्म्भरभारत 3.0) - भाग 2

- पैकेज के गुण
- पैकेज का उद्देश्य: विभिन्न वित्तीय गारंटी कार्यक्रमों की तरह, वित्तीय व्यय के आर्थिक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए उपाय तैयार किए गए हैं, जहां गारंटी द्वारा प्रवाहित प्रवाह संभावित राजकोषीय लागत से कई गुना अधिक है।
- खर्च को कैलिब्रेट किया जाता है, जैसा कि मनरेगा बजट के निरंतर विस्तार में देखा गया है, जिसे इसका दूसरा विस्तार मिला, यह देखते हुए कि पहले से विस्तारित बजट का तीन-चौथाई अक्टूबर तक उपयोग किया गया था।
- **भूख से निपटने के मुद्दे:** मुफ्त अनाज कार्यक्रम को नवंबर से आगे नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था अब कमोबेश पूरी तरह से खुली हुई है, और भूख को कम करने का जोखिम नि,निम्न है।

- **पीएलआई योजना की सफलता**: 10 नए क्षेत्रों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का विस्तार इस प्रकार हैंडसेट के लिए पीएलआई योजना की सफलता का परिणाम है। पीएलआई योजना आत्मनिर्भरता या आयात में कटौती के बारे में है, क्योंकि यह घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नकद प्रोत्साहन की पेशकश के बारे में है, जिससे रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।
- **तनाव सेक्टर्स को मान्यता दी गई:** पैकेज से सम्मानित क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए ऋण गारंटी योजना के विस्तार के माध्यम से ऋण योग्य धन की आपूर्ति का विस्तार होता है
- **रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा:** घर खरीदारों के लिए कर प्रोत्साहन संभावित रूप से अचल संपत्ति बाजार में एक मूल्य खोज को उजागर कर सकता है। रियल एस्टेट क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण गुणक प्रभाव डालता है, उच्च रोजगार सृजन क्षमता रखता है।
- **रोजगार को बढ़ावा देना:** भविष्य निधि अंशदान के लिए बिल की पेशकश करके, इसने बड़ी, छोटी कंपनियों को किराए पर देने के लिए तैयार किया है।
- **शहरी मनरेगा के लिए शहरी गरीब और मांग**: शहरी मनरेगा को साफ तौर पर लागू किया जा सकता है या नहीं, भले ही इसका असर ग्रामीण-शहरी प्रवास पर क्या होगा, भारत सरकार ने एक शार्प के माध्यम से इस समस्या को अप्रत्यक्ष रूप से लक्षित करने के लिए चुना है। शहरी किफायती आवास के लिए बजट में वृद्धि।

चिंता

- **बैंक उधार देने के लिए उत्साहित नहीं है:** मूल रूप से परिकल्पित क्रेडिट गारंटी योजना 3 ट्रिलियन के लक्ष्य संवितरण के साथ बैंकों द्वारा उधार ली जा रही राशि का लगभग आधे का प्रयोग किया गया है। इससे पता चलता है कि कम जोखिम के बावजूद, बैंक उधार देने के लिए असहज होते हैं।
- **भविष्य का जोखिम:** बैंकों को उन कंपनियों को ऋण देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जहां जोखिम का आकलन करना महामारी के कारण मुश्किल है।
- **मध्यम अवधि में इस प्रभाव महसूस किया जा सकता है:** 10 नए क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के रूप में 1,45,980 करोड़ रुपये का खर्च पांच साल से अधिक होगा, और अगले वित्तीय वर्ष में ही संभावित है

आगे का रास्ता

- सबसे पहले, इस वर्ष उधार लेने की आवश्यकता है, जिससे बांड बाजारों को कुछ राहत मिल सके।
- दूसरा, विशेष रूप से राज्य सरकारों द्वारा अतिदेय भुगतान को मंजूरी देना - उर्वरक बकाया कोसमाप्त करने का केंद्र का निर्णय सही दिशा में एक कदम है। यह खुद अर्थव्यवस्था को एक प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है।
- तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, राज्य और केंद्र सरकारों के लिए अगले वर्ष के बजट में एक प्रोत्साहन के रूप में निर्माण करना होगा।

निष्कर्ष

- पैकेज सरकार के 'राजकोषीय रूढ़िवाद' की विचारधारा को मजबूत करता है - बजाय बड़े नकद हस्तांतरण के।

- विकास दर्शन एक इकोसिस्टम बनाने के इर्द-गिर्द केंद्रित है जो घरेलू मांग को सहायता करता है, कंपनियों को रोजगार पैदा करने और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है, और साथ ही साथ गंभीर संकट में उन लोगों के लिए लाभ बढ़ाता है, जैसे कि यह फर्म या व्यक्ति

एशियाई अर्थव्यवस्थाओं का स्थानांतरण

- **संदर्भ:** महामा महामारी के बाद की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चाओं ने अक्सर भविष्यवाणी की है कि चीन की व्यावसायिक गंतव्य के रूप में अपील फीकी पड़ जाएगी, वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित होगा।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को साकार करने के बारे में क्या उम्मीद थी?

- **चीन से दूर उत्पादन स्थानों का फैलाव:** तर्क दिया गया है कि उत्पादन अन्य आकर्षक स्थानों में फैलाया जाएगा, और यहां तक कि बाहर के लोगों के लिए भी।
- **श्रम के लिए बदलाव प्रचुर मात्रा में अर्थव्यवस्था को लाभ:** यह उम्मीद थी कि उत्पादन के इस स्थानांतरण से उभरती हुई श्रम-प्रचुर अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा, क्योंकि चीन में श्रम लागत बढ़ रही है।
- **चीन + 1 रणनीति:** व्यापार युद्ध और COVID-19 संकट के संयोजन के परिणामस्वरूप कंपनियों ने अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर संचालन कहीं और स्थापित किया है। इसे चीन पर पूरी तरह से निर्भर होने के विरुद्ध एक बफर के रूप में माना जाता है, जिसे 'चाइना +1' रणनीति के रूप में जाना जाता है।
- कुछ श्रम-गहन उद्योग, जैसे कपड़ा बांग्लादेश और श्रीलंका में जा रहे हैं, लेकिन अन्य उद्योगों में रुझान बताते हैं कि व्यवसाय ज्यादातर चीन में बने हुए हैं।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला या ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन अभी भी प्रभुत्व क्यों बरकरार रखे हुए है?

- फर्मों के चीन में बने रहने के तीन कारण हैं लेकिन चीन + 1 की रणनीति को विफल करना चाहता है:
- **चीन में व्यापार में आसानी:** सबसे पहले, एक उद्यम शुरू करना और चीन में संचालन को बनाए रखना कहीं और से बहुत आसान है।
- **चपलता:** दूसरा, चीनी फर्म फुर्तीला और तेज हैं, जो लॉकडाउन के बाद चीनी विनिर्माण की त्वरित वसूली से स्पष्ट है।
- **उत्पादन केंद्रों को स्थानांतरित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है:** तीसरा, कई वैश्विक कंपनियों ने चीन में दशकों से आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण किया है। इसलिए, बाहर निकलने का मतलब होगा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें समय और खर्च शामिल है।

वैश्विक फर्मों की इस चीन + 1 रणनीति ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के तेज होने का कारण बना है कि उभरते हुए विनिर्माण परिदृश्य में 'प्लस वन'। इस दौड़ में भारत के सामने तीन चुनौतियां हैं।

1. **घरेलू सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने का कार्य**
2. **भारत को व्यापार नीति में ओवरहाल की जरूरत है**

3. श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- प्रतियोगिता की तीव्रता इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारत द्वारा 23 सितंबर को तीन श्रम संहिता विधेयकों को पारित करने के बाद, 5 अक्टूबर को इंडोनेशियाई संसद ने एक कानून पारित किया था जिसमें देश को और अधिक विदेशी खोलने के लिए 70 से अधिक अलग-अलग मौजूदा कानूनों में निहित विनियम शामिल थे।
- बदले हुए परिदृश्य के लिए भारत के दृष्टिकोण को अच्छी तरह से कैलिब्रेट किया जाना चाहिए।

Connecting the dots

- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल

GIS वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) भारत का डिजिटल मैप

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - अर्थव्यवस्था

समाचार में

- खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने भारत के जीआईएस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) डिजिटल मैप को लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- डिजिटल ODOP मानचित्र सभी राज्यों को ODOP उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है और हितधारकों को सुविधा प्रदान करता है।
- डिजिटल मैप में आदिवासी, एससी, एसटी, और आकांक्षात्मक जिलों के लिए संकेतक भी हैं।
- यह हितधारकों को इसके मूल्य श्रृंखला विकास के लिए ठोस प्रयास करने में सक्षम करेगा।

लक्ष्मी विलास बैंक (LVB) संकट

संदर्भ: आईएल एंड एफएस, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक और डीएचएफएल की विफलता और यस बैंक की खैरात के बाद, आरबीआई ने अब लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (LVB) पर 30-दिवसीय स्थगन लगाने का फैसला किया है।

आरबीआई ने सिंगापुर के डीबीएस की सहायक कंपनी डीबीएस बैंक इंडिया के साथ LVB के समामेलन के लिए एक मसौदा योजना भी रखी है और वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।

एलवीबी को स्थगन के तहत क्यों रखा गया और डीबीएस बैंक के साथ समामेलित किया गया?

- **लगातार नुकसान:** RBI ने कहा कि चेन्नई स्थित LVB की वित्तीय स्थिति, जिसमें 563 शाखाओं का नेटवर्क है और 20,973 करोड़ रुपये जमा हैं, ने पिछले तीन वर्षों में बैंक के जाल को खत्म करने के साथ लगातार घाटे में रहा है, LVB ने वित्त वर्ष 2011 की सितंबर तिमाही में 397 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जबकि जून तिमाही में 112 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।
- **बढ़ता एनपीए:** हाल के वर्षों में गंभीर सरकारी मुद्दों ने इसके प्रदर्शन में गिरावट का कारण बना है। बैंक की अग्रिम में से एक चौथाई ने खराब संपत्ति को बदल दिया है। इसकी सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) जून 2020 तक इसकी अग्रिम संख्या का 25.4% थी, जबकि एक साल पहले यह 17.3% थी।
- **कम तरलता:** यह जमा की निरंतर निकासी और तरलता के निम्न स्तर का भी अनुभव कर रहा था।
- **पूंजी जुटाने में असमर्थ:** बैंक इन मुद्दों को हल करने के लिए पर्याप्त पूंजी जुटाने में सक्षम नहीं है। बैंक प्रबंधन ने आरबीआई को संकेत दिया था कि वह कुछ निवेशकों के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन कोई ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विफल रहा

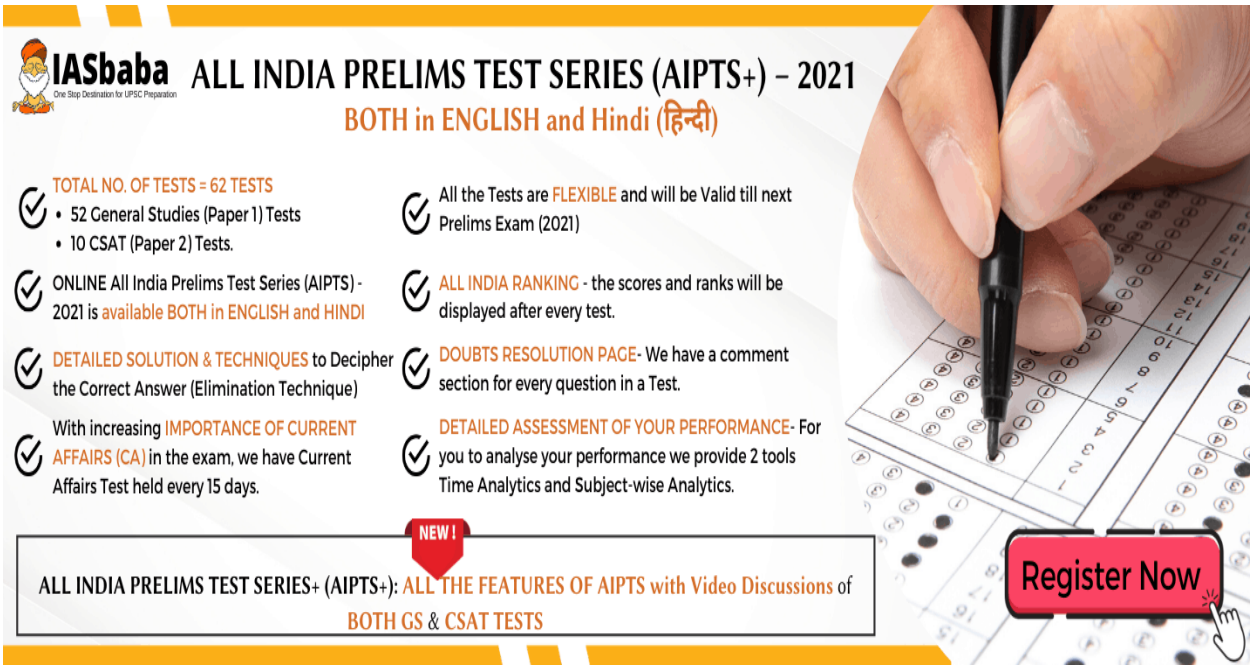

कृषि

केसर के कटोरे (Saffron bowl) का जल्द ही नॉर्थ ईस्ट का विस्तार किया जायेगा

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - I - भूगोल और GS - III - कृषि

समाचार में

- केसर का कटोरा, जो अब तक कश्मीर तक ही सीमित था, जल्द ही इसका विस्तार भारत के उत्तर पूर्व हो सकता है।
- जिन पौधों को कश्मीर से सिक्किम ले जाया गया था, वे वहां जम गए है और अब सिक्किम के दक्षिणी भाग में स्थित यंगयांग में केसर के फूल आ रहे हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- केसर उत्पादन लंबे समय तक J&K के केंद्र शासित प्रदेश में एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा है।
- हालांकि नेशनल मिशन ऑन केसर ने अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए कई उपायों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उपाय अभी भी कश्मीर के निर्दिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित थे।
- नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन और रीच (NECTAR), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय, भारत सरकार ने एक ही गुणवत्ता के साथ, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में बढ़ते केसर की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक पायलट परियोजना का समर्थन किया।
- सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान और बागवानी विभाग ने सिक्किम के यंगयांग की मिट्टी और वास्तविक पीएच स्थितियों को समझने के लिए परीक्षण किए और इसे कश्मीर के केसर के समान पाया।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

केसर

- यह एक पौधा है जिसके सूखे कलंक(dried stigmas) (फूल के धागे जैसे भाग) का उपयोग केसर का मसाला बनाने के लिए किया जाता है।
- माना जाता है कि केसर की खेती का आरंभ कश्मीर में मध्य एशियाई प्रवासियों द्वारा पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था।
- यह जम्मू और कश्मीर क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह एक बहुत ही कीमती और महंगा उत्पाद है।
- इसे प्राचीन संस्कृत साहित्य में "बहुकम" कहा जाता है।
- जम्मू-कश्मीर के करेवा (उच्चभूमि) में इसकी खेती और कटाई की जाती है।

- **उपयोग:** (1) यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है; (2) इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में और औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- आमतौर पर जून और जुलाई के दौरान और अगस्त और सितंबर में कुछ स्थानों पर इसकी खेती की जाती है।
- केसर समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर अच्छी तरह से बढ़ता है।
- इसे 12 घंटे की धूप की जरूरत होती है।
- यह कई अलग-अलग मिट्टी के प्रकारों में बढ़ता है लेकिन कैलकेरस (मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में होता है), 6 और 8 के बीच पीएच के साथ धरण युक्त और अच्छी तरह से सूखी मृदा में सबसे अच्छे से पनपता है।
- तापमान - गर्मियों में 35 या 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर सर्दियों में लगभग -15 या -20 डिग्री सेल्सियस तक।
- इसमें पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है - प्रति वर्ष 1000-1500 तक।

क्या आप जानते है?

- भारत में पंपोर क्षेत्र, जिसे आमतौर पर कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है, केसर उत्पादन में मुख्य योगदान देता है, इसके बाद बडगाम, श्रीनगर और किश्तीवार जिले आते हैं।

पर्यावरण/ प्रदूषण

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)

संदर्भ: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग गठित करने के लिए एक अध्यादेश को अधिसूचित किया है।

अध्यादेश के प्रमुख बिंदु

- **अति सक्रीय संस्था के रूप में:** सीएक्यूएम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), और साथ ही वायु प्रदूषण के मामले में राज्य सरकारों सहित सभी मौजूदा निकायों को सुपरसीड करेगा।
- **EPCA का उन्मूलन:** अध्यादेश के माध्यम से, केंद्र ने NCR के लिए पर्यावरण प्रदूषण निवारण और नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) को भंग कर दिया है।
- **एनजीटी की भूमिका:** केवल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), और सिविल कोर्ट नहीं, उन मामलों की सुनवाई के लिए अधिकृत हैं जहां आयोग शामिल है।

पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) क्या है?

- ईपीसीए का गठन 1998 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में किया गया था।
- इसमें पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति, प्रतिनिधि निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करने की शक्ति है।
- यह वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने, ईंधन गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने, यातायात योजना और प्रबंधन के लिए निगरानी और समन्वय कार्रवाई के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता है।

CAQM की रचना

- **ताकत:** नया 18 सदस्यीय आयोग एक सहयोगी मंच पर केंद्र, राज्यों और अन्य हितधारकों को एक साथ लाता है।
- **चेयरपर्सन:** इसमें एक पूर्णकालिक चेयरपर्सन होगा "जो भारत सरकार का सचिव या राज्य सरकार का मुख्य सचिव हो"। चेयरपर्सन तीन साल या जब तक एस / वह 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक पद संभालेगा।
- **राज्य के प्रतिनिधि:** आयोग में पांच पूर्व अधिकारी भी होंगे जो या तो मुख्य सचिव, या सचिव हैं जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभाग के प्रभारी हैं।

- **विशेषज्ञ:** "वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों में विशिष्ट वैज्ञानिक ज्ञान और अनुभव" के साथ तीन पूर्णकालिक स्वतंत्र तकनीकी सदस्य; CPCB से प्रत्येक तकनीकी सदस्य और ISRO द्वारा नामित, पदेन सदस्य।
- **सिविल सोसाइटी:** वायु प्रदूषण से निपटने के अनुभव वाले गैर सरकारी संगठनों के तीन प्रतिनिधि
- **अन्य:** इसमें Niti Aayog और कई मंत्रालयों के सदस्य शामिल होंगे

CAQM की आवश्यकता क्यों थी?

- **एकल निकाय की आवश्यकता:** दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की निगरानी और प्रबंधन अभी तक कई निकायों जैसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों सहित सीपीसीबी सहित कई निकायों द्वारा किया गया है।
- **समग्र दृष्टिकोण:** दिल्ली में वायु प्रदूषण के साथ समस्या यह है कि प्रदूषण का स्रोत कहीं और निहित है - यही कारण है कि विभिन्न निकायों द्वारा उठाए गए दृष्टिकोण के बजाय, पूरे क्षेत्र से निपटना महत्वपूर्ण है
- **अधिक शक्तियां:** ईपीसीए एक वैधानिक निकाय नहीं था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय (एम सी मेहता बनाम भारत संघ, 1988) से वैधता प्राप्त की। इसके पास अन्य राज्यों में सरकारों को जुर्माना या निर्देश और दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार था।
- **पिछले तंत्र की विफलता:** विशेषज्ञों का कहना है कि ईपीसीए 20 से अधिक वर्षों से लागू होने के बाद भी हवा को साफ करने में बुरी तरह विफल रहा है। ग्राउंड कार्यान्वयन और प्रदूषकों पर सख्त कार्रवाई की स्थिति में **CAQM** के सुधार की स्थिति में बदलाव का अनुमान लगाया जाएगा।

CAQM की मेरिट

- **प्रदूषण से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र:** स्थायी आयोग प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए एक बहु-क्षेत्रीय, सार्वजनिक भागीदारी, बहु-राज्य गतिशील निकाय की परिकल्पना करता है और वैधानिक स्थिति के साथ निकाय युद्ध स्तर पर प्रदूषण से निपट सकता है।
- **अधिक विविधता:** अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन के बारे में आयोग के निर्देशों का पालन करने के लिए राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी होगा। इसमें कमजोर क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रतिबंधित करने की शक्तियां भी होंगी, और यह औद्योगिक इकाइयों के स्थल निरीक्षण करने में सक्षम होंगे।
- **दंड शक्तियां:** गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना पांच साल तक कारावास या 1 करोड़ तक का जुर्माना होगा, या दोनों।
- **सुप्रीम कोर्ट को राहत देता है:** केंद्र सुप्रीम कोर्ट को प्रदूषण से संबंधित विभिन्न मामलों के माध्यम से लगातार प्रदूषण के स्तर की निगरानी करने से राहत देना चाहता है।

आलोचनाओं

- **अलोकतांत्रिक प्रक्रिया:** यह आलोचना की गई है कि अध्यादेश राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बिना पारित किया गया था।

- **दृष्टिकोण पर संदेह:** यह अनिश्चित है कि सीएक्यूएम (तीसरे पक्ष की निगरानी और नागरिक-संचालित प्रवर्तन के बिना) के माध्यम से शीर्ष-डाउन कार्यान्वयन दृष्टिकोण काम करेगा या नहीं।
- **अपर्याप्त लक्ष्य:** हवा को साफ करने के लिए समयबद्ध प्रतिबद्धता की कमी भी है।
- **केंद्र सरकार की अधिकता:** आयोग के पास केंद्र सरकार के सदस्यों की एक बड़ी संख्या है, जो राज्यों के साथ अच्छी तरह से नहीं चली है। दूसरी ओर, राज्यों में सिर्फ एक सदस्य होगा।

निष्कर्ष

जबकि **CAQM** का स्वागत है, यह अकेले हवा को साफ नहीं कर सकता है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह विभिन्न ब्याज समूहों से कैसे निपटता है; निर्धारित मानकों को प्राप्त करने के लिए एक समयबद्ध प्रतिबद्धता की रूपरेखा; प्रदूषण नियंत्रण निकायों के लिए पर्याप्त कर्मी और धन सुनिश्चित करता है।

गंगा उत्सव 2020

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - I - संस्कृति और GS- III - पर्यावरण

समाचार में

- हाल ही में, गंगा उत्सव 2020 की शुरुआत हुई है।
- यह राष्ट्रीय नदी गंगा की महिमा को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 4 नवंबर को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के उपलक्ष्य में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) द्वारा सभी हितधारकों की सहभागिता को बढ़ावा देने और गंगा ज्ञान केंद्र के तत्वावधान में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर साल इस दिवस को उत्सव के रूप में मनाता रहा है।
- **उद्देश्य:** हितधारक को बढ़ावा देना और सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना।
- यह उत्सव युवा पीढ़ी को उसके प्राचीन इतिहास और सांस्कृतिक महत्व से अवगत कराने के उद्देश्य आयोजित किया जाता है, ताकि वे नदियों को न केवल पानी के स्रोत के रूप में बल्कि हमारी सभ्यता के अभिन्न अंग के रूप में प्रतिष्ठित कर सके।
- गंगा टास्क फोर्स (जीटीएफ) ने राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) कैडेट और युवाओं के लिए शैक्षिक दौरे के साथ वनीकरण अभियान भी चलाया गया।
- मिनी गंगा क्वेस्ट भी आयोजित किया गया था जो युवाओं और छात्रों को पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूक करने और संरक्षण में उनकी भूमिका को समझाने के लिए बनाया गया था।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

गंगा नदी

- यह भारत की सबसे लंबी नदी है।
- यह हिंदुओं द्वारा पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी के रूप में प्रतिष्ठित है।
- यह हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी के रूप में उत्पन्न होती है।

- गंगा नदी बेसिन दुनिया के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है।
- गंगा नदी डॉल्फिन, एक लुप्तप्राय जानवर, विशेष रूप से इस नदी में निवास करती है।
- यह बंगाल की खाड़ी में खाली होकर अपनी यात्रा समाप्त करता है।
- गंगा को **4** नवंबर **2008** को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था।

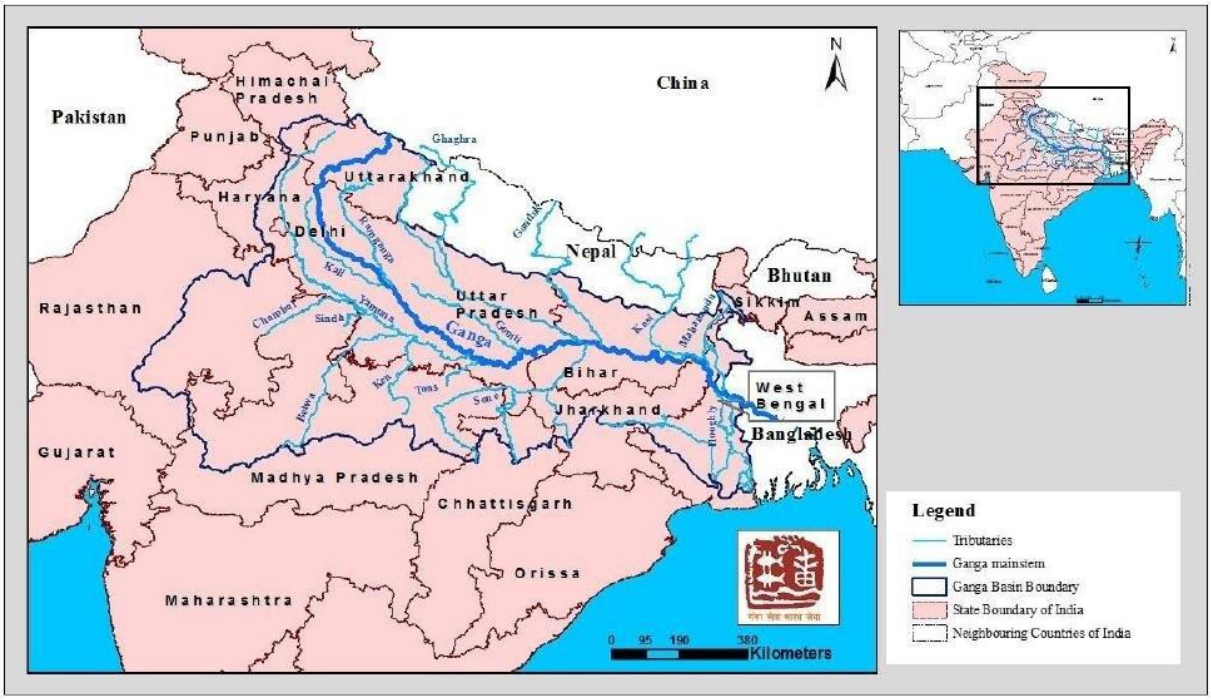

दिल्ली में वायु की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - प्रदूषण

समाचार में

- दिल्ली में वायु की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है।
- सिस्टम ऑफ़ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, SAFAR ने लोगों को सभी शारीरिक गतिविधियों से बचने की सलाह दी है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (SAFAR)

- स्वदेशी रूप से विकसित: भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे द्वारा
- भारत के मौसम विभाग (IMD) द्वारा चलाया जा रहे हैं।

- उद्देश्य: (1) 72 घंटे के अग्रिम मौसम पूर्वानुमान के साथ रंग कोडिंग के साथ 24x7 आधार पर वास्तविक समय की वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रदान करना; (2) नागरिकों को पहले से तैयार करने के लिए स्वास्थ्य सलाहकार जारी करना।
- निगरानी: प्रदूषक: PM1, PM2.5, PM10, ओजोन, CO, NOx (NO, NO2), SO2, BC, मीथेन (CH4), गैर-मीथेन हाइड्रोकार्बन (NMHC), ब्लैक कार्बन, VOC's, बेंजीन और मरकरी ।
- मौसम संबंधी पैरामीटर: यूवी विकिरण, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति, हवा की दिशा, सौर विकिरण।

ट्रिस्टन दा कुन्हा (Tristan da Cunha) ने अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा पूरी तरह से संरक्षित समुद्री भंडार घोषित किया

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - जैव विविधता

समाचार में

- ट्रिस्टन दा कुन्हा को अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा पूरी तरह से संरक्षित समुद्री भंडार घोषित किया गया था।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

ट्रिस्टन दा कुन्हा

- यह दुनिया की सबसे दूरस्थ मानव बस्ती है।
- यह ब्रिटेन का एक पार द्वीपीय क्षेत्र भी है।
- यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में ज्वालामुखी द्वीपों का एक दूरस्थ समूह है।
- इसका अपना संविधान है।
- यह लाखों समुद्री पक्षी और कई अद्वितीय भूमि पक्षियों का आवास भी है।
- यह विश्व धरोहर स्थल गफ (Gough) और दुर्गम द्वीपों का भी आवस है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री द्वीपों में से एक है।

क्या आप जानते हैं?

- यूके के ब्लू बेल्ट कार्यक्रम में शामिल होने के बाद, यह अटलांटिक में सबसे बड़ा नो-टेक ज़ोन और ग्रह पर चौथा सबसे बड़ा क्षेत्र बन जाएगा।

- इसका मतलब है कि मछली पकड़ने, खनन और ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यह 90% से अधिक पानी को हानिकारक गतिविधियों जैसे कि नीचे की ओर मछली पकड़ने, रेत निकालने और गहरे समुद्र में खनन करने के लिए इसे बंद कर देगा।

भारत ने दो नवीन रामसर साइटों को शामिल किया

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - पर्यावरण

समाचार में

- भारत ने हाल ही में दो और रामसर साइटों को इस सूची में जोड़ा है।
- एक महाराष्ट्र में लोनेरलेक है जो भारत की एकमात्र स्व निर्मित झील है।
- दूसरा सुर सरोवर है, जिसे आगरा, उत्तर प्रदेश में केथम झील के नाम से भी जाना जाता है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

रामसर कन्वेंशन

- इसे 2 फरवरी, 1971 को हस्ताक्षरित किया गया था।
- यह सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित सबसे पुराने अंतर-सरकारी समझौते में से एक है।
- उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उनके आर्द्र क्षेत्रों के पारिस्थितिक चरित्र को संरक्षित करना।
- इसका नाम ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया है, जहां संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- इसके अंतर्गत संरक्षण के लिए चुनी गई जगहों को 'रामसर साइट' का टैग दिया गया है।
- रामसर सूची का उद्देश्य: आर्द्रभूमि के एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना और बनाए रखना जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और उनके पारिस्थितिक तंत्र के घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के रखरखाव के माध्यम से मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

क्या आप जानते है ?

- हाल ही में, बिहार के बेगूसराय जिले में काबरताल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई थी।
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, रामसर कन्वेंशन के तहत यह राज्य का पहला ऐसा वेटलैंड है।
- देहरादून में आसन संरक्षण रिजर्व, रामसर सम्मेलन द्वारा मान्यता प्राप्त उत्तराखंड का पहला वेटलैंड इस साल अक्टूबर में सूची में जोड़ा गया था।

भारत की प्रथम हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - पर्यावरण

समाचार में

- ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL), बिजली और नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (DNRE), गोवा के मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रमों के एक संयुक्त उद्यम ने राज्य में भारत की प्रथम हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- एमओयू के तहत, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) और DNRE व्यवहार्यता अध्ययन और उसके बाद विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन करेंगे।
- EESL सौर ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करेगा; (1) कृषि पंपिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सरकारी जमीनों पर 100 मेगावाट विकेंद्रीकृत जमीन पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना; (2) बीईई स्टार रेटेड ऊर्जा कुशल पंपों के साथ लगभग 6,300 कृषि पंपों की जगह; (3) ग्रामीण घरेलू परिवारों के लिए लगभग 16 लाख एलईडी बल्ब वितरित करना।
- परियोजनाएँ अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में तेजी लाएगी, विशेष रूप से राज्य में कृषि और ग्रामीण बिजली की खपत के लिए।

डीम्ड वनों को समाप्त करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा पहल

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III – पर्यावरण

समाचार में

- हाल ही में, कर्नाटक के वन मंत्री ने घोषणा की कर्नाटक राज्य सरकार जल्द ही राज्य में 9.94 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले डीम्ड वनों के 6.64 लाख हेक्टेयर(लगभग 67%) हिस्से को विवर्गीकृत (Declassified) कर राजस्व अधिकारियों को सौंप देगी।
- वनों का मुद्दा कर्नाटक में एक विवादास्पद विषय है, विधायकों के साथ अक्सर आरोप लगाया जाता है कि बड़ी मात्रा में कृषि और गैर-वन भूमि "अवैज्ञानिक" रूप से वर्गीकृत हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 सहित किसी भी कानून में डीम्ड वनों की अवधारणा को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।हालांकि टी एन गोडवर्मन थिरुमलपाद (1996) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम के तहत वनों की एक विस्तृत परिभाषा को स्वीकार किया।
- 'शब्द' वन 'को इसके शब्दकोश अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए।
- यह परिभाषा वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त सभी जंगलों को शामिल करती है, चाहे वे वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (1) के उद्देश्य के लिये आरक्षित, संरक्षित या अन्यथा नामित हों।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, धारा 2 में शामिल 'वन भूमि' शब्द के तहत न केवल जंगल शामिल होगा जैसा कि शब्दकोष में समझा जाता है, बल्कि स्वामित्व के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में दर्ज क्षेत्र भी इस परिभाषा में शामिल होंगे।
- वन और संबंधित मामलों के संरक्षण के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किए गए प्रावधान सभी जंगलों में स्पष्ट रूप से लागू होने चाहिए।

रोरिडो माइसेस फाइलोस्टैचिडिस (Roridomyces Phyllostachydis) -चमकने वाले मशरूम (Bioluminescent Mushroom)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - जैव विविधता

समाचार में

पूर्वोत्तर भारत के जंगलों में एक मशरूम प्रलेखन परियोजना ने एक नई प्रजाति की खोज की है: इस चमकने वाले मशरूम (Bioluminescent Mushroom) की प्रजाति को वैज्ञानिकों ने रोरिडो माइसेस फाइलोस्टैचिडिस (Roridomyces Phyllostachydis) नाम दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- वैज्ञानिकों ने मेघालय के जंगलों में एक चमकने वाली मशरूम प्रजाति की खोज की है।
- वैज्ञानिकों ने इस चमकने वाले मशरूम (Bioluminescent Mushroom) को रोरिडो माइसेस फाइलोस्टैचिडिस (Roridomyces Phyllostachydis) नाम दिया है।
- दिन में यह किसी भी साधारण मशरूम की तरह दिखाई पड़ता है, लेकिन अंधेरा होने पर यह नीली-हरी रोशनी उत्सर्जित करता है।
- रात में अपनी इस हरी-नीली आभा के कारण यह दूर से ही पहचाना जा सकता है।
- मेघालय के स्थानीय लोग इसे इलेक्ट्रिक मशरूम के नाम से जानते हैं।
- इस मशरूम की खोज असम के एक एन.जी.ओ. और चाइनीज एकेडेमी ऑफ साइंसेज के शोधकर्ताओं ने मिलकर की है।
- ये दोनों संस्थाएं भारत के पूर्वोत्तर-राज्यों मेघालय, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में फफूंदीय जैव विविधता पर काम कर रहे थे।
- विश्वभर में अब तक जैविक रूप में प्रकाश उत्सर्जक (Bioluminescent) मशरूमों की 96 प्रजातियां ज्ञात थीं, मेघालय में खोजी गई यह नई प्रजाति 97वीं इस प्रकार की नस्ल है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- कुछ पशु, पौधे, कवक और बैक्टीरिया बायोलुमिनसेंस को दर्शाते हैं।
- बायोलुमिनसेंट जीव आमतौर पर समुद्र के वातावरण में पाए जाते हैं, लेकिन वे स्थलीय वातावरण पर भी पाए जाते हैं।
- जीव द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग उनके रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है।
- कवक के मामले में, ल्यूमिनेसेंस एंजाइम, ल्यूसिफरेज से आता है।

भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - पर्यावरण

समाचार में

- हाल ही में भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया था।
- इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इस पोर्टल में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सरकार द्वारा उठाए जा रहे सभी कदम प्रमुख होंगे।
- यह एकल-बिंदु सूचना संसाधन होगा जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की गई विभिन्न जलवायु पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता इन पहलों में अद्यतन स्थिति तक पहुँच बना सके।
- केंद्र सरकार के अनुसार, भारत ने व्यावहारिक रूप से 2020 से पहले के जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को हासिल कर लिया है।

'ब्लू टाइड' परिघटना को महाराष्ट्र में देखा गया

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - पर्यावरण; विज्ञान

समाचार में

- पिछले कुछ दिनों में, महाराष्ट्र के कुछ बीच पर समुद्री-ज्वार के कारण उत्पन्न हुई 'नीली रोशनी' देखी गई जिसे 'ब्लू टाइड' परिघटना कहते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस घटना को 'ब्लू टाइड' कहा जाता है।
- ऐसा प्रतीत होता है जब ल्यूमिनेसेंट समुद्री जीवन समुद्र को नीले रंग की एक गहरी छाया बनती है।
- यह तब होता है जब फाइटोप्लांकटन (सूक्ष्म समुद्री पौधे), जिन्हें आमतौर पर डिनोफ्लैगलेट्स के रूप में जाना जाता है, प्रोटीन में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जब डाइनोफ्लैगलेट्स/फाइटोप्लैंगटन्स (माइक्रोस्कोपिक मरीन प्लांट्स) प्रोटीन्स में रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान प्रकाश उत्पन्न करते हैं तब यह परिघटना घटित होती है।
- लहरें इन यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गनिज़्म्स (एककोशिकीय सूक्ष्मजीव) को अशांत करती हैं जिससे नीली रोशनी निकलती है।

क्या आप जानते है?

- Bioluminescence प्रकाश उत्पन्न करने और उत्सर्जित करने के लिए एक जीवित जीव की संपत्ति है।
- पशु, पौधे, कवक और बैक्टीरिया बायोलुमिनसेंस को दर्शाते हैं।
- समुद्री जानवरों और रोगाणुओं की एक उल्लेखनीय विविधता अपने स्वयं के प्रकाश का उत्पादन करने में सक्षम है।

- यह कई समुद्री जीवों जैसे बैक्टीरिया, शैवाल, जेलिफ़िश, कीड़े, क्रस्टेशियंस, समुद्री सितारों, मछली और शार्क में पाया जाता है।
- आम तौर पर गहरे जल में रहने वाले और उथले प्रजातियों की तुलना में प्लवक के जीवों में ल्यूमिनेंस अधिक होता है।
- यह एक पूर्व-विरोधी प्रतिक्रिया है।
- Bioluminescence को शिकारियों को चौंका देने वाला माना जाता है।

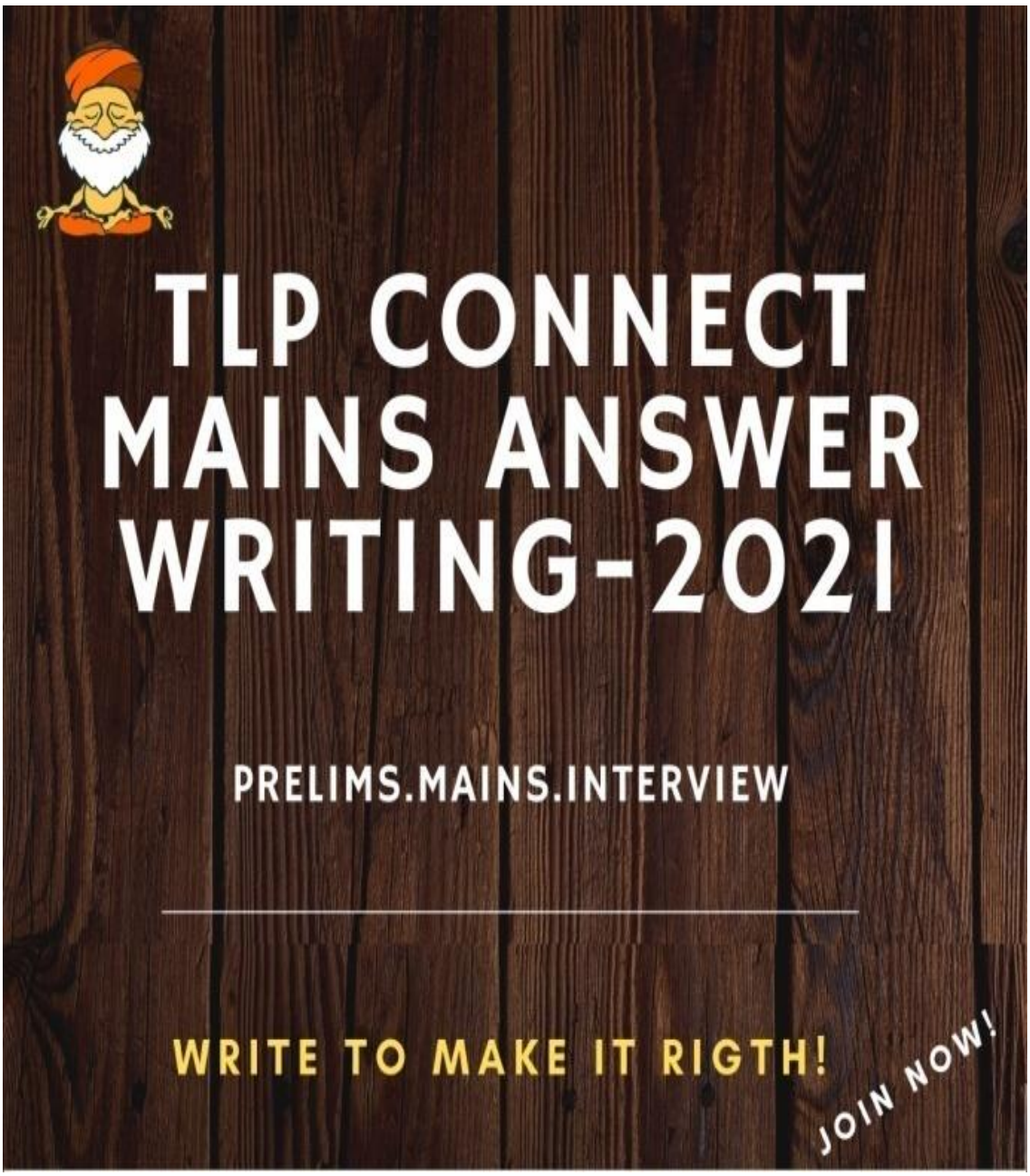

समाचारों में जंतु / रास्ट्रीय उद्यान

डेनमार्क के फॉर्मों में पल रहे मिंक या ऊदबिलाव के जरिए मनुष्यों में कोरोना वायरस (SARS-CoV-2) फैलने की पुष्टि की गई है।

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - जैव विविधता

समाचार में

- डेनमार्क, जिसने COVID-19 के 55,000 से अधिक मामले दर्ज किए हैं, इनमें SARS-CoV-2 वेरिएंट से संक्रमित 200 से अधिक मानव मामलों को भी दर्ज किया है जो कि डेनमार्क के फॉर्मों में पल रहे मिंक या ऊदबिलाव से सम्बंधित हैं।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

मिंक (ऊदबिलाव)

- ये गहरे रंग के, अर्धवृत्ताकार, मांसाहारी स्तनधारी होते हैं।
- प्रजाति: नेओविसन और मुस्टेला (Neovison and Mustela)।
- परिवार: मस्टेलिडे(Mustelidae)।
- इस परिवार में वेसल्स, ओटर और फेरेट्स भी शामिल हैं।
- दो विलुप्त प्रजातियां हैं जिन्हें "मिंक" कहा जाता है: अमेरिकी मिंक और यूरोपीय मिंक।
- यूरोपीय मिंक को आईयूसीएन द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ताकि संख्या में कमी न हो।

क्या आप जानते है?

- डेनमार्क दुनिया का सबसे बड़ा मिंक उत्पादक देश है, जिसकी 15-17 मिलियन मिंक आबादी को 1100 फर्मों में उत्पादित किया जाता है।

अंडमान में मेंढक की नई प्रजाति मिली

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - जैव विविधता

समाचार में

- हाल ही में वैज्ञानिकों के एक समूह ने स्ट्रिप्ड बबल-नेस्ट मेंढक नामक अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर भारत में पेडों पर रहने वाले मेंढक की नई प्रजाति का पता चला है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

धारीदार बबल-घोंसला मेंढक (Striped Bubble-nest frog)

- जैविक नाम: रोहनिक्सलस विट्टैटस (Rohanixalus vittatus)
- यह ओल्ड वर्ल्ड ट्रीफ्रॉग परिवार राकोफोराइडे की प्रजाति से संबंधित है।
- यह अंडमान द्वीप से पेडों पर रहने वाले मेंढक की पहली रिपोर्ट है।
- उन्हें एशियाई ग्लास मेंढक के रूप में भी जाना जाता है।
- इस मेंढक को अब तक शायद इसलिए नहीं देखा जा सका क्योंकि यह वर्ष के अधिकतर समय गुप्त जीवनशैली जीता है और प्रजनन के लिए बेहद कम समय के लिए बाहर निकलता है।"
- इस प्रजाति के नर मेंढक कीट-पतंगों जैसी कंपकंपाने वाली आवाज से मादा को बुलाते हैं। यह ध्वनि कीट-पतंगों के कोरस से निकलने वाली आवाज की तरह होती है। नर मेंढक आमतौर पर उथले पानी के पोखर के आसपास घास की पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं।
- इस मेंढक के पार्श्व भाग में आंखों की संरचना जैसे काले धब्बे होते हैं। नर मेंढक शरीर के पिछले भाग को उठाकर कमर पर मौजूद इन धब्बों को प्रदर्शित करते हैं। इन मेंढकों में इस तरह का व्यवहार उस वक्त देखा गया है, जब वे परेशान होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये धब्बे शिकारियों के खिलाफ रक्षात्मक भूमिका निभाते हैं।
- जीवों के आश्रय स्थलों के नष्ट होने के कारण उभयचर प्रजातियां भी विलुप्ति से जुड़े खतरों का सामना कर रही हैं। इस नये मेंढक के आवास संबंधी जरूरतों और इसके वितरण के दायरे के बारे में अभी

सीमित जानकारी है। इसलिए, इस मेंढक से संबंधित स्थलों को संरक्षित किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रजाति को बचाया जा सके।

विलो वॉर्ब्लर को भारत में पहली बार देखा गया

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - जैव विविधता

समाचार में

- हाल ही में, केरल के विलोय-पुंचकरी धान के खेतों में विलो वॉर्ब्लर को पहली बार भारत में देखा गया है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

विलो वॉर्ब्लर

- वैज्ञानिक नाम: Phylloscopustrochilus।
- वे पूरे उत्तरी और समशीतोष्ण यूरोप और पलेर्क्टिक में प्रजनन करते हैं।
- वे प्रारंभिक सर्दियों के दौरान उप-सहारा अफ्रीका में जाते हैं।
- यह छोटे पक्षियों में सबसे लंबे समय तक प्रवास करने वालों में से एक है।
- इसका वजन लगभग 10 ग्राम है और इसके लंबे पंख, लंबी दूरी तक उड़ान भरने में मदद करते हैं।
- साल में दो बार छोटे आकार और चिड़िया के पर या पंख में बदलाव के कारण वॉर्ब्लर की पहचान करना आमतौर पर मुश्किल होता है।
- खतरा: (1) इसके शीतकालीन तिमाहियों में सूखे की स्थिति; (2) मानव जनसंख्या विस्तार के कारण पर्यावास परिवर्तन।
- IUCN लाल सूची स्थिति: कम चिंताजनक।

क्या आप जानते है ?

- पलेर्क्टिक इकोज़ोन पृथ्वी की 8 इकोज़ोन में से एक है और यह हिमालय के उत्तर में एशिया को पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों और सहारा के उत्तर में पूर्वी एशिया और अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों के साथ कवर करता है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर / ऊर्जा

जल एयरोड्रम और सी-प्लेन सेवा का उद्घाटन किया (Water Aerodrome and Sea-Plane service inaugurated)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- भारत के प्रधान मंत्री ने केवडिया में वाटर एरोड्रोम और अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट के साथ केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाले सी-प्लेन सेवा का उद्घाटन किया।
- उन्होंने साबरमती रिवरफ्रंट में वाटर एरोड्रोम और साबरमती रिवरफ्रंट से केवडिया तक सीप्लेन सेवा का भी उद्घाटन किया।

क्या आप जानते है?

- एक वाटर एयरोड्रम या सीप्लेन बेस खुले पानी का एक ऐसा क्षेत्र होता है, जिसका उपयोग सीप्लेन, फ्लोट-प्लेन और एम्फीबियस विमानों द्वारा लैंडिंग और टेक ऑफ के लिये किया जाता है।
- अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट, नर्मदा जिले के केवडिया में सरदार सरोवर बांध, भावनगर जिले के पालीताना में शतरुंजी बांध और मेहसाणा जिले के धौरी बांध में वाटर एयरोड्रम की योजना बनायी गयी थी।
- साबरमती और सरदार सरोवर - स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मार्ग देश में पहचाने गये 16 सीप्लेन मार्गों में शामिल हैं। सरकार के अनुसार इस मार्ग के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरे हो चुके थे।
- मंडाविया ने कहा कि इस सेवा के शुभारंभ के बाद गुवाहाटी, अंडमान निकोबार और यमुना से उत्तराखंड में टप्पर बांध सहित विभिन्न मार्गों पर नियमित सेवा की योजना बनायी गयी है।

हिमालय के टेक्टोनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- हाल ही में, देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (WIHG) के वैज्ञानिकों के एक समूह ने पाया है कि हिमालय का सिंधु-त्संगपो सिवनी ज़ोन (ITSZ) टेक्टोनिक रूप से सक्रिय है।
- हिमालय के सेचर ज़ोन को परंपरागत रूप से स्थिर माना जाता था।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इसके तलछटी बेड झुके हुए और जोर से टूटे हुए पाए गए।
- इन नदियाँ, उत्थान वाले भागों (uplifted terraces) से जुड़ी थीं।
- बेडरॉक बहुत उथली गहराई पर भंगुर विरूपण दिखाता है।
- इन विकृती को भूवैज्ञानिक विशेषताओं को वैकल्पिक रूप से उत्तेजित Luminescence (OSL) की तकनीक का उपयोग करके दिनांकित किया गया था।
- भूकंपीयता और मूल्यह्रास दर के आंकड़ों की भी समीक्षा की गई है।
- ITSZ का क्षेत्र पिछले 78000-58000 वर्षों से नव-विवर्तनिक रूप से सक्रिय रहा है।
- इस खोज में भूकंप के अध्ययन, भविष्यवाणी, पहाड़ की श्रृंखला के भूकंपीय संरचना को समझने के साथ-साथ इसके विकास के बारे में प्रमुख निहितार्थ होंगे।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- टेक्टोनिक्स, चट्टानों की विकृति का वैज्ञानिक अध्ययन है जो पृथ्वी की क्रस्ट और ऐसी विकृति उत्पन्न करने वाली शक्तियों का निर्माण करता है।
- यह पर्वतीय भवन के तह और फॉल्टिंग, क्रस्ट के धीरे-धीरे ऊपर और नीचे की गतिविधियों से संबंधित है।
- ITSZ लद्दाख क्षेत्र में एक सेचर ज़ोन है।
- यह भारतीय प्लेट की सीमा को चिन्हित करता है जहाँ यह यूरेशियन प्लेट से टकराता है और बाद के नीचे दब जाता है।

क्या आप जानते है?

- Optically-Stimulated Luminescence: यह एक अंतिम चतुर्धातुक (भूवैज्ञानिक समय अवधि है जिसमें 2.6 मिलियन वर्ष पहले) अंतिम समय क्वार्ट्ज तलछट प्रकाश के संपर्क में आने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डेटिंग तकनीक थी।
- भूकंपीयता (Seismicity): यह एक क्षेत्र में भूकंप की आवृत्ति को मापने के लिए संदर्भित करता है।
- पदावनति (Denudation): यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतह का निर्माण और ह्रास होता है।

हजीरा और घोघा के बीच रो-पैक्स सेवा शुरू (Hazira-Ghogha Ro-Pax Ferry Service to be inaugurated)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- भारतीय प्रधानमंत्री ने गुजरात के हजीरा में रो-पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया और गुजरात में हजीरा और घोघा के बीच रो-पैक्स सेवा को हरी झंडी दिखायी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- हजीरा-घोघा रो-पैक्स नौका सेवा दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगी।
- यह घोघा और हजीरा के बीच की दूरी को 370 किलोमीटर से घटाकर 90 किलोमीटर कर देगा।
- इस यात्रा से लगभग 9000 लीटर प्रति दिन ईंधन की भारी बचत होगी और CO2 उत्सर्जन में लगभग 24 मिलियन टन प्रति दिन की कमी आएगी।
- फेरी सेवाओं की शुरुआत के साथ, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में बंदरगाह क्षेत्र, फर्नीचर और उर्वरक उद्योगों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

सभी चार पहिया वाहनों के लिए FASTags अनिवार्य कर दिया गया है (FASTags mandatory for all four wheelers)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए FASTags अनिवार्य करते हुए एक अधिसूचना जारी की है।
- यह 1 दिसंबर, 2017 से पहले बेचे जाने वाले पुराने वाहनों के साथ-साथ M और N श्रेणी के मोटर वाहनों पर भी लागू होगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, FASTag को 1 दिसंबर 2017 से नए चार पहिया वाहनों के सभी पंजीकरण के लिए अनिवार्य कर दिया गया था।
- वाहन निर्माता या उनके डीलरों द्वारा आपूर्ति की जा रही है।
- यह आगे कहा गया था कि परिवहन वाहनों के लिए FASTag के फिट होने के बाद ही फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाएगा।
- राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए 1 अक्टूबर, 2019 से FASTag का फिट होना अनिवार्य है।

- मंत्रालय ने कहा कि बीमा के प्रमाण पत्र में संशोधन के माध्यम से एक नया थर्ड पार्टी बीमा प्राप्त करते समय एक वैध FASTag भी अनिवार्य है, जिसमें FASTag आईडी के विवरण को कैप्चर किया जाएगा।
- यह 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा।
- यह अधिसूचना, यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख कदम होगा कि केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से टोल प्लाजा पर शुल्क का भुगतान 100% हो और वाहन शुल्क प्लाज़ा के माध्यम से निर्बाध रूप से गुजरें।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

FASTag

- FASTag भारत में एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है
- संचालन: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा।
- यह प्रीपेड या बचत खाते से सीधे या सीधे टोल मालिक से टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का प्रयोग करता है।

दूरसंचार विभाग अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए नियमों को आसान बनाते है (Department of Telecom eases rules for other service providers)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- दूरसंचार विभाग ने व्यापार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (BPO) और सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं (ITes) में अन्य सेवा प्रदाताओं (OSP) के लिए नियमों में ढील दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- OSP ऐसी कंपनियाँ या फर्म हैं जो विभिन्न कंपनियों, बैंकों या अस्पताल श्रृंखलाओं के लिए टेलीमार्केनिंग या टेलीमेडिसिन जैसी माध्यमिक या तृतीयक सेवाएँ प्रदान करती हैं।
- नए नियम OSPs के लिए पंजीकरण की आवश्यकता को हटाते हैं।
- ऐसे BPO जो केवल डेटा के काम में लगे हुए हैं उन्हें पूरी तरह से OSP की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।
- सरकार ने OSP कर्मचारियों को विस्तारित या दूरस्थ एजेंटों के रूप में मान्यता देने के साथ, ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को अब ऐसे सभी कर्मचारियों के विवरण को DoT को प्रदान करने का अतिरिक्त अनुपालन बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।
- लाइसेंस के नवीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी और इसलिए विदेशी कंपनियों को भारत में अपनी अन्य सेवा प्रदान करने वाली इकाइयों को स्थापित करने या विस्तार करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

- यह महत्वपूर्ण बदलाव, जो डेटा-आधारित OSP को पूरी तरह से BPO के दायरे से बाहर ले जाता है, का मतलब होगा कि ऐसी फर्में किसी भी अन्य सेवा फर्म की तरह सख्त और बोझिल दिशानिर्देशों जैसे स्थान पर एजेंट की उपस्थिति के बिना कार्य कर सकती हैं।

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना()Delhi-Ghaziabad-Meerut Regional Rapid Transit System Project

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- हाल ही में, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (NCRTC) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) ने-दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन $ का ऋण देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ को जोड़ने वाला एक 82.15 किलोमीटर लंबा, निर्माणाधीन, सेमी-हाई स्पीड रेल गलियारा है।
- यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) की क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (RRTS) परियोजना के चरण- I के तहत योजनाबद्ध तीन रैपिड-रेल कॉरिडोर में से एक है।
- रैपिड ट्रांजिट सिस्टम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक तेज, विश्वसनीय, सुरक्षित और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करेगा।
- उच्च गति की कनेक्टिविटी से पूरे क्षेत्र में संतुलित आर्थिक विकास होगा, जिससे समाज के सभी वर्गों को आर्थिक लाभ मिलेगा और एक ही स्थान पर होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों के बजाय विकास के कई नोड होंगे।
- यह एनसीआर में परिवहन क्षेत्र से यातायात की भीड़ और कुल उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

न्यू डेवलपमेंट बैंक

- यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।
- संयुक्त रूप से इसकी स्थापना: 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में 6 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) ने की थी।
- **उद्देश्य:** नवाचार और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से तेजी से विकास के लिए ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास प्रयासों का समर्थन करना।
- **मुख्यालय:** शंघाई, चीन।
- 2018 में, NDB को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला।

सतत वैकल्पिक वहन योग्य परिवहन (SATAT) की ओर (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation (SATAT)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SATAT) पहल के तहत, सरकार 2023-24 तक 5,000 सीबीजी संयंत्रों की स्थापना 15 मिलियन टन के उत्पादन लक्ष्य के साथ देख रही है।
- भारत 5,000 संयंत्र स्थापित करने में 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा।
- ये 2023-24 तक जैव और फसल अपशिष्ट से गैस का उत्पादन करेंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य

- सस्ती और स्वच्छ परिवहन ईंधन की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए, अडानी गैस और टोरेंट गैस जैसी कंपनियों द्वारा 900 संपीड़ित जैव-गैस या सीबीजी संयंत्रों की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- सैटैट नगरपालिका के कचरे के साथ-साथ वन और कृषि अपशिष्ट से गैस पैदा करने का प्रावधान करता है।
- पशुपालन और समुद्री कचरे को भी शामिल किया गया है।
- सीबीजी संयंत्रों में उत्पादित गैस का उपयोग बिजली से चलने वाले ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में किया जा सकता है।

महाराष्ट्र ने विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किए(Maharashtra sets up Desalination Plants)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - नीतियां और हस्तक्षेप और GS - III - जल संसाधन

समाचार में

- महाराष्ट्र ने मुंबई में एक अलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की।
- इस का प्रयोग करने वाला यह भारत का अब चौथा राज्य है।

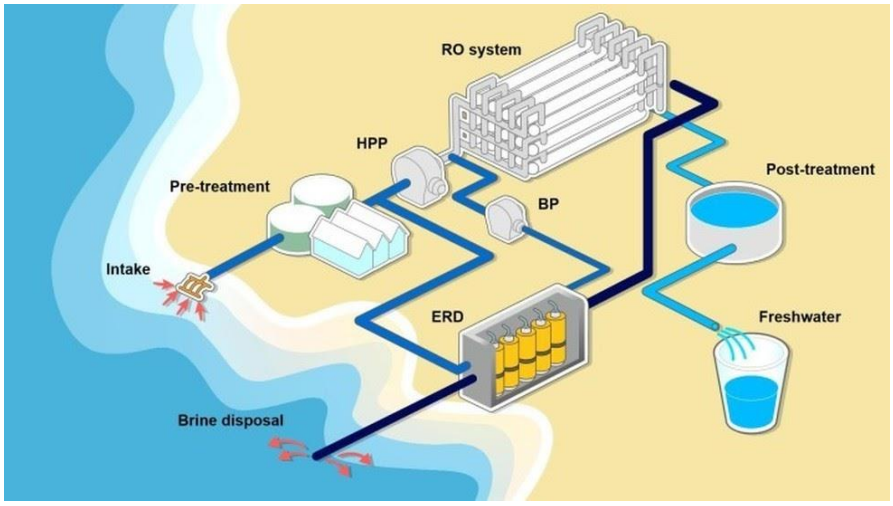

महत्वपूर्ण तथ्य

- एक विलवणीकरण संयंत्र खारे पानी को पानी में बदल देता है जो पीने के लिए उपयुक्त है।
- प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक रिवर्स ऑस्मोसिस है जहां एक झिल्ली के माध्यम से कम-घुला हुआ एकाग्रता के एक क्षेत्र में उच्च-विलेय सांद्रता के क्षेत्र से सॉल्वैंट्स को पुश करने के लिए एक बाहरी दबाव लागू किया जाता है।
- झिल्लियों में मौजूद सूक्ष्म छिद्र पानी के अणुओं को अंदर जाने की अनुमति देते हैं लेकिन नमक और अधिकांश अन्य अशुद्धियों को पीछे छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ से साफ पानी प्राप्त होता हैं।
- डिसेलिनेशन पेयजल उत्पन्न करने का एक महंगा तरीका है क्योंकि इसके लिए उच्च मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- दूसरी समस्या उपोत्पाद प्रक्रिया में नोर्मित बाई-प्रोडक्ट - अत्यधिक केंद्रित नमकीन को निपटान है ।
- जबकि अधिकांश स्थानों में नमकीन को वापस समुद्र में डाल दिया जाता है, वहाँ शिकायतें बढ़ रही हैं कि यह संयंत्र के आसपास की स्थानीय पारिस्थितिकी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है।

क्या आप जानते है?

- दुनिया भर में, पानी के संकट को दूर करने के लिए अलवणीकरण को एक संभावित उत्तर के रूप में देखा जाता है।
- यह पौधे ज्यादातर उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जिनकी समुद्र के पानी तक पहुंच है।
- विलवणीकरण काफी हद तक मध्य पूर्व में समृद्ध देशों तक सीमित है और हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है।
- भारत में, तमिलनाडु इस तकनीक का उपयोग करने में अग्रणी रहा है, 2010 में चेन्नई के पास और फिर 2013 में दो विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किए गए।
- जिन अन्य राज्यों ने इन संयंत्रों का प्रस्ताव किया है वे गुजरात और आंध्र प्रदेश हैं।

फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त संख्या संसाधन सुनिश्चित करने के संबंध में निर्णय (Decisions taken regarding Ensuring Adequate Numbering Resources for Fixed Line and Mobile Services)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- "फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त संख्या संसाधन सुनिश्चित करने" पर ट्राई की सिफारिश पर विचार करने के साथ, दूरसंचार विभाग कुछ निर्णयों को लागू करेगा।

निर्णय

- 15 जनवरी, 2021 से सभी फिक्स्ड मोबाइल कॉल को उपसर्ग 0 के साथ डायल किया जाएगा।
- डायलिंग प्लान में फिक्स्ड से फिक्स्ड, मोबाइल से फिक्स्ड और मोबाइल से मोबाइल कॉल में कोई बदलाव नहीं होगा।
- जब भी कोई ग्राहक 0 के बिना एक मोबाइल कॉल पर फिक्स्ड डायल करता है, तो एक घोषणा सुनाई देगी।
- सभी फिक्स्ड लाइन ग्राहकों को 0 डायल करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- उपरोक्त से लगभग 2539 मिलियन नंबरिंग श्रृंखला उत्पन्न होने की उम्मीद है।
- यह भविष्य में उपयोग के लिए पर्याप्त संख्या में संसाधनों को मुक्त करेगा।
- पर्याप्त संख्या में संसाधनों को मुक्त करने के साथ, भविष्य में अधिक संख्या में कनेक्शन जोड़े जा सकते हैं जो बड़े पैमाने पर मोबाइल ग्राहकों के लिए फायदेमंद होंगे।

NIIF का ऋण प्लेटफ़ॉर्म स्वीकृत (NIIF's Debt Platform approved)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - इन्फ्रास्ट्रक्चर

समाचार में

- भारत में बुनियादी ढांचे के निर्माण को चलाने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले दो वर्षों में राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष (NIIF) के ऋण मंच में 6,000 करोड़ इक्विटी डालने की मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- प्रस्तावित राशि में से, चालू वित्त वर्ष में 2,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा।
- NIIF ऋण मंच राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) द्वारा प्रायोजित है।
- NIIF के तहत, कई फंड हैं।
- NIIF का ऋण मंच बॉन्ड बाजार से ऋण उठाएगा और बुनियादी ढांचा कंपनियों को ऋण प्रदान करेगा।

- यह बांड बाजार और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं सीधे बॉन्ड बाजारों से पैसा नहीं जुटाती हैं क्योंकि उनके पास ऐसे बाजारों में विश्वसनीयता की कमी है।
- NIIF और इसके प्लेटफार्मों की रेटिंग अच्छी है क्योंकि सरकार ने इसमें 49% इक्विटी का निवेश किया है।

क्या आप जानते है?

- कोई भी फंड दो मार्गों - इक्विटी और डेट के माध्यम से पैसा जुटा सकता है और फिर इस पैसे को इक्विटी और डेट में फिर से निवेश कर सकता है।

विज्ञान और तकनीक

क्षुद्रग्रह 16 साइक (Asteroid 16 Psyche)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III –अंतरिक्ष

समाचार में

- हाल ही के एक अध्ययन में पाया गया है कि क्षुद्रग्रह 16 साइक (**Asteroid** 16 **Psyche),** जो मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षा में स्थित है, यह पूरी तरह से धातु से निर्मित है।
- इसकी अनुमानित कीमत10,000 **क्वाड्रिलियन डॉलर** है –जो पृथ्वी की पूरी अर्थव्यवस्था से अधिक।

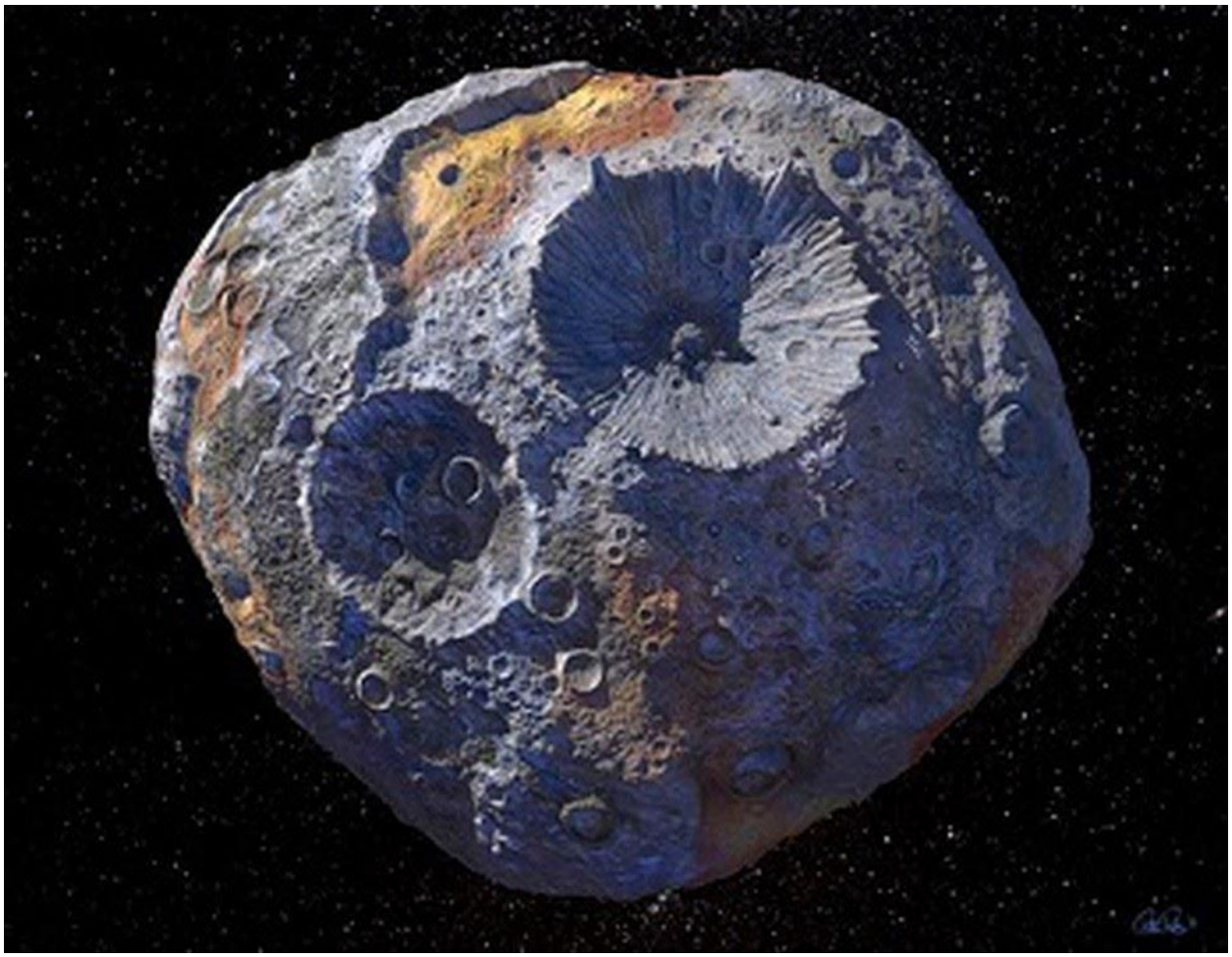

महत्वपूर्ण बिंदु

- नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप की नई छवियां ने क्षुद्रग्रह 16 साइक के नज़दीक का दृश्य प्रस्तुत करती हैं, जिसकी सतह में पृथ्वी के कोर के समान ज्यादातर लोहे और निकल शामिल हो सकते हैं।

- वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे सौर मंडल के निर्माण के दौरान कई टकरावों के बाद क्षुद्रग्रह पूर्व ग्रह का बचा हुआ कोर हो सकता है।
- इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी ने साइकी नामक अंतरिक्ष यान को डिजाइन किया है जो क्षुद्रग्रह के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। साथ ही क्षुद्रग्रह की स्थलाकृति और संरचना के बारे में तस्वीरों और डाटा को भी एकत्रित करेगा। इससे पिछली रिपोर्ट में नासा ने इसकी कंपनी स्पेस एक्स को मिशन में सहयोग करने को कहा था। अगर सब ठीक रहता है तो नासा स्पेस एक्स मिशन की शुरुआत साल 2022 में हो सकती है।

क्या आप जानते है?

- यह पृथ्वी से लगभग 370 मिलियन किमी दूर स्थित है।
- हमारे सौर मंडल में स्थित क्षुद्रग्रह बेल्ट सबसे विशाल वस्तुओं में से एक है।
- आलू के आकार के इस क्षुद्रग्रह का व्यास लगभग 140 मील है,
- यह पहली बार 17 मार्च 1853 को इतालवी खगोल विज्ञानी एनीबेल डी गैस्परिस द्वारा खोजा गया था और इसका नाम आत्मा के प्राचीन ग्रीक देवी, साइके के नाम पर रखा गया था।

NMM और HPC सुविधाओं के परिणामस्वरूप इसके आर्थिक लाभों में 50 गुना वृद्धि हुई है: NCAER रिपोर्ट (NMM and HPC facilities result in a 5 -fold increase in its economic benefits: NCAER Report)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III –विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

समाचार में

- हाल ही में, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) ने "मॉनसून मिशन और उच्च प्रदर्शन कम्प्यूटिंग (एचपीसी) सुविधाओं में निवेश के आर्थिक लाभों का अनुमान लगाने" पर रिपोर्ट जारी की थी।
- जारीकर्ता : विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- रुपये के प्रारंभिक निवेश के साथ। 1,000 करोड़, NMM और HPC सुविधाओं के परिणामस्वरूप इसके आर्थिक लाभों में 50 गुना वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसून मिशन (NMM) और उच्च निष्पादन कम्प्यूटिंग (HPC) सुविधाओं को स्थापित करने के लिए 1000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।
- 76% पशुपालक आश्रय के संशोधन पर निर्णय लेने के लिए मौसम की जानकारी का उपयोग कर रहे हैं; मौसमी बीमारी के खिलाफ टीकाकरण; और चारा प्रबंधन।
- समुद्र में उतरने से पहले हर बार 82% मछुआरों ने ओशन स्टेट फोरकास्ट (OSF) की सलाह का इस्तेमाल किया है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

राष्ट्रीय मानसून मिशन

- 2012 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
- उद्देश्य: मानसून की वर्षा के लिए अत्याधुनिक गतिशील भविष्यवाणी प्रणाली स्थापित करके पूर्वानुमान कौशल में सुधार करना है।
- NMM राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों शैक्षणिक और अनुसंधान और विकास (R&D) संगठनों के बीच एक कार्य साझेदारी का निर्माण करता है।
- उच्च निष्पादन कम्प्यूटिंग सुविधाओं के साथ इसकी वृद्धि ने देश में मौसम के पूर्वानुमान और परिचालन मौसम पूर्वानुमान के लिए जलवायु मॉडलिंग में बदलाव लाने में देश की मदद की है।

भविष्य में नई वैश्विक महामारियों के उभरने व फैलने की रफ़्तार और ज़्यादा तेज़ होगी: IPBES रिपोर्ट (Pandemics to emerge more often: New Report by IPBES)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - स्वास्थ्य और GS III -विज्ञान और प्रौद्योगिकी

समाचार में

- 'Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services' (IPBES) द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट में, लेखकों ने चेतावनी दी है कि संक्रामक बीमारियों का मुक़ाबला करने की रणनीतियों में अगर व्यापक फेरबदल नहीं किये ए तो भविष्य में नई वैश्विक महामारियों के उभरने व फैलने की रफ़्तार और ज़्यादा तेज़ होगी जोकि बड़ी संख्या में लोगों की मौतों और विश्व अर्थव्यवस्था को क्षति पहुँचने का कारण बनेंगी।

रिपोर्ट के मुख्य अंश

- रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 1918 में फैली महामारी 'स्पैनिश फ़्लू' के बाद यह कम से कम छठी बार है जब किसी विश्वव्यापी महामारी ने दुनिया की अपनी चपेट में लिया है।
- उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस नई बीमारी का स्रोत जानवरों में पाए जाने वाले रोगाणुओं में है लेकिन अन्य वैश्विक महामारियों की तरह, इसके उभरने के लिये मानवीय गतिविधियाँ ज़िम्मेदार हैं।
- महामारी के तीन वायरस इन्फ्लूएंजा वायरस के कारण होते थे, एक एचआईवी द्वारा और उसके बाद सार्स और सीओवीआईडी -19
- वर्तमान में 1.7 मिलियन से अधिक अनदेखे वायरस हैं जो स्तनधारियों और पक्षियों में मौजूद हैं, जिनमें से 827,000 तक लोगों को संक्रमित करने की क्षमता हो सकती है।
- 70% से अधिक उभरती हुई बीमारियाँ, जैसे कि इबोला, ज़िका और निपा, जानवरों में पाए जाने वाले रोगाणुओं के कारण होती हैं जो वन्यजीवों, पशुधन और लोगों के बीच संपर्क के कारण फैल जाते हैं।

- लगभग 30% उभरते संक्रामक रोगों को भूमि उपयोग परिवर्तन, कृषि विस्तार और शहरीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।
- रिपोर्ट बताती है कि जैव विविधता के नुकसान को कम करने वाली मानव गतिविधियों को कम करके, संरक्षित क्षेत्रों के अधिक संरक्षण से और उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों के निरंतर दोहन को कम करने वाले उपायों के माध्यम से महामारी के जोखिम को कम किया जा सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर अंतरसरकारी विज्ञान-नीति मंच (IPBES)

- यह जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मुद्दों पर विज्ञान और नीति के बीच इंटरफेस को बेहतर बनाने के लिए स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है।
- **स्थापना-** संयुक्त राष्ट्र द्वारा
- यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
- **गठन**: 2012
- **मुख्यालय:** बॉन, जर्मनी।

व्हाट्सएप ने आधिकारिक तौर पर एपेमेरल मैसेजिंग फीचर की घोषणा की है(WhatsApp officially announces Ephemeral Messaging feature)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - विज्ञान और प्रौद्योगिकी

समाचार में

- व्हाट्सऐप ऐप ने आधिकारिक तौर पर प्लेटफ़ॉर्म पर एपेमेरल मैसेजिंग (संदेशों को गायब करने) की एक नई सुविधा की घोषणा की है।
- यह नवंबर 2020 तक वैश्विक स्तर पर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

एपेमेरल मैसेजिंग

- यह मल्टीमीडिया संदेशों का मोबाइल-से-मोबाइल ट्रांसमिशन है जो संदेश देखे जाने के बाद प्राप्तकर्ता की स्क्रीन से स्वचालित रूप से गायब हो जाता है।
- शब्द " एपेमेरल " कुछ का वर्णन करता है जो केवल थोड़े समय के लिए रहता है।
- अन्य एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप जैसे टेलीग्राम, सिग्नल, वायर पहले से ही इस तरह का विकल्प देते हैं।
- गायब हो रहे संदेशों को चालू करने से, उपयोगकर्ताओं को कुछ और नियंत्रण मिलेंगे जिन पर चैट को सुरक्षित रखा जा सकता हैं।
- इसने सभी उपयोगकर्ताओं की समय सीमा सात दिनों में तय की है।

एक्स-रे और रेडियो संकेतों का मिश्रण पहली बार देखा गया **(Mix of X-ray and radio signals observed for the first time)**

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III – अंतरिक्ष

समाचार में

- नासा (NASA) ने अपने एक अध्ययन में बताया है कि मिल्की वे गैलेक्सी (Milky Way galaxy) में उसने हाल ही में एक्स-रे और रेडियो संकेतों (X-ray and radio signals) का मिश्रण देखा है, जो मिल्की वे में पहले कभी नहीं देखा गया था।
- गौरतलब है कि आकाशगंगा के भीतर देखा जाने वाला यह पहला तेज रेडियो फट (FRB) है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- अप्रैल, 2020 में मिल्की वे में फास्ट रेडियो बर्स्ट (FRB) के एक बहुत शक्तिशाली स्रोत का पता चला था।
- यह शक्तिशाली स्रोत 'एसजीआर 1935' या 'एसजीआर 1935 + 2154'[SGR 1935 or SGR 1935+2154] नामक शक्तिशाली चुंबकीय न्यूट्रॉन तारा (Powerful Magnetic Neutron) है, जिसे मैगनेटर (Magnetar)के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- यह तारा वल्पेकुला नक्षत्र (Vulpecula constellation) में स्थित है।
- 14,000-41,000 प्रकाश वर्ष दूर होने का अनुमान है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

मैगनेटर (Magnetar)

- मैगनेटर (Magnetar), ऐसे न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिनका चुंबकीय क्षेत्र काफी वृहद व शक्तिशाली होता है।
- ये सूर्य की तुलना में काफी बड़े तारे होते हैं।
- न्यूट्रॉन तारे तब बनते हैं जब कोई विशाल तारा (massive star) अपनी अंतिम अवस्था में होता है और वह टूट (collapse) जाता है।
- न्यूट्रॉन तारे तब बनते हैं जब किसी विशाल तारे का कोर गुरुत्वाकर्षण के पतन से गुज़रता है जब वह अपने जीवन के अंत तक पहुँचता है।
- दरअसल किसी तारे में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। प्रथम, तारे का गुरुत्वीय बल तथा द्वितीय तारे का ईंधन (हाइड्रोजन तथा हीलियम) से उत्पन्न होने वाला रेडियोएक्टिव बल।
- यदि तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है तो अन्दर का रेडियोएक्टिव विस्फोट, बाहर से दबाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता है।
- अतः क्षण भर के अन्दर तारा सिकुड़ कर बहुत छोटा हो जाता है परन्तु इस अचानक और तीव्र संपींडन के कारण अन्दर का तापमान अरबों डिग्री हो जाता है। अब इस के कारण तारा एक विस्मयकारी विस्फोट अर्थात सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है।

- इससे तारे के बाहरी तत्व बिखर जाते हैं जबकि केंद्र गुरुत्वाकर्षण के चलते और भी सिकुड़ता जाता है। विस्फोट के बाद जो पदार्थ बचता है वह धीरे धीरे सिमटना शुरू होता है और बहुत ही घने पिंड का रूप ले लेता है जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। अगर न्यूट्रॉन स्टार बहुत विशाल है तो गुरुत्वाकर्षण का दबाव इतना होगा कि वह अपने ही बोझ से सिमटता चला जाएगा और इतना घना हो जाएगा कि वे एक ब्लैक होल बन जाएगा।

PSLV-C49 ने सफलतापूर्वक EOS-01 लॉन्च किया (PSLV-C49 successfully launches EOS- PSLV-C49 successfully launches EOS-01)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - भारतीयों की उपलब्धियां; अंतरिक्ष

समाचार में

- भारत का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अपनी 51 वीं उड़ान (PSLV-C49) में, सतीशधवन स्पेस सेंटर (SDSC)से, श्रीहरिकोटा के नौ अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों के साथ सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस-01 (Earth Observation Satellite EOS-01) को लॉन्च कर दिया है।

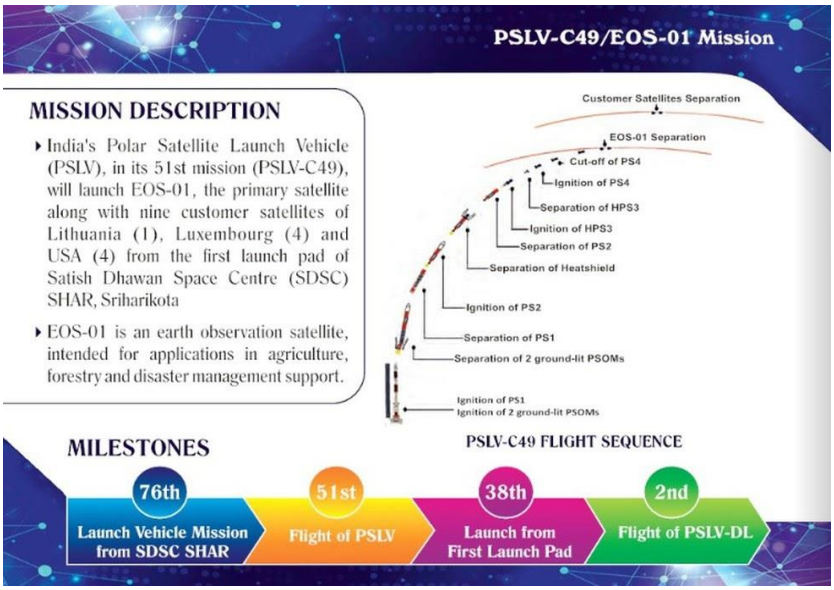

महत्वपूर्ण तथ्य

- PSLV-C49 'DL' विन्यास में (2 ठोस स्ट्रैप-ऑन मोटर्स के साथ) PSLV ने दूसरी उड़ान भरी है।
- EOS-01 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसका उद्देश्य कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन समर्थन में अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना है।
- लिथुआनिया (1), लक्समबर्ग (4) और यूएसए (4) के नौ ग्राहक उपग्रहों को न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के साथ एक वाणिज्यिक व्यवस्था के तहत लॉन्च किया गया था।

भारत मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2020 को वस्तुतः आयोजित किया जाना है (India Mobile Congress (IMC) 2020 to be held virtually)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - विज्ञान और प्रौद्योगिकी

समाचार में

- भारत मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2020 का चौथा संस्करण दिसंबर में आयोजित होने वाला है।
- यह वस्तुतः इस वर्ष चल रही महामारी को देखते हुए आयोजित किया जाएगा।
- मंत्रालय: सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

महत्वपूर्ण तथ्य

- संयुक्त रूप से आयोजित: दूरसंचार विभाग (DoT) और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAT)।
- इस कार्यक्रम में 50+ भाग लेने वाले देश, 110 + ग्लोबल स्पीकर, तीन दिवसीय कार्यक्रम में स्टार्ट-अप दिखाई देंगे।
- विषय: "समावेशी नवाचार - स्मार्ट, सुरक्षित, स्थायी"
- IMC को उद्योग, सरकार, शिक्षा और अन्य पारिस्थितिक तंत्र के खिलाड़ियों को एक साथ लाने के लिए एशिया में सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम माना जाता है, जिसमें प्रमुख उद्योग जैसे SG, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Al), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (loT) के बारे में नवीनतम उद्योग प्रौद्योगिकी रुझानों पर चर्चा की जाती है।) आदि।

क्या आप जानते है?

- COAI का गठन 1995 में एक पंजीकृत, गैर-सरकारी समाज के रूप में किया गया था।
- भारत को मोबाइल संचार अवसंरचना, उत्पादों और सेवाओं के वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना और ब्रॉडबैंड सहित 100% की राष्ट्रीय टेली घनत्व प्राप्त करना।

थर्टी मीटर टेलीस्कोप या तीस मीटर की दूरबीन (Thirty Meter Telescope)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - विज्ञान और प्रौद्योगिकी; अंतरिक्ष

समाचार में

- 2020 भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. एंड्रिया घेज़ ने हवाई में मौनाका में स्थापित किए जा रहे थर्टी मीटर टेलीस्कोप (टीएमटी) परियोजना के बैक-एंड इंस्ट्रूमेंट्स और संभावित विज्ञान संभावनाओं के डिजाइन पर भारतीय खगोलविदों के साथ मिलकर काम किया था।

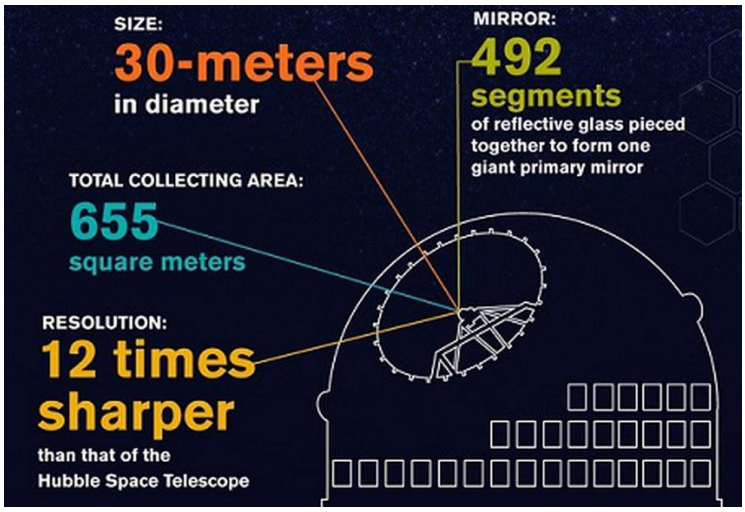

महत्वपूर्ण तथ्य

- टीएमटी परियोजना कैलटेक, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कनाडा, जापान, चीन और भारत के बीच एक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी है।
- "थर्टी मीटर" दर्पण के 30-मीटर व्यास को संदर्भित करता है, जिसमें ग्लास के 492 खंडों को एक साथ रखा गया है।
- एक बार पूरा होने के बाद, यह दुनिया के सबसे बड़े मौजूदा दृश्यमान प्रकाश दूरबीन के रूप में तीन गुना चौड़ा होगा।
- दर्पण जितना बड़ा होगा, उतनी अधिक रोशनी एक टेलीस्कोप पर एकत्रित कर सकता है, जिसका अर्थ है, बदले में, यह दूर की वस्तुओं को "देख" सकता है।
- यह वर्तमान दूरबीनों की तुलना में 200 गुना अधिक संवेदनशील होगा।
- यह हबल स्पेस टेलीस्कोप से 12 गुना बेहतर वस्तुओं को हल करने में सक्षम होगा।
- आवेदक: एक्सोप्लैनेट का अध्ययन

क्या आप जानते है?

- पहले से ही कई वेधशालाओं और 13 बड़े टेलीस्कोपों की साइट या स्था है, मौना के (Mauna Kea) को स्वदेशी या स्थानिक हवाई लोगों द्वारा इसे पवित्र माना जाता है जो मानते हैं कि इस तरह के निर्माण मौना के पर्वत ख़राब हो सकते हैं।
- यदि किसी वजह से हवाई में मौना के पर्वत पर तीस मीटर टेलीस्कोप नहीं बनाया जा सकता है, तो स्पेन का कैनरी द्वीप एक बैकअप साइट का भी निर्माण किया गया है।

एपोफिस का 2068 में पृथ्वी से टकराने की उम्मीद है (Apophis expected to hit Earth in 2068)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III – अन्तरिक्ष

समाचार में

- क्षुद्रग्रह एपोफिस 2068 में यार्कोवस्की प्रभाव नामक एक घटना के कारण पृथ्वी से टकरा सकता है।
- इस आशय ने अंततः क्षुद्रग्रह के प्रवाह को तेज कर दिया है और इसका मार्ग भी बदल दिया है।
- हवाई विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा मनोआ में नए गणना के अनुसार, क्षुद्रग्रह एपोफिस, जो 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के बेहद करीब होगा, अपनी वास्तविक कक्षा से भटक रहा है और 2068 में पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

-
- एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, सूरज, एक गैर-समान तरीके से एक क्षुद्रग्रह को गर्म कर सकता है, जिससे अंतरिक्ष चट्टान गर्मी ऊर्जा को विषम रूप से विकीर्ण कर सकती है।
- यह एक निश्चित दिशा में एक जोर या छोटे धक्का का कारण बन सकता है, कभी-कभी क्षुद्रग्रह का मार्ग बदल देता है। इस प्रभाव को यार्कोवस्की त्वरण कहा जाता है।
- यारकोवस्की प्रभाव की खोज से पहले, टकराव की संभावना असंभव थी।
- एपोफिस पर अभिनय करने वाले इस प्रभाव का पता लगाने का अर्थ है कि 2068 प्रभाव परिदृश्य अभी भी एक संभावना है।

क्या आप जानते है ?

- Asteroid Apophis स्पेस से एक एस्टेरॉयड एपोफिस Asteroid Apophis धरती की ओर बढ़ रहा है। इस एस्टेरॉयड की खोज साल 2004 में की गई थी, इसका आकार 3 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा है. वैज्ञानिकों को आशंका है कि यह एस्टेरॉयड धरती से टकरा भी सकता है। इसका नाम ग्रीक गॉड ऑफ कैओस के नाम पर रखा गया है।

परम सिद्धि ने 63 की वैश्विक रैंकिंग प्राप्त की

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - विज्ञान और तकनीकी में भारतीयों की उपलब्धियां

समाचार में

- भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने दुनिया के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली गैर-वितरित कंप्यूटर सिस्टम में 63 की वैश्विक रैंकिंग हासिल की है।
- हाल ही में यह रैंकिंग जारी की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य

- परम सिद्धि C-DAC में नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत स्थापित उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (HPC-AI) सुपरकंप्यूटर है।
- **विकसित:** सी-डैक
- **संयुक्त रूप से विकसित:** NSM के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)।

भारतीय वैज्ञानिकों ने डचेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या डचेनी पेशी अपविकास के इलाज का प्रस्ताव दिया है(ndian Scientist proposes to have found treatment for Duchenne Muscular Dystrophy)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- II - स्वास्थ्य और GS- III - विज्ञान और तकनीक में भारतीयों की उपलब्धियां

समाचार में

- संदीप ईस्वरप्पा, आईआईएससी, बेंगलुरु के सहायक प्रोफेसर ने डचेनी पेशी अपविकास के लिए नए आनुवंशिक उपचार प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है।

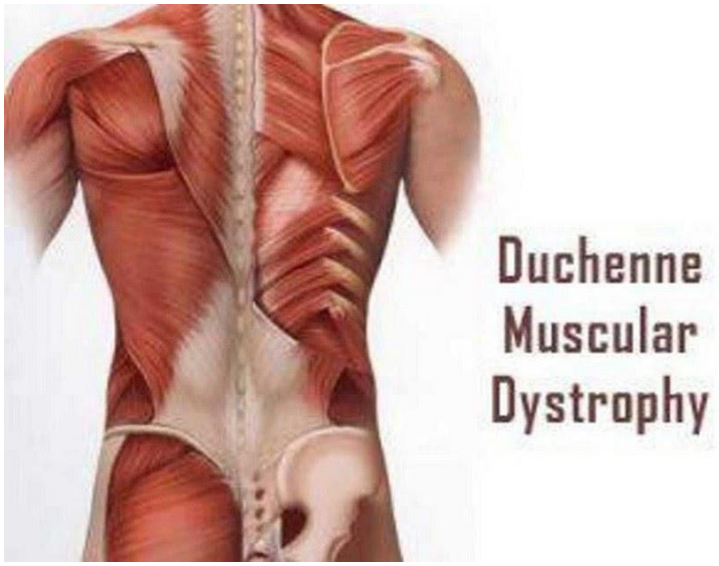

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (डीएमडी) एक गंभीर प्रकार की मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी है जो मुख्य रूप से लड़कों को प्रभावित करती है।
- दोषपूर्ण जीन की एक प्रति के साथ मादा हल्के लक्षण दिखा सकती है।
- मांसपेशियों की कमजोरी आमतौर पर चार साल की उम्र के आसपास शुरू होती है, और जल्दी खराब हो जाती है।
- मांसपेशियों का नुकसान आम तौर पर जांघों और श्रोणि में पहले होता है और उसके बाद बाहों में।

- इससे खड़े होने में परेशानी हो सकती है।
- अधिकांश 12 वर्ष की आयु तक चलने में असमर्थ हैं।
- इसमें स्कोलियोसिस भी आम समस्या है।
- कुछ में बौद्धिक विकलांगता हो सकती है।

क्या आप जानते है?

- यह प्रोटीन डाइस्ट्रोफिन के लिए जीन में एक उत्परिवर्तन के कारण निर्मित होता है।
- डिस्ट्रोफिन मांसपेशी फाइबर की कोशिका झिल्ली को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है।
- हालांकि कोई ज्ञात इलाज नहीं है, भौतिक चिकित्सा, ब्रेसिज़ और सुधारात्मक सर्जरी कुछ लक्षणों के साथ मदद कर सकती है।

प्रहरी -6 सैटेलाइट लॉन्च किया गया (Sentinel-6 Satellite launched)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में

- कोपर्निकस प्रहरी -6 माइकल फ्रीलिच उपग्रह को 21 नवंबर को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लांच किया गया था।
- उद्देश्य: इसे महासागरों की निगरानी के लिए बनाया गया
- संयुक्त रूप से विकसित: यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए), नासा, यूरोपीय संगठन मौसम विज्ञान उपग्रहों (Eumetsat), संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) और यूरोपीय संघ के लिए।

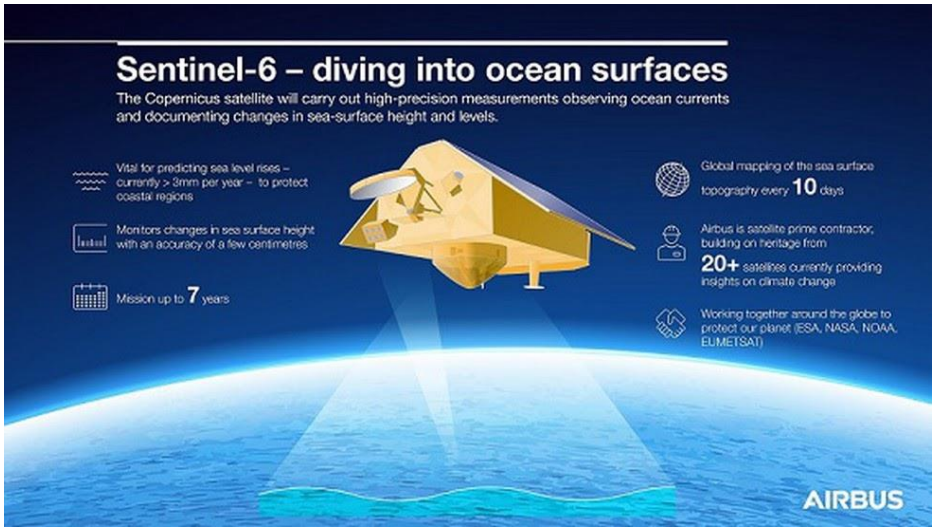

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह वैश्विक समुद्र तल में परिवर्तनों को मापने के लिए समर्पित अगले मिशन का एक भाग है।

- जेसन कॉन्टिनिटी ऑफ सर्विस (जेसन-सीएस) मिशन नामक मिशन को समुद्र की ऊंचाई मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- पृथ्वी की जलवायु कैसे बदल रही है, यह समझने में महासागर की ऊँचाई एक महत्वपूर्ण घटक है।
- अंतरिक्ष यान में दो उपग्रह हैं, जिनमें से एक को हाल ही में लॉन्च किया गया था, और दूसरे, जिसे सेंटिनल -6 बी कहा जाता है, इसे 2025 में लॉन्च किया जाएगा।

क्या आप जानते है?

- वैश्विक स्तर पर महासागरों में परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए 1992 से शुरू किए गए अन्य उपग्रहों में TOPEX / Poseidon, Jason-1 और OSTN / Jason-2 शामिल हैं।

कोरोनावायरस मरीज न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित कर रहे हैं(Coronavirus patients develop Neutralising Antibodies)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - स्वास्थ्य और GS - III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में

- दरअसल पुणे से आई एक नई स्टडी के मुताबिक 85 फीसदी लोग जो पहले कोरोनावायरस से संक्रमित पाए गए थे, उनमें अब कोरोना से लड़ने की क्षमता विकसित हो गई है

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- एक बीमारी पैदा करने वाले वायरस से प्रतिरक्षा "तटस्थ" या "सुरक्षात्मक" एंटीबॉडी के रूप में जानी जाती है।
- रिकवरी प्रोसेस के लिए एंटीबॉडी का बनना जरूरी है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि भविष्य में फिर से वहीं वारयस इम्युनिटी परअटैक ना करें।
- अन्य एंटीबॉडी की तरह, जो रोग से लड़ने के लिए बनाई गई हैं, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज प्रोटीन हैं।
- ये रोग-विशिष्ट एंटीबॉडी का एक छोटा सा उप-समूह हैं जो एक बार संक्रमण होने के बाद उत्पन्न होते हैं।
- तटस्थ एंटीबॉडी विशेष हो जाते हैं क्योंकि वे भविष्य में मानव शरीर के अंदर एक ही वायरस के प्रवेश को रोकने की क्षमता रखते हैं।
- अन्य एंटीबॉडीज वायरस से लड़ने में मदद करते हैं क्योंकि संक्रमण पहले ही हो चुका है।

चीन का चांग'ते-5 चंद्र मिशन (China's Chang'e-5 lunar mission)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - अन्तरिक्ष

समाचार में

- चीन के चांग'ते -5 चंद्र मिशन ने हाल ही में चंद्रमा के अस्पष्टीकृत हिस्से से चंद्र चट्टान के नमूने वापस लाने के प्रयास में चार दशकों में पहली बार जांच की है।
- अंतरिक्ष यान 15 दिसंबर, 2020 के आसपास पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- चांग'ते -5 की जांच चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन (CNSA) चंद्र नमूना वापसी मिशन द्वारा की गयी है।
- **लक्ष्य:** चंद्रमा के मोनस रुम्कर क्षेत्र में उतरने के लिए
- मिशन में एक चंद्र ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक एसेंट जांच शामिल है जो चंद्र नमूनों को कक्षा में वापस ले जाएगा और उन्हें पृथ्वी पर वापस लौटा देगा।
- जांच का नाम चीनी चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है जो पारंपरिक रूप से एक सफेद या जेड खरगोश के साथ है।

क्या आप जानते हो?

- 2019 की शुरुआत में, चीन के चांग'ओ -4 जांच ने चंद्रमा के दूर से सफलतापूर्वक प्रेषित छवियों को भी अंधेरे पक्ष के रूप में संदर्भित किया।
- चंद्रमा के इस हिस्से में उतरने वाली यह पहली जांच थी।

इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (Electronic Vaccine Intelligence Network)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - II - स्वास्थ्य और GS - III - विज्ञान और तकनीक

समाचार में

- भारत सरकार प्राथमिक लाभार्थियों और वैक्सीन वितरण नेटवर्क की पहचान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से eVIN (इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क) का उपयोग कर रही है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- eVIN एक स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक है।
- यह वैक्सीन स्टॉक को डिजिटाइज़ करता है और एक स्मार्टफोन एप्लिकेशन के माध्यम से कोल्ड चेन के तापमान पर नज़र रखता है।
- कोल्ड चेन पॉइंट्स में बेहतर वैक्सीन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का समर्थन करने के लिए अभिनव ईविन को पहली बार 2015 में 12 राज्यों में लॉन्च किया गया था।
- eVIN केंद्र सरकार के यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम का समर्थन करता है ताकि वैक्सीन स्टॉक और प्रवाह पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान की जा सके, और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोल्ड चेन पॉइंट्स पर स्टोरेज तापमान को नियमित किया जा सके।

क्या आप जानते है?

- सरकार ने कोविद -19 वैक्सीन की शुरुआत के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है और कोविद -19 (NEGVAC) के लिए वैक्सीन प्रशासन पर एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है जो वैक्सीन परिचय के लिए रणनीतियों का मार्गदर्शन करने वाले उच्चतम समूह के रूप में होगा।

ब्रेन फ़िंगरप्रिंटिंग (Brain Fingerprinting)

संदर्भ: उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय दलित लड़की के कथित बलात्कार और हत्या की जांच कर रही सीबीआई अधिकारियों की एक टीम चार आरोपियों के साथ गांधीनगर स्थित फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) में पहुंची। इन चारों पर एक ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग (brain electrical oscillation signature profiling- BEOSP) परीक्षण किया जाएगा

वास्तव में BEOSP टेस्ट क्या है?

- 'ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग' (BEOSP) को ब्रेन फ़िंगरप्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह पूछताछ का एक न्यूरो मनोवैज्ञानिक तरीका है, जिसमें अपराध की जाँच 'मानव मस्तिष्क के वैद्युत व्यवहार' की प्रतिक्रिया का अध्ययन करके की जाती है। इस परीक्षण में इलेक्ट्रोऐंसेफलोग्राम प्रक्रिया (Electroencephalogram process) के माध्यम से इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इम्पल्स को हटाकर अपराध में किसी संदिग्ध की भागीदारी का पता लगाया जाता है।
- इस परीक्षण के तहत अभियुक्त की सहमति लेकर उन्हें इलेक्ट्रोड कैप पहनाई जाती है, जिसके बाद अपराधी के दिमाग में न्यूरॉन्स के ट्रिगर, जो मस्तिष्क तरंगें (Generate Brainwaves) उत्पन्न करता है, की जाँच के लिये अपराध से सम्बंधित दृश्य या ऑडियो क्लिप दिखाई जाती है। अपराध में अभियुक्त की भागीदारी का निर्धारण परीक्षण परिणामों के आधार पर किया जाता है। यह परीक्षण 'ज्ञान' और 'अनुभव' पर आधारित है।
- इस प्रक्रिया से इतर पॉलीग्राफ टेस्ट में अभियुक्त से प्रश्न किये जाते हैं तथा आरोपी व्यक्ति के शारीरिक संकेतकों जैसे रक्तचाप, पल्स रेट, श्वसन और शारीरिक हाव-भाव के आधार पर अपराध में संलिप्तता का अध्ययन किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार कुछ व्यक्ति रक्तचाप और पल्स रेट को संकट के समय में नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं, जबकि बी.ई.ओ.एस.पी. परीक्षण अधिक विश्वसनीय परिणाम प्रदान करता है।

एक पॉलीग्राफ या एक झूठ डिटेक्टर से BEOSP परीक्षण को क्या अलग करता है?

- BEOSP प्रक्रिया में अभियुक्तों के साथ एक प्रश्न उत्तर सत्र शामिल नहीं है और यह उनके मस्तिष्क का एक न्यूरो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है।
- पॉलीग्राफ टेस्ट में, आरोपी व्यक्ति के शारीरिक संकेतकों को ध्यान में रखा जाता है जिसमें रक्तचाप, नाड़ी की दर, श्वसन और त्वचा की चालकता शामिल होती है।

- हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि जबकि कोई व्यक्ति संकट के समय में भी अपनी पल्स दर और बीपी को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकता है, बीईओएसपी परीक्षण बहुत अधिक विश्वसनीय परिणाम प्रदान करता है।

आरोपियों को गांधीनगर एफएसएल में क्यों लाया गया?

- 1974 में स्थापित, गांधीनगर में गुजरात राज्य FSL फोरेंसिक विज्ञान और तकनीकी जांच के लिए भारत की प्रमुख प्रयोगशाला है।
- एफएसएल में कुल 1100 कर्मचारी हैं और संदिग्ध पहचान प्रणाली, कंप्यूटर फोरेंसिक, नार्को विश्लेषण के साथ-साथ एक मान्यता प्राप्त गाय के मांस के परीक्षण मोबाइल प्रयोगशाला सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है।
- अन्य राज्यों ने अपने मामलों का संदर्भ यहां दिया है क्योंकि प्रयोगशाला में नवीनतम अत्याधुनिक तकनीकी प्रगति के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता है जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार हैं
- गुजरात एफएसएल द्वारा अध्ययन किए गए हाई-प्रोफाइल मामलों में निठारी हत्याकांड, आरुषि हत्या कांड, गोधरा ट्रेन जलाने का मामला, शक्ति मिल गैंगरेप का मामला और बॉलीवुड पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मामले शामिल है।

क्या इन परीक्षणों को प्रमाण के रूप में भर्ती किया जा सकता है?

- स्टैंडअलोन के रूप में नहीं।
- 2010 में, सुप्रीम कोर्ट ने सेलवी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी अभियुक्त को उसकी सहमति के बिना नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग परीक्षणों के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही, परीक्षण के परिणाम एकमात्र साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं। हालांकि, इन परिणामों को साक्ष्य का हिस्सा बनाया जा सकता है।
- हालांकि, परीक्षणों के दौरान खोजी गई किसी भी जानकारी या सामग्री को साक्ष्य का भाग बनाया जा सकता है।

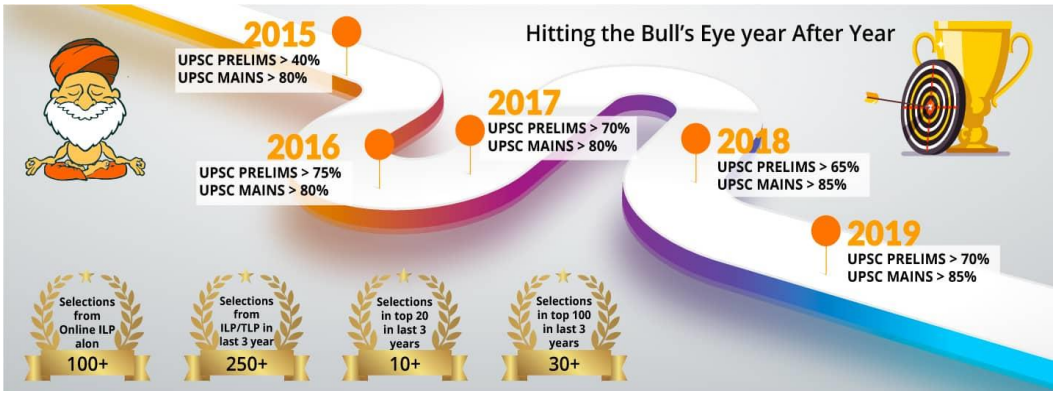

आपदा प्रबंधन

DRDO ने फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम (FDSS) विकसित किया(**DRDO develops Fire Detection and Suppression System (FDSS)**

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - I - आपदा प्रबंधन

समाचार में

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने यात्री बसों के लिए 'फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम (FDSS)' नामक एक तकनीक विकसित की है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- एफडीएसएस तकनीक 30 सेकंड से कम समय में बसों में आग का पता लगा सकती है और इसे 60 सेकंड में बुझा सकती है जिससे जीवन और संपत्ति के लिए खतरा काफी हद तक कम हो सकता है।
- इंजन आग के लिए यात्री डिब्बे और एयरोसोल-आधारित FDSS के लिए वाटर मिस्ट आधारित FDSS का उपयोग किया गया।
- यात्री डिब्बे के लिए FDSS में 80 लीटर की क्षमता वाला पानी का टैंक होता है, बस में उपयुक्त स्थान पर स्थापित 200 बार के लिए 6.8 किलोग्राम नाइट्रोजन सिलेंडर पर दबाव डाला जाता है।
- इंजन के लिए FDSS में एक एरोसोल जनरेटर होता है जिसके साथ सिस्टम सक्रियण के 5 सेकंड के भीतर आग का दमन हासिल किया जा सकता है।

राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC)(National Crisis Management Committee (NCMC))

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - आपदा प्रबंधन

समाचार में

- हाल ही में, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) चक्रवात निवार के संबंध में खबरों में थी।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- राष्ट्रीय स्तर पर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) और नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी (NCMC) शीर्ष स्तर के निर्णय लेने वाली आपदा प्रबंधन (DM) में शामिल प्रमुख समितियाँ हैं।
- यह बड़े संकट से निपटता है जिसमें गंभीर या राष्ट्रीय प्रभाव होते हैं।
- मुख्य कार्य: (1) आपदा प्रतिक्रिया की कमान, नियंत्रण और समन्वय की निगरानी; (2) आवश्यक समझे जाने पर संकट प्रबंधन समूह (CMG) को दिशा दें।
- संरचना: कैबिनेट सचिव (अध्यक्ष); विशिष्ट आपदा प्रबंधन जिम्मेदारियों के साथ मंत्रालयों / विभागों और एजेंसियों के सचिव

चक्रवात का पूर्वानुमान (Cyclones forecast)

संदर्भ: चक्रवात निवार, जो तमिलनाडु के माध्यम से बार-बार आता है और इसके मद्देनजर पर्याप्त बारिश लाता है, इस साल भारत के तट पर उतरने वाला तीसरा प्रमुख चक्रवात था, इसके अलावा अम्फान और निसारगा। हालांकि, मई में पश्चिम बंगाल में अम्फन द्वारा किए गए कहर की तुलना में अपेक्षाकृत कम जीवन खो गया था। निवार की प्रत्याशा में राहत-सहायता का काम यह था कि यह मुख्य रूप से भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुरूप था।

चक्रवात का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है?

- कुछ वर्षों में, चक्रवातों के गठन को ट्रैक करने की भारत की क्षमता में काफी सुधार हुआ है।
- **रडार नेटवर्क:** देश में 21 डॉपलर मौसम रडार (DWR) (12 तट के साथ) का एक नेटवर्क है। एक तूफान कहां बन रहा है, इसके आधार पर, ये रडार रेडियो तरंगों के साथ-साथ उस गति को भी भेजते हैं जिस गति से पानी की बूंदें बढ़ रही हैं।
- **वास्तविक समय प्रतिक्रिया:** रडार की पहले की पीढ़ी वास्तविक समय में इस तरह की प्रगति को ट्रैक करने में असमर्थ थी, लेकिन DWRs के साथ, अब मौसम रडार के आधार मानक, आमतौर पर कम से कम चार-पांच दिन पहले संभावित तूफान का पता लगाना संभव है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**: आईएमडी भी इसी तरह के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के साथ सहयोग करता है, जैसे कि जापान मौसम विज्ञान एजेंसी, अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र और अमेरिकी मध्य प्रशांत तूफान केंद्र, और ये निकाय समुद्र के मौसम में बदलाव के बारे में लगातार चेतावनी और पूर्वानुमान देते हैं।
- **तकनीकें जो कि रडार को पूरक करती हैं:** महासागर-बुआओं की सर्वव्यापी निकटता (near ubiquity of ocean-buoys) जो समुद्र के समुद्र की सतह के तापमान के साथ-साथ समर्पित मौसम संबंधी उपग्रहों में परिवर्तन को ट्रैक करती है, प्रारंभिक पहचान के बाधाओं में सुधार करती है

रडार कैसे काम करता है?

- डार (Radar) वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्मतरंगों(माइक्रोवेव) तथा रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। इसकी सहायता से गतिमान वस्तुओं जैसे वायुयान, जलयान, मोटरगाड़ियों आदि की दूरी (परास), ऊंचाई, दिशा, चाल आदि का दूर से ही पता चल जाता है। इसके अलावा मौसम में तेजी से आ रहे परिवर्तनों (weather formations) का भी पता चल जाता है। 'रडार' (RADAR) शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका प्रयोग अमेरिका की नौसेना ने 1940 में 'रेडियो डिटेक्शन ऐण्ड रेंजिंग' (radio detection and ranging) के लिये प्रयोग किया था। बाद में यह संक्षिप्त रूप इतना प्रचलित हो गया कि अंग्रेजी शब्दावली में आ गया और अब इसके लिये बड़े अक्षरों (कैपिटल) का इस्तेमाल नहीं किया जाता।
- रडार का आविष्कार टेलर व लियो यंग (Teller and Liyo ying (यू.एस.ए.) ने वर्ष 1922 में किया था। यह यंत्र आकाश में आने-जाने वाले वायुयानों के संचालन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। रडार, एक यंत्र है जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग दूर की वस्तुओं का पता लगाने में तथा उनकी स्थिति, अर्थात् दिशा और दूरी, ज्ञात करने के लिए किया जाता है।
- आँखों से जितनी दूर दिखाई पड़ सकता है,वस्तू उतनी बड़ी होगी, उतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा राडार पर वापस आएगी। यह हमें वातावरण में बारिश की बूंदों को "देखने" की क्षमता प्रदान करता है।

- इसके अलावा, ऊर्जा के किरण को संचारित करने और रडार पर वापस आने में लगने वाला समय भी हमें उस वस्तु की दूरी प्रदान करता है।

डॉपलर रडार

- उनके डिजाइन से, डॉपलर रडार सिस्टम लक्ष्य की गति के साथ-साथ उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
- जब रडार रेडियो तरंगों के को प्रसारित करता है, तो सिस्टम उन पल्स के चरण (आकार, स्थिति और रूप) पर नज़र रखता है।
- एक संचरित नाड़ी और एक प्राप्त प्रतिध्वनि के बीच चरण में बदलाव (या परिवर्तन) को मापकर, रडार से सीधे या दूर लक्ष्य की गति की गणना की जाती है।
- एक सकारात्मक चरण पारी का अर्थ है रडार की ओर गति और एक नकारात्मक बदलाव रडार से गति को इंगित करता है।
- चरण परिवर्तन प्रभाव ध्वनि तरंगों के साथ देखे गए "डॉपलर शिफ्ट" के समान है। "डॉपलर शिफ्ट" के साथ, ध्वनि तरंगों के संपीड़न (चरण में बदलाव) के कारण आपके स्थान की ओर बढ़ने वाली वस्तु की ध्वनि पिच अधिक होती है। जैसे ही कोई वस्तु आपके स्थान से दूर जाती है, ध्वनि तरंगें खिंच जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप कम आवृत्ति होती है।

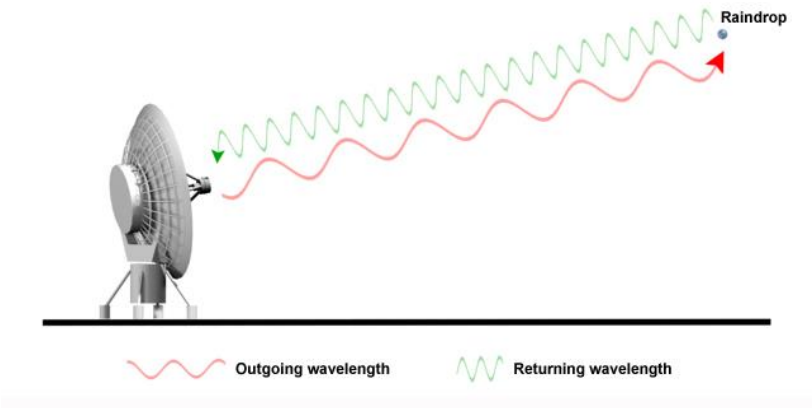

रक्षा / आंतरिक सुरक्षा / सुरक्षा

राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल(National Cybercrime Reporting Portal)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - साइबर स्पेस

समाचार में-

- गृह मंत्रालय (**MHA)** ने सभी राज्यों को राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (**www.cybercrime.gov.in)** पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (**FIR)** की जांच और पंजीकरण करने के लिए लिखा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- कम रूपांतरण दर: गृह मंत्रालय के अनुसार, पोर्टल पर पंजीकृत कुल शिकायतों का केवल 2.5% FIR में परिवर्तित होता है।
- साइबर अपराध स्वयंसेवक: पोर्टल के माध्यम से, सरकार अवैध / गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री की पहचान, रिपोर्टिंग और हटाने के लिए साइबर अपराध स्वयंसेवकों को बढ़ावा देना चाहती है।
- मामलों में वृद्धि: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में पंजीकृत साइबर अपराधों की संख्या में 63.5% की वृद्धि हुई है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल

- यह एक नागरिक-केंद्रित पहल है जो नागरिकों को साइबर अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है।
- इसे 2019 में लॉन्च किया गया था।
- यह पोर्टल विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, बाल पोर्नोग्राफी, रेप / सामूहिक बलात्कार से संबंधित ऑनलाइन सामग्री आदि के खिलाफ अपराधों पर केंद्रित है।
- यह साइबर हमलों आदि जैसे अपराधों पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
- यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता में सुधार करेगा।

बुडापेस्ट कन्वेंशन

- यूरोप काउंसिल ऑफ साइबर क्राइम कन्वेंशन, जिसे बुडापेस्ट कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, साइबर अपराध पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से एकमात्र बहुपक्षीय संधि है।
- यह राष्ट्र-राज्यों के बीच साइबर अपराध जांच का समन्वय करता है और कुछ साइबर अपराध का संचालन करता है।
- भारत इसका पक्षकार नहीं है।

पिनका रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया(ENHANCED PINAKA Rocket successfully flight tested

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III - रक्षा और सुरक्षा

समाचार में

- ओडिशा तट के पास चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से पिनका रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया
- **विकसित:** रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, (डीआरडीओ) द्वारा

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह रॉकेट अत्याधुनिक दिशासूचक प्रणाली से लैस है जिसके कारण यह सटीकता से लक्ष्य की पहचान कर उसपर निशाना साधता है।
- इसे भारतीय सेना द्वारा तैनात किया जाएगा।
- पिनाका रॉकेट सिस्टम के उन्नत संस्करण मौजूदा पिनाका एमके-आई का स्थान लेंगे, जिसका वर्तमान में उत्पादन हो रहा है ।

DRDO भवन में एंटी सैटेलाइट (A-SAT) मिसाइल स्थापित किया गया।(Anti-Satellite (A-SAT) Missile installed inside the DRDO Bhawan)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - रक्षा और सुरक्षा

समाचार में

- हाल ही में, रक्षा मंत्री ने DRDO भवन में एक एंटी-सैटेलाइट मिसाइल के एक मॉडल का उद्घाटन किया।
- एंटी सैटेलाइट (A-SAT) मिसाइल प्रणाली को राष्ट्रीय तकनीकी प्रगति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- 'मिशन शक्ति' भारत का पहला एंटी-सैटेलाइट (ASAT) मिसाइल परीक्षण था जिसका 27 मार्च 2019 को ओडिशा के डॉ. एपी जे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।
- इसने लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) अर्थात निचली-कक्षा में तेजी से आगे बढ़ने वाले भारतीय परिक्रमा लक्ष्य उपग्रह को पिनपॉइंट सटीकता के साथ बेअसर कर दिया था।
- इसने भारत को बाहरी अंतरिक्ष में अपनी संपत्ति की रक्षा करने की क्षमता रखने वाला दुनिया का चौथा राष्ट्र बना दिया है।

कलवरी-क्लास सबमरीन INS वागीर को लॉन्च किया गया (Kalvari-Class Submarine INS Vagir launched)

भाग: GS प्रीलिम्स और जीएस- III - रक्षा और सुरक्षा

समाचार में

- भारतीय नौसेना के पांचवें कलवरी श्रेणी के डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी आईएनएस वागीर को मुंबई के मझगांव डॉक पर लॉन्च किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारतीय नौसेना पोत (INS) वागीर कलवरी श्रेणी की छह पनडुब्बियों में से पांचवां है, जिनका निर्माण भारत में किया जा रहा है।
- इस श्रेणी अन्य पोत आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांदेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला और आईएनएस वाघेशर हैं।
- इनमें से कलवरी और खांदेरी को 2017 और 2019 में कमीशन दिया गया है।
- वेला और करंज का अभी भी समुद्री परीक्षणों चल रहा हैं।
- वाघशीर अभी निर्माणाधीन है।

तकनीकी जानकारी

- पनडुब्बियों के कलवरी वर्ग का डिज़ाइन पनडुब्बियों के स्कॉर्पीन वर्ग पर आधारित है।
- पनडुब्बियों के इस वर्ग में डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम होता हैं।
- ये मुख्य रूप से पनडुब्बियों या हंटर-किलर प्रकार पर हमला करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रतिकूल नौसेना जहाजों को लक्षित और डुबाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- यह सतह पर आने पर 11 समुद्री मील की उच्चतम गति तक पहुँच सकते है और जल के अन्दर यह 20 समुद्री मील तक की की उच्चतम गति तक पहुँच सकते है।
- इन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) है जो सतह पर ऑक्सीजन तक पहुंच के बिना गैर-परमाणु पनडुब्बियों को लंबे समय तक संचालित करने में सक्षम बनाता है।

क्या आप जानते है?

- कलवरी (जिसका अर्थ टाइगर शार्क है) की तरह, वागीर का नाम एक सैंड फिश के नाम पर रखा गया है, जो एक शिकारी समुद्री प्रजाति है।
- खांदेरी का नाम छत्रपति शिवाजी द्वारा निर्मित एक द्वीप वाले किले के नाम पर रखा गया है।
- करंज का नाम मुंबई के दक्षिण में स्थित एक द्वीप के नाम पर भी रखा गया है।

क्विक रिएक्शन सतह से हवा मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया(Quick Reaction Surface-to-Air Missile System successfully test-fired)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - III- रक्षा और सुरक्षा

समाचार में

- हाल ही में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने क्विक रिएक्शन-सरफेस-टू-एयर अर्थात सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम (QRAMAM) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- QRSAM एक कनस्तर-आधारित प्रणाली है।
- इसका मतलब है कि यह विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए डिब्बों से संग्रहीत और संचालित है।

- कनस्तर में, अंदर के वातावरण को नियंत्रित किया जाता है, इस प्रकार इसके परिवहन और भंडारण को आसान बनाने के साथ-साथ हथियारों की शेल्फ लाइफ में भी काफी सुधार होता है।
- यह प्रणाली लक्ष्य का पता लगाने और ट्रैकिंग करने में सक्षम है और छोटे पड़ावों के साथ आकर्षक लक्ष्यों को पूरा करती है।
- यह कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एसएएम) प्रणाली है।
- यह मुख्य रूप से डीआरडीओ द्वारा दुश्मन के हवाई हमलों से सेना के बख्तरबंद स्तंभों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है।
- संपूर्ण हथियार प्रणाली को एक मोबाइल पर कॉन्फ़िगर किया गया है और यह इस कदम पर हवाई रक्षा प्रदान करने में सक्षम है।
- इसे सेना में शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

क्या तुम जानते हो?

- इसकी सीमा **25** से **30** किमी है।
- इसमें दो रडार भी होते हैं - एक्टिव ऐरे बैटरी सर्विलांस रडार और एक्टिव ऐरे बैटरी मल्टीफ़ंक्शन रडार - अन्य लॉन्चर के साथ।
- दोनों राडार में "चाल पर खोज" और "ट्रैक ऑन मूव" क्षमताओं के साथ **360**-डिग्री कवरेज है।
- सिस्टम एकल चरण ठोस प्रोपेल्ड मिसाइल का उपयोग करता है।

असम-मिजोरम सीमा पर अशांति (Unrest along Assam-Mizoram border)

संदर्भ: असम-मिजोरम सीमा पर हालिया हिंसा और तनाव दोनों राज्यों द्वारा अपनी सीमाओं के बारे में मतभेदों को रेखांकित करता है।

क्या आपको पता है?

- 1972 में मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में असम से बाहर किया गया था।
- मिजोरम 198**7** में एक राज्य बना।
- राष्ट्रीय राजमार्ग **306 (**पहले एनएच **5**4**)** असम और मिजोरम राज्य को जोड़ता है।
- मिजोरम एनएच 306 के माध्यम से अपनी सभी आवश्यक वस्तुओं**,** खाद्यान्नों**,** परिवहन ईंधन और विभिन्न अन्य वस्तुओं और मशीनों को फेरी करता है और इसलिए इसे मिजोरम की जीवन रेखा कहा जाता है

क्या अशांति शुरू हुई?

- दक्षिणी असम के बराक घाटी के तीन जिले - कछार**,** हैलाकांडी और करीमगंज - सीमा कोलासीब और मिज़ोरम के ममित जिले।
- 9 अक्टूबर को करीमगंज (असम) और ममित जिलों (मिजोरम) की सीमा क्षेत्र में दो मिजोरम निवासियों से संबंधित एक खेत की झोपड़ी और सुपारी के पेड़ में आग लगा दी गई।

- असम के कुछ लोगों ने अगले दिन मिजोरम के पुलिस कर्मियों पर कथित रूप से पथराव किया और मिजोरम के निवासियों ने जवाबी कार्रवाई की।
- असम स्थित संगठनों ने NH306 और मिजोरम की ओर जाने वाली अन्य सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। दोनों राज्यों के बीच बातचीत और गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद 22 अक्टूबर को नाकाबंदी हटा दी गई थी।
- लेकिन मिजोरम पुलिस ने विवादित क्षेत्रों से वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसके कारण 28 अक्टूबर से एक और नाकाबंदी की गई।
- स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाने की धमकी दी गई जब मिजोरम में इम्तियाज अली लस्कर नाम के एक असामयिक व्यक्ति की हिरासत में मौत हो गई। विले मिजोरम ने दावा किया कि वह एक ड्रग पेडलर था, असम ने कहा कि वह एक गरीब फायरवुड वर्कर था।

क्या अब तनाव कम हो गया है?

- सीमा सुरक्षा बल और सशत्रबल के कर्मियों ने सीमा पर तीन फ्लैशपोतों में गश्त करना शुरू किया तो तनाव कम हो गया है।
- **9** नवंबर को नाकाबंदी हटा दी गई थी।

क्या यह एकतरफा संघर्ष था?

- नहीं। असम-मिजोरम सीमा पर हिंसा की आखिरी घटना फरवरी 2018 में थी, जब मिज़ोर्ज़लाई पावल (छात्र संघ) ने एक जंगल में किसानों के लिए लकड़ी का विश्राम गृह बनाया था।
- असम पुलिस और वन अधिकारियों ने संरचना को ध्वस्त कर दिया, यह दावा किया कि यह असम के क्षेत्र में था।
- मिजो छात्र संघ के सदस्य असम के पुलिस कर्मियों से भिड़ गए, जिसके कारण तनाव बढ़ गया। हिंसा का पैमाना सीमा पर पहले रुक-रुक कर होने वाले संघर्षों से बड़ा था।

क्या मिजोरम का कोई और सीमा विवाद है?

- मिजोरम में त्रिपुरा के साथ सीमा मुद्दे भी हैं, विशेष रूप से उत्तरी त्रिपुरा जिले के फुलडुंगसी गांव पर दावों और जवाबी दावों पर।
- ब्रू आदिवासी लोगों द्वारा एक पुराने मंदिर को फिर से बनाने के लिए फुलडूंगसी मुद्दा, **2020** ऑक्टा नाकाबंदी के रूप में लगभग उसी समय भड़क गया था।

उत्पत्ति के कारण?

असम का तर्क	मिजोरम का तर्क
असम में अधिकारियों का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार चुनाव लड़ने वाली भूमि असम की है।	मिजोरम के अधिकारियों ने कहा कि असम के लोगों ने यथास्थिति का उल्लंघन किया - जैसा कि कुछ साल पहले दो राज्य सरकारों के बीच सहमति हुई थी - वर्तमान संकट को ट्रिगर करने के लिए "किसी व्यक्ति की भूमि" में नहीं।
असम में अधिकारियों और स्थानीय लोगों का दावा	मिजोरम के समूह असहमत हैं, उनका दावा है कि

है कि मिज़ोस अंतर-राज्य की सीमा से 1-3 किमी दूर क्षेत्रों में स्क्वैट कर रहा है।	असम में अधिकारी "अवैध बांग्लादेशियों" का इस्तेमाल अपने क्षेत्र में 10-12 किलोमीटर अंदर करने के लिए कर रहे हैं
असम सीमाओं के सीमांकन के लिए 1933 के ब्रिटिश युग की अधिसूचना का अनुसरण करता है।	मिज़ो नेताओं का कहना है कि यह **1**933 की अधिसूचना स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उनके पूर्वजों से सलाह नहीं ली गई थी।

क्या पूर्वोत्तर में अन्य सीमा मुद्दे हैं?

- असम में मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर सभी उत्तर-पूर्वी पड़ोसियों के साथ सीमा संबंधी समस्याएं हैं, जो अलग-अलग संस्थाओं के रूप में मौजूद थीं।
- राज्य पुनर्गठन के बाद की स्वतंत्रता: का प्राथमिक कारण यह है कि अन्य राज्य, जो ब्रिटिश शासन के दौरान असम के सभी भाग थे, सीमाओं का मुकाबला किया है क्योंकि वे असम से अलग हो गए थे और समय के साथ-साथ पूर्ण राज्य बन गए (नागालैंड राज्य में) 1963, 1971 में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य; अरुणाचल प्रदेश और 1987 में मिजोरम राज्य का दर्जा)
- संवैधानिक समाधान बनाम ऐतिहासिक आधार: असम ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित सीमा आयोगों की कई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अन्य राज्य "ऐतिहासिक सीमाओं" से चिपके हुए हैं जो 1826 से पहले की अवधि में वापस चले जाते हैं, जब ब्रिटिश ने असम को विभाजित किया और इसमें शामिल किया इसके प्रांतों के रूप में पहाड़ियों।
- नागालैंड का मुद्दा: नागालैंड सरकार जोर देकर कह रही है कि 1960 का 16-बिंदु समझौता, जिसके कारण नागालैंड का निर्माण हुआ, इसमें उन सभी नगा प्रदेशों का "जीर्णोद्धार" भी शामिल था, जो अंग्रेजों के सफाये के बाद नागालैंड के बाहर स्थानांतरित कर दिए गए थे। 1826 में असम।
- मेघालय का मुद्दा: मेघालय ने 1971 के असम पुनर्गठन अधिनियम को चुनौती दी है, जिसमें दावा किया गया है कि असम के कार्बीअंगलोंग जिले के दो ब्लॉक 1835 में बनाए गए संयुक्त खासी और जयंतिया हिल्स के थे।
- असम का दृष्टिकोण: असम का कहना है कि उसके पड़ोसियों ने 75,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। असम सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में कहा गया है कि नागालैंड ने 2001 के बाद से 19,819.62 हेक्टेयर, अरुणाचल प्रदेश में 5,756.02 हेक्टेयर और मेघालय में 65.62 हेक्टेयर में अतिक्रमण किया है।

आगे की राह

- **आम आदमी द्वारा उत्पन्न किया गया बोझ:** सीमा के निवासियों को अशांति का खामियाजा भुगतना पड़ेगा जब तक कि कोई स्वीकार्य समाधान नहीं निकलता है।
- अंतर-राज्य सीमा के साथ केंद्रीय बलों के साथ दोनों राज्यों के पुलिस कर्मियों द्वारा संयुक्त गश्त का आयोजन।
- **शांति और व्यवस्था बनाए रखना:** विवादास्पद सीमा की रखवाली के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने के अलावा**,** राज्य सरकारों को सीमा पर आने वाले अपराधियों और असामाजिक

गतिविधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के बीच समन्वय को मजबूत करना होगा।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट
- **नागा मुद्दा**

हिमालय में वाटर बम (Water bomb in the Himalayas)

संदर्भ: 1962 के युद्ध के बाद से भारत-चीन के संबंध अपने सबसे निचले बिंदु पर हैं, अतः सीमा पर बुनियादी ढांचे की गहन जांच की गई है।

चीनी पक्ष पर यारलुंग (ब्रह्मपुत्र) नदी के किनारे कई बांधों का निर्माण भारतीय अधिकारियों और स्थानीय लोगों के लिए चिंता का कारण रहा है, जिनकी आजीविका और सुरक्षा नदी पर निर्भर करती है।

ब्रह्मपुत्र नदी की अजीबोगरीब विशेषताएं जो चिंता का कारण हैं

- **दो बारबाढ़:** नदी के साथ आने वाले निवासियों को सालाना दो बार बाढ़ से निपटना पड़ता है, एक गर्मियों में हिमालय की बर्फ के पिघलने के कारण और दूसरा मानसून प्रवाह के कारण
- **जलवायु परिवर्तन के खतरे:** इन बाढ़ों की आवृत्ति बढ़ गई है और जलवायु परिवर्तन और उच्च और निम्न प्रवाह पर इसके प्रभाव के कारण विनाशकारी हैं।
- **प्रकृति में गतिशील:** नदी अपने आप में गतिशील है क्योंकि अक्सर भूस्खलन और भूगर्भीय गतिविधि इसे बहुत बार पाठ्यक्रम बदलने के लिए मजबूर करती है।

चीन के पानी के मुद्दे

- **संसाधन की कमी:** चीन, जो दुनिया की आबादी का 20 प्रतिशत के करीब है, के पास अपने जल संसाधनों का केवल 7 प्रतिशत है।
- **औद्योगीकरण का परिणाम:** तेजी से औद्योगिकीकरण के कारण इसकी सतह और भूजल का गंभीर प्रदूषण चीनी योजनाकारों के लिए चिंता का विषय है।
- **चीन के भीतर क्षेत्रीय असंतुलन:** पानी के दबाव वाले उत्तरी भाग की तुलना में चीन के दक्षिणी क्षेत्र पानी से समृद्ध हैं। दक्षिणी क्षेत्र एक प्रमुख खाद्य उत्पादक है और वहां रहने वाले अधिक लोगों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षमता है।
- **नदी के बीच की योजनाएँ:** चीन की नहरों, एक्वाडक्ट्स और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख नदियों को जोड़ने के माध्यम से अपने दक्षिण (पानी से समृद्ध) और उत्तर (पानी पर जोर) को जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन:** उपरोक्त लक्ष्यों की खोज में, चीन, एशिया में एक ऊपरी रिप्रियनियन राज्य होने के नाते, मेकांग और उसकी सहायक नदियों जैसे नदियों को अवरुद्ध कर रहा है, जिससे थाईलैंड, वियतनाम,

लाओस और कंबोडिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश प्रभावित होते हैं। इसने क्षेत्र में पर्यावरण और परिवर्तित नदी के प्रवाह को काफी नुकसान पहुंचाया है

- **भू-राजनीतिक उपकरण:** चीन द्वारा इस तरह की परियोजनाओं में गतिरोध और उच्च तनाव के समय में प्रवाह दर को बदलने की क्षमता है। वास्तव में, भारत और चीन के बीच **2018** डोकलाम सीमा गतिरोध के दौरान, चीन ने अपने बांधों से जल प्रवाह के स्तर के संचार को रोक दिया, प्रभावी रूप से भारत को गतिरोध के दौरान बाढ़ के लिए अंधा प्रदान किया।
- **हेगामोनिक एटिट्यूड:** चीन इस तरह की परियोजनाओं को अपनी ऐतिहासिक सहायक प्रणाली की निरंतरता के रूप में देखता है क्योंकि छोटे राज्यों के पास प्रभावी ढंग से बातचीत करने या यहां तक कि महत्वपूर्ण लाभ उठाने का कोई साधन नहीं है। हिमालय में चीनी परियोजनाएं हाल ही में भारत के विरोध के बीच शुरू हुई हैं।

यारलुंग त्संगपो बेसिन में अब अधिक परिचालन बांधों के साथ और निर्माणाधीन कई परिचालन बांध हैं। ये निर्माण भारतीय योजनाकारों के लिए एक अनूठी चुनौती पेश करते हैं क्योंकि

1. **इससे पूरे बेसिन का क्षरण होगा**
    - नदी द्वारा किए गए गाद की भारी मात्रा में बांधों को अवरुद्ध कर दिया जाएगा, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आएगी और कृषि उत्पादकता में कमी आएगी।
2. **पारिस्थितिक विविधता पर प्रभाव**
    - ब्रह्मपुत्र बेसिन दुनिया के सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। इसकी पहचान दुनिया के **34** जैविक हॉटस्पॉटों में से एक के रूप में की जाती है।
    - यह क्षेत्र वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियों को देखता है जो दुनिया के केवल इस हिस्से के लिए स्थानिक हैं - काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में **35** स्तनधारी प्रजातियां हैं, जिनमें से **15** को **IUCN** संरक्षण सूची में खतरे के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
    - नदी स्वयं गंगा नदी डॉल्फिन का घर है, जिसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है
    - पानी के बहाव में कमी से आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र के वनस्पतियों और जीवों के नकारात्मक परिणाम होंगे
3. **आपदाओं का खतरा**
    - हिमालय में बांधों का स्थान जोखिम पैदा करता है। भूकंपविज्ञानी हिमालय को भूकंप और भूकंपीय गतिविधि के लिए सबसे अधिक संवेदनशील मानते हैं।
    - भूकंप से उत्पन्न भूस्खलन ने एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर दिया - **2015** नेपाल भूकंप और परिणामी भूस्खलन ने कई बांधों और अन्य सुविधाओं का सफाया कर दिया।
    - चीन द्वारा शुरू की गई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का व्यापक आकार भूकंप और भूस्खलन के क्षेत्र की भेद्यता को बढ़ाता है
4. **जीवन और आजीविका खतरे में है**
    - भारत में ब्रह्मपुत्र बेसिन में दस लाख के करीब लोग रहते हैं और दसियों लाख बांग्लादेश में नीचे की ओर बहते हैं।
    - हिमालय में परियोजनाओं से सैकड़ों हजारों लोगों के अस्तित्व को खतरा है।

आगे का रास्ता: जल संकट को हल करने के लिए वैकल्पिक उपाय हैं।

- दोनों पक्षों को नदी पर नए निर्माण को रोकना चाहिए और संभावित रूप से कम विनाशकारी समाधान के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।
- चेक बांधों, वर्षा-कैप्चरिंग झीलों के विकेन्द्रीकृत नेटवर्क का निर्माण और पानी पर कब्जा करने के पारंपरिक साधनों का उपयोग करके स्थायी रूप से क्षेत्रों की आबादी का समर्थन करते हुए पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने में प्रभावी परिणाम दिखाए गए हैं।
- इस वाटर बम को बेअसर करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ आना चाहिए

ब्रह्मोस मिसाइल का भूमि-पर हमला करने वाले संस्करण सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया (Land-attack Version of BrahMos Missile successfully test-fired)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS -III - रक्षा और सुरक्षा

समाचार में

- हाल ही में, भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के भूमि-हमले संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- मिसाइल की रेंज को मूल 290 किमी से 400 किमी तक बढ़ाया गया है।
- इसकी गति 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना बनाए रखी गई है।
- परीक्षण "टॉप-अटैक" कॉन्फ़िगरेशन में किया गया था।
- शीर्ष हमले मोड में, मिसाइल को लॉन्च के बाद तेजी से चढ़ने, एक निश्चित ऊंचाई पर यात्रा करने और फिर लक्ष्य के ऊपर गिरने की आवश्यकता होती है।
- सीधे हमले के मोड में, मिसाइल कम ऊंचाई पर यात्रा करती है, सीधे लक्ष्य को भेद सकती है।

भारतीय नौसेना द्वारा सी-गार्जियन ड्रोन (Sea Guardian Drones from USinducted by the Indian Navy)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS- III - रक्षा और सुरक्षा

समाचार में

- हाल ही में, दो अमेरिकी MQ9B सी गार्जियन निहत्थे ड्रोन को भारतीय नौसेना द्वारा शामिल किया गया है।
- ड्रोन एक वर्ष के लिए भारत के साथ पट्टे पर होगा।

महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन

एमक्यू 9 बी सी गार्जियन

- यह प्रीडेटर MQ9 मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) का समुद्री संस्करण है।
- इसमें 40 घंटे की अधिकतम सहनशीलता और 40,000 फीट की अधिकतम उड़ान ऊंचाई है।
- इसमें 3600 समुद्री निगरानी रडार और एक वैकल्पिक मल्टीमोड समुद्री सतह खोज रडार है।
- इसका उपयोग एंटी-सरफेस वारफेयर, एंटी-सबमरीन वारफेयर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस / डिजास्टर रिलीफ, सर्च एंड रेस्क्यू, लॉ एनफोर्समेंट (ड्रग ट्रैफिकिंग, अवैध इमिग्रेशन और पाइरेसी), आदि जैसे ऑपरेशन्स में किया जा सकता है।
- ड्रोन हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी करने के लिए हैं और जरूरत पड़ने पर चीन सीमा पर तैनात किए जा सकते हैं।

सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (Information Management And Analysis Centre -IMAC)

भाग: GS प्रीलिम्स और GS - **III** - रक्षा और सुरक्षा

समाचार में

- सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (**IMAC)** हाल ही में 26/11 हमलों की **12** वीं वर्षगांठ के संबंध में समाचार में था।

महत्वपूर्ण बिंदु

- IMAC की स्थापना नवंबर 2014 में हुई थी।
- यह गुड़गांव, भारत में स्थित है।
- यह नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है।
- यह समुद्री सुरक्षा जानकारी के एकत्रीकरण और प्रसार के लिए नोडल केंद्र है।
- यह भारत के हित क्षेत्र में समुद्री यातायात की निगरानी के लिए राष्ट्रीय कमान नियंत्रण संचार और खुफिया नेटवर्क की आधारशिला है।
- IMAC का कार्य विभिन्न राष्ट्रीय हितधारकों के बीच समुद्री सुरक्षा सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना और एक सामान्य परिचालन चित्र तैयार करना है।
- IMAC केवल गैर-सैन्य या वाणिज्यिक जहाजों को ट्रैक करता है, जिन्हें सफेद शिपिंग के रूप में जाना जाता है।
- सैन्य जहाजों, या ग्रे पतवार वाले जहाजों को नौसेना संचालन निदेशालय द्वारा ट्रैक किया जाता है, क्योंकि यह एक वर्गीकृत नेटवर्क पर है।

विविध

समाचार में	विवरण
1. सुपर टाइफून गोनी	• साल 2020 का अब तक का दुनिया का सबसे खरतनाक तूफ़ान माना जा रहा सुपर टाइफून गोनी दक्षिणी फिलीपींस के लूजोन के मुख्य द्वीप तक पहुँच गया है। साल 2013 के Haiyan तूफ़ान के बाद से फिलीपींस को हिट करने वाला गोनी सबसे तेज तूफानों में से एक है, जिसमें लगभग 6,300 से अधिक लोग मारे गए थे। • लगभग दस लाख लोगों वंहा से निकाला गया है। • वर्ष का अब तक का सबसे शक्तिशाली आंधी-तूफान कैटांडुआनस द्वीप पर आया। • एक हफ्ते पहले, टाइफून मोलवे भी उसी क्षेत्र से टकराया था।
2. सुपर टाइफून	• 2009 से हांगकांग ऑब्जर्वेटरी ने टाइफून को तीन अलग-अलग वर्गीकरणों में विभाजित किया है: टाइफून, गंभीर टाइफून और सुपर टाइफून। • एक टाइफून में हवा की गति 64-79 समुद्री मील (73–91 मील प्रति घंटा; 118–149 किमी / घंटा) होती है, एक गंभीर टाइफून में कम से कम 80 समुद्री मील (92 मील प्रति घंटे; 150 किमी / घंटा) और एक सुपर टाइफून में कम से कम 100 समुद्री मील (120 मील प्रति घंटे; 190 किमी / घंटा) की हवाएं प्रवाहित होती है ।
3. क्रॉनिक ट्रॉमैटिक एन्सेफैलोपैथी **(CTE)**	• यह एक ऐसी बीमारी है जो बार-बार सिर की चोटों के कारण मस्तिष्क को गंभीर नुकसान पहुंचाती है और स्मृति हानि, अवसाद और मनोभ्रंश से जुड़ी होती है। • पूर्व मुक्केबाजों का सबसे अधिक निदान किया जाता है। • हालांकि, प्रो कुश्ती, मिश्रित मार्शल आर्ट, आइस हॉकी, रग्बी, बेसबॉल, ऑस्ट्रेलियाई नियम फुटबॉल और फुटबॉल जैसे कई अन्य संपर्क खेलों में सीटीई के उदाहरण हैं। • मनोभ्रंश स्मृति, भाषा, समस्या को सुलझाने और अन्य सोच क्षमताओं के नुकसान के लिए एक सामान्य शब्द है जो दैनिक जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए गंभीर है। • अल्जाइमर मनोभ्रंश का सबसे आम कारण है।
4. COVID-19 शक्ति चैलेंज	• संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के सहयोग से **MyGov** ने अप्रैल **2020** में **COVID-19** शक्ति चैलेंज शुरू किया। • **उद्देश्य:** महिलाओं को प्रोत्साहित करने और स्टार्टअप को शामिल करने

	के लिए अभिनव समाधानों के साथ आने के लिए जो **COVID19** के खिलाफ लड़ाई में मदद कर सकते हैं या उन समस्याओं को हल कर सकते हैं जो बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रभावित करती हैं। • इस चुनौती को **MyGov** के इनोवेट प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया गया था जिसने महिलाओं से स्टार्टअप्स के साथ-साथ स्टार्टअप्स के लिए भी आवेदन किया था जिनके पास ऐसे समाधान हैं जो बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों का समाधान करते हैं।
5. मलखंब	• खेल का यह प्राचीन भारतीय रूप चिन्मयपत्तनकर और प्रज्ञापत्तनकर नामक युगल के प्रयासों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में खिलाड़ियों की एक स्थिर धारा में आ रहा है। • मल्लखंब उन कुछ खेलों में से एक है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खेले जाते हैं। • यह मन और शरीर के तालमेल पर कार्य करता है**,** प्रत्येक पेशी को इस तरह से नियोजित करता है जो व्यक्ति को गति, सहनशक्ति और बेहतर स्वास्थ्य विकसित करने में सक्षम बनाता है। • नाम पहलवानों द्वारा अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पोल से निकला है। • फिर भी, दो अन्य मल्लखंभ की शैलियाँ हैं, जैसे 'रस्सी मल्लखंब' और 'हैंगिंग मल्लखंभ'। • इसकी उत्पत्ति का पता 12 वीं शताब्दी के पूर्व भाग से लगाया जा सकता है। • लकड़ी के खंभे पर अभ्यास करने वाले पहलवानों का उल्लेख **1153** ईस्वी में चालुक्य द्वारा लिखित मानशोलों में मिलता है। • इसे **19** वीं शताब्दी में देर से पुनर्जीवित किया गया था**,** बलभट्ट दादा देवधर**,** बाजीराव पेशवा **II** के भौतिक प्रशिक्षक थे।
6. लीशमैनियासिस	• पूर्ण शोध कार्य/योगदान को मान्यता देने के लिए सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्स (इंडिया)नेडॉ सुशांत कार**,** वरिष्ठ वैज्ञानिक**,** मोलेक्युलर पेरासीटोलोजी एंड इम्यूनोलॉजीविभाग**,** सीएसआईआर-सीडीआरआई**,** लखनऊ को इस साल के प्रोफेसर ए.एन. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड के लिए चुना है। • लीशमैनिया डोनोवानी एक प्रोटोजोआ परजीवी है जो मैक्रोफेज को संक्रमित करता है। • यह आंत के लीशमैनियासिस (काला अजार) का एक प्रेरक एजेंट है**,** जो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए घातक संक्रामक बीमारी है।

7. मोटो टनल	• हाल ही में, पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अयूबिया नेशनल पार्क में पुनरुद्धार के बाद पर्यटकों के लिए 129 वर्षीय मोटो टनल खोला। • यह 250 फीट लंबा, 6 फीट ऊंचा और 4 फीट चौड़ा मोटो टनल पत्थर और मिट्टी से बना है। • यह अयूबिया राष्ट्रीय उद्यान में 'प्रकृति पाइपलाइन वॉक' का भाग है।
8. विल्मायापतजक्सा फीमेल हंटर	• **9,000** साल पहले की एक महिला किशोर की पहचान अमेरिका में पाए जाने वाले सबसे पुराने दफन की गयी शिकारी के रूप में की गई है। • इस खोज ने इस धारणा को पलट दिया है कि शिकार केवल एक पुरुष डोमेन था जबकि महिलाएं केवल इकट्ठा होती थीं। • दफन रिकॉर्ड का विश्लेषण इंगित करता है कि एक समान अवधि के 30-50% शिकारी महिला थे। • लगभग 9,000 साल पहले, शिकारी कुत्तों ने दक्षिण अमेरिका के एंडीज पहाड़ों में एक किशोरी को शिकार के औजार के साथ दफनाया था। • जब शोधकर्ताओं ने अवशेषों का विश्लेषण किया, तो 2018 में पता चला, उन्होंने पाया कि शिकारी एक महिला थी, जिसकी मृत्यु 17 से 19 के बीच थी। • 2018 में पेरू में उच्च ऊंचाई वाली साइट विल्मायापात्जक्सा में खुदाई के दौरान, पुरातत्वविदों को छह व्यक्तियों के साथ पांच दफन गड्ढे मिले। • विल्मायापात्जक्सा मादा शिकारी को अमेरिका में पाए जाने वाले सबसे पुराने शिकारी दफन के रूप में पहचाना गया है
9. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव	• डेमोक्रेट जो. बिडेन को अमेरिका के 46 वें राष्ट्रपति बनने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प को हराकर 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। • डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। • हैरिस को संयुक्त राज्य की सीनेट का सदस्य बनने के लिए भारतीय-अमेरिकी और अफ्रीकी-अमेरिकी मूल की पहली महिला होने का श्रेय भी दिया जाता है। • लोकप्रिय मतों द्वारा चुने गए निर्वाचक मंडल के प्रतिनिधि अगले महीने

	की 14 तारीख को आधिकारिक रूप से नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए अपने वोट डालेंगे। • इसके बाद नए राष्ट्रपति उद्घाटन समारोह के बाद अगले साल 20 जनवरी को कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे।
10. बंदरगाह मंत्रालय, जहाजरानी और जलमार्ग	• भारतीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि भारत सरकार जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदल रही है। • इसे पोर्ट, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा।
11. जिंगटांग बंदरगाह	• जिंगटांग बंदरगाह हाल ही में खबरों में था। • जग आनंद नाम का जहाज इस साल जून से चीन के हेबेई प्रांत में तांगशान के पास चीनी बंदरगाह जिंगतांग में लंगर का इंतजार कर रहा था। • चीन ने जहाज को प्रस्थान से इनकार करने के लिए **COVID-19** नियमों का हवाला दिया है • पोर्ट ऑफ जिंगटांग उत्तरी चीन में तांगशान नगर पालिका, हेबै के तट पर एक कृत्रिम गहरे पानी का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। • जिंगतांग बंदरगाह टियांजिन बंदरगाह के करीब बोहाई खाड़ी (बोहासिया) में स्थित है।
12. स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट	• हाल ही में, स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान छह लोगों के एक दल को छह महीने के लंबे मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) तक ले जाएगा। • मिशन नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम का भाग है। • **उद्देश्य:** अपनी लागत के संदर्भ में अंतरिक्ष तक पहुंच को आसान बनाने के लिए, ताकि कार्गो और चालक दल को आईएसएस से और अधिक आसानी से ले जाया जा सके, जिससे अधिक से अधिक वैज्ञानिक शोध हो सके। • आईएसएस में, क्रू **-1** टीम माइक्रोग्रैविटी अध्ययन करेगी और नए विज्ञान हार्डवेयर और प्रयोगों को वितरित करेगी जो वे क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार होने के लिए अपने साथ ले जाएंगे। • यह नासा द्वारा प्रमाणित पहला अंतरिक्ष यान है। इसका मतलब है कि स्पेसएक्स अब अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नियमित उड़ानें संचालित कर सकता है। • इससे पहले मई में, नासा के स्पेसएक्स डेमो -2 परीक्षण उड़ान ने आईएसएस के लिए उड़ान भरी थी, जो 2011 में अंतरिक्ष शटल युग के समापन के बाद से अमेरिकी मिट्टी से लॉन्च करने वाली पहली

	चालक दल वाली उड़ान बन गई।
13. लियोनिद उल्का बौछार	• लियोनिद उल्का वर्षा वर्तमान में भारत में अपनी वार्षिक उपस्थिति बना रहे हैं। • लियोनिड्स , टेम्पल-टटल धूमकेतु से निकलते हैं। • इस धूमकेतु को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 33 साल लगते हैं • ये उल्काएं चमकीली होती हैं और सबसे तेज चलती हैं। • लियोनिड्स का जन्म नक्षत्र लियो द लायन से हुआ है • जैसे ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह बड़े ब्रह्मांडीय मलबे से गुजरती है। ये मलबे धूमकेतु के अवशेष होते हैं। • धूमकेतु द्रव्य के जमे हुए टुकड़े हैं। यह बर्फ और चट्टान की ट्रेल्स को छोड़ देता है जो धूमकेतु के गुजरने के बाद भटकते हैं। • जब पृथ्वी इन अवशेषों से गुजरती है, तो वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह की ओर नीचे गिरने लगते हैं। नीचे गिरते समय, वे पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण के कारण आग पकड़ लेते हैं। • अवशेषों का यह आग का गोला उल्का वर्षा कहलाता है।
15. शांति की प्रतिमा	• भारतीय प्रधान मंत्री ने जैनाचार्य श्री विजय वल्लभसूरीश्वरजी महाराज की 151 वीं जयंती समारोह को चिह्नित करने के लिए 'स्टैच्यू ऑफ़ पीस' का अनावरण किया। • वह एक जैनचार्य थे। • प्रतिमा अष्टधातु यानी 8 धातुओं से बनाई गई है, जिसमें तांबा प्रमुख घटक है। • यह राजस्थान के पाली में विजय वल्लभसाधना केंद्र, जेटपुरा में स्थापित है।
16. श्री विजय वल्लभसूरीश्वरजी महाराज (1870-1954)	• उन्होंने एक जैन संत के रूप में निष्ठापूर्वक जीवन व्यतीत किया और भगवान महावीर के संदेश को फैलाने के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। • उन्होंने जनता के कल्याण, शिक्षा के प्रसार, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए भी अथक परिश्रम किया, उन्होंने प्रेरक साहित्य लिखा और स्वतंत्रता आंदोलन और स्वदेशी का सक्रिय समर्थन दिया।
17. जॉली ग्रांट एयरपोर्ट	• उत्तराखंड के पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार के लिए एक परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं। • देहरादून हवाई अड्डे को जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता

	है। • यह गढ़वाल के एयर गेटवे के रूप में भी जाना जाता है और उत्तराखंड के पर्यटन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। • उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए इसे अपग्रेड करने के उद्देश्य से देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार का प्रस्ताव दिया है। • यह देहरादून जिले के डोईवाला गाँव में **87** हेक्टेयर वन भूमि और परियोजना के लिए **17.41** हेक्टेयर गैर-वन भूमि का प्रस्ताव है।
18. तूफान Iota	• तूफान **Iota** ने हाल ही में मध्य अमेरिका के निकारागुआ में लैंडफॉल बनाया। • यह एक श्रेणी पांच तूफान में विकसित हुआ है। • अटलांटिक तूफान का मौसम जून से नवंबर तक चलता है और अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को कवर करता है। • पूर्वी प्रशांत तूफान का मौसम **15** मई से **30** नवंबर तक चलता है।
19. उष्णकटिबंधीय चक्रवात या तूफान	• ऐसे चक्रवात ईंधन के रूप में गर्म, नम हवा का उपयोग करते हैं। • इसलिए, वे भूमध्य रेखा के पास गर्म महासागरीय जल बनाते हैं। • उष्णकटिबंधीय महासागर जो अटलांटिक महासागर या पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर बनते हैं, तूफान कहलाते हैं। • उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में बनने वाले लोगों को टाइफून कहा जाता है। • उष्णकटिबंधीय तूफान जो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बनते हैं, चक्रवात कहलाते हैं। • तूफान को सैफिर-सिम्पसन तूफान पवन पैमाने पर वर्गीकृत किया गया है, जो उन्हें हवा की गति के आधार पर **1** से **5** के पैमाने पर दर देता है। • तूफान जो तीन या उच्च श्रेणी में पहुंचते हैं, उन्हें प्रमुख तूफान कहा जाता है क्योंकि उनकी वजह से जीवन और संपत्ति को विनाशकारी नुकसान होता है।
20. लीलावती पुरस्कार -2020	• हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने वस्तुतः लीलावती पुरस्कार -2020 लॉन्च किया। • यह AICTE का (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अभिनव शिक्षा कार्यक्रम है। • **विषय:** महिला सशक्तिकरण

	• **उद्देश्य:** स्वच्छता स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता, रोजगार, महिलाओं के बीच अधिकार आदि जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
21. बुकर पुरस्कार	• स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट ने अपने पहले उपन्यास शगनी बैन के साथ फिक्शन के लिए **2020** बुकर पुरस्कार जीता है, जिसमें **1980** के दशक में ग्लासगो में एक लड़के को एक नशे की लत से जूझते हुए बड़ा होने का वर्णन किया गया था।
22. भारत-थाईलैंड समन्वित गश्ती	• हाल ही में, भारत-थाईलैंड समन्वित गश्ती (कॉर्पैट) के **30** वें संस्करण का समापन मलक्का जलडमरूमध्य के पास अंडमान सागर में किया गया है। • भारत और थाईलैंड 2005 से एक वर्ष में दो बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ कॉर्पोरेट को आगे बढ़ा रहे हैं। • **उद्देश्य:** (1) वाणिज्यिक शिपिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हिंद महासागर का भाग सुरक्षित और सुरक्षित रखना; (2) समुद्र के कानून (**UNCLOS)** पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
23. इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल	• इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय का कैलेंडर इवेंट है जो शिलॉन्ग में सालाना बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। • हाल ही में **COVID-19** महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। • यह भारत में एकमात्र चेरी ब्लॉसम त्योहार है।
24. चेरी ब्लॉसम	• यह जीनस प्रूनस के कई पेड़ों का एक फूल है। • **Prunuscerasoides** को जंगली हिमालय चेरी, भारतीय जंगली चेरी और खट्टा चेरी भी कहा जाता है। • इसे हिंदी में पदम, पज्जा, या पद्माक्ष के रूप में जाना जाता है। • हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिंदुओं के बीच, यह पवित्र माना जाता है और विष्णु और शिव से सम्बंधित है।
25. SITMEX	• भारतीय नौसेना (IN) जहाजों ने हाल ही में अंडमान सागर में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास SITMEX-20 के दूसरे संस्करण में भाग लिया। • जहाजों में स्वदेशी तौर पर निर्मित ASW corvette Kamorta और मिसाइल कार्वेट करमुक शामिल थे। • IN, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी (RSN) और रॉयल थाई नेवी (RTN) के बीच आपसी अंतर-संचालन को बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए SITMEX श्रृंखला का आयोजन किया जाता है।

	• आरएसएन द्वारा अभ्यास के 2020 संस्करण की मेजबानी की जा रही है।
26.SIMBEX-20	• भारतीय नौसेना भारत के **27** वें संस्करण की मेजबानी करने वाली है - सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SIMBEX-20 2**3** नवंबर को अंडमान सागर में आयोजित हुआ। • इस अभ्यास को आपसी अंतर-संचालन को बढ़ाने और एक दूसरे से सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था हैं। • **SIMBEX** का **2020** संस्करण अभिन्न चेतक हेलीकाप्टर के साथ विध्वंसक राणा और स्वदेश निर्मित कोरवेट कामोर्टा और करमुक सहित भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा भागीदारी की।
27. रोडचेनकोव अधिनियम	• रोडचेनकोव अधिनियम हाल ही में खबरों में था। • यह अमेरिकी सीनेट द्वारा पारित किया जाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। • यह यूएसए को डोपिंग रिंग में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देता है**,** भले ही वे यूएसए के निवासी न हों या यदि डोपिंग का कार्य यूएसए के बाहर हुआ हो। • रोडचेनकोव अधिनियम का मुख्य उद्देश्य एथलीटों के बीच दवाओं की सुविधा प्रदान करना है।

IASbaba's
Baba's 8 fold path to success!!
e - Classroom Learning Programme (eCLP)
UPSC - 2021
Learn more

अपने ज्ञान का परीक्षण करें)

मॉडल प्रश्न: (उत्तर अंत में दिए गए हैं)

Q.1 मानसर झील कहाँ स्थित है?

a) जम्मू और कश्मीर
b) उड़ीसा
c) राजस्थान
d) हिमाचल प्रदेश

Q.2 रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है।
2. प्रत्येक राज्य को ढांचे के रूप में अपने स्वयं के कानून के साथ अपना नियामक स्थापित करना होगा।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.3 हाल ही में 16 साइकी (16 Psyche) चर्चा में था। यह निम्नलिखित में से किससे सम्बंधित है?

a) मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्रग्रह की परिक्रमा।
b) ग्रह बृहस्पति के नए खोजे गए चंद्रमा।
c) 2022 में मंगल पर भेजे जाने वाले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान।
d) उल्कापिंड जो दिसंबर में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा

Q.4 प्रथम सीप्लेन परियोजना का उद्घाटन हाल ही में भारत के किस राज्य में किया गया है?

a) गुजरात
b) महाराष्ट्र
c) केरल
d) तमिलनाडु

Q.5 हाल ही में, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में डेयरी उत्पादन के निशान हाल ही में पाए गए:

a) गुजरात
b) राजस्थान
c) हरियाणा
d) लाहौर

Q.6 बुडापेस्ट कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह साइबर अपराध पर एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय संधि है।
2. भारत इसका पक्षकार नहीं है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.7 गंगा नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह गंगोत्री ग्लेशियर से गंडक्रीवर के रूप में निकलती है।
2. गंगा नदी डॉल्फिन इस नदी में पाई जाती है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.8 राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) भारत की एक पहल है:

a) भारतीय रिजर्व बैंक
b) विश्व बैंक
c) एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी)
d) रिलायंस ग्रुप

Q.9 राष्ट्रीय मानसून मिशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है?

a) कृषि मंत्रालय
b) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
c) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
d) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

Q.10 जानवरों में पाए जाने वाले रोगाणुओं के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जंगली जीव, पशुधन और लोगों के बीच संपर्क के कारण फैल जाती है?

1. इबोला
2. जिका
3. निपा
4. एचआईवी

सही कोड का चयन करें:

a) केवल 1 और 4
b) केवल 1 और 3
c) केवल 1 और 2
d) केवल 1, 2 और 3

Q.11 जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर अंतर सरकारी विज्ञान-नीति मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

a) जर्मनी
b) फ्रांस
c) नॉर्वे
d) स्विट्जरलैंड

Q.12 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उत्प्रेषण(Certiorari) एक निचली अदालत या सरकारी एजेंसी के फैसले की न्यायिक समीक्षा करने के लिए एक अदालती प्रक्रिया है।
2. परमादेश (Mandamus): एक न्यायिक रिट जो एक अवर न्यायालय के आदेश के रूप में जारी की जाती है या किसी व्यक्ति को सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य करने का आदेश देती है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.13 मोटो टनल हाल ही में खबरों में था। यह कहा स्थित है?

a) पाकिस्तान
b) अफगानिस्तान
c) उज़्बेकिस्तान
d) भारत

Q.14 संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

a) ऑस्ट्रिया
b) ऑस्ट्रेलिया
c) नॉर्वे
d) डेनमार्क

Q.15 अवधनाम निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है?

a) कविताएं
b) नृत्य
c) ड्रामा
d) वास्तुकला

Q.16 एपीमेरल मैसेजिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह मल्टीमीडिया संदेशों का मोबाइल से मोबाइल ट्रांसमिशन है जो एक निश्चित अवधि के बाद गायब हो जाता है।
2. यह व्हाट्सएप द्वारा पहली बार विश्व स्तर पर लॉन्च किया जा रहा है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.17 बॉडी मास इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके रूप में मापा जाता है?

a) मीटर में ऊंचाई से विभाजित किलो में वजन
b) सेंटीमीटर में ऊंचाई के वर्ग से विभाजित किलो में वजन
c) सेंटीमीटर में ऊंचाई से विभाजित किलो में वजन
d) मीटर में ऊंचाई के वर्ग से विभाजित किलो में वजन

Q.18 भारत द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए EOS-01 उपग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है।
2. यह कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में उपयोगी होगा।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.19 टाइग्रेग्रेयन हाल ही में खबरों में था। यह कहाँ हैं?

a) इथियोपिया
b) सूडान
c) इरिट्रिया
d) तंजानिया

Q.20 सारनाथ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह बुद्ध द्वारा तीर्थयात्रा के चार स्थानों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है, जंहा उनके भक्त अनुयायियों को जाना चाहिए।
2. बुद्ध ने इस शहर में ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला शिक्षण धम्मचक्कपत्तनोत्सर्ग दिया था।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.21 हाल ही में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 'फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम (FDSS)' नामक एक तकनीक विकसित की है। यह किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है?

a) यात्री ट्रेनों के लिए
b) यात्री बसों के लिए
c) ऊंची इमारतों के लिए
d) नौसेना के जहाजों के लिए

Q.22 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मिशन शक्ति 'भारत की पहली एंटी-सैटेलाइट (ASAT) मिसाइल है।
2. भारत बाहरी अंतरिक्ष में अपनी संपत्ति की रक्षा करने की क्षमता वाला दुनिया का एकमात्र राष्ट्र है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.23 भारत मोबाइल कांग्रेस निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाती है?

a) दूरसंचार विभाग
b) सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
c) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
d) दोनों (a) और (b)

Q.24 केसर के पौधों को हाल ही में J&K से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में से एक स्थान में ले जाया गया था जहाँ उनमें लहलहाते हुए फूल खिले थे। पौधों को कहाँ ले जाया गया?

a) सिक्किम
b) अरुणाचल प्रदेश
c) असम
d) त्रिपुरा

Q.25 केसर की वृद्धि की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे रोजाना 8 घंटे की धूप की जरूरत होती है।
2. यह केवल गर्मियों में अच्छी तरह से बढ़ता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.26 यार्कोवस्की प्रभाव निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है?

a) क्षुद्रग्रह
b) उल्का
c) भूकंप
d) शनि के वलय

Q.27 वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान (SAFAR) के सिस्टम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह ISRO द्वारा विकसित किया गया है।
2. यह केवल प्रदूषकों के मापदंडों की निगरानी करता है

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.28 सरना धर्म हाल ही में खबरों में था। यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है?

a) मध्य प्रदेश
b) झारखंड
c) छत्तीसगढ़
d) बिहार

Q.29. कलवारी श्रेणी के डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी में से कौन सा हाल ही में लॉन्च किया गया था?

a) आईएनएस कलवरी
b) आईएनएस वागीर
c) आईएनएस खांदेरी
d) आईएनएस करंज

Q.30 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक मंदी एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रदर्शन में गिरावट की अवधि है जो कई महीनों तक रहती है।
2. अवसादों को अक्सर तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने वाली मंदी के रूप में पहचाना जाता है या जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 10% की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट होती है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.31 निम्नलिखित में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है?

a) इंडोनेशिया
b) मलेशिया
c) फिलीपींस
d) ब्रुनेई

Q.32 हाल ही में ज्वालामुखी द्वीपों के निम्नलिखित दूरस्थ समूह में से कौन सा अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा पूरी तरह से संरक्षित समुद्री भंडार घोषित किया गया था?

a) बैलेनी द्वीप समूह
b) अमेरिकन समोआ
c) एंटीपोड द्वीपसमूह
d) ट्रिस्टन दा कुन्हा

Q.33 केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और केंद्रीय सूचना आयुक्तों (ICs) की संख्या पांच से अधिक नहीं होगी, जिन्हें आवश्यक समझा जा सकता है।
2. उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट के बाद साबित हुए दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से CIC या IC को पद से हटाया जा सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1 और न ही 2

Q.34 हाल ही में रामसर साइटों में कौन सा जोड़ा गया?

1. लोनार झील
2. आसन संरक्षण रिजर्व
3. काबर ताल

4. सुर सरोवर

सही कोड का चयन करें

a) केवल 1 और 3
b) केवल 4
c) केवल 1 और 4
d) 1 और 2

Q.35 एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरता है?

1. वेनेजुएला
2. पेरू
3. अर्जेंटीना
4. ब्राजील
5. कोलंबिया

सही कोड का चयन करें:

a) केवल 1, 2 और 3
b) केवल 3 और 4
c) केवल 1, 2 और 4
d) केवल 1, 2, 3 और 5

Q.36 क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम (QRSAM) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. क्यूआरएसएएम एक कनस्तर-आधारित प्रणाली है।
2. प्रणाली चाल पर लक्ष्य का पता लगाने और ट्रैकिंग करने में सक्षम है और छोटे पड़ावों के साथ आकर्षक लक्ष्यों को पूरा करती है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.37 हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया गया था?

a) राजस्थान
b) गुजरात
c) उत्तर प्रदेश
d) बिहार

Q.38 नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के महत्वपूर्ण आंकड़ों पर रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अरुणाचल प्रदेश ने भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया है।
2. दमन और दीव ने भारत में सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.39 पारस्परिक पारस्परिक समझौते पर हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के बीच हस्ताक्षर किए गए?

a) जापान और ऑस्ट्रेलिया
b) यूएसए और ऑस्ट्रेलिया
c) भारत और यूएसए
d) भारत और जापान

Q.40 निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का भाग नहीं है?

a) ब्राजील
b) रूस
c) चीन
d) जापान

Q.41 निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है।
2. उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को तूफान कहा जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.42 भारत की पहली हरित ऊर्जा रूपांतरण परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू की जाएगी?

a) गोवा
b) राजस्थान
c) हिमाचल प्रदेश
d) ओडिशा

Q.43 जीआईएस एक जिला भारत का एक उत्पाद डिजिटल नक्शा हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था?

a) खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय
b) कृषि मंत्रालय
c) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय
d) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

Q.44 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. परम सिद्धि को हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर-वितरित कंप्यूटर सिस्टमों में शीर्ष 100 में स्थान दिया गया था
2. परम सिद्धि राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम) के तहत स्थापित उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एचपीसी-एआई) सुपर कंप्यूटर है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.45 Duchenne पेशी अपविकास (DMD) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह मुख्य रूप से महिलाओं को प्रभावित करता है।
2. यह प्रोटीन डाइस्ट्रोफिन के लिए जीन में एक उत्परिवर्तन के कारण होता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.46 विलो वार्बलर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह सबसे लंबे समय तक प्रवास करने वाले छोटे पक्षियों में से एक है।
2. IUCN लाल सूची की स्थिति कम से कम चिंताजनक है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.47 न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है?

a) ब्राजील

b) रूस
c) चीन
d) दक्षिण अफ्रीका

Q.48 तरलीकृत प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह मुख्य रूप से मिथेन के कुछ मिश्रण के साथ इथेन है।
2. यह डीजल की तुलना में 50% महंगा है।
3. इससे प्रदूषण बहुत कम होता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल1 और 3
b) केवल 3
c) केवल 1 और 2
d) केवल 2 और 3ही

Q.49. निम्नलिखित में से किस देश के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अपने नेविगेशन सिस्टम को मान्यता दी गई है?

1. जापान
2. संयुक्त राज्य अमेरिका
3. रूस
4. चीन
5. भारत

सही कोड का चयन करें:

a) केवल 1, 2 और 3
b) केवल 2, 3 और 4
c) केवल 2, 3, 4 और 5
d) केवल 1 और 3

Q.50 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रधानमन्त्री मत्स्यसंपदा योजना का लक्ष्य 2024-25 तक 22 मिलियन टन मछली उत्पादन प्राप्त करना है।
2. मछली पालन और एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF) केवल समुद्री क्षेत्र में मत्स्य पालन बुनियादी सुविधाओं के निर्माण को पूरा करता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 3
b) केवल ही
c) केवल 1 और 2
d) केवल 2 और 3

Q.51 सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SATAT) निम्नलिखित में से किस कचरे से गैस उत्पन्न करने के लिए प्रदान करता है?

1. नगर निगम का कचरा
2. कृषि अपशिष्ट
3. पशुपालन बर्बाद
4. समुद्री कचरा

सही कोड का चयन करें:

a) केवल 1, 2 और 3
b) केवल 3 और 4
c) केवल 1
d) केवल 1, 2, 3 और 4

Q.52 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एंटीबॉडी वसा से बनी होती हैं।
2. न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज में मानव शरीर के अंदर एक ही वायरस के प्रवेश को रोकने की क्षमता होती है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.53 डिमेंशिया और डेलारियम के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें:

1. डेलारियम की शुरुआत थोड़े समय के भीतर होती है। डिमेंशिया धीरे-धीरे खत्म हो जाता है।
2. ध्यान बनाए रखने की क्षमता डिमेंशिया से काफी प्रभावित होती है। प्रलाप के प्रारंभिक चरण में एक व्यक्ति आम तौर पर सतर्क रहता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.54 निम्नलिखित तकनीकों पर विचार करें जिन्हें हाल ही में बेहतर पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं के लिए अनुशंसित किया गया था:

1. प्रेस्टो ऑनलाइन क्लोरीनेटर पानी की कीटाणुशोधन के लिए एक बिजली आधारित ऑनलाइन क्लोरीनेटर है।
2. जोकसौ तकनीकिस एक इनबिल्ट सीवेज और रसोई उपचार प्रणाली है जिसमें केवल एरोबिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसे भूमिगत स्थापित किया जा सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.55 जलजीवन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका लक्ष्य प्रति परिवार 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना है।
2. इसका उद्देश्य 2030 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर में पानी की आपूर्ति करना है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.56 उमंग ऐप भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत विकसित किया गया था?

a) कृषि मंत्रालय
b) वित्त मंत्रालय
c) विदेश मंत्रालय
d) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय

Q.57 चीन चांग'ई -5 चंद्र मिशन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें जो हाल ही में खबरों में था:

1. यह 40 वर्षों में पहली बार है जो चंद्रमा के छुपे हुए भाग से रॉक के नमूने वापस लाने का प्रयास करेगी।
2. यह चंद्रमा के मॉन्स रोमकेरियन क्षेत्र में उतरेगा।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.58 ऋणात्मक-उपज बांड आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं?

a) केंद्रीय बैंक
b) केंद्र सरकारें
c) दोनों (a) और (b)

d) केवल निजी कंपनियाँ

Q.59 भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है?

a) सिक्किम
b) पश्चिम बंगाल
c) असम
d) बिहार

Q.60 सहकार प्रज्ञ को हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था?

a) कृषि मंत्रालय
b) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
c) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय
d) वस्त्र मंत्रालय

Q.61 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अलवणीकरण संयंत्र की तकनीक का प्रयोग किया गया है?

1. महाराष्ट्र
2. केरल
3. आंध्र प्रदेश
4. गुजरात
5. तमिलनाडु

सही कोड का चयन करें:

a) केवल 1, 2 और 3
b) 2, 3 और 5 केवल
c) केवल 1 और 3
d) केवल 1, 3, 4 और 5

Q.62 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भवई राजस्थान की एक लोक कला है।
2. नमन - महाराष्ट्र के रत्नागिरी में खेली गई प्राचीन लोक कला।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.63 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एफडीआई की अनुमति देता है?

1. सिगार का विनिर्माण
2. एटामिक एनर्जी
3. दूरसंचार सेवाएं
4. फार्मा क्षेत्र

निम्नलिखित में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और ही
b) केवल 2 और 4
c) केवल 3 और 4
d) केवल 3

Q.64 भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसमें राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा उठाए गए सभी प्रमुख कदम होंगे।
2. यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई जलवायु पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.65 ब्रेन फ़िंगरप्रिंटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?

a) अपराध में आरोपी की भागीदारी की जांच उसके मस्तिष्क की प्रतिक्रिया का अध्ययन करके की जाती है।
b) परीक्षण इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम के रूप में जाना जाता है एक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।
c) अभियुक्त की सहमति की आवश्यकता नहीं है।
d) आरोपी को उसके मस्तिष्क में होने वाले न्यूरॉन्स की ट्रिगर का अध्ययन करने के लिए अपराध से संबंधित दृश्य या ऑडियो क्लिप दिखाए जाते हैं।

Q.66 bioluminescence के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. केवल फफूंद और जीवाणु ही जीवविश्लेषण दर्शाते हैं।
2. यह आम तौर पर गहरे रहने वाले जीवों की तुलना में उथली प्रजातियों में अधिक है।
3. यह एक एंटी-प्रिडेटरी प्रतिक्रिया है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1 और 2ही
b) केवल 2
c) केवल 3
d) केवल 2 और 3

Q.67। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ब्रु जनजाति को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता देता है?

a) मिजोरम
b) असम
c) मणिपुर
d) त्रिपुरा

Q.68 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अल नीनो का तात्पर्य मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के ठंडा होने से है।
2. ला नीना अल नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO) का गर्म चरण है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

नवम्बर 2020 महीने के करेंट अफेयर्स MCQs की उत्तरकुंजी

1	A	18	C	35	D	52	B
2	D	19	A	36	C	53	A
3	A	20	C	37	A	54	D
4	A	21	B	38	A	55	D
5	A	22	A	39	A	56	D
6	C	23	D	40	D	57	C
7	B	24	A	41	D	58	C
8	A	25	D	42	A	59	D
9	C	26	A	43	A	60	A
10	D	27	D	44	C	61	D
11	A	28	B	45	B	62	B
12	C	29	B	46	C	63	C
13	A	30	C	47	C	64	A
14	A	31	D	48	B	65	C
15	A	32	D	49	C	66	C
16	A	33	B	50	B	67	D
17	D	34	C	51	D	68	D